FOR TNIGHTLY REVIEW

1952 G. K. U.

62

FORTNIGHTLY REVIEW

of News and Events

January 6 to January 19

62

1952

HINDI

Issued by the

BRITISH INFORMATION SERVICES

Eastern House, Mansingh Road, New Delhi

इस अंक के मुख्य संकलन:

... नए भारत के प्रति ब्रिटेन में सहानुभूतिमय अभिरूचि और उसके विषय में अधिक जानने की इच्छा है

न व भा र त में ब्रि टे न की रू चि

आएन स्टीवेन्स,
'स्टेट्समैन' (नई दिल्ली और
कलकत्ता) के भूतपूर्व सम्पादक जो
हाल में ब्रिटेन वापस गए।

ब्रिटन के समाचारपत्रों में भारतीय घटनाओं के विषय में अधिक नहीं छपता। भारत से ब्रिटेन गए व्यक्ति को , चाहे वह भारतीय अथवा ब्रिटिश हो , इस बात से पहले कुछ आश्चर्य हो सकता है । इससे एक अभाव का अनुभव होता है । अखबारी कागज की कमी के कारण पत्रों के आकार में कमी इसका एक कारण हो सकता है। पर यह एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता ।

पर आगन्तुक को शीघ्र ही इस बात का कि भारतीय विषयों के प्रति अप्रत्यक्ष किन्तु सजीव रुचि है पता चल जाएगा । उसे यह रेल की यात्रा अथवा होटलों इत्यादि में लोगों से बात करने पर मालूम होगा । भारत को न वे लोग

... भूले हैं

भूले हैं जिन्होंने स्थिर पदों पर से उसकी सेवा की थी और न सेनाओं के वे नवयुवक जिन्हें युद्ध की ज्वारभाटा कुछ समय के लिये भारत ले गई थी। इंग्लैंड में नव आगन्तुक से उत्सुकताभरे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न प्राय: उचित और जानकारीयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, एकबार जब मैं हाल में रेल से यात्रा कर रहा था मुझे मालूम हुआ कि मेरे दोनों साथी उन दिनों भारत में रह चुके थे। एक वायुसेना और दूसरे स्थल सेना में थे। परिणामत: यात्रा की समाप्ति तक मेरा गला बैठ गया था; इधर रेल की गड़गड़ाहट से कान फटे जा रहे थे, उधर, ये लोग सवाल के बाद सवाल पूछ रहे थे।

स्वतन्त्रता के समय से सफलताएँ

स्वतन्त्रताप्राप्ति के समय से भारत की बड़ी सफलताओं में से कईयों के विषय में लोग जानते हैं। कम से कम इनकी रूपरेखा वे पहचानते हैं। इस समय तो ध्यान स्वाभाविकतया भारत के साधारण निर्वाचन पर जमा है: यह निर्वाचन मनुष्य के इतिहास की एक अद्वितीय घटना है। इतना विराट निर्वाचन, ऐसी जनसंख्या से जिसमें इतने अधिक लोग अपढ़ हैं न्यायोचितरूप से मत दिलवाने का प्रबन्ध — इनसे ब्रिटिश जनता का मन बहुत प्रभावित हुआ है।

यह बात भी ब्रिटेन में भलीभांति समझी जाती है कि इतना विराट मताधिकार नए संविधान के परिणामों में से एक है। और स्वयं यहसंविधान एक महान कार्य था। यह शीघ्रता से सम्पादित हुआ था। और जब, गणराज्य बनने तथा मुकुट के चिन्ह को छोड़ने के बाद भी, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा तो ब्रिटेन के लोगों को स्वभावत: सन्तोष — यद्यपि प्रारंभ में कुछ आश्चर्य — हुआ।

क्या निर्वाचन के फलस्वरूप एक ठोस संसदीय प्रतिपक्ष उत्पन्न होगा? यह प्रश्न प्राय: पूछा जाता है। एकदलीय शासन राष्ट्र-निर्माण और संक्रमण के समय के लिये अनुचित नहीं समझा जाता। पर यदि वह जारी रहा तो यह सोचा जाएगा कि भारत में जनतन्त्र उचितरूप में विकसित नहीं हो रहा।

अन्य सफलताएँ, जिनके विषय में नव भारत अभिमान कर सकता है शायद कम पहचानी जाती हैं। और इनके सम्बन्ध में आगन्तुक द्वारा जानकारी दी जा सकती है।

.... इनमें से

इनमें से एक प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने में उच्चतर असैनिक और सैनिक अधिकारियों की सफलता है। इस विषय पर प्रकाश डालने में आगन्तुक — यदि वह ब्रिटिश है तो — अपने को विशेष रूप से अच्छी स्थिति में पाता है। १९४७ में प्रशिक्षित ब्रिटिश कर्मचारियों के इतनी बड़ी संख्या में हट जाने से एक भयंकर अन्तर, एक अभाव, की अवस्था उत्पन्न हो गई थी। स्तरों में बड़ी अवनति और असाध्य आपत्ति तक की आशंकाएं सामने थीं। पर ऐसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सामान्यतया अनुचित सिद्ध हुईं। मेरा विश्वास है कि ऐसा कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति, जो स्वतन्त्रता के पश्चात् वाले समयों में भारत में रह चुका है, यह अस्वीकार नहीं करेगा कि उच्च सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों का समुदाय अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकुशलता का सुन्दर परिचय दे चुका है। और क्योंकि ये योग्य भारतीय मौलिकरूप से ब्रिटिश-प्रशिक्षित व्यक्ति थे इसलिए इस बात से भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन को भी सन्तोष हो सकता है।

विभाजन की विपत्तियों पर विजय

कार्यपालिका की और न्यायपालिका की अबतक स्वतन्त्र प्रवृत्ति, विभाजन के कारण पदच्युत प्राणियों की इतनी विशाल संख्या के पुनर्वास में प्रगति, सरदार पटेल द्वारा पुरानी रियासतों को नव भारत में मिलाने के प्रभाव और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत की सफलताएं — ये हैं अन्य सराहनीय बातें।

ब्रिटिश जनता अभीतक भलीभांति नहीं समझती कि, सीमाओं के दोनों ओर, पुनर्वास की समस्या कितनी विकराल थी, कि शरणार्थियों की विशाल संख्या ने सामान्यतया कैसा धैर्य दिखाया, यथाकाल व्यवस्था की कैसी क्षमता प्रदर्शित की। यह कहना सम्भवत: सत्य होगा कि संसार के अन्य कोई दो देश विभाजन की विपत्तियों पर ऐसी विधियों से विजय न प्राप्त कर सकते।

इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वतन्त्रता के समय से भारत की जो नीतियां रही हैं उनमें से किसी ने भी आलोचना के अवसर नहीं दिए। नहीं, आलोचना के विषय तो कई रहे हैं। विशेषतया, अपने सबसे पास के पड़ोसी : और वह भी राष्ट्रमंडल के एक साथी देश : के साथ भारत के असन्तोषप्रद सम्बन्ध गहरी चिन्ता उत्पन्न करते हैं। किन्तु अपने अधिक विस्तृत अंगों में भारत की विदेशी नीति

... ब्रिटेन की

ब्रिटेन की भावना के कुछ अंगों के अनुकूल प्राय: रह चुकी है । सचमुच, १९५० में कुछ समय के लिये श्री० नेहरू सुदूरपूर्व के मामलों में और साम्यवाद की ओर प्रवृत्ति के विषय में ब्रिटिश विचारधारा की महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रधानतम प्रवक्ता बन गए थे। हां, उस समय से कुछ मतभेद उत्पन्न हुए ।

यद्यपि भारतीय विषयों को ब्रिटिश पत्रों में अधिक स्थान नहीं मिलता, यद्यपि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों से रह रहकर गहरी चिन्ता उत्पन्न होती है पर ब्रिटेन में नव भारत के विषय में सहानुभूतिमय अभिरूचि और अधिक जानने की इच्छा पाई जाती है ।

काश्मीर के विषय में 'टाइम्स' ने लिखा है : डाक्टर ग्रैहम का धैर्यपूर्ण कार्य व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने दोनों पक्षों के अन्तर को घटा दिया है। इसके बाद पत्र

काश्मीर की समस्या

दोनों पक्षों का अन्तर घटा

ने आगे की प्रगति के लिये असैन्यीकरण, शस्त्रपात रेखा के दोनों ओर के सैन्यबलों की संख्या और जनमत संग्रह प्रशासक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि — इन तीनों बातों पर भारत तथा पाकिस्तान में सहमति की आवश्यकता का उल्लेख किया है। आगे चलकर पत्र ने लिखा है : जबतक निर्वाचन के बाद भारत की नई सरकार पद ग्रहण नहीं करती तबतक पाकिस्तान के साथ की तनातनी को कम करने के लिये दिल्ली से कोई उपयोगी चरण नहीं उठाया जा सकता। यदि निर्वाचन के बाद अधिकार की बागडोर फिर श्री० नेहरू के हाथों में आती है — और यही सम्भावना दीखती है — तो पाकिस्तान के प्रति समझौते की नीति अपनाने में (यदि वे चाहें तो) वे अपने को पर्याप्त रूप से शक्तिशाली पा सकते हैं। यह शायद एक आशाप्रद लक्षण है कि उस सैन्यबल के मौलिक अनुमान में जो वह काश्मीर में रखना आवश्यक समझता है भारत ७,००० की कमी करने पर राज़ी हुआ। फिर भी भारत द्वारा स्वीकृत संख्या और उस संख्या में जो पाकिस्तान उचित समझता है एक बड़ा अन्तर बना हुआ है।

'काश्मीर में आशा' शीर्षक से 'डेली टैलीग्राफ' ने सुरक्षा परिषद में श्री० मलिक के 'अत्यन्त आश्चर्यजनक' शब्दों को डाक्टर ग्रैहम के कार्य की एक प्रकार की अप्रत्यक्ष प्रशंसा कहा है। मलिक द्वारा डाक्टर ग्रैहम पर अमेरिकन प्रतिरक्षा विभाग के गुप्त एजेंट होने और ब्रिटेन तथा अमेरिका पर काश्मीर के झगडे को बढ़ाने के प्रयत्न का दोषारोपण केवल दूषित विचारशैली और कल्पना ही नहीं प्रकट करता। वास्तव में मलिक ने यह भय प्रकट किया है कि कहीं भारत और पाकिस्तान के मतभेदों का अन्त न हो जाए और कहीं काश्मीर को इन दोनों महान राज्यों का सामान्य संरक्षण न मिलता रहे — उस आशंका और धमकी के विरुद्ध जो साम्यवादीकृत सिंकियांग तथा चीनी अधिकृत तिब्बत जैसे उसके पड़ोसियों की ओर से इनके सामने उपस्थित है।

अमेरिकन कांग्रेस में चर्चिल का भाषण

कठिनाइयों पर विजय की ब्रिटिश योग्यता का आश्वासन

अमेरिकन कांग्रेस के सम्मुख श्री० चर्चिल के भाषण पर 'टाइम्स' ने १७ जनवरी के अंक में लिखा है : श्री० चर्चिल का भाषण ऐसे व्यक्ति का भाषण था जिसे पारस्परिक समझ प्राप्त करने में विश्वास है, जो अपने लक्ष्य को भलीभांति जानता है और जो अन्तत: सफलता को निश्चय मानता है। यदि ब्रिटेन और अमेरिका में मध्यपूर्व तथा सुदूरपूर्व विषयक नीतियों के सम्बन्ध में अभी तक सम्पूर्ण मतैक्य नहीं हुआ है तो भी इतना अवश्य हुआ है कि इनके विषय में उन्होंने मिलजुलकर अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है।

श्री० चर्चिल की यात्रा से पहले, पत्र ने आगे चलकर कहा है, यह भय था कि कहीं दोनों राष्ट्र योरप की समस्याओं में ही न उलझ जाएं, कहीं निश्चय के साथ ये न सोचने लगें कि योरप की रक्षा केवल शस्त्रास्त्रों से हो सकती है, कहीं रशिया में साम्यवाद के खतरे की उपेक्षा न करें। यद्यपि यह भय अब सम्भव नहीं दीखता पर इन दोनों राजनीतिज्ञों का कर्तव्य है कि लोगों को यह स्पष्टतया समझाएं कि उन्होंने इस भ्रम का परित्याग कर दिया है कि प्रत्येक समस्या का उत्तर अधिकाधिक शस्त्रास्त्र में निहित है — हां, शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता तो बहुत है — और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने की तैयारी से ही सारी समस्याओं का समाधान सम्भव है।

जहांतक योरप की एकता और उसके बचाव की बात है, इन सब विषयों में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिये ब्रिटेन को क्षमा याचना करनी पड़े। वास्तव में, इस विषय में ब्रिटेन अपने कई कार्यों पर गर्व कर सकता है। यह बहुत समय से आवश्यक था कि कोई इस बात को प्रकट करे। और श्री० चर्चिल के अतिरिक्त अन्य कौन इस विचार को प्रकट कर सकता था? उन्होंने इतने ही बलपूर्वक बताया था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल अटलांटिक के किसी और किसी योरोपीय व्यवस्था के अन्दर एक राज्य अथवा राज्यों का समूह बनने के लिये तैयार नहीं है। यदि श्री० चर्चिल की यात्रा से और कुछ नहीं तो इन विषयों में ब्रिटेन के भाग पर बहुत कुछ उचित जानकारीविहीन और अनुचित आलोचना का अन्त हो सकेगा।

स्टर्लिंग क्षेत्रीय संचयों की कमी के कारण

भुगतान सन्तुलन के सुधारार्थ ब्रिटिश विधियां

जान किंग्सले

१९५१ के अन्तिम त्रैमासिक के दौरान में स्टर्लिंग क्षेत्रीय स्वर्ण और डालर संचयों में, जैसाकि अनुमान किया गया, बहुत भारी कमी हुई थी। यह कमी ९४,००,००,००० डालर थी। पर इसमें १७,६०,००,००० डालर की वह रकम सम्मिलित थी जो अमेरिका तथा कैनेडियन क्रेडिट (ऋण) और ब्रिटेन के लिये अमेरिकी उधार-पट्टा ऋण के लेनदेन की प्रथम किश्त के रूप में दी गई।

इस प्रकार सामान्य 'व्यापारिक' घाटा ७६,४०,००,००० डालर रहा जिसमें से ३२,००,००,००० डालर अक्तूबर में कम हुए थे। जबकि इसकी तुलना में १९५१ के तीसरे त्रैमासिक में ६३,८०,००,००० डालर का घाटा हुआ था और दूसरे में ५,४०,००,००० डालर तथा प्रथम त्रैमासिक में ३६,००,००,००० डालर की बचतें हुई थीं।

चौथे त्रैमासिक में प्राप्त किये गये मार्शल सहायता के ६०,००,००० डालर जमा करने के बाद संचयों का सन्तुलन ३१ दिसम्बर को २,३३,५०,००,००० डालर रहा जबकि इस की तुलना में सितम्बर के अन्त में ३,२६,९०,००,००० डालर और ३० जून १९५१ को ३,८६,७०,००,००० डालर (युद्धोत्तरकालिक उच्चतम स्तर) था। १९४९ के तीसरे त्रैमासिक के अन्त में, स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कुछ दिनों बाद, सम्पूर्ण रकम केवल १,४२,५०,००,००० डालर था। इसलिये स्वर्ण और डालर का क्रय मूल्य तब से गिर गया है।

... पिछले वर्ष

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में भारी कमी के कारणों पर विचार करते हुए यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ये संचय केवल ब्रिटेन के ही काम नहीं आते बल्कि आस्ट्रेलिया, लंका, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिणी रोडेशिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य-क्षेत्रों के साथ साथ आयरिश गणराज्य, बर्मा, आइसलैंड तथा जार्डन जैसे अराष्ट्रमंडलीय देशों का काम भी निकालते हैं। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका स्टर्लिंग क्षेत्र का एक सदस्य होते हुए भी अपनी दुर्लभ मुद्रा की आवश्यकताएं स्वयं पूरी करता है। केवल लंका और कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों को छोड़कर सारे ही सदस्य हाल के महीनों में स्वर्ण तथा डालर के घाटे प्रकट कर रहे हैं।

स्टर्लिंग क्षेत्रीय घाटा

ऐसे घाटे केवल डालर क्षेत्र के ही साथ नहीं हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों के साथ वाले घाटे शायद उतने ही बड़े हैं जितना कि डालर घाटा। इकट्ठा होने वाला यह घाटा, जो ब्रिटेन हाल के महीनों में आंशिकरूप से स्वर्ण में योरोपीय भुगतान संघ को चुका रहा है, वास्तव में सम्पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र का घाटा है। यही बात संसार के अन्य भागों में हो रही है या आगे चलकर हो सकती है। ये सारे भुगतान, वे चाहे किसी भी देश की ओर से हों, केन्द्रीय संचय से निकलते हैं।

विस्तृत रूप से देखा जाए तो हाल की प्रवृत्ति के तीन मुख्य कारण रहे हैं: स्टर्लिंग क्षेत्रीय निर्यातों से होने वाली डालर आमदनी में गिरावट जिसमें ब्रिटेन की तैयार चीज़ों और विदेशी स्टर्लिंग क्षेत्रीय सामग्रियों जैसे दोनों तरह के निर्यात सम्मिलित हैं, डालर आयातों का एक निरन्तर उच्चस्तर उस हालत में जबकि ब्रिटेन की चौथे त्रैमासिक की सम्पूर्ण संख्या तीसरे त्रैमासिक की संख्या की तुलना में अपरिवर्तित थी पर बाकी क्षेत्र की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी और योरोपीय भुगतान संघ के साथ भारी घाटे का जारी रहना।

ब्रिटेन के मामले में मुख्य कारण ये थे : १. आयातों की लागत में एक भारी वृद्धि। अधिक ऊंची कीमतों ने १९५१ के आयात खर्च में अनुमानतया अस्सी करोड़ पौंड से नब्बे करोड़ पौंड तक वृद्धि कर दी थी, जबकि सामरिक सामग्री-संग्रह १९५० में कम हुए व्यावसायिक संग्रहों के पुनर्निर्माण और पश्चिमी योरप के साथ व्यापार खुलने की सुविधा के फलस्वरूप बढ़े हुए आयातों के लिये और भी तीस करोड़ पौंड की आवश्यकता थी।

... इस बात

२.इस बातने अन्तर को विस्तृत कर दिया कि निर्यात मूल्यों की वृद्धि आयात मूल्यों की तुलना में पीछे रही थी। निर्यात के उसी परिमाण से हुई अतिरिक्त आमदनी शायद तीस करोड़ से चालीस करोड़ पौंड तक से अधिक नहीं बैठी, जबकि निर्यातों के परिमाण में की गई वृद्धि से कोई दस करोड़ पौंड का लाभ हुआ था। ३. ईरानी तेल की हानि कोई ३५,००,००,००० डालर वार्षिक की दर से अतिरिक्त डालर खर्च उत्पन्न कर रही है। यह ध्यान रखने की बात है कि इसका एक भाग स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य सदस्यों की ओर से खर्च किया जाता है। तेल राज्यकर भुगतान और जगह बढ़ गये हैं। ४. अमेरिकी और कैनेडियन डालर ऋणों के ब्याज और ऋणांश का भुगतान। ५. विदेशों में सैनिक खर्च में हुई वृद्धि।

अन्य सदस्यों के घाटों के मुख्य कारण ये रहे हैं: सामग्री मूल्यों के उन अधिक ऊँचे स्तरों में गिरावट जो १९५१ के प्रारम्भ में चल रहे थे, सामग्रियों की विश्व खरीद में कमी और उस समय सभी तरह के आयातों का एक ऊंचा स्तर होना जब निर्यातों की कीमतों के बहुत ज्यादा बढ़ने से घरेलू सम्पन्नता पैदा होगई थी। निर्यातों की गिरावट का एक विशेष उदाहरण अमेरिका की वह नीति है जिससे मार्च, १९५१ के बाद मलाया के टिन की खरीदारियों को रोका गया था।

नई ब्रिटिश विधियां

ब्रिटेन संचयों का उस कमी को घटाने के लिये सक्रिय और कठोर विधियां अपना रहा है जिसका कारण वह स्वयं है। साढ़े तीस करोड़ पौंड मूल्य वार्षिक के आयातों में आजकल वे कटौतियां की जा रही हैं जो पिछले नवम्बर में घोषित की गई थीं। निर्यात बढ़ाने के लिये नई नीतियां तैयार की जा रही हैं; विशेषतया इंजीनियरिंग, पूंजीगत और अन्य धातु-प्रयोगक सामान के सम्बन्ध में। आवश्यक सप्लाइयों को घरेलू बाजार के लिये होने वाले बटवारों को घटाकर और उत्पादन में अधिकाधिक किफायत के साथ कच्ची सामग्री आयातों के बढ़े हुए प्रयोग तथा अन्य तरीकों के जरिये पूरा किया जायेगा।

राष्ट्रमंडल का वित्त सम्मेलन

'परिणाम से सन्तोष का कारण'

जनवरी १५ को लन्दन में राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन प्रारम्भ हुआ था। इसने स्टर्लिंग क्षेत्र की गम्भीर समस्याओं पर सोचविचार किया था। सम्मेलन की समाप्ति पर प्रकाशित विज्ञप्ति के विषय में 'डेली टेलीग्राफ' ने कहा है कि मंत्रियों के विचार विनिमय पर सन्तोष करने का अच्छा कारण दीखता है। पत्र के विचार से सम्मेलन में एकत्रित वित्तीय मंत्रियों में से कई श्री० बटलर के उदाहरण से — सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता और प्रत्यय पर प्रतिबन्ध — प्रभावित हुए थे और स्वयं अपने देशों में ऐसे उपायों से काम लेंगे। आगे चलकर पत्र ने कहा है कि वर्तमान संकट का सामना करने से ही काम न चलेगा : भविष्य में ऐसे संकट रोकने के उपायों पर भी सोचविचार आवश्यक है। समस्याओं के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए दो आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी : प्रत्येक देश साधन और शक्ति की सीमा के बाहर न जाने का दृढ संकल्प ले। दूसरी आवश्यकता उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने की है। 'यार्कशायर पोस्ट' ने लिखा है : सोने और डालर की भयंकर कमी को रोकने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकट हो रही है। सम्मेलन के अन्त में श्री० बटलर ठोस उन्नति की सूचना दे सके।

** ** **

कोलम्बो योजना के उद्देश्यों का निदर्शन

प्रदर्शिनी का आयोजन

अगले महीने कोलम्बो में होने वाली कोलम्बो योजना प्रदर्शिनी में चाय उद्योग का बहुत जोरदार प्रदर्शन किया जायेगा। इन्टर्नेशनल टी मार्केट एक्सपेन्शन बोर्ड (अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार विस्तार मंडल) एक ऐसा मंडप तैयार कर रहा है जो चाय उद्योग का एक सम्पूर्ण चित्र और चाय उत्पादक देशों की अर्थ व्यवस्था में इसका महत्वं प्रकट करेगा। इस प्रदर्शिनी का मुख्य अभिप्राय, जो लंका सरकार द्वारा संगठित की जा रही है, यह है कि अविकसित राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिये कोलम्बो योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाले। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की आवश्यकताओं के अलावा पूंजीगत सामान तथा टेक्निकल सहायता रूपीउस अंशदान पर भी प्रकाश डाला जायेगा जो राष्ट्रमंडलीय देशों और अमेरिका द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये दिया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सभा में विशिंस्की के प्रस्ताव का अर्थ

रूस के मनोरथ

डब्ल्यू०एन०ईवर

सोवियट राजनीतिज्ञ अपनी चालों के उद्देश्य सदैव छिपाना चाहते हैं। मैं इसे उनके सिद्धान्त का स्वाभाविक परिणाम समझता हूं : इस सिद्धान्त की दृष्टि में समस्त सम्बन्ध विरोधियों के मध्य के संघर्ष होते हैं।

सोवियट की कूटनीतिक चालों से पहले सार्वजनिक वाद विवाद के रूप में प्राक्कथन नहीं हुआ करता : इन चालों का अर्थ जितना कम सम्भव हो उतना कम समझाया जाता है। फलत: दूसरों को सोवियट की करनी और कथनी के अर्थ और उनके लक्ष्य समझने के प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसीलिये संयुक्त राष्ट्रीय सभा के सम्मुख प्रस्तुत नवीनतम प्रस्ताव के उद्देश्य को विशिंस्की अथवा उनके साथियों की ओर से किसी प्रकार की सहायता बिना हमें समझना है।

प्रस्तावों में से दो के विषय में कठिनाई नहीं है। 'सामूहिक उपाय समिति' को हटाने से सम्बन्धित प्रस्ताव केवल यह दिखाता है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सोवियट निषेधाधिकार का निशाना बने बिना किसी कार्य का करना कितना अप्रिय है। दूसरा प्रस्ताव समय समय पर सुरक्षा परिषद की सभा बुलाने की बात कहता है। यह तो स्पष्टतया प्रचार लगता है। रूस ने सम्भवत: यह सोचा था कि पश्चिमी शक्तियां इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगी —(कारण , पिछले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति को घटाने की विधियों पर सोचविचार के लिये चार राष्ट्रों के मध्य सम्मेलन का उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ था।) और तब सोवियट के प्रस्ताव

... को अस्वीकार

को अस्वीकार करने के कारण पश्चिमी शक्तियों पर दोषारोपण करना सम्भव होगा — 'कोल्ड वार' की समाप्ति के सोवियट प्रयत्न को बेकार करने का ।

पर सचमुच रोचक तो तीसरा प्रस्ताव है । इसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद कोरिया में चल रही युद्ध बन्दी बातचीत को सफल बनाने की विधियां सोचे। इस प्रस्ताव को देखते ही लगता है कि स्थिति को सुधारने में इससे सहायता नहीं मिल सकती । यह तो निरर्थक तक कहा जा सकता है । उस समय जब श्री० विशिंस्की ने सुरक्षा परिषद को घसीटने का विचार प्रकट किया था पानमुंजान में चल रहा विचार विनिमय युद्ध विराम काल में नई वायुभूमियों के निर्माण तथा बन्दियों के विनिमय की विधियों जैसे विषयों से टक्कर खाकर आगे बढ़ने से असमर्थ हो गया था । यह सोचना ही कि ऐसे विषयों पर एक ही समय पानमुंजान में सैनिकों और पेरिस में राजनय के विशेषज्ञों द्वारा बातचीत की जाए बेढंगी बात लगती है । हमें तो परिस्थिति को अस्पष्ट बनाने और विलम्ब कराने की सम्पूर्ण सामग्री इसमें मिलती है ।

यह एक बात हो सकती है । कौन जाने , सोवियट सरकार किसी कारण से यह सोच रही है कि यदि चीनी और संयुक्त राष्ट्रीय अधिकारीगण हस्तक्षेप से मुक्त हों तो सारे बचेखुचे विषयों पर समझौता कर लेंगे , कि युद्ध विराम हो जाएगा, कि रूस के दृष्टिकोण से यह अच्छा न होगा । यह सम्भावना भी दीखती है ।यदि यही बात है तो इससे अधिक अच्छा क्या हो सकता है कि यह बातचीत सुरक्षा परिषद में लाई जाए ताकि सोवियट प्रतिनिधि यदि समझौता रोक न सके तो कम से कम उसमें विलम्ब करा पाए ।

मास्को पीकिंग सम्बन्ध

पर इस तर्क के अनुसार तो हमें इस विश्वास को अपना आधार बनाना है कि युद्ध विराम के विषय में मास्को और पीकिंग के उद्देश्य एकसे नहीं हैं । तब तो यही समझना पड़ेगा कि पीकिंग युद्ध रोकना चाहता है पर उसे ऐसा करने से मास्को रोकना चाहता है । यह असम्भव नहीं है : पर इस तर्क को औचित्य देने वाला कोई प्रमाण भी पास नहीं है । मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मास्को और पीकिंग दोनों युद्ध विराम चाहते हैं , यद्यपि वे अपनी अपनी कराने की पूरी कोशिश करेंगे पर युद्ध विराम के पक्ष में निर्णय ले चुके हैं ।

... पर यदि

पर यदि ऐसी बात है तो, रूस के दृष्टिकोण से, पानमुंजान में हुए उस युद्ध विराम में जिसमें सोवियट ने भाग न लिया हो तथा पेरिस अथवा न्यूयार्क में सोवियट के साथ हुए युद्ध विराम में बहुत बड़ा अन्तर है। यदि लड़ाई समाप्त होने जा रही है तो रूसी यह कहना चाहते हैं कि उन्हीं के हस्तक्षेप के कारण यह समाप्त हुई। वे कोरिया में शान्ति की पुनर्स्थापना का श्रेय लेना चाहेंगे — विशेषरूप से एशिया में। जहांतक उनके बस की बात है, युद्ध को रोकने का श्रेय वे संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा चीन को न लेने देंगे। स्तालिन का शान्ति के दूत के रूप में प्रकट होना तो बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्व एशिया में रूस की लम्बी अवधि की नीति के लिए यह इस समय आवश्यक है कि युद्ध रुक जाए। १६५० की योजना तो असफल रही। अब लड़ाई के जारी रहने में कोई लाभ नहीं। यद्यपि सोवियट यूनियन ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था पर उसके साधनों और यातायात व्यवस्था पर जो बोझ पड़ा वह अल्प अथवा साधारण नहीं कहा जा सकता।

यों लड़ाई के जारी रहने में कोई लाभ नहीं है। युद्ध विराम के पश्चात् जैसी सन्धि की सम्भावना दीखती है उससे उसे निश्चित लाभ हो सकता है — सच तो यही है। रूस के दृष्टिकोण से उस शान्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसकी वह आशा कर रहा है वह होगा जिसमें कोरिया से न केवल संयुक्त राष्ट्रीय सेना पर चीनी सेना के हटाने की बात भी कही जाएगी।

समस्त कोरिया की मुक्ति और उसके संयुक्तीकरण को रोकने के लिए मास्को ने चीन के हस्तक्षेप को स्वीकार किया था। स्वयं रूस के हस्तक्षेप को छोड़ते हुए सामने बस यही मार्ग था। और स्तालिन उन आपत्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहते थे जो वे स्वयं रूस के हस्तक्षेप में देखते थे — यदि इस काम के लिये वे एक साथी की सहायता पा सकते थे।

स्तालिन के उद्देश्य

स्तालिन यह नहीं चाहते कि चीनी उत्तरी कोरिया में आवश्यकता से अधिक समय तक रहें। वे नहीं चाहते कि उत्तरी कोरिया चीनी कठपुतली बने, कि वह चीन के प्रभाव में आए।

... रूस को

रूस को उस अवस्था में वापस लाना जो , १६०४ के रूसी- जापानी युद्ध के पहले , उत्तर पूर्व एशिया में उसे प्राप्त थी , यही स्तालिन का लक्ष्य है । इस लक्ष्य का प्रमाण स्तालिन के उन शब्दों में मिलता है जो , जापान के आत्मसमर्पण के समय, उन्होंने कहे थे । इस लक्ष्य में मन्चूरिया पर रूसी नियन्त्रण और , यदि सारे कोरिया पर सम्भव न हो तो , यथासम्भव बड़े भाग पर रूस का नियन्त्रण सम्मिलित हैं ।

यह निस्सन्देह अन्तत: लक्ष्य है । और जब यह बात इतनी स्पष्ट है तो तात्कालिक उद्देश्य , १६४५ से १६५० तक की भांति , उत्तरी कोरिया को सम्पूर्ण सोवियट नियन्त्रण में लाना है । यहां यह कहना असंगत न होगा कि उत्तरी कोरिया की सेना (चीनी सेना के विपरीत) सम्पूर्णतया रूसी प्रशिक्षित , रूस से साधन सामग्री प्राप्त और रूस द्वारा नियंत्रित है और युद्धकाल में ऐसी ही थी ।

इसलिये रूस के लिये उत्तरी कोरिया से चीन का हटना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दक्षिणी कोरिया से संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं का हटना । जैसा कि स्तालिन ने एकबार कहा था , रूस अन्य किसी के हित की चिन्ता नहीं करता , उसे चाहिये हित केवल अपना । अतएव क्रेमलिन के दृष्टिकोण से यह बड़ी अच्छी बात होगी कि रूस युद्ध विराम वार्ता के समाप्त होने से पूर्व उसमें यथासम्भवशीघ्र सम्मिलित होने पाए ।

उ द् दे श्य औ र उ पा य

* ` ऐसा बांध बनाना जिसके पीछे स्वतन्त्रता फलफूल सके `
* ` अपने घर की स्थिति सुधारने का दृढ संकल्प `
* ` इस कार्य में अपने हाथ हम लगा चुके हैं ... इसे हम अवश्य करेंगे `
* ` सूडान के लिए १९५२ एक महत्वपूर्ण वर्ष `

स्वतन्त्र जनतन्त्रों ने अधिनायकतन्त्रवादी सिद्धान्तों को उनके गुण-दोषों के आधार पर अस्वीकार कर दिया । ये सिद्धान्त बलात् लादे नहीं जा सकते । ऐसा करना पूर्वजों से प्राप्त गुणों के प्रति विश्वासघात होगा । हमारी सशस्त्र शक्ति का उद्देश्य है ऐसा बांध बनाना जिसके पीछे स्वतन्त्रता का फलना फूलना सम्भव हो सके। यदि यह बांध बना रहता है तो स्वतन्त्रता भय पर निस्सन्देह विजय प्राप्त करेगी। उस नई शक्ति का उपयोग , जिसका निर्माण हम कर रहे हैं , हम अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहते ।

एन्टनी ईडैन ,
विदेश मन्त्री —— ११ जनवरी

** ** **

आजकल ब्रिटेन एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है । यह संकट युद्ध के समय से तीसरा है और सबसे अधिक बुरा है । चाहे कुछ हो , चाहे जितना बलिदान आवश्यक हो , हम अपने घर की स्थिति सुधारने का दृढ संकल्प ले चुके हैं : साथ ही साथ

... हम स्वतन्त्र

हम स्वतन्त्र संसार की रक्षा में भी अपना पूरा भाग लेना चाहते हैं। यह कोई न सोचे कि अब हमारे लिए अपनी स्थिति को सुधारना सम्भव नहीं है। पहले भी लोग ऐसा सोच चुके हैं और इस भूल का कठोर सबक सीख चुके हैं। यद्यपि ब्रिटेन इस समय आर्थिक दृष्टि से पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिहीन हो गया है पर समूचा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल पहले से अधिक बलशाली बन गया है।

लार्ड इस्मे
राष्ट्रमंडल सम्बन्ध सचिव
१४ जनवरी

** ** **

दो महीने पूर्व, संकटकालिक नीति सम्बन्धी उपाय प्रकाशित करते समय, मैंने संसद को बताया था कि, यदि स्टर्लिंग का बल बनाए रखने के लिए अन्य किसी कार्य की आवश्यकता पड़ी, तो हम उसे करने में संकोच न दिखाएंगे। तब मैंने कहा था : स्टर्लिंग को सबल बनाने और सबल बनाए रखने के हमारे उद्देश्य में किसी को सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उद्देश्य के अतिरिक्त हमारी योग्यता में सन्देह करना भी आवश्यक नहीं है। देश की आर्थिक शक्ति के पुनर्निर्माण और दृढ़ आधार पर उसकी स्थापना : इस कार्य में अपने हाथ हम लगा चुके हैं। चाहे कुछ हो, यह हम अवश्य करेंगे।

आर०ए० बटलर,
ब्रिटिश वित्त मन्त्री : ७ जनवरी

** ** **

सूडान के लिये १९५२ एक महत्वपूर्ण वर्ष बनने जा रहा है। क्योंकि वर्ष की समाप्ति से पूर्व सूडानियों को सूडानी मंत्रिमंडल सहित स्वशासन का संविधान मिलने वाला है। इस मंत्रिमंडल को सूडान की वर्तमान सरकार (जिसके प्रमुख महाराज्यपाल हैं) की सत्ता नई सूडानी सरकार को सौंपने की प्रक्रिया के अन्तिम चरणों का प्रबन्ध करना होगा।

सर जेम्स रावर्टसन,
सूडान सरकार के असैनिक सचिव
७ जनवरी

उ च्च आ द र्श प र आ च र ण

*****

राजा जार्ज का जीवन

इन पंक्तियों के लेखक, हैक्टर बोलीथो 'ए सेंचुरी आफ ब्रिटिश मानर्की' नामक पुस्तक के लेखक हैं। 'देयर मैजेस्टीज़' नामक इनकी नई पुस्तक इस वर्ष प्रकाशित होगी।

वसन्त ऋतु में राजा जार्ज 'वैंगार्ड' नामक युद्ध पोत पर एक समुद्री यात्रा करने वाले हैं। यह उनके स्वास्थ्यलाभ कार्यक्रम का एक अंग होगी।

एक समय (राजा बनने के विचार से बहुत पहले) राजा जार्ज षष्ठ ने जनता के सामने कुछ सारगर्भित शब्द कहे थे। वे तब एक युवक थे। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति उस समय तक किसी का मार्गदर्शक नहीं हो सकता जबतक उसमें दूर तक देखने और सोचने का गुण और संसार की अवस्था में सुधार की इच्छा नहीं है। राजा जार्ज की पिछले सितम्बर मास की बीमारी में राष्ट्रमंडल के लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि उन्होंने एक उच्च सिद्धान्त को अपने जीवन का नियम बना लिया है, कि उन्होंने बड़े नैतिक और शारीरिक साहस से इस नियम का पालन किया है।

इन गुणों की पहली सच्ची परीक्षा प्रथम विश्वयुद्ध में, जटलैंड की लड़ाई से कुछ पूर्व, हुई थी। उन दिनों आप निरन्तर शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त होने पर भी ब्रिटिश नौ सेना में कार्य सात वर्षों से कर रहे थे। मई, १६४६ में वे चिकित्सा के लिए अपने जहाज़ से बाहर ले जाए गए थे। पर वे स्वयं अपनी इच्छा से

... जहाज़ पर

जहाज़ पर वापस चले गए और काम में जुट गए । उन दिनों साहस और शान्त चित्तता के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा की गई थी । चौथे विलियम के समय से ब्रिटेन के किसी भावी राजा ने नौसेना युद्ध में भाग नहीं लिया था । दस वर्षों की अवधि में (राजा पांचवें जार्ज की मृत्यु के पूर्व) राजा के परिवार ने लगभग तीन हज़ार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया था जिनमें से ड्यूक आफ यार्क का ८०० से सम्बन्ध था : लारी ड्राइवरों के कल्याण , कैन्टीनों के निर्माण , पैंशन स्कीमें , दुर्घटना रोकने के विधियां, इत्यादि के प्रश्न । उद्योग के साथ राजा का सम्बन्ध इतना सच्चा हो गया कि नवम्बर १६४० में ट्रेड यूनियन पदक दिया गया था । इस पदक से उन्हें इच्छा होने पर किसी भी ट्रेड यूनियन सम्मेलन में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त हुई । राजा जार्ज की कार्यतत्परता का एक सुन्दर उदाहरण १६४७ में उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से मिलता है । वे यात्रा के समय भी कार्यव्यस्त थे : रेल में उनका विशेष कार्यालय था और मुख्य स्टेशनों से इंग्लैंड अथवा राष्ट्रमंडल के किसी भाग को टेलिफोन करने का प्रबन्ध भी ।

प्रत्येक राष्ट्र के अपने आदर्श , की अपनी जीवनशैली , होती है । अन्य देशवासियों के लिये राजा और ब्रिटिश संविधान के पारस्परिक सम्बन्ध समझना सरल नहीं है । ब्रिटिश जीवन में राजतन्त्र के महत्त्व की परिभाषा देते समय यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इसका ढांचा क्रमश: विकसित हुआ है , शताब्दियों से विकसित होता आ रहा है । हम कह सकते हैं कि राजा विधि (कानून) में निहित भावना का रक्षक है और लोग इसीलिये उसे समस्त राजनैतिक उद्देश्यों से पृथक रखते हैं । यह बात राजा की बीमारी के अत्यन्त चिन्ताजनक दिनों में सिद्ध हो गई थी: मेरा तात्पर्य अक्तूबर ४ को ब्रिटिश लोक सभा में प्रधान मन्त्री ऐटली और प्रतिपक्ष के प्रधान चर्चिल द्वारा अपनी अपनी भक्तिभावना और प्रेम राजा के प्रति प्रकट करने से है । यद्यपि चर्चिल और ऐटली राजनैतिक क्षेत्र में एक दूसरे के विरोधी थे पर सिंहासन के प्रति उनकी भक्ति में इस कारण से कोई अन्तर न आ सका । जैसा कि चर्चिल ने कहा है , राजा जार्ज का आत्म अनुशासन उनकी अस्वस्थता का एक कारण था । यह आत्म-अनुशासन राज्याभिषेक काल से निरन्तर चला आ रहा है। वह उनके उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुरूप ही है :

> .... 'कोई व्यक्ति उस समय तक किसी का मार्गदर्शक नहीं हो सकता जबतक उसमें दूर तक देखने और सोचने का गुण और संसार की अवस्था में सुधार की इच्छा नहीं है ।'

जनरल टेम्पलर : मलाया के नए हाई कमिश्नर

नए प्रयत्नों की सफलता के अच्छे अवसर

मलाया के नए हाई कमिश्नर के रूप में जनरल टेम्पलर की नियुक्ति का स्वागत करते हुए "टाइम्स" पत्र ने १६ जनवरी के अंक में कहा है कि इनमें ठीक वैसे ही गुण हैं जो मलाया में विधिवत जीवन और शासन की पुनर्स्थापना के नए प्रयत्न की सफलता के सर्वश्रेष्ठ अवसर दे सकते हैं। नए हाई कमिश्नर को ऐसे अधिकार दिये जाएंगे जिनसे वे प्रशासन, नियमित सेना, पुलिस और जनसाधारण — इन सब के साधनों को मुख्य कार्य की सफलता के लिए प्रयुक्त कर सकेंगे। उत्तरदायित्व एक व्यक्ति में रखा गया है। प्रशासन, सैनिक अथवा असैनिक, का ऐसा कोई क्षेत्र न होगा जो इनके नियन्त्रण से बाहर हो।

इसका अर्थ, पत्र ने आगे चलकर बताया है, असैनिक प्रशासन को स्थान से च्युत करना अथवा मलाया को एक प्रकार के सैनिक क़ानून के अन्तर्गत रखना नहीं है। सरकार का यह विश्वास बना हुआ है कि साम्यवादियों के विरोध में सफल होना समानरूप से एक राजनैतिक और सैनिक कार्य है। और सरकार नए हाई कमिश्नर को जो आदेश दे रही है उसमें मलाया संघ के संवैधानिक तथा राजनैतिक विकास पर बल डाला गया है। नए हाई कमिश्नर विचारों की लड़ाई के निर्देशक होने के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति के विस्तीर्ण उपायों से भी सम्बन्ध रखेंगे। मलय लोगों के हितों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना वे चीनी समुदाय को आश्वासन देंगे और उसके सहयोग की प्राप्ति के प्रयत्न भी करेंगे।

शिष्टमंडलों की प्रणाली और सोवियट के विचार

वाल्टर कोलार्ज

यों तो रूस जाने वाले प्रत्येक विदेशी शिष्टमंडल की यात्रा और उसके पर्यटन का कार्यक्रम जाने और बुलाने वाले के मध्य पारस्परिक समझौते से तय होता है, पर यह कोरी औपचारिकता है।

रूस आने वाले विदेशी शिष्टमंडलों —— विशेषतया कामकाजियों —— के विषय में सोवियट और साम्यवादी समाचारपत्र महायुद्ध की समाप्ति के समय से बहुत शोर मचा रहे हैं। सोवियट 'लिटरेरी गज़ेट' में पहली मई, १९५१ को प्रकाशित एक लेख के अनुसार विगत तीन वर्षों में २०,००० शिष्टमंडल-सदस्य सोवियट यूनियन आ चुके हैं। 'सर्वश्रेष्ठ प्रचार' —— यह उपर्युक्त लेख का शीर्षक था। खैर, शीर्षक तो उसके अनुरूप ही था। किन्तु क्या कामकाजियों के शिष्टमंडल सोवियट शासन को सचमुच प्रचार की सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर चाहे जो हो पर सोवियट के राजनैतिक युद्ध में ये शिष्टमंडल निस्सन्देह उपयोगी अस्त्रों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

यद्यपि हाल के वर्षों में सोवियट यूनियन जाने वाले कामकाजी शिष्टमंडल विशेष महत्त्व पा गए हैं पर नई चीज़, नए प्रयास, ये कदापि नहीं हैं। कामकाजियों के शिष्टमंडलों को सोवियट यूनियन बुलाने के प्रयास बड़े स्तर पर पहले पहल १९२० और ३० के मध्य किए गए थे। ये पश्चिमी और केन्द्रीय योरप के कामकाजियों पर विजय पाने के जीतोड़ प्रयत्नों के दिन थे।

...द्वितीय महायुद्ध

दिवतीय महायुद्ध के बाद शिष्ठमंडल फिर सोवियट यूनियन जाने लगे । पर शिष्ठमंडलों ने कुछ नए गुण ग्रहण किए । जब हम उन शिष्ठमंडलों पर जो विगत कुछ वर्षों में सोवियट यूनियन गए हैं दृष्टि डालते हैं तो क्या देखते हैं ? यही कि कई सोवियट गुट में बसे और साम्यवादी शासित देशों के हैं । कठपुतली देशों के शिष्टमंडल सीखने के लिए प्रमुख रूप से सोवियट रूस जाते हैं ।

पर पश्चिमी देशों से आने वाले शिष्ठमंडलों की बात दूसरी है । इनसे क्या आशा की जाती है ? यही कि सोवियट रूस को कामकाजियों का सच्चा स्वर्ग कहें और इस साम्यवादी प्रचार का समर्थन करें कि सोवियट यूनियन शान्ति का उपासक है और उत्तर अटलांटिक सन्धि के देश नए विश्वयुद्ध के प्रोत्साहक हैं ।

चाहे जैसे नचाएं

सोवियट दृष्टिकोण से पश्चिमी शिष्ठमंडलों का रूस आना स्वयं एक लक्ष्य नहीं है —— वह तो एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है । सोवियट के लिए पश्चिमी अतिथियों की यात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यात्रा के अन्त में उनके वक्तव्य, उनके कथन हैं । इस बात का निर्णय कि किसी विदेशी शिष्ठमंडल के वक्तव्य का प्रचार कितना किया जाए सोवियट प्रचारक उसकी राजनैतिक उपयोगिता की दृष्टि से करते हैं । `अच्छा` शिष्ठमंडल हुआ (स्वतन्त्र विचार न रखने वाला) तो सोवियट पत्र उसकी चर्चा से सारा पृष्ठ भर देते हैं : `आलोचना` करने वाला, `बुरा`, शिष्ठमंडल हुआ तो उसके वक्तव्य को बिल्कुल दबा देते हैं । देखिए : १६४५ की गर्मियों में ब्रिटिश लोहा और इस्पात कामकाजियों के यूनियन का एक शिष्ठमंडल रूस गया था । इसके सदस्यों ने कहा कुछ पर पत्रों में कुछ और छपा था । इन्होंने सोवियट की औद्योगिक उत्पादन की प्रशंसा में `अच्छा` शब्द प्रयुक्त किया पर `अच्छा` के स्थान में `विशाल` शब्द लग गया ।

ब्रिटिश अथवा अमेरिकन यूनियन को बुलाने में सोवियट ट्रेड यूनियन काफी आपत्ति मोल लेते हैं । इसका उदाहरण हम लोहा और इस्पात कामकाजियों के उपर्युक्त शिष्ठमंडल में पाते हैं । इसलिए , सोवियट प्रचार के दृष्टिकोण से , साधारण कामकाजियों के शिष्ठमंडल बुलाना अधिक अच्छा होता है । चाहे ऐसे शिष्ठमंडल में निर्वाचित लोग हों , चाहे इनमें अधिकांश असाम्यवादियों का हो , फिर भी साम्यवादी संगठनकर्ताओं का समूह उनपर सरलता से छा सकता है ।

... ऐसे शिष्ठमंडलों

ऐसे शिष्टमंडलों का चुनाव प्राय: राजनैतिक अनुभव और विदेशों की यात्रा के अनुभव न रखने वालों के मध्य से किया जाता है । इसलिए उनकी यात्रा का प्रबन्ध करने वाला रूसी संगठन उन्हें अपनी इच्छानुसार नचाता है । ट्रेड यूनियनों की अखिल संघीय केन्द्रीय परिषद अथवा सोवियट शान्ति समिति अथवा 'वाक्स' इन्हीं में से कोई यात्रा - प्रबन्धक संगठन होता है ।

यों तो प्रत्येक शिष्टमंडल की यात्रा का कार्यक्रम उसके और उसे बुलाने वाले संगठन के मध्य पारस्परिक समझौते से तय होता है पर इसे हम कोरी औपचारिकता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कह सकते । पहली बात यह कि सोवियट सम्बन्धी ज्ञान बहुत कम होने के कारण आने वाले लोग अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव नहीं दे सकते । दूसरे, वे अतिथि ठहरे : ये दिखाओ, वह दिखाओ कैसे कहें ? इस प्रकार यात्रा के सोवियट प्रबन्धक अपने को स्वतन्त्र पाते हैं । परिक्रम का कार्यक्रम निर्बाध निश्चित कर सकते हैं ।

वास्तविकता कैसे जान पाएं ?

यह कहना आवश्यक है कि अतिथि के सत्कार में सोवियट लोग बड़े उदार होते हैं । अतिथियों के सारे व्यय सोवियट द्वारा दिए जाते हैं । वे स्वागत समारोह और प्रीतिभोजों में बुलाए जाते हैं । यों सोवियट यूनियन की यात्रा, जो प्राय: तीन सप्ताहों की होती है, एक सुखद अनुभव, एक स्मरणीय घटना, बन जाती है।

पर शिष्टमंडल के कुछ सदस्य चाहे जितना आनन्द मनाएं सच्चे सोवियट रूस को वे कैसे देख पाएं ? घरों के बारे में संकट, कुछ उपभोक्ता सामानों की दिक्कत, बड़े शहरों में भीड़ के समय यातायात की कठिनाइयां, रूसी जीवन की अन्य बुराइयां ये सब विदेशी आगन्तुक की आंखों के सामने नहीं आ पातीं । अतिथि लोग लम्बी यात्राएं प्राय: वायुयान पर करते हैं । पश्चिमी शिष्टमंडल प्राय: लेनिनग्राद, स्तालिनग्राद, कीव, स्वर्डलोवस्क और तिफलिस तथा काकेशस में सोची और सुखूमी और क्राइमिया में याल्टा के स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान देखते हैं ।

शायद उन स्थानों का उल्लेख करना अधिक महत्वपूर्ण है जो पश्चिमी आगन्तुकों की प्रवेश सीमा से बाहर बसे हैं । इनमें सोवियट रूस द्वारा द्वितीय महायुद्धकाल में और उसके बाद लिए गए सारे प्रदेश सम्मिलित हैं । १९४६ की समाप्ति के समय से किसी ब्रिटिश शिष्टमंडल को किसी बाल्टिक रिपब्लिक जाने की अनुमति नहीं मिल सकी है ।

... पश्चिमी आगन्

पश्चिमी आगन्तुकों में ऐसे बहुत थोड़े हैं जो मध्य एशिया में जाने की अनुमति पा सके हैं। हाल के वर्षों में आगन्तुकों के रूस के सुदूरपूर्वीय तथा सुदूरउत्तरीय क्षेत्रों में जा सकने के वृत्तान्त एक भी नहीं मिले हैं। और यहीं रूस के कुछ बहुत बड़े बेगारी शिविर बसे हैं। उन स्थानों में भी जहां ये जाने पाते हैं सोवियट के सच्चे रूप को समझने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इन्हें केवल चुने हुए स्थान दिखाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, सर्वश्रेष्ठ सामूहिक खेत, नए और सर्वोत्तम अस्पताल, उत्तमोत्तम उद्योगशालाएं और यातायात के साधनादि —— इन्हीं के दृश्य वे देखने पाते हैं। चुनी हुई उद्योगशालाओं में जाने वाले शिष्टमंडल के उत्सुक और जिज्ञासु सदस्य ऐसी सूचना नहीं प्राप्त कर पाते जिनके बलपर वे प्रदर्शित वस्तुओं का महत्व समझ सकते हैं। पिछली मई में सोवियट यूनियन गए ब्रिटिश विद्यार्थियों के शिष्टमंडल के अनुसार, सोवियट अधिकारीगण संख्या और आंकड़े बताने में बहुत संकोच करते हैं।

प्रथा का अंग

सोवियट रूस के सम्बन्ध में कुछ सीखने और सोवियट सर्वसाधारण के विचार जानने की इच्छा रखने वालों को रूसी भाषा के अज्ञान से कठिनाई का अनुभव होता है। उन्हें दुभाषिए पर आश्रित होना पड़ता है : और दुभाषिया साधारणतया किसी सोवियट संस्था का कर्मचारी होता है।

मान लीजिए कि विदेशी शिष्टमंडल का कोई सदस्य रूसी भाषा जानता है। मान लीजिए कि उसे मुक्तरूप से घूमने फिरने का अवसर मिलता है। फिर भी इस विदेशी को कोई सोवियट यूनियन की सच्ची बातें नहीं बताएगा। राष्ट्रीय अभिमान अथवा गुप्त पुलिस के ज्ञान से वह कोई असन्तोष प्रकट करने से हिचकिचाएगा। शिष्ठमंडलों की समस्या का एक और अंग होता है। यदि विदेशी व्यक्ति केवल शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में ही रूस जा सकता है तो साधारण सोवियट नागरिक 'डेलीगेट' बनने की सुविधा प्राप्त करने पर ही विदेश में पैर रख सकता है। इसका अर्थ क्या निकलता है ? शिष्ठमंडलों की प्रथा, जैसाकि सोवियट सरकार उसे समझती है, उस प्रथा का एक अंग है जो सोवियट यूनियन तथा असाम्यवादी देशों के मध्य व्यक्ति विशेषों का आवागमन रोकती है। सावधानी से चुने लोगों के सोवियट शिष्ठमंडलों से जो प्राय: बाहर जाया करते हैं संसार के राष्ट्रों के मध्य समझ और मित्रता बढ़ाने में सहायता भला कैसे मिल सकती है ? सच तो यह है कि विदेश यात्रा का वह एकाधिकार जो सोवियट शिष्ठमंडलों को प्राप्त है उन साधनों, उन विधियों, में से एक है जिससे सोवियट सरकार सोवियट लोगों को सम्पूर्ण पृथकता की अवस्था में रखती है।

औषधिशास्त्र में ब्रिटेन का अनुसन्धान

युद्धोत्तरकालिक वर्षों की प्रगति

ट्रेवर० आई० विलियम्स

औषधिशास्त्र में मौलिक अनुसन्धान की बहुत सी दीर्घकालिक स्कीमें जिनसे उपयोगी परिणाम निकलने वाले थे द्वितीय युद्ध के कारण रुक गई थीं। युद्ध समाप्त होने पर पुनर्संगठन के लिये समय चाहिये था और पिछले दो या तीन वर्षों में यह सम्भव हुआ है कि आम तथा आवश्यकरूप से असैनिक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। इसलिये १९४८ ५० के वर्षों के सम्बन्ध में ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च कौंसिल (औषधिशास्त्र अनुसंन्धान परिषद) द्वारा हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट विशेषतया उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें विस्तृत प्रगति के प्रथम वर्षों का विवरण दिया गया है।

फिर भी औषधिशास्त्र से सम्बन्धित अनुसन्धान पर युद्ध का प्रभाव पूर्णतया हानिदायक नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि पेनिसिलिन , जिसके अपूर्व गुण सबसे पहले आक्सफोर्ड में युद्ध के प्रारम्भिककाल में खोजे गये थे , केवल साथी सेनाओं की अत्यावश्यक औषधिशास्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप ही इतनी जल्दी औद्योगिकरूप से विकसित की गई थी। इस खोज ने , जो स्वयं विशिष्ठ है , औषधिशास्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान के एक विशाल क्षेत्र को नया रूप प्रदान कर दिया है

१९३६ में मेडिकल रिसर्च कौंसिल ने लन्दन में नई और विशेषतया आवश्यक साधनों से अच्छी तरह लैस प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये एक स्कीम स्वीकृत की थी। पर युद्ध के परिणामस्वरूप ये प्रयोगशालाएं औपचारिक रूप से १९५० तक खोली नहीं गई थीं। इस नवीन इमारत का प्रधान अभिप्राय यह था कि 'कैमोथेरेपी' (स्पर्श रोग की ऐसी दवाओं से चिकित्सा करना जो सूक्ष्म जीवों के लिये प्राणघातक हों किन्तु मनुष्य शरीर को अपेक्षाकृत हानि न पहुंचाये) से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य के लिये उच्चकोटि की सुविधाएं प्रदान की जाएं।

... क्षयरोग की

क्षयरोग की केमोथैरेपी के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने भी आ चुके हैं। इनमें से एक क्षयरोग विरोधी दवाओं के चिकित्सा सम्बन्धी मूल्य की ठीक-ठीक जांच करने के लिये एक कठिन विधि का विकास है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि रोग अक्सर बहुत लुके-छुपे तौर पर बढ़ता रहता है।

रोचक प्रयोग

पैरा-अमिनोसैलिसाइलिक ऐसिड (पी ए एस) नामक दवा का विशेषरूप से अध्ययन किया गया है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा के साथ विशेषतया उपयोगी सिद्ध हुई है। बी सी जी (क्षयरोग विरोधी सुई) की विस्तृत जांच भी बहुत ही सावधानी से नियन्त्रित अवस्थाओं के अन्तर्गत की जा रही है जिसके लिये पिछले तीस वर्षों में परस्पर विरोधी दावे किये गये हैं।

जुखाम या नजले की बीमारी के सम्बन्ध में सैलिस्बरी (दक्षिणी इंग्लैंड) के विशेष अनुसन्धान यूनिट में बहुत गहरा अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि इसके कारण हर साल लाखों कार्य घन्टों की हानि होती है। इस यूनिट द्वारा किये गये बहुत से रोचक प्रयोगों में एक वह था जिसमें वालंटियरों के एक समूह को स्काटलैंड के एक निर्जन द्वीप में लेजाकर दस सप्ताहों के लिये छोड़ा गया था। यह स्थान स्पर्शरोग के किसी सम्भव जरिये से बहुत दूर था। वालंटियरों को सैलिस्बरी में आरम्भ होने वाले नजले का बीमार बनाकर उस द्वीप में भेजा और स्पर्शरोग के विस्तार को जांचा गया था। यद्यपि निश्चित परिणाम सामने नहीं आये पर आगामी कार्य के लिये उपयोगी संकेत मिल गये थे।

कुछ समय पहले तक ब्रिटेन सौभाग्य से पालिओमाइयलाइटिस (शिशु पक्षाघात) की गम्भीर बीमारी से मुक्त था किन्तु यह स्थिति १९४७ के गम्भीर व्यापक रोग के साथ समाप्त हुई दीखती है। मेडिकल रिसर्च कौंसिल द्वारा इंग्लैंड और वेल्स में इस विषैले तत्व के वितरण, इसके फैलने के रूप और लकवाग्रस्त होने वाले उन कारणों के सम्बन्ध में गहरा अध्ययन किया गया है जो मामूली स्पर्शरोग उत्पन्न करते हैं।

इसके अतिरिक्त किसी एक ही अंग में लकवा मारने और डिफ्थीरिया

... कंठ का

(कंठ का एक संक्रामक रोग) और हूपिंग कफ (कुक्कर खांसी) जैसे रोगों की रुकावट के लिये औषधि सुइयों के बीच प्रस्तावित सम्बन्ध पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अबतक के परिणामों से पता चलता है कि डिफ्थेरिया के विरुद्ध ढेरों सुइयां लगाने से यह रोग केवल रुकता ही नहीं बल्कि शिशु पक्षाघात से होने वाली मृत्यु का रेट भी कम हो जाता है ।

महत्वपूर्ण अनुसंधान

नासूर सम्बन्धी कार्य भी बहुत सी प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है । तम्बाकू पीने और फेफड़े के नासूर के बीच एक स्पष्ट सम्बन्ध को भी स्थिर किया जा चुका है । यह अनुसन्धान इतना महत्वपूर्ण रहा है कि अधिक अध्ययन के लिये केन्द्र ब्रिस्टल , कैम्ब्रिज , लीड्स और न्यूकासिल में खोल दिये गये हैं । तम्बाकू के धुवें की रचना के सम्बन्ध में भी रसायनिक अध्ययन किया जा रहा है , क्योंकि इसमें निहित विष मिश्रण के चिन्ह हानिदायक होते हैं ।

फिर भी यह स्पष्ट है कि केवल तम्बाकू पीने से ही फेफड़े का नासूर उत्पन्न नहीं होता , क्योंकि तम्बाकू न पीने वालों के भी कुछ मामले सामने आते हैं । सूक्ष्म रसायनिक परीक्षाओं से पता चलता है कि साधारण वायु में भी नासूर पैदा करने वा[ले] कुछ अंश मिले होते हैं । इनका अन्तिम ज़रिया घरेलू आग आदि का धुवां हो सकता है । यह अनुसन्धान , जो स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है , नासूर की सम्पूर्ण समस्या पर भी अधिक प्रकाश डालने वाला सिद्ध हो सकता है ।

भारत ब्रिटिश व्यापार का बढ़ता हुआ परिमाण

सन्तुलन भारत के पक्ष में

लन्दन में व्यापार मंडल द्वारा प्रकाशित विदेशी व्यापार सम्बन्धी सबसे ताज़ी रिपोर्ट से पता चलता है : भारत ने ब्रिटेन को अक्तूबर में १,४४,६०,००० पौंड मूल्य की चीज़ें निर्यात कीं जबकि १९५१ के तीसरे त्रैमासिक में १,२३,३०,००० पौंड, वर्ष की प्रथम छमाही में १,२५,८०,००० पौंड, १९५० में ८२,००,००० पौंड और १९४९ में ८२,५०,००० पौंड की मासिक औसतें बैठी थीं। भारत ने ब्रिटेन से अक्तूबर में १,०९,५०,००० पौंड मूल्य का सामान आयात किया था जबकि १९५१ के तीसरे त्रैमासिक में ९९,८०,००० पौंड, वर्ष की प्रथम छमाही में ९१,६०,००० पौंड, १९५० में ८१,१०,००० पौंड और १९४९ में ९७,६०,००० पौंड की मासिक औसतें रही थीं।

जनवरी - सितम्बर १९५१ के व्यापार सन्तुलन की मासिक औसत के रूप में ३०,४०,००० पौंड भारत के पक्ष में प्रकट किये गये हैं जबकि १९५० में उसके पक्ष में ९०,००० पौंड और १९४९ में ब्रिटेन के पक्ष में १५,४०,००० पौंड बैठे थे। पिछले वर्ष के तीसरे त्रैमासिक में भारत ने ब्रिटेन के आयातों के कुल मूल्य का ३.४८ प्रतिशत अंश दिया जबकि वर्ष की प्रथम छमाही में ४.०७ प्रतिशत, १९५० में ३.७७ प्रतिशत और १९४९ में ४.३५ अंश प्रदान किया था। पिछले वर्ष के तीसरे त्रैमासिक में भारत ने मूल्य की दृष्टि से ब्रिटेन के कुल निर्यातों का ४.३४ प्रतिशत अंश लिया जबकि वर्ष की प्रथम छमाही में ४.२३ प्रतिशत, १९५० में ४.३१ प्रतिशत और १९४९ में ६.३७ प्रतिशत लिया था।

नेपाल को वनस्पति अभियान

हिमालय पर्वत के लिये एक त्रिजन ब्रिटिश वनस्पति सम्बन्धी अभियान अगले महीने ब्रिटेन से नेपाल की ओर प्रस्थान करने वाला है। ब्रिटिश म्यूजियम के वनस्पति विभाग के ३६ वर्षीय जान विलियम्स इस अभियान के नेता हैं। दल के अन्य सदस्य चार्टर हाउस स्कूल के ३८ वर्षीय विज्ञान अध्यापक , आलेग पाल्यूनि और रायल हार्टिकल्चरल (उद्यान विद्या सम्बन्धी) सोसाइटी के २४ वर्षीय विलियम साइक्स हैं ।

आशा की जाती है कि यह अभियान बम्बई के लिये २८ फरवरी को प्रस्थान करेगा । हिमालय के नीचे वाले ढलानों पर घोलागिरी और करनीली नदी के मध्य दल के लिये एक शिविर गाड़ने के लिये काठमंडू से अनुमति प्राप्त कर ली गई है । यह दल सम्भवत: अपने देश से लगभग नौ महीनों तक बाहर रहेगा । विलियम साइक्स से असाधारण पौधों पर ध्यान देंगे जो ब्रिटेन भेजने के लिये उपयुक्त हों और जान विलियम्स तथा पाल्यूनिन नैचुरल हिस्टरी (पशु जीवनशास्त्र) म्यूजियम के लिये पौधों के नमूने इकट्ठे करेंगे ।

** ** **

वार्सा के 'एक्सप्रेस विरज़ार्नी 'नामक सायंकालिक पत्र ने एक रोचक सम्वाद छापा है। बात ने लिया काम का स्थान कैमेराल्ना आहारगृह के सामने लोगों की भीड़ थी । इनके चेहरों से भूख स्पष्टतया प्रकट होती थी । दिन को ढाई बज गए थे । पर भोजन के दर्शन नहीं हुए थे । वेटरों का समूह एक सम्मेलन में व्यस्त था । ग्राहकों की सेवा अधिक अच्छी तरह करने की विधियों पर भाषण सुन रहा था । यही देर का कारण था ।।

ब्रिटिश विशेषज्ञों की भारत यात्रा

एक विशिष्ठ नगर निर्माण योजना परामर्शदाता और एक पदार्थ वैज्ञानिक ब्रिटिश कौंसिल की देखरेख के अन्तर्गत भारत भ्रमण के लिये ब्रिटेन से इसी महीने दिल्ली आने वाले हैं। वे लोग श्री० मैक्स लाक, एफ.आर.आई.बी.ए., एम.टी.पी.आई और श्री० ए.जे. फिलपाट हैं।

श्री० लाक (जो १६ जनवरी को दिल्ली आये) अपनी एक महीने की यात्रा में शिमला, अमृतसर, पटना, कलकत्ता भुवनेश्वर, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और बम्बई की यात्रा करेंगे। आप नगर निर्माण की योजना बनाने वालों, शिल्पकारों तथा कार्यपालक इंजीनियरों से बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों के सामने भाषण देंगे। श्री० फिलपाट, जिनकी विशिष्ठ जीवनवृत्ति में प्रोफेसर थाम्सन और लार्ड रथरफर्ड के अन्तर्गत किया गया अनुसन्धान कार्य सम्मिलित है, १९४६ में ब्रिटेन की ब्रिटिश साइन्टिफिक इस्टुमेंट रिसर्च एसोसिएशन और साइन्टिफिक इंस्टुमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नामक दोनों संस्थाओं के संयुक्त निर्देशक नियुक्त किये गये थे। आप (२५ जनवरी को दिल्ली आने पर) दो भागों में भारत का भ्रमण करेंगे —— १३ जनवरी तक और तब १८ फरवरी से (कोलम्बो से वापस आने पर) ८ मार्च तक। आप इस अवधि में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई जायेंगे और विज्ञान प्रयोगशालाओं, युद्ध सामग्री कारखानों, विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों का दौरा तथा अलग अलग समूहों में बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों के सामने भाषण देंगे।

भारत में ब्रिटिश वादविवाद दल

एक ब्रिटिश वाद विवाद दल दिल्ली आ गया है जिसमें ग्लैसगो विश्वविद्यालय के श्री० ऐलेस्टर मैक्डोनल्ड और क्लेयर कालेज, कैम्ब्रिज, के श्री० ब्रायन ऐबलस्मिथ नामक दो विद्यार्थी सम्मिलित हैं। ये लोग अपनी यात्रा के दौरान में, जो ब्रिटिश कौंसिल द्वारा आयोजित की गई है, भारतीय कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ वाद विवादों में भाग लेंगे। दिल्ली के दो वाद विवादों में भाग लेने के बाद ये ब्रिटिश विद्यार्थी मद्रास, तिरुचिरापल्ली, बंगलौर, मैसूर, हैदराबाद, नागपुर, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ तथा अमृतसर की यात्रा करेंगे और फरवरी के मध्य तक ब्रिटेन लौट जायेंगे।

संकुचित हुआ संसार,
धन्य, नव वायु युग के सूत्रधार!
सत्वर, सुखदायी यात्रा,
धन्य यन्त्रविद, कुशल निर्माता!

'सू प र का मे ट' का प रि च य

चार्ल्स गार्डनर,
बी०बी०सी० के वायु सम्वाददाता

इस नए वायुयान का नाम 'एवान' है। इसके निर्माता इसे 'सीरीज़ टू' के नीरस नाम से पुकारते हैं। समाचारपत्रों के शीर्षक इसे 'सूपर कामेट' कहते हैं। वह अपनी उड़ान के परीक्षण प्रारम्भ करने जा रहा है। यह वायुयान ब्रिटेन में आजतक बने तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण वायुयानों में से एक है। अन्य दो है साधारण 'सीरीज़ वन कामेट' और 'विकर्स वाइकाउंट'। ऊपर मैंने कहा है कि 'सूपर कामेट' ब्रिटेन में आजतक बने तीन महत्वपूर्ण वायुयानों में से एक है — सचमुच इसे ब्रिटेन के स्थान में संसार के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण वायुयानों में गिनना अतिशयोक्ति न होगी।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि 'सीरीज़ टू' वायुयान का नमूना पहले बने 'सीरीज़ वन' द्वारा यात्रियों की सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व ही वायु में प्रकट होगा। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि, जहाँतक मैं समझता हूँ, इस नए वायुयान का विकास साधारण 'कामेट' की इंजन में कुछ परिवर्तनों की सहायता से हो गया था। इसे बार 'एवान' इंजनों की अधिक शक्ति के उपयुक्त बनाना — यही उपर्युक्त परिवर्तन का उद्देश्य था। मैं इन दोनों बातों को एक दूसरे से सम्बद्ध समझता हूँ। खैर।

...'सीरीज़ टू'

निर्माता की निपुणता

'सीरीज़ टू' (इसके विभिन्न नाम न भूलिए) की लम्बी रेंज उसकी दूसरी बड़ी विशेषता है। (एकबार भरे ईंधन से वायुयान जितनी दूर तक उड़ सकता है उसे उसका 'रेंज' कहते हैं) हाँ, 'रेंज' इतनी काफी है कि उसके बल पर यह वायुयान उत्तर अटलांटिक और प्रशान्तपार के मार्गों के लिये स्वीकार्य हो सकता है। इधर 'एवान कामेट' नए और पुराने संसार तक और आस्ट्रेलेशिया से उत्तर अमेरिका के प्रशान्त तट तक नियमितरूप से उड़ना प्रारम्भ करेगा, उधर अमेरिका की वायु सर्विस के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ वायुयान इन्हीं मार्गों पर उड़ते होंगे। 'सूपर कामेट' न केवल जेट वायुयान यात्रा की समस्त सुख सुविधाएं देगा पर अपने प्रतिस्पर्द्धी साधारण वायुयानों की तुलना में यात्रा का समय आधा कर देगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यात्रियों की दूर दूर की उड़ान में यह एक क्रान्ति मचा देगा। ब्रिटिश ओवरसीज़ ऐरवेज़ कार्पोरेशन द्वारा इस वायुयान का उपयोग इसी वर्ष प्रारम्भ हो जाएगा।

'सीरीज़ टू' वायुयान बना सकने में ब्रिटिश सफलता का रहस्य क्या है? यह प्रश्न स्वाभाविकतया उठता है। मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर, इस सफलता का रहस्य, इंजन का नक्श (डिज़ाइन) बनाने वालों की प्रतिभा में पाया जाता है। ईंधन के उपभोग में कमी कराने वाली और बड़ी जेट इंजन बनाने की कठिन समस्याएं इनके सामने थीं। पर ये निरुत्साहित न हुए। परिणाम? 'एवान' और 'सेफ़ायर' —— जो निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ गैस टर्बाइन इंजन है —— शीघ्र बने।

ब्रिटिश सैनिकों पर गुरिल्लों का आक्रमण

समाचारपत्रों का विष-वमन

मिश्र की परिस्थिति के विषय में 'डेली टैलीग्राफ' ने १५ जनवरी के अंक में लिखा है : नहर क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को तंग करने के लिये एक नया, शोचनीय अध्याय खुल रहा है। गुरिल्लों के छोटे समूह को काहिरा में भर्ती किए गए मतान्ध युवकों का योग मिल रहा है। ये युवक अधिकांशतया विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं। ब्रिटिश सैनिकों पर आक्रमण की इन्हें प्रेरणा दी जाती है। ब्रिटिश 'अत्याचारों' की कल्पित कहानियां सुना सुना कर इनकी राष्ट्रवादी भावना प्रज्ज्वलित की जाती है।

मिश्र की सरकार का राजनैतिक आचरण मूर्खता से पूर्ण है। और यह नया प्रचार आन्दोलन तो दायित्व से और भी दूर है। सरकार के मन्त्रिगण और उनके साथ मिले विष उगलने वाले समाचारपत्रादि इन छोटे गुरिल्लों को मरना और मारना सिखा रहे हैं। इस प्रकार वे मिश्र की अशांति बढ़ा रहे हैं, और ब्रिटेन के विरूद्ध विरोध की नई भावना जगा रहे हैं। वास्तव में केवल ब्रिटेन के विरूद्ध नहीं पर ऐसी सब जातियों के विरूद्ध जो अरब नहीं है।

शाह फारूख ने नरम विचार वाले दो राजनीतिज्ञों को अपना सलाहकार बनाया है। इसे नहस पाशा और उनके साथियों ने अपने पद्च्युत किये जाने की चेतावनी समझा है। ईराक के प्रधान मन्त्री और अरब लीग के अन्य सदस्यों ने इस स्थति में समझदारी का समावेश करने का प्रयत्न किया। इसे कट्टर पन्थियों ने अपने अधिकार और अपनी सत्ता के लिये खतरा समझा। उनके इस प्रत्युत्तर से अनुचित पथ पर चलने वाले युवकों ने अपने रक्त बहाने की प्रेरणा प्राप्त की।

... यदि भड़काने

यदि भड़काने वाले ये व्यक्ति इस समय अपने पदों से हटा दिये जाते हैं तो वे कहेंगे कि ऐसे समय जब मृत व्यक्ति प्रतिहिन्सा की मांग कर रहे हैं देशभक्त निकाले जा रहे हैं। यदि ये अधिकार के पदों पर आसीन रहते हैं तो वे ब्रिटेन को उत्तेजित करने का कार्य जारी रखेंगे, कितने व्यक्तियों को उनके कारण मृत्यु की घाट उतरना पड़ा इस बात को वे न सोचेंगे। वे तो यही आशा करेंगे कि जब उनका पतन होगा तो वह एक छोटेमोटे युद्ध के वातावरण में होगा।

पत्र ने आगे चलकर लिखा है : ब्रिटेन के लिये सन्धि के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को उस समय तक बनाए रखना जबतक सन्धि का स्थान कोई नया स्वीकार्य समझौता नहीं लेता और सूडान के निवासियों के प्रति दायित्व —— ये ही दो विचार प्रमुख विचार बने हुये हैं। हमारे विदेशी मित्रों को यह अब अधिकाधिक स्पष्टतया समझ में आ रहा होगा कि सहयोग और समझौते की भावना की आशा वाफ्द सरकार से नहीं की जा सकती।

मिश्र की वर्तमान सरकार को उन आंग्ल मिश्री प्रतिरक्षा प्रबन्धों के स्थान में जिन्हें उसने ठुकरा दिया है एक मध्यपूर्वीय प्रतिरक्षा पैक्ट में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। इस अवसर को भी उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। पत्र ने अन्त में यह विचार प्रकट किया है कि इस बात की सम्भावना नहीं है कि मिश्र की वर्तमान सरकार बलिदान और आतंक के उस वातावरण में जिसके लिये वह उत्तरदायी है समझौते की इच्छा पहले से अधिक दिखायेगी।

र डा र को पु र स्का र

*****

'टाइम्स' पत्र ने 'रडार पुरस्कृत' शीर्षक से १५ जनवरी के अंक में लिखा है : सर राबर्ट वाट्सन वाट और उनके कुछ चुने हुए साथियों को एक सुन्दर और करमुक्त पुरस्कार देने का अर्थ उन अधिकांशयता अज्ञात वैज्ञानिकों, और इंजीनियरों की राष्ट्रीय प्रशंसा के करने के समान है जिनका इस सफलता में अंशदान रहा है।

पत्र ने आगे चलकर बताया है कि रडार प्रमुखतया मिलेजुले कार्य का फल था। किन्तु इसके पीछे सर एडवर्ड ऐपिल्टन के आधारभूत अनुसन्धानों का समूह था। सर एडवर्ड ऐपिल्टन ने प्रतिबिम्बित वितन्तु (वायरलेस) तरंगों का पता लगाना सम्भव बनाया था। उनकी प्रेरणा से ही तैयार हुआ था वह पथ जिसका विश्वविद्यालय और सरकारी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने अनुसरण किया था। इन सबके मिलेजुले प्रयत्नों ने ब्रिटेन की लड़ाई जीतने में सहायता पहुंचाई और, ज्यों ज्यों युद्ध अपना क्रम पूरा करता गया, सम्पूर्ण विजय में इनकी ओर से नियमितरूप से बढ़ता हुआ अंशदान प्राप्त हुआ।

पत्र ने अन्त में कहा है कि उनके प्रति हमारा जो ऋण है उसका अनुमान धन में नहीं लगाया जा सकता पर विज्ञान उस सम्मान और मान्यता का भलीभांति अधिकारी है जो अब उसके सेवकों को मिली है।

BRITISH INFORMATION SERVICES

FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

April 1 to April 14, 1951.

HINDI
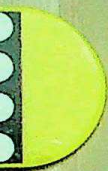
स्तालिन की सफलता का सोपान

—

लियोनर्ड शपीरो,
ब्रिटिश विधि-विशेषज्ञ और
इतिहासकार

चौथी अप्रैल, १९२२ को रूसी दैनिक समाचारपत्रों में एक साधारण सूचना के रूप में रूसी साम्यवादी दल के तीनों नवनिर्वाचित मंत्रियों के नाम प्रकाशित हुए थे। इनमें एक नये व्यक्ति का नाम भी था : जनरल सेक्रेटरी जोज़ेफ़ स्तालिन का। १९२२ में यह नाम जनसाधारण के लिए परिचित नामों में नहीं था। उस समय लेनिन सार्वजनिक जीवन से लगभग अवकाश ग्रहण कर चुके थे। क्रान्ति और गृहयुद्ध से संबंधित नामों में ट्राट्स्की, ज़िनोविएव, बुखारिन, कामेनेव और रिकाव के नाम सबसे अधिक परिचित नामों में थे। जनरल सेक्रेटरी के पद पर स्तालिन की नियुक्ति के पन्द्रह वर्षों बाद ये सब लोग — और अन्य कई लोग भी — देशद्रोह के अपराध में मृत्यु के घाट उतारे जा चुके थे। इस प्रकार स्तालिन सारे रूस के स्वेच्छाचारी शासक के रूप में प्रकट हुए। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी।

जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति स्तालिन की सचमुच पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति थी। इसने स्तालिन के हाथों में वे सारे साधन रख दिए जिनकी उनको ज़रूरत थी : अपने व्यक्तिगत विरोधियों को अलग कर अपनी व्यक्तिगत प्रभुता की पुष्टि के लिए। किन्तु दल के ऊपर एक व्यक्ति की तानाशाही, अकेले व्यक्ति का आधिपत्य स्तालिन की उन्नति की परिस्थितियों का अनिवार्य परिणाम था।

१९२२ में निर्वाचित केन्द्रीय समिति द्वारा नए जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति दल के अन्दर के एक कटु संघर्ष की समाप्ति की सूचिका थी। यह संघर्ष १९२० में प्रारम्भ हुआ था। गृहयुद्ध की समाप्ति पर रूसी साम्यवादी दल उत्तेजना से भरा हुआ था।

से भरा हुआ था। लेनिन के नेतृत्व में केन्द्रीय समिति की निर्दयी तानाशाही का उस समय तक सहन किया गया जबतक जीवन-मरण का संग्राम चल रहा था। किन्तु बाल्शेविक तानाशाही के सब सशस्त्र विरोधियों की पराजय के पश्चात दल के लोग अपना असन्तोष प्रकट करने लगे। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनसे आज्ञाओं का पालन भर कराया जाता था पर दल की नीति के निर्माण में उनका कोई भाग नहीं था, कि नौकरशाही बढ़ रही थी, दल के नेताओं की स्वार्थपरता और उनके भ्रष्टाचार वृद्धि पर थे, कि केंद्र द्वारा दल की शाखाओं में नियुक्ति स्थानीय निर्वाचनों का स्थान ले रही थी। वे अल्पसंख्यक साम्यवादी जो छलकपट और बल द्वारा ट्रेड यूनियनों पर नियंत्रण जमाए हुए थे अधिक अधिकारों और केन्द्रीय दल के नियंत्रण से अधिक छुटकारे की मांग कर रहे थे।

किन्तु दल के अन्दर दल के नेतृत्व से असन्तोष कुछ भी नहीं था उस घृणा की तुलना में जो साम्यवादी शासन के प्रति दल के बाहर देखने में आता था। किसानों ने हज़ारों की संख्या में विद्रोह किया और कठिनाई के साथ लाल सेना उसे शांत कर पाई। और क्रान्स्टाद में बाल्टिक बेड़े के नाविकों ने दल की तानाशाही के विरुद्ध बलवा कर दिया।

बाहर और अन्दर
विरोध

दल के अन्दर के विद्रोह में और उस विद्रोह में जो दल के बाहर था, सारे देश में था एक बड़ा अन्तर था। असन्तुष्ट साम्यवादी अपने लिए अधिक आज़ादी चाहते थे; वे नहीं चाहते थे कि इस आज़ादी में अन्य कोई भाग ले – उदाहरणार्थ, समाजवादी दल जिन्हें ट्रेड यूनियनों और किसानों से अधिकाधिक समर्थन मिल रहा था।

जहाँतक समाजवादी दलों का सम्बन्ध था, उनका विरोध तानाशाही से था। वे सारे समाजवादी दलों के लिए स्वतन्त्रता चाहते थे। क्रान्स्टाद नाविकों के बलवे ने इनकी माँगों को बल प्रदान किया।

लेनिन के सामने दो मार्ग थे: या तो देश की मांगों के सामने झुकना और अपनी तानाशाही को कम कठोर बनाना या दल के अनुशासन को और भी कठोर बनाकर और आतंक के बल पर विरोध को शान्त कर तानाशाही को बनाए रखना।

उन्होंने निस्संकोच दूसरा मार्ग चुना। सोवियट इतिहासकारों ने और पश्चिम में उनकी प्रतिध्वनियों ने १९२१ में लेनिन की नीति को क्रान्ति विरोधिनी क्रान्ति से रूस की रक्षा करने की नीति कहा था और उस समय से ये इस नीति की व्याख्या यही कहकर करते आए हैं। पर वास्तव में साम्यवादी तानाशाही के सामने उपस्थित खतरा क्रान्ति-विरोधिनी क्रान्ति से नहीं पर साधारण ट्रेड यूनियन और ग्राम्य समाजवाद की ओर से था। साम्यवादियों की विरोधिनी श्वेत सेनाएँ नवम्बर, १९२० तक परास्त होगई थीं; साथी राष्ट्रों के हस्तक्षेप का खतरा जाता रहा था।

नई नीति क्या थी?

नई नीति १९२१ के प्रारम्भ में शुरू हुई; बचेखुचे समाजवादी पकड़ लिए गए और समाजवादी दलों को एकदम समाप्त करने का काम शुरू हुआ। इसके बाद स्वयं साम्यवादी दलों को फिर से संगठित करने का काम हाथ में लिया गया। मार्च, १९२१ में लेनिन ने दल के कार्यालय से तीन अपेक्षाकृत नरम विचार वाले व्यक्तियों को अलग कर दिया: इनके नाम थे सेरेब्रियाकव, क्रेस्तिन्स्की और प्रियोब्राज़ेन्स्की। ये लोग दल के अन्दर वाद-विवाद की अधिक आज़ादी और दल के अधिकारियों पर अधिक कठोर नियंत्रण के पक्ष में थे। इनके स्थान में लेनिन ने नए लोगों को चुना। इनमें मालोटाव, जो १९१२ से स्तालिन के सन्निकट साथी रह चुके थे, प्रधान थे। एक वर्ष के कार्यकाल ने यह दिखा दिया था कि ये लोग भी आशा के बराबर नहीं बैठे। इनमें अभी भी केन्द्रीय समिति की खुली आलोचना का साहस था। साम्यवादी दल से उसके तीन कटु आलोचकों को अलग करने के प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया था। ऐसी "अनुशासनहीनता" के लिए कठोर कार्यवाई आवश्यक समझी गई और इस नीरस काम के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति स्तालिन समझा गया। यह समझने का कोई कारण नहीं दिखता कि अप्रैल, १९२२ में जनरल सेक्रेटरी के पद पर स्तालिन की नियुक्ति लेनिन की अनुमति के बिना हुई थी।

जहाँ मालोटाव असफल रहे वहाँ स्तालिन ने सफल होने में समय नहीं लगाया।

गुप्तचरों की व्यवस्था के ज़रिए, आतंक फैलाकर और मुख्य नियुक्तियों पर नियंत्रण जमा कर स्तालिन ने आज्ञाकारी अनुचरों का जो गुट तैयार किया वह लेनिन के उस सुखद स्वप्न का साक्षातकार था जिसे वे १९०२ में देखा करते थे।

स्तालिन की सफलता
और सर्वोच्चता

आनेवाले वर्षों में क्रान्ति के जित वीरों ने स्तालिन प्रणाली का विरोध किया था उन्होंने बहुत देर में यह अनुभव किया कि दल की व्यवस्था पर नियंत्रण ने स्तालिन को वह सारा अधिकार दे दिया था जिसकी स्तालिन को ज़रूरत थी — आलोचना को अनुशासनहीनता का नाम देने के लिए और अनुशासनहीनता को देशद्रोह कह कर उसका दमन करने के लिए।

ट्राट्स्की और उनके अनुयायियों ने स्तालिन को लेनिन की नीति के साथ विश्वासघात करने वाले कपटी और अहितकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। पर स्तालिन अहितकारी और कपटी भले ही हों, उन्होंने लेनिन की नीति के साथ विश्वासघात नहीं किया। कारण, लेनिन का विश्वास था कि अल्पमत को देश के विशाल बहुमत पर अधिकार चलाने का हक़ है।

वर्तमान पद्धति लेनिन की योजना का तर्कयुक्त परिणाम है। वे जो अक्तूबर १९१७ में लेनिन की बातों में विश्वास कर यह समझते थे कि वे जनता के राज्य की स्थापना कर रहे हैं वास्तव में साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित कर रहे थे। इस एक बात में निहित था सोवियट इतिहास का आनेवाला क्रम, उसकी आगामी घटनाएँ। लेनिन चाहते तो १९२१ में इस क्रम को पलट सकते थे। पर वे ऐसा करते तो उन्हें अपने एकाधिकार से वंचित होना पड़ता, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता कि शासनकार्य में भाग लेने का अधिकार समाजवादी दलों को भी है। और समाजवादी दल भाग लेने के लिए तैयार और इच्छुक दोनों थे।

ट्राट्स्की ने बहुत वर्ष पहले — लेनिन के दल में सम्मिलित होने से पहले — यह कहा था कि एक केन्द्रीय समिति की तानाशाही अन्त में जाकर एक व्यक्ति की तानाशाही के रूप में प्रकट होती है। स्तालिन ने ट्राट्स्की की भविष्यवाणी की सत्यता प्रमाणित कर दी है। कारण, एक व्यक्ति की तानाशाही सबसे तगड़ी तानाशाही है। १९२२ में स्तालिन की नियुक्ति साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति की सर्वोच्चता पुष्ट करने के लिए हुई थी। पर वह सहायक हुई स्वयं इनकी सर्वोच्चता पुष्ट करने में।

N.E.H.38

सोवियट निवासस्थान योजना का सफल न होना

युद्धोत्तर स्तालिन पांच-वर्ष योजना की अवधि में निवासस्थानों के लिये १४,००,००० वर्ग मीटर ज़मीन मास्को में तैयार की गई है। केवल १९५० में ५,३५,००० वर्ग मीटर पर काम पूरा हुआ था जो १९४९ से ३५ प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार १९५० का निवासस्थान कार्यक्रम ९.८ प्रतिशत बढ़ा हुआ था । टास एजेंसी की यें संख्याएं मास्को के ट्रेड यूनियन हाउस में हुई एक सभा में बताई गई थीं ।

पांच-वर्ष योजना के अन्तर्गत मास्को के लिये निर्धारित संख्या ३०,००,००० वर्ग मीटर थी ।

H/L.P.S.165

भारत में खाद्य संकट

"अभी तक अमेरिका ही मुख्य आशा"

"टाइम्स" अपने ६ अप्रैल वाले सम्पादकीय में "खाद्य के लिये भारत की
शीर्षक से लिखता है : भारत में खाद्य संकट लगातार कई आपत्तियों के कारण उत्पन्
हुआ है। भारत इतना विशाल देश है और उसकी जलवायु इतनी भिन्न है कि फ़सल
हानि का प्रभाव आमतौर पर स्थानीय होता है और संकट को आस-पास के
क्षेत्रों से अन्न मंगाकर दूर किया जा सकता है ।

ब्रिटिश शासन भारत को अकाल से बचाने में एक ऐसी विस्तृत व्यवस्थ
की सहायता से निरन्तर सफलता प्राप्त की थी जो बचत वाले क्षेत्रों से अनाज
करने के लिये शीघ्र ही संचालित की जा सकती थी। जब कभी अन्न मौजूद नहीं था
ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी तो संकट पैदा होते थे , जैसे कि १९४३ में बंगाल का अकाल

आज यह खतरा सामने है कि १९४३ की दुर्घटना एक और भी बड़े पैमाने
पुनःउपस्थित हो सकती है। तीन वर्षों की ख़राब फसल के साथ-साथ भूकम्पों , जल-
अनावृष्टि और महामारियों ने उपलब्ध अन्न का परिमाण गम्भीरता से कम कर दि
है।

भारत सरकार को विदेश से ३,५०,००० टन मासिक के हिसाब से खाद्या
आयात करने पड़े थे , किन्तु ये खरीदारियां (यद्यपि वे देश के विदेशी विनियमों
गम्भीर बोझ डालती हैं) बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिये काफी नहीं हैं
भारत विदेश से जल्दी ही लगभग दस लाख टन खाद्य प्राप्त नहीं करता और उन स
पर नहीं भेजता जहां उनकी अत्यधिक आवश्यकता है तो अकाल क्षेत्रों के दो करोड़

...में से बहुत

से बहुत सारे भूख के कारण मर जायेंगे । आगे चलकर पत्र लिखता है कि समस्या दो पी है, पहले तो अनाज प्राप्त करना है और तब उसे बांटना है । जैसाकि कृषि मन्त्री संसद में बताया है, भारत सरकार, विदेश से अधिक अनाज आने तक, अकाल क्षेत्रों के लिये अपने लघु संचयों से थोडा-बहुत अनाज निकाल कर भेज रही है।

अमेरिका कीसरकार एक नि:शुल्क उपहार के रूप में दस लाख टन गेहूं इस शर्त र भेजने के लिये सैद्धान्तिक रूप में तैयार हो गई है कि इसको बेचने से वसूल होने वाली रकम भारतीय लोगों को लाभ पहुंचाने वाली विकास योजनाओं के लिये खर्च की जायेगी और अगर यह योजना सफल हुई तो और भी दस लाख टन गेहूं भेजा जायेगा । इस उदार प्रस्ताव ने भारत की सारी चिन्ता दूर कर दी होती यदि सरकार को यह भरोसा होता कि अन्न समय पर आ जायेगा । किन्तु दुर्भाग्यवश इस मामले में देर हो रही है।

इसलिये दिल्ली अनुभव करती है कि उसे किसी और जगह पर प्रयत्न करना चाहिये और वह आजकल रूस तथा चीन के प्रस्तावों परविचारकर रहीहै। येस्पष्ट व्यावसायिक प्रस्ताव हैं लेकिन कठिनाई यह है कि रूस अन्न के बदले में अधिकांश वही चीज़ें लेना चाहता जिनकी भारत में कमी है औरयदि चीन भारी प्रस्तावित मात्रा दे भी सकता है तो उसे जल्दी से भारत लाने वाले जहाज़ मौजूद नहीं हैं।

कनाडा ने भी अमेरिका जैसी शर्त पर गेहूं देना स्वीकार किया है किन्तु यह गेहूं घटिया दर्जे का है (आजकल केवल इसी तरह का गेहूं उपलब्ध है) और भारत सरकार को इसे अस्वीकार करना पड़ा है।

भारत की मुख्य आशा अभीतक अमेरिका ही है, जितनी जल्दी आशा पूरी हो उतना अच्छा । इस बीच में यह बहुत ज़रूरी है कि उसके पास जितना अन्न है वह जितनी अच्छी तरह हो सके बांटा जाए। अन्त में पत्र ने भारत को यह स्मरण दिलाया है कि लार्ड वेवल ने सेना और उसके यातायात साधनों से १९४३ के अकालको अन्त में जाकर काबू में किया था ।

H.S.10/51

प्रतिरक्षा के लिए धन की प्राप्ति का प्रश्न

आर्थिक और वित्तीय विषयों के सुपरिचित ब्रिटिश लेखक गार्डेन कमिंग्स लिखते हैं : प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक अतिरिक्त साधनों का प्रबन्ध और साथ ही सा मुद्रास्फीति रोकने के प्रयत्न , यही वह सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है जो आज अधिकांश देशों के सामने है । सफलतापूर्वक इस समस्या का समाधान राज्य की कार्रवाई से ही हो सकता है और बजट की नीति के ज़रिए सबसे अधिक प्रभावदायक ढंग से । बल्कि और अधिक प्रयत्नों की मांग शांतिकाल में उतनी सरल नहीं है जितनी आसान वह युद्ध की अवधि में होती है । इसलिए बजट की नीति को सफल होने के लिये केवल इन साधनों का ही प्रबन्ध नहीं करना होता , केवल मुद्रास्फीति को रोकने की व्यवस्था नहीं करनी होती , किन्तु ये सब अधिक परिश्रम के प्रोत्साहन को नष्ट किए बिना करना होता है ।

ब्रिटेन का प्रतिरक्षा बजट , जो १० अप्रैल को प्रकाशित किया गया था, इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करता है । और ये आवश्यकताएं हैं क्या ?

१. जनता की व्यय शक्ति को सीमित करना , ताकि वह सार्वजनिक उपभोग के लिये उपलब्ध सामग्रियों और सेवाओं से अधिक न हो।
२. विशेष प्रकार के व्यय को निरूत्साहित करना , अर्थात् ऐसे व्यय को जो प्रतिरक्षा कार्यक्रम से मेल न खाते हों ।
३. इस बात का ध्यान रखते हुए कि बढ़ते हुए मूल्यों का भार सबसे अधिक कम आय पाने वालों के समूहों पर पड़ता है और बन्धी हुई आय के लोगों पर भी , कम आयवालों की कठिनाइयां कम करना।

H/L.P.S. 164

ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति संकलन

बजट और उसकी प्रतिक्रिया

कई ब्रिटिश समाचारपत्रों ने १९५१ ५२ के ब्रिटिश बजट पर, जो दस अप्रैल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, टीका टिप्पणी की है।

"डेली टेलीग्राफ" ने "कठिन समयों के लिये कठिन बजट" शीर्षक लेख में लिखा है कि उस भाषण से, जिसके साथ वित्त मन्त्री, श्री० ह्यू० गेतस्केल, ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, उनका राजनैतिक स्तर निश्चय ही बढ़ेगा।

पत्र कहता है कि वित्त मन्त्री के कुछ प्रस्तावों की आलोचना औचित्य के साथ की जा सकती है। कुछ अन्य प्रस्ताव समझदारी के सूचक हैं और वित्त मन्त्री के विरोधी भी उनके इस दावे से असहमत नहीं हो सकते कि बजट सचाई का परिचायक है। यह आशा आमतौर पर की जाती थी कि वित्त मन्त्री को नए करों के ज़रिये १५,००,००,००० पौंड प्राप्त करने होंगे और इस धन को प्राप्त करने में वित्त मन्त्री ने समुदाय के किसी एक अंग पर अत्यधिक बोझ न डालने के लिये भार को विस्तृत क्षेत्र में बांटा है। अन्त में पत्र कहता है कि बजट करदाता पर उतने अधिक बोझ नहीं लादता जितने की उसे आशंका थी।

"डेली हैरल्ड" ने बजट को औचित्य और सचाई का सूचक बताते हुए लिखा है कि बलिदानों के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा सम्भव नहीं है। बजट ने इसी सचाई का सामना किया है। यदि हमें अपनी सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना है (जैसा करने के लिये हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण बाध्य हुए हैं) तो हमें इस समय अपने जीवनस्तर

... को गिराने

को गिराने के लिये तैयार रहना है । बजट ने बढ़े हुए करों का भार उनपर डाला है जो उसे सहन करने की योग्यता सबसे अधिक मात्रा में रखते हैं । इसीलिये हम उसे उचित कहते हैं ।

वृद्धावस्था के निवृत्तिवेतनोंमें वृद्धि को न्यायोचित बताते हुए पत्र कहता है कि इससे ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें बढ़ते हुए खर्चों के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं

बजट के अन्य अंगों पर विचार प्रकट करते हुए पत्र अन्त में लिखता है कि यदि बढ़ते हुए लाभांशों पर रोक लगाने के लिये कोई कार्रवाई न की गई होती तो न्यायोचित बजट का यह चित्र अधूरा ही रह जाता । पत्र ने वितरित लाभों पर अधिक कर के प्रस्ताव को ठीक और उचित बताया है ।

'टाइम्स' ने लिखा है कि उन आम आर्थिक बातों की दृष्टि से जिसपर बातों आधारित है इस वित्तीय वर्ष में नए बजट प्रस्तावों द्वारा राष्ट्रीय वित्तों में वृद्धि के वित्त मन्त्री के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती ।

विस्तृत आलोचना करते हुए पत्र ने कारबार लाभों पर कर का खासतौर से उल्लेख किया है और लिखा है कि यदि कर इस स्तर पर बहुत समय तक जारी रहेंगे त उनके फलस्वरूप उद्योगों को हानि होगी, मूल्यों में वृद्धि होगी और निर्धनता तथा बेकारी का सामना करना पड़ेगा । यही त्रुटि आयकरों की वृद्धि में भी है । पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वित्त मन्त्री को पूरे वर्ष में अतिरिक्त राजस्व का ती चौथाई से अधिक भाग इन्हीं दो स्रोतों से मिलेगा । बजट बनाने में वित्तमन्त्री को इन बुराइयों में से चुनाव करना था ।

'यार्कशायर पोस्ट' ने कहा है कि श्री० गैतस्केल का पहला बजट एक संकटकालीन अवस्था का सामना करने के लिये बनाया गया था । वित्तमन्त्री के सामने उपस्थित बहुत कठिन और बड़े कार्य का ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उ अपनी समस्या को निपुणता के साथ सम्हाला और, जैसाकि श्री० चर्चिल ने कहा है काफी सचाई के साथ भी ।

'न्यूज़ क्रानिकल' ने इसे 'परिवार' का बजट कहा है और लिखता 'एक योग्य किन्तु उत्साहहीन ढंग से श्री० गैतस्केल ने एक योग्य किन्तु उत्साहहीन ब उपस्थित किया । एक या दो बातों के अतिरिक्त उनके प्रस्ताव सच्चे और न्यायो हैं, विशेषतया पारिवारिक व्यक्ति के लिये । किन्तु उनमें उत्साह या आर्थिक प्रोत का अभाव है ।

... बजट की

बजट की सबसे बड़ी त्रुटि सरकार के खर्चों में मुख्य कमी के प्रस्तावों का न होना है। पत्र की दृष्टि में यह बहुत शोचनीय है कि राजनैतिक कारणों से यह अवस्था अनिवार्य थी। इन बातों का ध्यान रखते हुए वित्तमन्त्री के पास बहुत सीमित क्षेत्र था। उनकी मुख्य भूल थी वितरित लाभों और पेट्रोल पर करों में वृद्धि के ज़रिए आवश्यक अतिरिक्त करों का इतने बड़े भाग पाने की चेष्टा।

पत्र ने पेट्रोल पर कर की आलोचना करते हुए बताया है कि उससे जीवनव्यापन के खर्चों में वृद्धि होगी। वृद्धावस्था के निवृत्तिवेतन भोगियों को दी जाने वाली राहत की प्रशंसा, और आयकरों में वृद्धि पर दुःख प्रकट करते हुए "न्यूज़ क्रानिकल" ने नकली दांतों और चश्मों के लिये पैसे देने के प्रस्ताव को "साहसी और समझदारी का सूचक" कहा है।

"डेली मेल" ने इसे एक मध्यमश्रेणी का और आकर्षणहीन बजट बताया है।

"डेली ग्राफिक" ने लिखा है कि अगले वर्ष और उसके बाद वाले वर्ष में प्रतिरक्षा के खर्च में और भी वृद्धि होगी। सच बात यह है कि देश ने अभी तक पुनःशस्त्रीकरण के लिये भुगतान शुरू भी नहीं किया है। यदि सरकार की फिज़ूलखर्ची रोकी नहीं जाती और हम सरकारी अनुमानों से भी अधिक उत्पादन नहीं कर दिखाते तो हम सब पर आगामी बारह महीनों की अवधि में अधिक कटु बोझ लादे जायेंगे।

F.H.181

तरुण अपराध का अध्ययन

भारतीय महिला का मत

(सिल्विया मैथिसन)

तरुण अपराधियों और बुरे प्रबन्ध के कारण भ्रष्ट तरुणों की समस्याएं ब्रिटेन में विधियों से, और कई विशेषता-प्राप्त संस्थाओं द्वारा, सुलझाई जाती हैं।

मद्रास के 'बाल सहायता समाज' की निरीक्षिका, कुमारी कोकिला दोराइस्वामी, इनसे बहुत प्रभावित हुई हैं। उन्होंने ब्रिटेन में तरुणों के कारागारों स्कूलों का चक्कर लगाया, साधारण स्तर से कम विकसित बच्चों के स्कूल देखे, माताओं और बच्चों के घरों में ये घूम आईं और आवासों, धायघरों तथा अन्य संगठनों से परिचित हुईं। इन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और तरुणों के न्यायालयों इत्यादि में उपस्थित थीं।

खुले कारागारों को देखकर आप बहुत प्रसन्न हुईं। कुमारी कोकिला दोराइस्वामी ने कहा: मैं चाहती हूँ कि मद्रास में भी ऐसे कारागार स्थापित किए जाएं

> 'मुझे निश्चय है', उन्होंने कहा, 'कि ऐसे कारागार, जहां लो को बन्द नहीं किया जाता और जहां, उचित लोगों की देखरेख में, भा का प्रयत्न न करना उनकी न्याय की भावनाओं के भरोसे छोड़ दिया है, बहुत हितकारी सिद्ध हो सकते हैं।

ब्रिटिश कौंसिल के प्रबन्ध के अन्तर्गत ब्रिटेन आईं कुमारी दोराइस्वामी ने तरु की नियुक्ति की समस्या में, जिनका समाधान ब्रिटेनमें बड़े स्तरपर, विशेषताप्राप्त सर विभागों द्वारा किया जाता है, गहरी रुचि दिखाई।

F.H.167

साम्यवादी चीन में आतंक का साम्राज्य

गाई विन्ट,
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के सुपरिचित
टीकाकार जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया
और सुदूरपूर्व की विस्तृत यात्रा की है।

अ धि कां श लोग सामाजिक उन्नति के लिए क्रान्ति की अपेक्षा क्रमिक विकास का मार्ग इसलिये अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि क्रान्ति में लगभग सदैव ही नर नारियों का बड़ी संख्या में संहार किया जाता है। महान क्रान्तियों, जैसे फ्रांस और रूस की, का स्मरण उनके आतंक के कारण किया जाता है। आतंक इन क्रान्तियों में से किसी के प्रारम्भ में नहीं हुये थे। प्रारंभिक कुछ महीने में तो आश्चर्यजनक संयम देखने में आया था, यहां तक कि रूस में भी। किन्तु क्रान्तिकारी शासनों ने मुश्किलों में पड़ते ही अपने देश के लोगों पर ऐसी निर्दयता दिखाई जिससे सभ्य संसार सिहर उठा।

यही आज चीन में हो रहा है। सत्ता प्राप्त करने के बाद वाले कुछ महीनों में चीनी साम्यवादियों ने नियमित रूप से नरमियत और संयम दिखाया था। यद्यपि चीनी साम्यवादियों का शासन एक कठोर शासन था और वे लोगों से पूर्ण आज्ञापालन की मांग करते थे किन्तु उन्होंने चीनी जनता को उनकी जान के डर से ग्रस्त नहीं किया था। क्रान्ति का यह संयमपूर्ण अध्याय कोरिया के युद्ध में पीकिंग शासन के लगने के बाद समाप्त हो गया था।

... ज्यों ज्यों

ज्यों ज्यों समय बीतता जायेगा कोरिया में हस्तक्षेप करने का चीन का निर्णय इन समयोंकी ऐसी घटनाओं में एक समझा जायेगा जिसने संसार की गतिविधि को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया है। इस निर्णय ने ऐसी घटनाओं का क्रम प्रारम्भ कर दिया है जो बहुत आपत्तिजनक है। और आन्तरिक मामलों में इसने चीन में आतंक के राज्य का अध्याय खोला है।

मृत्युदंडभोगियों की भरमार

२१ फरवरी को पीकिंग सरकार ने एक आज्ञप्ति द्वारा कई प्रकार के अपरा के लिये मृत्युदंड की घोषणा की थी। यहां तक कि उन लोगों के लिये भी मृत्युदंड निर्धारित किया गया था जिन्होंने साम्यवादी क्रान्ति का विरोध किया था और, साम्यवादियों की सफलता के बाद से, 'श्लाघनीय कृत्यों' द्वारा अपनी 'शुद्धि' नहीं की है। यह आज्ञप्ति इस ढंग से तैयार की गई है कि उसमें ऐसे सब व्यक्ति, जि साम्यवादी छुटकारा पाना चाहते हैं, सम्मिलित किये जा सकते हैं। सचमुच, इस आज्ञप्ति से चीनी लोग शासकों की दयादृष्टि के लिये उनके दास बना दिये गये हैं। माओत्से तुंग ने आज्ञप्ति पर स्वयं हस्ताक्षर कर मानो यह दिखाया कि इस आज्ञप्ति सरकार कितनी गम्भीरता से लेती है। कारण, इस आज्ञप्ति पर स्वयं माओत्से तुंग हस्ताक्षर करना साम्यवादी चीन के अध्यादेशों (आर्डिनेन्स) के लिये बड़ी असाधार बात है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि सारी बात इस आज्ञप्ति के वास्तविक अमल पर निर्भर है। यह सोचा जा सकता था कि यह आज्ञप्ति केवल असाधारण परिस्थिति में शासन के हाथ को शक्तिशाली बनाने के लिये असाधारण अधिकार देने के उद्देश्य बनाई गई थी। किन्तु उसके पास होने के समय से मृत्युदंडभोगियों की संख्या में भा वृद्धि हुई है। यद्यपि यह सत्य है कि फारमोसा में कुओमिन्तांग सरकार द्वा प्रकाशित संख्याएं प्रचारार्थ बढ़ाचढ़ा कर दी गई हैं पर स्वयं पीकिंग सरकार मृत्युदंड प्राप्त लोगों की लम्बी लम्बी सूचियां प्रकाशित कर रही है। यह अच्छा है कि वह विषय में सत्य पर पर्दा डालने की बजाय उसे सबके सामने रख रही है। किन्तु इससे भी स्पष्ट है कि जानबूझ कर जनता को भयग्रस्त करना उसकी नीति है।

और ये अभागे व्यक्ति हैं कौन? साधारणतया इन्हें कुओमिंतांग के पुरा अधिकारी, पश्चातापहीन 'प्रतिक्रियावादी' या 'विशेष एजेन्ट' कहा गया

... कोरिया के

कोरिया के युद्ध के दिनों में कुओमिन्तांग की सरकार ने मुख्यभूमि पर साम्यवादियों का विरोध करने के लिये गुरिल्लों को सफलतापूर्वक उभाड़ा था । बस , इस बात ने साम्यवादियों को बहुत नाराज़ कर दिया और उनकी निगाह में हर जगह कुओमिन्तांग के "विशेष एजेन्ट" छिपे हुये हैं ।

आतंक का राज्य

मृत्युदंड के "अधिकारी" बनने के लिये कोई विशेष अपराध करना आवश्यक नहीं मालूम पड़ता । क्योंकि पीकिंग रेडियो के अनुसार "प्रतिक्रियावादियों" को प्रतिक्रियावादी होने से इन्कार करने और प्रतिक्रियावादियों की सूचियों में नाम न लिखाने के अपराध में प्राणदंड दिये जा रहे हैं । साम्यवादी राज्य में उन लोगों की दशा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है जिन्होंने अपने नाम "प्रतिक्रियावादियों" की सूचियों में अंकित कराये हैं । और जिन्होंने अपनी "प्रतिक्रियावादिता" स्वीकार नहीं की उनकी दशा ?

कई वर्ष पुराने और अप्रमाणित अपराधों के लिये लोगों को दंड दिया जा रहा है । हाल में पीकिंग में एक व्यक्ति को इसलिये प्राणदंड दिया गया था क्योंकि उसने २४ वर्ष पहले किसी साम्यवादी प्रोफेसर की हत्या कर डाली थी । पीकिंग में हाल की विध्वंसक कार्रवाइयों के बल पर गिरफ्तारियों का आन्दोलन उचित और आवश्यक कहा जा रहा है। ५६ ट्राम गाड़ियां जला दी गईं और एक कारखाना तोड़ डाला गया : इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए एक साम्यवादी पत्र ने अपने पाठकों से पूछा है कि क्या ऐसी भयंकर घटनाओं का अन्त करना आवश्यक नहीं है? पर सच यह है कि यह विध्वंसक कार्रवाई सितम्बर , १९४६ की घटना है

एक विशेष आन्दोलन , बौद्ध और "टाओइस्ट" जिसके मुख्य शिकार हैं, धार्मिक संगठनों के विरुद्ध चल रहा है । पीकिंग की आज्ञा से पुराने मुकदमें फिर चलाये जा रहे हैं । कुछ समय पहले चुंकिंग शहर में चार हज़ार लोग गिरफ्तार किये गये थे ।

राजनैतिक दृश्य के रूप में इन प्राणदंडों का प्रयोग इस आतंक के शासन की सबसे भयंकर बात है । समाज की दृष्टि में सार्वजनिक प्राणदंड असभ्यता के उदाहरण हैं । किन्तु नए चीन में विशाल जनसमुदायों के सामने हुये प्राणदंडों की सूचना साम्यवादी रेडियो निरन्तर दिया करता है । कुछ प्राणदंड तो ५० हज़ार "दर्शकों" के सामने दिये जा चुके हैं

चुके हैं। इस प्रसंग में मैं लाल चीन की राजधानी , पीकिंग , में हुई एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। ५,५०० `जनप्रतिनिधियों` के सामने २५ अभियुक्त उपस्थित किये गये थे। एक उच्च अधिकारी ने लोगों से पूछा : इन विशेष एजेन्टों , इन डाकुओं और लुटेरों और गुप्त धार्मिक समाजों के नेताओं को क्या दंड मिलना चाहि लोगों ने चिल्लाकर जवाब दिया : इन्हें गोली से उड़ा दो और जनता की तरफ बदला लो।

यह आतंक चीनी क्रान्ति के विषय में बाहिरी संसार के विचार पर गहरा प्रभाव डालेगा।

N.E.H.39

आहार के अभाव से पशुओं का संहार

केन्द्रीय और पूर्वी चीन में खाद्यान्न की आम कमी से हल खींचने वाले बैल भूख के कारण मर रहे हैं।

<u>यांगत्सी डेली</u> (हैंको) नामक पत्र लिखता है कि चीन के केन्द्रीय भाग में अवस्थित छः मध्य और दक्षिण प्रान्तों में सभी जगह सर्दी, पैर तथा मुंह रोग और निरन्तर भूख जैसी तीन बातें खिंचाई करने वाले जानवरों को बहुत बड़ी संख्या मेंमारने के लिये एक साथ पैदा हो गई हैं। मृत्यु का मुख्य कारण पशु खाद्य की कमी थी ।

=====================

H/L.P.S.166

ब्रिटिश विज्ञान एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन

विज्ञान की उन्नति से सम्बन्धित ब्रिटिश एसोसिएशन के इस वर्ष के सम्मेलन संसार के लिये पिछले सौ वर्षों में ब्रिटेन दव्ारा दिये गये विज्ञान और टेक्नालाजी (शिल्प कला विज्ञान)सम्बन्धी अंशदानों पर प्रकाश डाला जायेगा । यह घोषणा की गई है कि सभा का यही आम विषय रहेगा किन्तु अन्य बातों पर भी चर्चा चलाई जा सकेगी है ।

ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे इस वर्ष का सम्मेलन,जो एडिनबरो में अगस्त में होने वाला है , ब्रिटेन के समारोह के एक भाग का रूप धारण कर लेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष , सर हैराल्ड हार्टले , ने कहा था कि मेरे विचार से इस सभा में कम से कम चार हज़ार व्यक्ति सम्मिलित होंगे ।

एक पूरा दिन अविकसित देशों के लिये वैज्ञानिक सहायता , जिसमें ब्रिटेन सक्रिय भाग ले रहा है , के सम्बन्ध में विचार-विनिमय में ख़र्च किया जायेगा। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल की जायेगी और उन्हें पूरा करने के सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे ।

इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण एसोसियेशन के अध्यक्ष एडिनबरो के ड्यूक द्वारा दिया जायेगा।

N.E.H.40

भारतीय विद्यार्थियों का एसोसिएशन और उसके कार्य

जी०वी०टी० चर्च

ब्रिटेन और योरप में भारतीय विद्यार्थी एसोसिएशनों का संघ, 'फेडरेशन आफ इंडियन स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन्स,' अपने संक्षिप्तरूप में 'फेडिन्ड' कहलाता है। इस फेडरेशन में, जिसकी स्थापना १९३६ में हुई थी, १२ ब्रिटिश नगरों और ज़्यूरिच(स्विज़रलैंड) के तेरह भारतीय विद्यार्थी संगठन सम्मिलित हैं। ये अपने अपने विश्वविद्यालयों और प्रादेशिक केन्द्रों में स्वतन्त्ररूप से काम करते हैं। सम्मिलित निकायों की सम्पूर्ण सदस्य संख्या लगभग ६०० है।

सांस्कृतिक कार्य, वाद विवाद, भाषण और सामाजिक सभाएं 'फेडिन्ड' के सदस्य संगठनों के मुख्य कार्य हैं। इन कार्यों का उद्देश्य एक ओर ब्रिटिश, औपनिवेशिक और अन्य विदेशी विद्यार्थियों और दूसरी ओर भारत के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों में अधिक घनिष्ठ पारस्परिक समझ पैदा करना है। इन सदस्य संगठनों के कार्य का आयोजन 'फेडिन्ड' अपने सांस्कृतिक विभाग के ज़रिए करता है। यात्रा और कल्याण सम्बन्धी उसके अन्य विभाग भारतीय विद्यार्थियों को ब्रिटेन और योरप में यात्रा करने का प्रोत्साहन देते और उनकी रहने का स्थान जैसी समस्याएं सुलझाते हैं।

'फेडिन्ड' ने कुछ समय पहले अपना पन्द्रहवां वार्षिक सम्मेलन बुलाया था जिसमें ब्रिटिश नगरों के विश्वविद्यालयों के 'फेडिन्ड' में सम्मिलित भारतीय विद्यार्थी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भारत भवन, लन्दन, के शिक्षा विभाग के मन्त्री श्री० एल. आर. सेठी ने अपने भाषण में बताया कि १९३९ में ब्रिटेन स्थित भारतीय विद्यार्थियों की संख्या एक हज़ार चार

... सौ थी

सौ थी और १६५० तक यह संख्या दुगनी हो गई थी। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने आवश्यक कार्य करने के साथ साथ शिक्षायुक्त आमोद प्रमोद का आस्वादन भी किया था। वे लोग ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेक डिस्ट्रिक्ट की प्राकृतिक रमणीयता देखने गये थे।

सम्मेलन के अवसर पर लीड्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर जी. पैट्रिक मेरेडिथ ने 'संगठन का विज्ञान' नामक विषय पर भाषण दिया। कलकत्ता के श्री० बी. बेनर्जी, जो लीड्स विश्वविद्यालय के खान खोदाई विभाग में अनुसन्धान कर रहे हैं, ने 'भारत में अनुसन्धान संगठन' को अपने भाषण का विषय बनाया था। लन्दन मजलिस की कुमारी के. सेनजित 'भारत में सिनेमा और सिनेमादर्शक' पर बोली थीं। भारती और सामान्य रुचि के चित्रपटों का कार्यक्रम, भारतीय गायन और नृत्यों का आयोज और ब्रिटिश लोकसभा के उपाध्यक्ष मेजर जे० मिलनर द्वारा 'संसदीय जनतन्त्र' पर भ ये सम्मेलन की कुछ अन्य उल्लेखनीय घटनाएं थीं।

लन्दन की महिला गाइड

ब्रिटिश ट्रैवेल एन्ड हालिडे एसोसियेशन के लिये काम करने वाली पच्चीस पंजीवद्ध महिला गाइडों (मार्गदर्शिकाओं) में सबसे छोटी, लन्दन की सी० स्मिथ इस 'व्यवसाय' कई वर्षों से काम कर रही है इसलिये उसको लन्दन के सम्बन्ध में एक कुशल टैक्सी ड्राइवर सी जानकारी प्राप्त हो गई है। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उसके साथ ाले अजनबी (यात्री) जल्दी से जल्दी अपने को किसी देखे हुए स्थान में आया हुआ मझने लगें और यह भांपने का भी प्रयत्न करती है कि हरेक यात्री कौन-कौन सी बातें सन्द करता या देखना चाहता है।

** ** **

साइकिल चलाने का पुरस्कार

ब्रिटेन में साइकिल चलाने से सम्बन्धित बिडलेक मेमोरियल प्राइज नामक महत्वपूर्ण पुरस्कार एक महिला ने प्राप्त किया था जिसका नाम श्रीमती ई० शेरिडन है। कावेन्ट्री की यह गृहणी एक नन्हें-मुन्ने की माता और इस पुरस्कार को (जो १९३४ में प्रारम्भ किया गया था) प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है।

** ** **

कन्या किसान

ब्राइटन के निकट फाल्मर में ऐडा (टिना) टीग नामक कन्या ने अपने बीस एकड़ वाले फार्म में सात गऊएं, एक वर्षीय बछियां, चार बछड़े, एक घोड़ा, एक

... कुत्ता और

कुत्ता और बीस मुर्गियें इत्यादि जानवर पाल रखे हैं। उसका कोई सहायक नहीं है उसकी आमदनी के चार साधन हैं : दूध, अंडे, पौधे और आलू और बछड़ों या बेकार बछियों की बिक्री। बीस वर्ष की होने से पूर्व (पांच साल पहले) टिना को कृषि कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी किन्तु जब उसके पिता बिल्कुल पंगु हो गये तो उसने खेत में हररोज़ चौदह घन्टों तक काम करना प्रारम्भ कर दिया था। टिना इस विकसित कृषिशाला से लगभग पांच पौंड (६७ रूपये) प्रति सप्ताह निखर्च नफ़ा कमाती है।

** ** **

घरेलू परिचारिका

केन्ट काउन्टी कौंसिल की घरेलू परिचारिका श्रीमती ई०एम०शार्प १९३७ से एक घरेलू सेविका के रूप में काम कर रही है इसलिये उसकी उदाहरणीय कर्तव्य परायणता के लिये उसकी ब्रिटिश साम्राज्य पदक नामक एक पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती शार्प पहले केवल गर्भवती स्त्रियों की सेवा करती थी पर बाद में वह तपेदिक और अन्य संक्रामकरोगों वाले लोगों के घर भी जाने लगी थी। उसने अपने वचन को कभी भंग नहीं किया और वह इस कार्य की खातिर कारखाने की अधिक आमदनी को ठुकरा चुकी है।

** ** **

... ब्रिटेन की

शिक्षात्मक यात्राएं

ब्रिटेन की शिक्षात्मक यात्राओं और अदला-बदलियों से सम्बन्धित सेन्ट्रल ब्यूरो (केन्द्रीय कार्यालय) ने अपनी रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया था कि यदि आवश्यक प्रोत्साहन मिलता रहा तो भविष्य में ऐसा एक भी ब्रिटिश युवक नहीं मिलेगा जिसे पड़ोसी देशों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि पिछले वर्ष तीस हज़ार ब्रिटिश लड़के-लड़कियां शिक्षात्मक यात्राओं के लिये विदेश गये थे। ब्यूरो के निर्देशक ने फ्रांस के बत्तीस केन्द्रों की यात्रा की थी जहां बाल-बच्चे बुलाये गये थे और यह पाया था कि छोटे नगरों के आगन्तुकों ने प्रसिद्ध यात्री केन्द्रों का भ्रमण करने वालों की तुलना में अपनी यात्राओं से अधिक लाभ उठाया था।

** ** **

बच्चों का आश्रम

मैनचेस्टर के निकट हालिन्स मूर पर अवस्थित "दि कैट एन्ड दि फिडल" नामक बाल आश्रम में बच्चे किसी भी सप्ताहांत को या पूरे एक सप्ताह तक ठहर सकते हैं। इस आश्रम की मालिका कुमारी ऐशटन (एक भूतपूर्व गर्ल गाइड संचालिका) ने इसको निर्धन बच्चों के लिये विशेषतया आवश्यक समझा था। वह सप्ताहांत के लियें केवल दस शिलिंग (६-१०-० रूपये) और एक सप्ताह के लिये एक पौंड से कम किराया लेती है। यहां पर छुट्टी मनाने वाले तरुण तैराकी, नौका बिहार, घूमने-फिरने और चढ़ाई-उतराई जैसी बातों का आनन्द लूट सकते हैं।

** ** **

... दुर्घटना बचाव

सड़क शिष्टाचार

दुर्घटना बचाव से सम्बन्धित ब्रिटिश रायल सोसाइटी सड़क दुर्घटनाओं में बाल हानियों की संख्या घटाने के दृष्टिकोण से इस वर्ष एक मार्ग शिष्टाचार आन्दोलन कर रही है जो पिछले वर्ष स्कूलों , सड़क सुरक्षा समितियों और स्थानीय प्राधिकारि दव्‌ारा किये गये प्रयत्नों को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। इन निकायों को इस सोस के कार्यक्रम की सूचना भेज दी गई हैं जिसमें पोस्टरों और अभ्यासों दव्‌ारा बच्चों को उपयोगी बातें बताई जायेंगी।

** ** **

शिक्षक की कहानी

बच्चों के माता - पिता लन्दन में होने वाले ब्रिटिश महोत्सव की उस प्रदर्शि में बहुत रूचि लेंगे जो पिछले सौ वर्षों में एक विद्यालय शिक्षक की कहानी बताने के दृ से आयोजित की गई है। यह प्रदर्शिनी "आप के दादा के शिक्षक" से प्रारम्भ होकर "आप के पिता के शिक्षक" , "आप के शिक्षक" तथा "आपके बच्चे के शिक्षक" जै अवस्थाओं का परिचय देती हुई आजके उस शिक्षक के जटिल कार्य पर प्रकाश डालेगी स्कूल चिकित्सा, भोजन , बाल निर्देशन , युवक नियोजन आदि से सम्बन्धित व्यवस्थ के अतिरिक्त शिक्षा सुधार अधिकारी और स्कूल बचत समूह को भी सहयोग प्रदान क पड़ता है ।

ब्रिटिश अन्न उत्पादन का रिकार्ड

आजकल ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों का उत्पादन युद्धपूर्व की तुलना में चालीस प्रतिशत [illegible] हुआ है । यह बात कृषि मन्त्री श्री० टाम विलियम्स ने लन्दन में २६ मार्च को भाषण देते हुए बताई थी। ब्रिटिश कृषि से सम्बन्धित भावी नीति पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन खाद्य पदार्थों की सप्लाइयों के बढ़ते हुए अंश के लिये अपने [कि]सानों पर भरोसा कर रहा है। वर्तमान घरेलू खाद्य उत्पादन किसानों के प्रयत्नों के [फल]स्वरूप युद्धपूर्व के परिमाण से चालीस प्रतिशत से अधिक तक की महत्वपूर्ण सतह तक पहुंचा [ग]या है। इस बात को बताने का मुख्य लक्ष्य यह है कि उत्पादन को राष्ट्रीय आवश्यकताओं [के] अनुसार बढ़ाना चाहिये । सरकार के विचार से अब मांस के उत्पादन पर मुख्यतया [ध्या]न दिया जाना चाहिये और दूध उत्पादन के लिये चालू विशेष कार्यवाइयों को ढीला [कि]या जा सकता है ।

F.H./L.P.S.159

तिब्बत - चीन सम्बन्ध

शीघ्र समझौते की सम्भावना

लन्दन टाइम्स ६ अप्रैल वाले सम्पादकीय में तिब्बत की हाल की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए और पीकिंग जाने वाले तिब्बती शिष्टमंडल पर टीका टिप्पणी करने के बाद लिखता है : चीनी लोग बातचीत के लिये समय देना चाहते थे और यही कारण है कि सेनायें आगे बढ़ने से रुकी रहीं । उन्होंने तिब्बत की असली हालत को तरह से जांचने पर यह समझ लिया कि उस देश में "साम्राज्यवादी षड़यन्त्र" सम्बन्धी उनका प्रारम्भिक भय आधारहीन था । पीकिंग रेडियो ने दलाई लामा और इसकी पर प्रहार करना बन्द कर दिया था और यह घोषणा की थी कि चीन उसके राजनैतिक और धार्मिक पद को मानने के लिये तैयार है ।

पत्र आगे चलकर लिखता है कि फरवरी के प्रारम्भ में (चीनी नव वर्ष के सम अधिकार करने वाले प्राधिकारियों ने चाम्दा में तिब्बतियों की एक सभा में बताया कि चीन तिब्बत में ऐसा कोई अभिप्राय लेकर नहीं आया जिसे लासा सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसका केवल यही अर्थ निकल सकता है कि दलाई लामा को स्थानीय स्वायत्तता देने को चीन तैयार था। इस घटना के कुछ समय बाद ही दलाई लामा ने अपने उन कुछेक अधिकारियों को वापस बुला लिया जिनको उन्होंने भारत में पनाह लेने अनुमति दी थी और स्वयं लासा लौटने की व्यवस्था करने लगे ।

ऐसा दिखाई देता है कि इस समय पीकिंग जाने वाले शिष्टमंडल ने ऐसे समझौते की बारीकियों को ही भरना है जिसका विस्तृत रूप पहले ही तय किया जा चुका है । दिल्ली में विश्वास किया जाता है कि एक समझौता हो गया है जिसके

... तिब्बत स्वा

तिब्बत स्वाधीनता का अपना दावा छोड़ देगा और स्थानीय स्वायत्तशासन तथा दलाई लामा के सैद्धान्तिक शासन का चालू रहना स्वीकार करने के बदले में प्रतिरक्षा और परराष्ट्र सम्बन्धों पर चीनी नियन्त्रण स्वीकार कर लेगा ।

यदि यही बात है तो भारत में इसे बहुत अच्छा समझा जायेगा । तिब्बत पर चीनी आक्रमण के समय भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था और भी मज़बूत बना दी गई थी।

दिल्ली में श्री० नेहरू के हाल के एक वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार अब यह समझती है कि चीन ने तिब्बत के साथ अपने मतभेदों को सैनिक कार्रवाई के ज़रिये तय करने के अपने प्रारम्भिक इरादे को (जो चीनी सेनाओं को भारतीय सीमा तक ले आया होता) कतई त्याग दिया है ।

N.E.H.41

यहां की ईंट, वहां का रोड़ा

फिनलैंड की सोशल डिमाक्रेटिक पार्टी के मुखपत्र ने द्वितीय मार्च के अंक में जाहवे
नामक लेखक की निम्नलिखित पंक्तियां प्रकाशित की हैं :

फिनलैंड के साम्यवादी दैनिक पत्र, 'वापा साना', के २७ फरवरी वाले अं
में ये शीर्षक पढ़ने को मिले थे : इंग्लैंड में जहाज़ी घाट मज़दूरों की हड़ताल : संक
की घोषणा : कामकाजी पीछे नहीं हटे । लेकिन इसके नीचे वेलिंग्टन के जहाज़ी घा
मज़दूरों की हड़ताल का हाल छपा था ।

हमें पहले तो वाटर्लू के वीर का स्मरण आया, तब यह बात सूझी कि
वेलिंग्टन तो न्यूज़ीलैंड की राजधानी है और शीर्षक में उल्लिखित इंग्लैंड की हड़ताल से
उसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

हमने 'वापा साना' में प्रकाशित इस सम्वाद को फिर देखा और एक उप
पर हमारी निगाह गई : वेल्स में हड़ताल जारी । लेकिन नीचे जो समाचार छपा
था वह सिडनी, अर्थात् आस्ट्रेलिया, के बारे में था । और उसमें था हाल वेल्स
ब्रिटेन की कोयला हड़तालों का नहीं किन्तु न्यूसाउथ वेल्स की हड़ताल का ।

अधिक क्या कहें ? यह उदाहरण अपनी कहानी स्वयं सुनाता है । इससे मालूम
होता है कि साम्यवादी पत्रों में योरप का इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड या आस्ट्रेलिया बन सकता
है । फिनलैंड का साम्यवादी दल संसार के एक भाग में झूठ का प्रचार करने से सन्तु
नहीं है । वह सारे संसार को अपना शिकार बनाना चाहता है ।

F.H.148

१९५१ का "आर्थिक अवलोकन" ..

बचाव तैयारियां और अधिक औद्योगिक परिश्रम

ब्रिटिश अर्थ नीति के मुख्य प्रयोजन

हैरल्ड हचिन्सन,
औद्योगिक सम्वाददाता, "डेली मिरर", लन्दन

लोगों को राष्ट्र की आर्थिक स्थिति से अवगत करने के लिए और यह बताने के लिए कि उन्हें क्या करना है और क्यों ब्रिटिश सरकार पिछले पांच वर्षों से वसन्त ऋतु में एक "आर्थिक अवलोकन" प्रकाशित करती रही है। १९५१ के "आर्थिक अवलोकन" में, जो तीसरी अप्रैल को प्रकाशित हुआ था, इस बात पर ज़ोर डाला गया है कि पुन:शस्त्रीकरण कार्यक्रम को, जो हाल में इतना अधिक बढ़ा दिया है, ब्रिटिश अर्थ नीति का पहला लक्ष्य मानकर आगे बढ़ाना होगा।

यद्यपि पुन:शस्त्रीकरण की बात और उसके आर्थिक परिणाम "आर्थिक अवलोकन" पर छाए हुए हैं, पर उसमें दूसरा मुख्य राष्ट्रीय प्रयोजन भी स्पष्टतया प्रकट किया गया है। बचाव की तैयारियों के साथ साथ ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति और स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के प्रयत्न भी जारी रखे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के अभाव में प्रतिरक्षा कार्य अन्त में जाकर अपना सच्चा प्रभाव और गति खो सकता है।

...पिछले तीन

नया बोझ

पिछले तीन सालों के अन्दर मार्शल सहायता का बल प्राप्त ब्रिटिश प्रयत्नों ने राष्ट्रीय वित्त में विलक्षण उन्नति दिखाई थी। और इन प्रयत्नों का सम्पूर्ण महत्व आज समझा जा सकता है क्योंकि इन प्रयत्नों द्वारा डाली गई बुनियाद पर ही बचाव का विशाल कार्यक्रम आगे बढाया जा रहा है।

पिछली आर्थिक जांचों की एक मुख्य बात हुआ करती थी लोगों को यह समझाना कि युद्धपूर्व की आर्थिक परिस्थिति तुरत प्राप्त करना असम्भव है और उनका ध्यान कठिन किन्तु तय किए जाने योग्य रास्ते की ओर आकर्षित करना जिसपर चलने रहनसहन के स्तरों में सुधार सम्भव है। इस मार्ग के निर्धारक , उस समय के वित्त मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स , ने उसे 'संयम' का मार्ग कहा था : उत्पादन क्षमता में उन्नति , मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण और निर्यातों में वृद्धि के ज़रिए , विदेशी भुगतानों का सन्

ये सारे लक्ष्य पिछले वर्ष तक पूरे हो गये थे । उत्पादन १९४७ से तीस प्रति अधिक था और निर्यात साठ प्रतिशत ऊंचे । विदेशी घाटा ठोस बचत में परिवर्तित गया था और खाद्य संचय बढे थे । इन परिस्थितियों के कारण संयम के स्वरूप में जं परिवर्तन हुआ था उसका बहुत स्वागत किया गया था ।

किन्तु अब पुन:शस्त्रीकरण का नया बोझ , जिसमें सबसे ज़रूरी समस्या , अर्थात् मूल महत्व वाली कच्ची सामग्रियों का अभाव , सम्मिलित है , सामने आया आगामी तीन वर्षों में ब्रिटेन प्रतिरक्षा पर चार अरब सत्तर करोड़ पौंड खर्च करने जा है। यह संख्या पिछले तीन वर्षों की संख्याओं से लगभग दुगनी है। इस उत्पादन कार्य का प्रभाव सबसे अधिक गहरे रूप में इंजीनियरिंग तथा धातु प्रयोगक उद्योगों पर पड़ेगा अर्थात् ठीक उन्हीं उद्योगों पर जो सारे ब्रिटिश निर्यात व्यापार के आधार हैं।

ताकि अन्य उद्योगों , विशेषतया कपड़ा उद्योग और जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाने वाले , के सामने निर्यात के और भी बड़े लक्ष्य रक्खे जा सकें सम्पूर्ण निर्यातों न केवल बनाए रखना किन्तु बढ़ाना भी आवश्यक है। ऐसे अवसरों को छोड़ कर जब के लिए उनकी आवश्यकता हो , इन क्षेत्रों में निर्यातों को आम तौर पर देश के की तुलनामें प्राथमिकता दी जाएगी। यों स्पष्ट है कि देश के लोगों को वस्तुओं की कम मात्रा में होगी। डालर बाज़ारों को पहली प्राथमिकता मिलना जारी रहेगा।

... हाल के

हाल के वर्षों में प्रतिव्यक्ति की उत्पत्ति में सात प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। किन्तु, 'आर्थिक अवलोकन' के अनुसार, उद्योगों के असैनिक से सैनिक उत्पत्ति में परिवर्तित किए जाने और कच्ची सामग्रियों के अभाव के कारण, इस वर्ष चार प्रतिशत से अधिक वृद्धि सम्भव नहीं दीखती। किन्तु जो कुछ भी वृद्धि हो वह ब्रिटेन में कच्ची सामग्रियों के पर्याप्त प्रवाह पर निर्भर है और इस मामले पर सम्बन्धित राष्ट्र वाशिंगटन में विचार विनिमय कर रहे हैं।

प्राथमिक लक्ष्य

एक ओर पुन:शस्त्रीकरण कार्यक्रम ने उद्योगधन्धों पर नई मांगे लाद दी हैं और दूसरी ओर खाद्य और कच्ची सामग्रियों, ब्रिटेन जिनका आयात करता है और जिनका भुगतान वह अपने निर्यातों द्वारा करता है, के मूल्य बढ़ रहे हैं। 'आर्थिक अवलोकन' के अनुसार उसी परिमाण के आयातों का अतिरिक्त खर्च १९५१ में ७० करोड़ पौंड बैठता है। ब्रिटिश निर्यातों के बढ़ते हुए मूल्यों से आयातों के खर्च में वृद्धि का कुछ अंश पूरा हो जाएगा, पर सारा नहीं।

ये हैं ब्रिटेन के जीवन के आर्थिक अंश जिन्हें 'आर्थिक अवलोकन' ने स्पष्ट शब्दों में 'कठोर और अप्रिय' कहा है। पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वास्तविकता का सामना करने का संकल्प ले चुकी है। 'आर्थिक अवलोकन' के शब्दों में :

> राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति की आवश्यकता से ब्रिटिश लोगोंकी शक्ति और स्फूर्ति, निपुणता और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की योग्यता की परीक्षा होगी।

इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह है कि प्रतिरक्षा और निर्यातों को सर्वप्राथमिकता दी जाएगी और देश के व्यक्तिगत उपभोगों तथा असैनिक नियोजनों में कमी होगी। इन कमियों और उत्पादन वृद्धि की सहायता से दोनों प्राथमिक महत्व वाले लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी।

F.H./L.P.S.153

ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति संकलन :

'१६५१ का आर्थिक
अवलोकन'

वित्तमंत्री की कठिनाइयों का विश्लेषण

'आर्थिक अवलोकन' की बातों को दोहराने के बाद 'टाइम्स' आगामी बजट में वित्त मन्त्री के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार प्रकट करता है। पत्र का कहना है : ऐसे बजट के पक्ष में बातें मौजूद हैं जो बहुत अंश तक अप्रत्यक्ष करों में चुनी हुई वृद्धि तक सीमित रहे और मुख्य काम मूल्यों में स्वत: वृद्धि और एक निश्चित मूल्य सम्बन्धी नीति पर छोड़ दे । ऐसी अवस्था में करों में बढ़ती का बोझ अपेक्षाकृत हल्का रहेगा। पर इस बात से किसी को धोखे में न पड़ना चाहिये : ऐसी नीति स्वयं अकेले एक सन्तोषप्रद विदेशी भुगतान सन्तुलन को बनाए रखने या घरेलू मुद्रास्फीति को पूर्णतया दबाने में सहायक न होगी। इसके विपरीत, ऐसी नीति का अर्थ होगा इन गम्भीर बुराइयों को उनसे भी अधिक गम्भीर बुराइयों के मुकाबले में चुनना । अन्त में पत्र लिखता है : मूल्य हर हालत में बढ़ेंगे और यदि करों में विशाल वृद्धि नहीं की जाती तो मूल्यों में अतिरिक्त वृद्धि के रूप में नए बोझ उठाने पड़ेंगे । मन्त्री को बुराइयों में से चुनाव करना है ।

आर्थिक अवस्था का स्पष्टीकरण

यदि स्तालिन को इस बात में सचमुच सन्देह है कि ब्रिटिश सरकार शांति की इच्छुक है या नहीं तो वे '१६५१ के आर्थिक अवलोकन' पर एक सरसरी निगाह डालकर ही अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। अवलोकन युद्धप्रियता से उतनी ही दूर है जितनी दूर कोई चीज़ हो सकती है। इसपर

... प्रतिरक्षा के

प्रतिरक्षा के लिये धन और सामग्री पाने की आवश्यकताएं छाई हुई हैं। और इससे प्रकट होता है कि ऐसी सरकार का चित्र जो निराशा के वातावरण में भी यह आशा लगाए बैठी है कि देश से युद्ध की अर्थ व्यवस्था स्वीकार करने के लिये कहना आखिरकार आवश्यक न पड़ेगा। 'आर्थिक अवलोकन' ने परिस्थिति पर स्पष्ट प्रकाश डाला है। मैनचेस्टर गार्जियन

'डेली टैलीग्राफ' के मत में 'आर्थिक अवलोकन' एक योजना नहीं किन्तु एक प्रार्थना है। संख्याओं की तालिका से यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि उपभोक्ता के जीवनस्तर में बहुत साधारण गिरावट आएगी। पर यह बात उन परिस्थितियों के विस्तृत विश्लेषण से प्रमाणित नहीं होती जो सम्भवत: उसके भाग्य का निर्णय करेंगी।

आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

चार वर्ष पहले, ब्रिटेन के राजनैतिक इतिहास में प्रथम बार, सरकार ने जनता को राष्ट्र के पुनरुत्थान कार्यक्रम से अवगत करने के लिए एक 'आर्थिक अवलोकन' प्रकाशित किया था। तब, युद्ध के अभिशापों के कारण, अनेक आपत्तियां हमारे सामने खड़ी थीं। किसी प्रकार की शीघ्र मुक्ति बड़ी मुश्किल मालूम देती थी, डालर का घाटा कितना डरावना था। जो महान परिवर्तन हो चुके हैं उनका सूचक '१९५१ का आर्थिक अवलोकन' है। आज ब्रिटेन अपने पैरों पर खड़ा है। इस महान पुनरुत्थान में ब्रिटिश लोगों के योजनाबद्ध अध्यवसाय ने प्रधान अंशदान दिया है। यदि पुन:शस्त्रीकरण की आवश्यकताएं प्रकट न होती तो हम जीवनयापन के स्तरों में ऐसे सुधार की आशा कर सकते जो आधुनिक युगों के लिए विलक्षण होता है। डेली हेरल्ड

F.H.163

मदिरा के आदियों को नई आशा

एक ब्रिटिश फर्म 'क्रोनटेल' नामक एक ऐसी दवा तैयार कर रही है जो अधिक मदिरा पान से उत्पन्न रोग अथवा शराब पीने की पुरानी आदत से छुटकारा दिलवाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस दवा की खूबी यह है कि रोगी मदिरा पी की अपनी आदत को आत्मशक्ति का सहारा लिये बिना ही छोड़ सकता है : दवा रोगी को कुछ इस तरह से झनझना देती है कि थोड़ी सी मात्रा से ही उसका जी बहु घबराने लगता है । एकबार ऐसी घबराहट को अनुभव करने पर अधिकांश पियक्कड़ तबतक मदिरा पान नहीं करेंगे जबतक कि वे इसे प्रयुक्त करते हैं । लेकिन यह दवा किसी अस्पताल में डाक्टर की देखरेख में ही दी जानी चाहिये। 'क्रोनटेल' ब्रिटिश औद्योगिक मेले में जो ३० अप्रैल से ११ मई तक होगा, प्रदर्शित की जायेगी ।

** ** **

पेनिसिलिन उत्पादन में वृद्धि

पेनिसिलिन तैयार करने वाली एक बड़ी ब्रिटिश फैक्टरी ने पिछले तीन महीनों में कामकाजियों की संख्या बढ़ाये बिना ही अपने उत्पादन में सत्तर प्रतिशत की वृद्धि की ली है। निर्माता लोग कहते हैं कि उत्पादन क्षमता में यह असाधारण वृद्धि व्यक्तिगत कामकाजी के अथक परिश्रम और टेक्निकल सुधारों के कारण पैदा हुई है ।
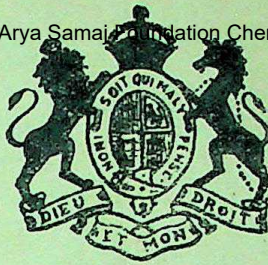
BRITISH INFORMATION SERVICES

FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

April 15 to April 28, 1951.

HINDI
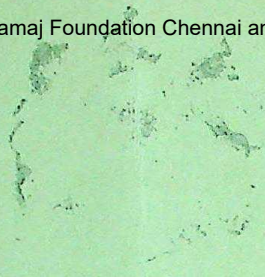
ब्रिटेन में
महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है?

लेखक,
ब्रिटिश महोत्सव (फेस्टिवल
आफ़ ब्रिटेन) के महानिर्देशक
जेराल्ड बैरी

कुछ समय पहले मेरे एक भारतीय मित्र ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया था कि संसार की इतनी गम्भीर परिस्थितियों में ब्रिटेनवासी उत्सव की तैयारियों में कैसे जुट सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में मुझे ब्रिटिश महोत्सव के मूल प्रयोजन पर प्रकाश डालना पड़ेगा। और यह अच्छी ही बात है क्योंकि मेरे विचार से महोत्सव का उद्देश्य सब को पूरी तरह नहीं मालूम। यह सोचना गलत है कि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण महोत्सव का आयोजन 'अवसर बिन फ़ीकी लगे बिन अवसर की बात' का उदाहरण है।

हां यदि युद्ध छिड़ गया तो दूसरी बात है। पर जबतक ऐसा नहीं होता यह न सोचना चाहिये कि हमें या तो बचाव की तैयारियाँ करनी हैं या उत्सव की पर दोनों की नहीं।

> 'यदि मुझे महोत्सव के मूल उद्देश्यों को एक वाक्य में प्रकट करना पड़े तो मैं कहूंगा : संसार को यह स्मरण दिलाना कि ब्रिटेन जहां था वहीं है। महोत्सव की मुख्य बात है ब्रिटेन की शक्ति का प्रदर्शन और पश्चिमी राष्ट्रों के संयुक्त प्रयास में सम्पूर्ण भाग लेने के उसके संकल्प का, जनतन्त्र में हमारी सजीव श्रद्धा का प्रमाण और स्वतन्त्र नर नारियों की हैसियत से सम्पन्न बने रहने के हमारे दृढ़ निश्चय का।'

... यदि मुझे

यदि मुझे महोत्सव के मूल उद्देश्य को एक वाक्य में प्रकट करना पड़े तो मैं कहूंगा : संसार को यह स्मरण दिलाना कि ब्रिटेन जहां था वहीं है । महोत्सव की मु बात है ब्रिटेन की शक्ति का प्रदर्शन और पश्चिमी राष्ट्रों संयुक्त प्रयास में सम्पूर्ण भाग के उसके संकल्प का, जनतन्त्र में हमारी सजीव श्रद्धा का प्रमाण और स्वतन्त्र नर नारि की हैसियत से सम्पन्न बने रहने के हमारे दृढ निश्चय का । मैं यह कहने का स करता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में ब्रिटेन का यह प्रयास केवल उचित ही नहीं आवश भी है।

इसलिए ब्रिटेनवासी मई से सितम्बर तक सारे संसार का आतिथ्य सत्कार जा रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं जिसके अन्त लन्दन के मध्य में एक विशाल प्रदर्शिनी होगी और अन्यत्र अन्य कई प्रदर्शिनियां , वि शहरों में कलाओं के कई उत्सव होंगे और नगरों तथा ग्रामों में कई उल्लेखनीय घटनाएं विधियों से ब्रिटेन संसार में अपने पद को फिर आंकना चाहता है और सभ्यता की प्र में अपनी पुरानी और नई देन से दुनिया को परिचित करना चाहता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि महोत्सव में हंसीखेल का हिस्सा भी होगा। ठीक है क्योंकि दस से अधिक वर्षों से हम अपने को कठिन अनुशासन में बांधे हुए हैं। रा में नई उत्साह उमंग भरने के लिये और उत्पादन की संख्याएं बढाने के लिये ऐसा का अच्छा ही है । इसलिये हम ऐसी चीज़ों — रोशनी , आतिशबाज़ी , इत्यादि— का ध्यान रखेंगे जिनके बिना ऐसे प्रयास अत्यधिक गम्भीर होने के कारण असफल हो स हैं । गर्मियों में हमारी सब संगीतशालाएं , हमारे नाट्यगृह और कलाशालाएं अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होंगी। कई ऊंचे श्रेणी के खेल कूदों का कार्यक्रम भी बनाया गया

किन्तु हमारा मुख्य सम्बन्ध तो शांति की कलाओं से , राष्ट्रीय जीवन राष्ट्रीय विचारशैली के रचनात्मक अंग से है। ऐसे समय ज़रा पीछे की ओर दृष्टि डाल उन विचारों का स्मरण करना जो हमें जीवन की प्रेरणा देते हैं और जिनके बल पर हम स्वतन्त्र हैं अनुचित कौन कह सकता है ? अन्त में मैं यही कहूंगा कि (उन लोगों से समझते हैं कि महोत्सव पर खर्च किया जाने वाला धन शस्त्रास्त्रों पर खर्च किया जाता अच्छा होता) यदि हमें सभ्यता के वर्तमान संकट का सफलता के साथ सामना क है तो अपनी योग्यता में विश्वास और अपने भविष्य में विश्वास नितान्त आवश्यक है ।

F.H.208

मोटर चालकों की महिमा

तीस दिनों में संसार की परिक्रमा

एक छोटी ब्रिटिश मोटरकार को लेकर मोटरचालकों का एक समूह तीस दिनों में संसार का भ्रमण समाप्त करने के लिए लन्दन से पहली जून को रवाना होने वाला है। इस यात्रा के अन्तर्गत बम्बई से कलकत्ता तक सड़क द्वारा सफर भी सम्मिलित है। यात्रा यथासम्भव सड़क द्वारा की जाएगी और एक वायुयान में, जो विशेषतया इसी कार्य के लिए बनाया गया है, यह मोटर समुद्रों के ऊपर भी उड़ेगी।

यात्रा का मार्ग इस प्रकार होगा : फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, लेबानान, सीरिया, ट्रान्सजार्डन, ईराक, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनडा और तब इंग्लैंड वापस।

ईराक को पार करने के बाद मोटर बसरा से बम्बई (जहां वह जून ६ को पहुंचने वाली है) तक वायुयान में उड़कर आएगी। दो मोटर चालक इसे बम्बई से नासिक तक ले आएंगे और तब कानपुर होते हुए इलाहाबाद। तब अन्य चालक जो बम्बई से इलाहाबाद वायुयान द्वारा आएंगे मोटर को बनारस होते हुए कलकत्ता ले जाएंगे। कलकत्ते के बाद मोटर फिर वायुयान में बैठाई जाएगी और बैंगकाक, ग्वाम, वेक आइलैंड और होनोलूलू होते हुए लास एन्जेल्स पहुंचेगी। तब यह ३,८०० मीलों की दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण करेगी और मान्ट्रियल तक जाएगी।

मोटरचालकों के इस समूह में सब अनुभवी लोग हैं। इस भ्रमण कार्यक्रम की बात "आस्टिन मोटर कम्पनी" के प्रबन्धक निर्देशक श्री० लार्ड ने लन्दन के एक प्रीतभोज में प्रकट की थी। उनके अनुसार, यह दिखाना कि बड़ी मोटरों की भांति छोटी मोटरें भी ऐसे कामों के योग्य हैं, इस प्रयास का प्रधान उद्देश्य है।

H.S.11

कलकत्ते तक जेट वायुयान
— की उड़ान

अभ्यास के तौर पर

डी हैविलैंड कम्पनी दव्ारा तैयार किए गए दूसरे 'कामेट' जेट वायुयान ब्रिटेन और कलकत्ता के मध्य अभ्यास और परीक्षा के लिए उड़ान की जाने वाली है वायुयान कुछ समय हुए 'ब्रिटिश ओवर्सीज़ एयरवेज़ कार्पोरेशन' : बी०ओ०ए०सी० सौंपा गया था। अपने वायुमार्गों पर 'कामेट' से नियमित काम लेने के पूर्व उसकी आज़माइशी उड़ान बी०ओ०ए०सी० प्रथम आवश्यकता समझती है। कलकत्ता तक 'कामे की उड़ान के बाद तबतक के अनुभव के अनुसार अन्य उड़ानमार्गों के विषय में निर्णय कि जाएगा। आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त या नए वर्ष के प्रारम्भ तक 'कामेट वायुयान बी०ओ०ए०सी० की नियमित व्यावसायिक सर्विस का अंग बन सकेगा ।

N.E.H.42/51

मुर्दे की माया

पुलिस को 'भेद' बताया

हंगेरी का एक हाल सुनिए । कुछ समय हुए एक मृत शरीर ज़मीन को खोदकर से निकाला गया था। मास्को से आज्ञा मिली कि इसे चंगेज़ खां का मृत शरीर प्रमाणि करने का पूरा प्रयत्न किया जाए। कुछ समय बाद हंगेरी की प्राचीन इतिहास संस्था मास्को को बताया कि इसमें प्रमाणित करने की क्या बात है, यह तो चंगेज़ खां का मृत शरीर है ही ।

'यह कैसे मालूम हुआ', मास्को ने पूछा । 'बहुत आसानी से । हमने मा सुरक्षा पुलिस को सौंप दिया और मृत शरीर ने भेद खोल दिया ।'

H.S.12

भारतीय विद्यार्थियों के लिए छुट्टियों का कार्यक्रम

८० भारतीय विद्यार्थियों के एक समूह ने, जिनमें से अधिकांश लन्दन में अध्ययन कर रहे हैं और कुछ प्रान्तीय नगरों के हैं, भारत भवन के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित चार दिनों का एक अवकाश कार्यक्रम पूरा किया है। यह कार्यक्रम, जिसका स्थान लन्दन था, पिछले वर्ष की ईस्टर छुट्टियों में आयोजित कार्यक्रम की भांति प्रमुख व्यक्तियों द्वारा भाषण इत्यादि को मिलाकर बना था।

"यह सब किस लिए है" यह पहले भाषण का विषय था और भाषणकर्ता थे "इम्पीरियल कालेज आफ़ सायंस एन्ड टेक्नालाजी", के प्रोफ़ेसर एच० लेवी। इन्होंने इस भाषण में जीवन के प्रति साधारण दृष्टिकोण और विशिष्टता प्राप्त शिक्षा में सम्बन्ध पर प्रकाश डाला था।

अन्य प्रमुख व्यक्तियों के भाषणों के विषय थे : "वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास", "जनसंख्या की समस्या और सामाजिक परिवर्तन" और "विश्वविद्यालय स्नातकों के अधिकार और दायित्व।"

H.S.13/51

मलाया में लोगों को फिर से बसाना

जोहोर का लोगों को फिर से बसाने का कार्य, जिससे ७० हज़ार लोग नए गांवों में बस सकेंगे, पहली मई को समाप्त हो जाएगा। ३७ हज़ार लोग तो २४ नई बस्तियों में बस चुके हैं। शेष के विषय में कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है।

F.H.189

पश्चिमी अफ्रीका के संवैधानिक सुधार

नाइजीरिया के निर्वाचन इस साल

(ट्रेवर ब्लोर)

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण ब्रिटि[श] पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रमंडलके अन्दर स्व शासन की ओर तीव्रता से प्रगति कर रहा है, गोल्ड कोस्ट द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ।

इस संवैधानिक प्रगति के प्रसंग में दो आदेशों का उल्लेख करना आवश्यक है । आदेश ने विभिन्न जातियों वाले और उपनिवेशों में सबसे बड़े, अर्थात् नाइजीरि[या] के राज्यपाल को विधान सभा के तीनों सदनों के लिये निर्वाचनों का प्रबन्ध करने[का] अधिकार दिया है ।

दो वर्षों से अधिक समय तक सारे नाइजीरिया में इस बात पर विचार-विनि[मय] होता रहा है कि इस देश के लिये सरकार की भावी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये । इस विस्तृत सार्वजनिक वाद-विवाद, जिसमें सभी भागों के प्रतिनिधि सम्मिलित हु[ए] थे, के फलस्वरूप एक रचनात्मक संवैधानिक योजना सामने आई है।

नाइजीरिया के लिये नवीन संविधान तीन महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है
संयुक्त नाइजी

१. संयुक्त नाइजीरिया में अधिक विकसित प्रादेशिक स्वायत्तता ।

२. प्रदेशों और केन्द्र में विस्तृत अधिकारयुक्त विशाल और अधिक उत्तरदायी विधान-मंडलें ।

३. मन्त्रिमंडल प्रणाली की स्थापना के साथ नाइजीरियनों को सरकारी नीति की रचना और कार्यपालिका सरकार के कार्य को निर्देश देने में पूरा हिस्सा मिले ।

आशा की जाती है कि नाइजीरिया के चुनाव लगभग इस वर्ष के मध्य में प्रारम्भ हो जाएंगे और नये प्रादेशिक सदनों तथा नये प्रतिनिधि सदन की प्रथम बैठकें १९५१ के अन्त से पूर्व अथवा १९५२ के प्रारम्भ में हो सकेंगी, क्योंकि चुनाव कम से कम पांच महीनों में समाप्त होंगे ।

यद्यपि नाइजीरिया और गोल्ड कोस्ट के संविधानों में कई बातों का अन्तर रहेगा किन्तु यों दोनों राज्यक्षेत्रों की संवैधानिक प्रगति का स्तर लगभग एक सा होगा।

सिएरा लिओन

सिएरा लिओन के लिये प्रस्तावित संविधान इस उपनिवेश अवस्था के कारण उतना उन्नत नहीं है जैसाकि नाइजीरिया का । वर्तमान संविधान के अन्तर्गत , जो १९२४ से लागू है , सिएरा लिओन की विधान परिषद और कार्यपालिका परिषद में सरकारी बहुमत रहता रहा है किन्तु नया संविधान एक ऐसी विधान परिषद प्रदान करता है जिसमें निर्वाचित गैर सरकारी लोगों का बड़ा बहुमत होगा। नई कार्यपालिका परिषद में चार पदेन सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद के कम से कम चार अन्य निर्वाचित सदस्य रहेंगे ।

फ्रीटाउन और उपनिवेश के अन्य क्षेत्रों में विधान मंडल के लिये चुनाव सम्पत्ति अर्हता के साथ वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे ।

सबसे अधिक रोचक उपबन्ध वह है जो उपनिवेश के "प्रोटेक्टोरेट" (संरक्षण प्राप्त प्रदेश) विभाग में परम्परागत नेतृत्व के सर्वोत्तम अंगों को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। जनजाति के अधिकारियों और सरदारों के अधिकार ज़िला परिषदों पर केन्द्रित होंगे। पारस्परिक लाभ के लिये आधुनिक और परम्परागत का यह सम्मिश्रण ब्रिटिश उपनिवेशों में हो रही संवैधानिक प्रगति का मूल्यवान सिद्धान्त है। उत्तरी रोडेशिया की विधान परिषद के चार सदस्यों का एक शिष्टमंडल इस महीने लन्दन की यात्रा करने वाला है। यों अफ्रीका में और भी संवैधानिक प्रगति की आशा की जा सकती है। ये लोग उपनिवेशों के राज्यमन्त्री , श्री० जेम्स ग्रिफिथ्स , से इस उपनिवेश से सम्बन्धित संवैधानिक मामलों के बारे में बातचीत करेंगे ।

H/L.P.S.183

ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति संकलन :

श्री० बेवान का पदत्याग

बजट नीति पर असहमति

श्री० एन्युरन बेवान के पदत्याग के विषय पर "टाइम्स" ने एक सम्पादकीय में लि है कि श्रम दल का वह समूह , जिसकी ओर श्री० बेवान समर्थन के लिये देखेंगे, कुछ मही से सरकार की सामाजिक नीतियों पर पुन: शस्त्रीकरण कार्यक्रम के प्रभाव के विषय में चि रहा है ।

शायद इस समूह के सदस्य श्री० बेवान की भांति अपनी अधिकांश आलोचना ब पर आधारित करें पर उनके असन्तोष का मुख्य कारण पुन: शस्त्रीकरण कार्यक्रम का स्तर और देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में उनका मुख्य अंशदान होगा यह प्रस्ताव कि सामरिक खर्च में तुरत कमी की जाए ।

आगे चलकर पत्र कहता है कि पुन: शस्त्रीकरण कार्यक्रम ने न केवल सामाजिक सेवा का विस्तार असम्भव बना दिया है पर इसका अर्थ यह भी है कि वर्तमान सामाजिक से में शायद कमी करनी पड़े । यों इस परिस्थिति ने श्रम दल के सदस्यों के सामने एक ज समस्या खड़ी कर दी है ।

मुख्य बात यह है कि पुन: शस्त्रीकरण कार्यक्रम आवश्यक है और यदि श्री० बेवा उसके आकार प्रकार के औचित्य को मानने से इन्कार करते हैं तो उनके विरोध और पदत्याग का समय उसी समय था जब मन्त्रिमंडल ने , जिसके वे सदस्य थे उसपर विचार विमर्श कर उसे स्वीकार किया था । पुन: शस्त्रीकरण कार्यक्रम की मांगों का ध्या देते हुए सब लोगों द्वारा बलिदान की आवश्यकता अनिवार्य थी । अन्त में पत्र लिख है कि श्री० गेतस्केल के प्रस्तावों का उद्देश्य सबके उपभोग में कमी करना है और यदि वे श्री० बेवान की उस सलाह को मानते जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया है और केवल

... धनियों पर

धनियों पर अधिक बोझ लादते तो असैनिक मांगों को कम करने का सवाल तब भी वैसे ही बना रहता ।

"डेली हेरल्ड" ने लिखा है : हमारी राय में बजट पर श्री० बेवान का आक्रमण बिल्कुल अनुचित है । पुन:शस्त्रीकरण, देश के परिश्रम के बल पर पुन:शस्त्रीकरण, बजट का आधार है । पत्र ने आगे लिखा है : वित्त मन्त्री ने व्यय का मुख्य बोझ उसे सम्हालने की योग्यता रखने वालों पर डाला है । यह कहना कि सरकार ने किसी सामाजिक सेवा का सर्वनाश प्रारम्भ कर दिया है बिल्कुल निरर्थक है । यद्यपि श्री० बेवान के पदत्याग से शोक होगा पर हमें निश्चय है कि श्रम आन्दोलन की विचारधारा मन्त्रिमंडल की नीति को विशाल बहुमत्त से अपना समर्थन देगी ।

"न्यूज़ क्रानिकल" ने यह कहने के बाद कि श्री० बेवान के पदत्याग से आम निर्वाचन अधिक पास आ गए हैं, लिखा है कि श्रम दल में श्री० बेवान की प्रतिष्ठा ऊंची है : देखें उन्हें कैसे साथी मिलते हैं । अन्त में पत्र लिखता है कि श्रम दल के लिये यह सच्चा संकट है । इस विषय में किसी प्रकार की गलती न हो ।

H/L.P.S.188

ब्रिटिश मन्त्रियों का पदत्याग

सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार

कच्ची सामग्रियों की प्राप्ति के बारे में श्री० विल्सन की निराशापूर्ण भविष्य को अस्वीकार करते हुये और वाशिंगटन में इस विषय पर हो रही बातचीत का उल्लेख करने के बाद "डेली हेरल्ड" ने पूछा है : यह क्यों समझा जाए कि पश्चिमी को बलशाली बनाने में इतना अधिक भाग लेने के बाद अमेरिका अपने साथियों के प्रति कार्यक्रमों में रूकावट और उनकी अर्थ व्यवस्थाओं का छिन्न भिन्न होना उदासीनता से देखेगा। अन्त में पत्र लिखता है कि यदि हम कच्ची सामग्रियां काफी मात्रा में नहीं प्राप्त करते तो न केवल हमारा शस्त्रास्त्र कार्यक्रम किन्तु असैनिक उत्पत्ति भी हानि उठाएगी। तब राष्ट्र को अधिक निर्धन बनना पड़ेगा, अधिक सम्पन्न नहीं।

"डेली ग्राफिक" ने लिखा है : श्री० विल्सन के विचार न केवल प्रतिरक्षा कार्यक्रम के बारे में बदल गये हैं पर अमेरिका के बारे में भी। "दुर्लभ सामग्रियां अमेरिका के नियन्त्रण में हैं और इनके बटवारे के विषय में वाशिंगटन में बातचीत हो रही है। १६ अप्रैल को श्री० विल्सन ने विश्वास प्रकट किया था कि निर्णय लेने वाले उत्तरदायित्व की भावना दिखाएंगे। "डेली ग्राफिक" तब पूछता है : एक सप्ताह पहले की तुलना में आज उत्तरदायित्व की कम भावना कौन दिखा रहा है, अमेरिका या विल्सन? तब पत्र कहता है कि श्री० विल्सन का भाषण और बेवान की कटु आलोचना उन लोगों को जिन्होंने हमारे प्रति इतनी अधिक उदारता दिखाई है फिर हमारे सहायता के लिये प्रोत्साहित नहीं करेगी। अन्त में पत्र लिखता है कि श्री० विल्सन के अनुसार विश्व की शांति में सामाजिक सेवाओं का अंशदान प्रतिरक्षा कार्यक्रम के भाग की तुलना में कम

...वास्तविक नहीं

वास्तविक नहीं है । नकली दान्तों और चश्मों के लिये थोड़े से पैसे लेने के कारण ही सामाजिक सेवाएं समाप्त न हो जायेंगी । किन्तु यदि हम आक्रमण का डटकर सामना करने योग्य न बनें तो हमें सामाजिक सेवाओं के साथ साथ उन सब चीज़ों से बिदा लेनी होगी जिन्हें हम बहुमूल्य समझते हैं ।

"टाइम्स" ने लिखा है कि इस समय ऐसा मालूम होता है कि श्री० एटली और श्री० मारिसन संसद के बाहर और भीतर अपने अनुयायियों के व्यापक समर्थन पर भरोसा रख सकते हैं । पत्र समझता है कि अस्पताल से वापस आने के बाद अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अपने शांत और दृढ़ ढंग से हाथों में फिर लेना प्रधान मन्त्री के स्वभाव के अनुरूप है । निश्चय ही प्रधान मन्त्री को यह मालूम है कि उनकी सरकार अब थोड़े ही दिनों के लिये है । निश्चय ही उनको बड़े बूढ़े राजनीतिज्ञों की अनुपस्थिति का अनुभव होता होगा । पर, पत्र कहता है , जबतक श्री० एटली पर कार्यभार रहेगा तबतक वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कसर नहीं रक्खेंगे ।

फ़ारस और फ़ारसियों को लाभ

ब्रिटिश तेल हितों का बड़ा भाग

लेखक,
औद्योगिक पत्रकार फ़िलिस
डेवीज़

आंग्ल ईरानी तेल कम्पनी की फ़ारस स्थित सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के फ़
फ़ारसी मजलिस का मत उन लाभों का ध्यान दिलाता है जो इस कम्पनी ने फ़ारस
वहां के लोगों को पहुंचाये हैं ।

लगभग पचास वर्ष पूर्व ब्रिटिश वैज्ञानिक अन्वेषण और उपक्रमण ने दक्षिण पश्चि
फ़ारस में अवस्थित एक बिल्कुल वीरान परती भूमि में विश्व व्यापक महत्व की सक्रिय
उत्पन्न कर दी थी । अबादान में आज संसार के सबसे विशाल तेल शोधक यन्त्र
लगे हुये हैं जिनकी क्षमता २,५०,००,००० टन वार्षिक है। इसके इर्द गिर्द एक सुव्यवस्थि
आधुनिक नगर खड़ा हो गया है जहां आस पास की देहातों और समुदायों को मिला
१,७३,००० से अधिक लोग रहते हैं ।

फारस के विकास से सम्बन्धित कुछेक उल्लेखनीय बातें ये हैं : फ़ारस में आंग
ईरानी तेल कम्पनी के कुलजमा ७६,५०० कामकाजियों में केवल ४५०० ग़ैर फारसी हैं जि
पारिश्रमिक के रूप में १५,००,००० पौंड (२ करोड़ रूपये) मासिक दिये जाते हैं ।
प्रौढ़ साधारण कामकाजी की प्रारम्भिक साप्ताहिक मज़दूरी औसतन २ पौंड ४ शिलिं
(२६-५-४ रूपये) और अबादान के तेल शोधक कारखाने में प्लान्ट पर काम करने

....वाले सा

वाले साधारण कामकाजी की साप्ताहिक मजदूरी औसतन ४ पौंड (५३-५-४ रुपये) बैठती है। कामकाजी छुट्टियों तथा बीमारी अवकाश का पूरा वेतन और निर्धारित अवधि से अधिक के काम के लिये ३५ प्रतिशत अतिरिक्त वेतन भी प्राप्त करता है। इसके अलावा कामकाजी अपनी नियुक्ति की अवधि के अनुसार कम्पनी द्वारा बनाये गये विशाल निवासस्थान अहातों में मामूली किराये पर रहने के मकान भी प्राप्त कर सकते हैं।

सामाजिक सुविधाएं

१९३९ तक आंग्ल ईरानी कम्पनी ने कामकाजियों के लिये मकानों, दुकानों, स्कूलों, चिकित्सालयों, क्लबों, तैराई तालाबों, टेक्निकल विद्यालयों, सिनेमाओं और मनोरंजन केन्द्रों की व्यवस्था पर लाखों पौंड खर्च किये थे। युद्धकालीन बाधाओं के बावजूद भी १९३९ से १९४५ तक ४४,००,००० पौंड (५.८६ करोड़ रुपये) निवासस्थानों के निर्माण पर खर्च हुए थे। १९४९ में २६०० मकान बनाये गये और १९५० में दुकानों तथा सहायक भवनों सहित और भी २८०० मकानों को पूर्ण किया गया था जिनपर द्वितीय युद्ध के बाद कुलजमा एक करोड़ पौंड से अधिक की लागत बैठ चुकी है। कम्पनी ने इन स्कीमों में हरके सामाजिक तथा शिक्षात्मक सुविधा, आधुनिक सफाई, बिजली और पानी इत्यादि की पूरी व्यवस्था की थी।

केवल अबादान में ही २१ स्कूल और ६ किंडर गार्टन हैं जिनमें १२००० से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। आंग्ल ईरानी कम्पनी द्वारा बनाये गये ये तथा सात अन्य स्कूल फ़ारस के शिक्षा मन्त्रालय को सौंप दिये गये हैं। फराहाबाद प्राइमरी स्कूल नामक सबसे नया विद्यालय १९४९ में पूरा किया गया था। इसपर औसतन ५४,१०० पौंड (७.२१ लाख रुपये) की लागत आई थी और यहां लगभग एक हज़ार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

इस स्कूल में रात्रि के समय अशिक्षित कामकाजियों को पढ़ाया जाता है। फ़ारस सरकार द्वारा संचालित इन रात्रि कक्षाओं के लिये कई सौ अध्यापकों का वेतन कम्पनी द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अबादान में एक टेक्निकल इंस्टिट्यूट (शिल्पी विद्यालय) का निर्माण किया गया है। पिछले शिक्षाकाल में फ़ारस के सभी भागों से ११६१ छात्र भर्ती किये गये थे।

... १९३९ में

१९३९ में कम्पनी ने तेहरान विश्वविद्यालय को एक प्रयोगशाला का सारा ... भेंट किया था। युद्ध के बाद से इसने उस विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग की प्रयोगशालाओं के लिये सामान की व्यवस्था करने का काम भी अपने हाथों लिया ... विभाग अत्यन्त कुशल इंजीनियरों की देखरेख में चलता है जो बिल्कुल पूर्ण होने ... तथा अमेरिका के ऐसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों से तुलना के योग्य होगा। यह कम्पनी ... लोगों को ब्रिटेन में विशेष विषयों की शिक्षा और शिल्पी प्रशिक्षण भी दिलवाती ... इंग्लैंड में नब्बे लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं और अबतक सब मिलकर २२९ व्यक्ति आं... कम्पनी के खर्च पर ब्रिटेन भेजे जा चुके हैं।

चिकित्सा सेवाएं

फारस की चिकित्सा सेवाओं के लिये अंशदान विस्तृत रहे हैं। खूजिस्तान ... में, जहां अबादान और तेल क्षेत्र अवस्थित हैं, आंग्ल ईरानी कम्पनी के कामका... और उनके आश्रितों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं में एक हजार से अधिक लोग हैं। अबाद... कम्पनी के दो अस्पताल हैं जिनमें से एकमें आम इलाज के लिये ३५० और दूसरे में ... मामलों के लिये १५० चारपाइयों का प्रबन्ध रहता है। मसजिदे सुलेमान और आग... के तेल क्षेत्रों में दोनों तरह के रोगियों के लिये लगभग दो सौ चारपाइयां रहती ... स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सम्बन्धित एक विशाल कार्यक्रम, जिसपर लगभग ... ००० पौंड की लागत बैठेगी, प्रगति कर रहा है। आंग्ल ईरानी तेल कम्पनी अब... के लिये एक म्यूनिसिपल अस्पताल की लागत का पचास प्रतिशत भाग अदा करेगी ... लगभग १,५०,००० पौंड (२० लाख रुपये) के बराबर बैठेगा, और वह तेहरान के ... एक क्षयरोग चिकित्सालय में लगभग १,००,००० पौंड (१३.३३ लाख रुपये) की लाग... एक विशेष विभाग भी तैयार कर रही है। इसके अलावा कम्पनी के सार्वजनिक स्वा... संगठन में १४०० से अधिक लोग नियुक्त हैं जिसपर मूलगत खर्च को छोड़कर, ९,००,... पौंड (१.२ करोड़ रुपये) वार्षिक व्यय किये जाते हैं।

फारस में परिचारिका कार्य (नर्सिंग) का स्तर ऊंचा करने में सहायता ... के लिये कम्पनी ने अबादान में नर्सिंग का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति नियुक्त किये ... जो हर वर्ष में १५ नर्सों को प्रशिक्षित करते हैं। यह कम्पनी तेहरान में स्थापित एक अस्पताल को भी काफी सहायता देती है।

कम्पनी के कामकाजियों के लिये संचालित सामाजिक तथा कल्याण सेवाएं ...

... दूर के

दूर के तेल क्षेत्रों तक पहुंचती है। संचालन के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में सिनेमा खुले हुए हैं और कुलजमा २३ सिनेमाओं में हर सप्ताह आधुनिक फिल्मों तथा सामयिक न्यूज़रीलों के नये प्रोग्राम चला करते हैं। अबादान और तेलक्षेत्रों में जहां छः महीनों तक सख्त गर्मी पड़ती है, तैराई एक अत्यन्त लोकप्रिय मनोरंजन है। अकेले अबादान में कम्पनी ने छः तैराई तालाब बनाये हैं और सबसे पुराने तेलक्षेत्र, मसजिदे सुलेमान में भी तीन तालाब हैं। सर्दियों में कम्पनी के खेल कूद मैदानों में लगभग हर तरह का खेल खेला जाता है लेकिन फुटबाल सबसे अधिक लोकप्रिय है। कम्पनी की इंटर डिपार्टमेन्टल फुटबाल लीग की २८ टीमें हैं। अबादान में १९ फुटबाल मैदान, ११ हाकी मैदान, ३६ टेनिस कोर्ट, दो क्रिकेट मैदान, ८ वालीबाल कोर्ट, १२ स्क्वैश रैकेट कोर्ट और कसरती खेलों के लिये तीन मैदान बने हुये हैं। अनेकों क्लबें फारसी और गैर फारसी कामकाजियों के लिये सभा सम्मेलन स्थान प्रदान करते हैं जहां पर नाच गान, वाद विवाद, शौकिया नाटक जैसी चीज़ें चला करती हैं।

ये तो हैं आंग्ल ईरानी कम्पनी के कामकाजियों को उपलब्ध प्रत्यक्ष लाभ। इसके अतिरिक्त फारसको कम्पनी की सक्रियता से और भी लाभ हुये हैं, उदाहरणार्थ, रायल्टियों और करों के ज़रिये। इस रूप में फारस की सरकार ने कम्पनी से अबतक ७ करोड़ पौंडों से अधिक प्राप्त किया है।

N.E.H.43

केन्द्रीय चीन में भ्रष्टाचार

धन का ग़बन

अकुशलता और भ्रष्टाचार से अधिकांश राज्य खज़ानों और गोदामों के खाते असंतुलित और खर्चे क्रम और नियमहीन हो गये हैं —— यह बात यांगत्से डेली (हांको) ने अपने ८ मार्च के अंक में केन्द्रीय चीन के सार्वजनिक खातों की जांच से सम्ब[illegible] एक रिपोर्ट में लिखी थी।

पत्र ने आगे चलकर लिखा था कि केन्द्रीय चीन के छः प्रान्त राज्य खज़ानों औ[र] गोदामों के खातों की जांच-पड़ताल कर रहे थे। प्रारम्भिक निरीक्षणों से यह पता चला है कि अधिकांश राजस्व कार्यालयों और राज्य कोषों द्वारा अंकित संख्याएं संतु[लित] नहीं थीं, राजस्व कार्यालय खज़ानों की आशा से कम रकम दिखा रहे थे। कई चुंगी विभाग ऐसे भी मिले जो रसीदें जारी किये बिना ही रकमें उगाह चुके हैं ताकि धन [का] ग़बन करने में आसानी रहे। कई काउन्टिओं में भ्रष्टाचार और ग़बन साथ-साथ फल[ता] गया है। हूनान प्रान्त के दि काउन्टी बैंक आफ़ यंग मिंग के बारे में यह मालूम हुआ [कि] उसने लोगों से सरकारी दर से नीची कीमत पर चांदी खरीद ली तथा ग़ैरकानूनी नफ़े को चांदी की सलाइयों (जो चीन में भोजन करने के लिये प्रयुक्त की जाती हैं) का रूप दिया। मैनेजर को दो जोड़े तथा प्रत्येक क्लर्क को एक दी गई। उसी प्रान्त की चैलिंग काउन्टी का राजस्व कार्यालय सामूहिक ग़बन का अपराधी पाया गया था।

चावल गोदामों के खाते इतने उलझे हुए थे कि यह समझना मुश्किल था कि [चावल] केन्द्र के लिये है या स्थानीय सरकार के लिये। इसके अतिरिक्त बहुत से गोदाम वाले यह भी ठीक से नहीं जानते थे कि उन्होंने कितना माल प्राप्त किया और कितना बा[हर] भेजा था। लेकिन सबसे गम्भीर बात यह रही कि कई गोदामों में लेन-देन की कोई लिखत ही नहीं थी। पत्र ने लिखा था कि ऐसे मामलों में जांच-पड़ताल स्पष्टरूप से असम्भव थी। क्यांगसी में जहां हिसाब-किताब उपलब्ध था तो अन्धाधुंध खर्च और धन [का] ग़बन पाया गया था।

F.H.182

कोलम्बो योजना की प्रगति का अवलोकन

बाहरी सहायता की सम्भावनाओं का विश्लेषण

जान किंग्सले,
आर्थिक और वित्तीय विषयों के
सुपरिचित टीकाकार

यद्यपि यों तो कोलम्बो योजना जुलाई तक प्रारम्भ नहीं होती , पर योजना के महत्वपूर्ण अंग अभी से कार्यान्वित हो रहे हैं और उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों की तैयारी हो रही है । बहुत कुछ काम जो किया जा चुका है और जिसके विषय में कार्यक्रम बनाया जा चुका है सरलता से स्पष्ट नहीं होता । सचमुच योजना का बहुत कुछ अंश अभी बातचीत के अध्याय में है । पर, जैसाकि पिछली फरवरी में हुए कोलम्बो सम्मेलन ने दिखाया था, सम्मेलन में उपस्थित चौदह शिष्टमंडलों के पारस्परिक वाद विवाद ने भावी व्यावहारिक प्रयासों के लिये एक अच्छा आधार प्रशस्त कर दिया है ।

यह कहना कि फरवरी के सम्मेलन से बहुत कम सच्चा लाभ हुआ था उस समय तक की प्रगति की अनभिज्ञता प्रदर्शित करना है । अबतक हुई प्रगति पर दृष्टि डालने से चार मुख्य बातें स्पष्ट हो जातीं हैं :

१. अमेरिका अब परामर्श समिति का सम्पूर्ण सदस्य है और "अन्तर्राष्ट्रीय बैंक" ने उसके कार्य से घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित कर लिया है ।
२. १ अरब और ८० करोड़ पौंडों की योजनाओं को यथार्थ बनाने के यत्न किए जा रहे हैं ।

... पिछले कोलम्बो

३. पिछले कोलम्बो सम्मेलन ने योजना के क्षेत्र के बाहर और अन्दर के प्रतिनिधिमंडलों को आपस में मिलाया था, विशेषतया अमेरिका को, और मतों के बहुत ही मुक्त और स्पष्ट आदान प्रदान के अवसर उन्हें मिले थे।

४. योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक देशों के लिये कोलम्बो जानकारी का बहुत अच्छा क्षेत्र सिद्ध हुआ था।

क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि १ अरब और ८० करोड़ पौंडों के खर्चे के आधे से अधिक भाग को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर प्राप्त करना होगा इसलिये स्पष्ट है कि वित्त का प्रश्न मुख्य प्रश्न है। अबतक उन एक अरब पौंडों, जिन्हें बाहर से प्राप्त करना है, से सम्बन्धित सब वायदे राष्ट्रमंडलीय क्षेत्रों से आये हैं।

अनुकूल और प्रतिकूल अंग

इस सूची में सबसे आगे ब्रिटेन का नाम है। प्रधानतया स्टर्लिंग पावनों में से छूट के रूप में ब्रिटेन छः वर्षों में तीस करोड़ पौंड देगा और इनमें से भारत को सबसे बड़ा भाग मिलेगा। आस्ट्रेलिया ने कम से कम २ करोड़ और ५० लाख पौंडों, जिनमें से ७० लाख पहले वर्ष में प्राप्त होंगे, का वायदा किया है। कैनडा पहले वर्ष में २ करोड़ और ५० लाख डालर देगा और न्यूज़ीलैंड ने योजना के पहले तीन वर्षों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दस लाख पौंड का वायदा किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि, प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर, अन्तर घटकर लगभग ६५करोड़ पौंड रह जाता है।

'प्राप्त करने वाले' देशों द्वारा उनके प्रारम्भिक अनुमानों से अधिक मात्रा में आत्मसहायता कर सकना कोलम्बो योजना की सफलता का एक अन्य उल्लेखनीय सूचक है। यद्यपि इसका मूल्य निश्चित रूप में अभी नहीं आंका जा सकता पर अत्यन्त लाभकारी वह अवश्य होगा। इस अनुकूल परिस्थिति का कारण वस्तुओं के विश्व मूल्यों में निरन्तर वृद्धि है। इस क्षेत्र के कई भाग आज वस्तुओं के निर्यात द्वारा पहले से अधिक कमा रहे हैं। उदाहरणार्थ, रबड़ के मूल्यों में वृद्धि का अर्थ यह है कि लंका को योजना के पहले, और शायद दूसरे भी, वर्ष में बाहरी वित्तीय सहायता की आवश्यकता न होगी।

कोलम्बो में जनित सद्भावना इस योजना के अनुकूल अंगों में एक है। यदि योजना को सम्पूर्णतया सफल बनना है तो अमेरिका से और विश्व बैंक से सहायता अवश्य मिलनी

... चाहिये। पूरे

चाहिये। पूरे सदस्य के रूप में अमेरिका की उपस्थिति निस्सन्देह एक अच्छा लक्षण है। विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि ने सम्मेलन के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। बाहरी सहायता को बांटने की कार्य पद्धति पर वाद विवाद, यह सूचना कि राष्ट्रमंडलीय देश, विशेषतया ब्रिटेन, योजना को सम्पूर्णतया सफल बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं और अबतक सम्पादित कार्य की सामान्य स्वीकृति : ये सब अन्य बातें जो योजना के अनुकूल हैं कोलम्बो सम्मेलन में पैदा हुई थी।

अन्त में टैक्निकल सहायता स्कीम में हुए उपयोगी विस्तार का उल्लेख करना चाहिये। जैसाकि आपको मालूम होगा, इस स्कीम की वित्तीय व्यवस्था राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा दी गई ८० लाख पौंडों की निधि से किया जा रहा है।

कोलम्बो योजना के प्रतिकूल अंग में केवल एक उल्लेखनीय बात है : अर्थात् विश्व के पुन:शस्त्रीकरण से पूंजीगत सामग्रियों की उपलब्धि पर प्रभाव। यद्यपि प्रतिरक्षा कार्यक्रम ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था और उसके साधनों पर और भी दबाव डाल रहा है पर ब्रिटेन की सरकार योजना को कार्यान्वित करने में अपना पूरा अंशदान देने के लिये कृतसंकल्प है। १९४६ से ब्रिटेन पूर्वी एशिया के देशों को प्लान्ट और मशीनरी बड़े परिमाण में भेज रहा है और इस दिशा में उन्नति का इच्छुक है : यदि और किसी कारण से नहीं तो कम से कम इसी कारण से कोलम्बो योजना को सफल बनाने के लिये ब्रिटेन अपनी ओर से कोई कसर उठा न रक्खेगा।

F.H.R.13

खान खोदाई का ब्रिटिश ढंग

भारतीयों को प्रशिक्षण

आजकल ब्रिटेन में २६ भारतीय नवयुवक कोयले की खानों में सतह की खान खोदाई की विधि और उसका व्यवहार सीख रहे हैं। ये भारतीय नवयुवक, जिनका प्रशिक्षण दो वर्षों में समाप्त होगा, और जिनमें से कुछ को आप इन चित्रों में देख रहे हैं लीड्स, साउथवेल्स, एडिनबरो और न्यूकासिल में है।

जिन स्थानों में ये प्रशिक्षण पा रहे हैं वे सर लिन्डसे पार्किन्सन ऐन्ड कम्पनी के नियन्त्रण में है। यह कम्पनी, जो ब्रिटिश ईंधन और शक्ति मन्त्रालय की ओर से काम करती है, बिहार में एक सतह की खान खोदाई के स्थान का संचालन भी करती है।

आशा की जाती है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकने के बाद ये भारत में विभिन्न मुख्य पदों पर नियुक्त किये जायेंगे : सतह की खान खोदाई के स्थानों के अतिरिक्त भारत सरकार की जलविद्युत योजनाओं में भी।

यद्यपि अन्य कई प्रकार के ईंधन उपलब्ध हुए पर ब्रिटेन के लिये कोयले का महत्व कम नहीं हुआ। ब्रिटेन में कोयले का उपयोग बीस हजार टन प्रति घन्टे के हिसाब से दिन में चौबीस घन्टे किया जाता है। कोयले की नौ सौ खानों में काम करने वाले ७ लाख श्रमिक कारखानों इत्यादि को सप्ताह में तीस लाख टन कोयला देते हैं और ब्रिटेन

... के घरों को

के घरों को अन्य कई लाख टन। सचमुच, वाष्प इंजन के आविष्कार के समय से ब्रिटेन की अभिवृद्धि कोयले पर अवलम्बित रही है। और इस देश का कोयला उद्योग संसार के सर्वाधिक उन्नत और विकसित उद्योगों में गिना जाता है। १९४७ में "राष्ट्रीय कोयला मंडल" ने इस उद्योग को अपने अधिकार में लिया था और उत्पत्ति में वृद्धि उसका अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य था। पिछले चार वर्षों में हुई दो करोड़ तीस लाख टनों की वृद्धि उसकी सफलता प्रकट करती है।

ये २९ भारतीय सतह की खान खोदाई के अत्यन्त आधुनिक समझे जाने वाले ब्रिटेन के स्थानों में उत्पादन की अत्यन्त उन्नत विधियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकने के बाद ये भारत में विभिन्न मुख्य पदों पर नियुक्त किये जायेंगे।

H/L.P.S.168

ज़बरदस्त जनवादी — महान नेता

अर्नेस्ट बेविन को 'टाइम्स' की श्रद्धांजलि

अर्नेस्ट बेविन के निधन पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए 'टाइम्स' लिखता है : उनकी निष्ठाएं सीधीसादी थीं। उनकी निष्ठाओं ने, जो सच्चे विश्वास से उत्पन्न हुई थीं, देशवासियों में विश्वास जागृत किया था। श्री० बेविन ने प्रारंभ से अंत तक अपने देशवासियों का साथ दिया, उन्होंने अपने नेताओं का साथ और अपने विचारों तथा आदर्शों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे सदैव एक जनवादी थे, सदैव एक देशभक्त।

१९४५ के बाद वाले प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने साहस के साथ और संकोच के बिना रूस की चुनौती स्वीकार की थी। स्वयं उनके दल के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था किन्तु श्री० बेविन ने अपना मार्ग न छोड़ा और यही समय था जब उन्होंने विश्व के मामलों में ब्रिटेन के प्रभाव को ज़ोर के साथ प्रकट किया था।

श्री० बेविन उनके गुणों के प्रशंसक श्री० चर्चिल की भांति १८वीं शताब्दि के आगन्तुक मालूम पड़ते थे। चैदम और सैम्युएल जान्सन की भांति श्री० बेविन ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा उसपर उन्होंने इंग्लैंड की कुछ न कुछ छाप छोड़ डाली थी।

H.S.14

भारत को गेहूं का ऋण

वापसी स्थगित करने का ब्रिटिश निर्णय

भारत स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर, सर आर्चिबाल्ड नाई, ने भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से सूचित किया है कि उसने ४२,५७८ टन आस्ट्रेलियन गेहूं, जो उसने भारत को दिया था, की वापसी मध्य जुलाई तक के लिये स्थगित करने का निश्चय किया है।

मूल समझौते के अनुसार यह गेहूं मार्च, १९५१ में वापस किया जाने वाला था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार गेहूं की वापसी स्थगित करने की अवस्था में नहीं है पर उसने यह निश्चय "भारत सरकार की वर्तमान कठिनाइयों का ध्यान रखते हुये" किया है।

F.H.209

ब्रिटिश स्कूली बच्चों के अन्वेषण कार्य

केन्द्रीय आइसलैंड की यात्रा

(जान रिग)

"ब्रिटिश स्कूल अन्वेषण समाज" का लन्दन केन्द्र आजकल बहुत कार्यव्यस्त है : कारण, गर्मियों की छुट्टियों में लगभग ६० बच्चे केन्द्रीय आइसलैंड की साहसी यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। यह इस समाज की तेरहवीं यात्रा होगी : पहली साहसी यात्रा १९३२ : में वह फिनिश लैपलैंड की खोज करने निकला था। अन्वेषण समूह में सम्मिलित किए जाने के लिए सारे ब्रिटेन के स्कूली बच्चे प्रार्थनापत्र भेज रहे हैं।

इस "समाज" द्वारा आयोजित यात्राएं सचमुच साहसी यात्राएं होती हैं : लड़के विभिन्न प्रकार की आवश्यक साधन सामग्रियां अपने साथ ले जाते हैं। इनके साथ एक साधारण और एक चीरफाड़ करने वाला डाक्टर रहता है। ये लोग प्राय: अपने डेरे बहुत ठंडे प्रदेशों में लगाते हैं, प्राय: ये बरफ से ढके हुए निर्जन स्थानों की लम्बी छानबीन करते हैं। "स्कूल अन्वेषण समाज" के सदस्यों द्वारा बनाए गए नकशे — अन्वेषण के स्थान की आकृति और आकार का पता लगाना अन्वेषणकर्ताओं का एक मुख्य कार्य होता है — अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ, एकबार अन्वेषणकर्ताओं ने न्यूफाउंडलैंड में कई नई झीलों का पता लगाया था।

"ब्रिटिश स्कूल अन्वेषण समाज" की स्थापना ब्रिटिश नौसेना के सर्जन कमाण्डर जी० मरे लेविक ने की थी। उन्होंने अनुभव किया था कि ब्रिटिश स्कूली बच्चे इस दिशा में ऐसी कई सुविधाओं से वंचित है जो राष्ट्रसमूह के कई भागों के स्कूली बच्चों को उपलब्ध ... हैं। इसलिए

है। इसलिए १९३२ में वे स्कूली बच्चों के एक समूह को उत्तरी फिनलैंड ले गए थे और बच्चे ले गए थे साधन सामग्री और खानेपीने की चीज़ें अपनी अपनी पीठों पर लादकर। उस समय से न्यूफाउंडलैंड , फिनिश लैपलैंड और उत्तरी नार्वे की यात्राएं की जा चुकी हैं। १९४८ में स्कूली बच्चों का एक दल उत्तरी क्विबेक गया था ।

उत्साह का वातावरण

यद्यपि अन्वेषण समाज कैनडा या न्यू फाउंडलैंड जाने के लिए बहुत उत्सुक है पर जहाज़ी यात्रा के बढ़े हुए किरायों के कारण संकोच कर रहा है। फिर भी आइसलैंड की यात्रा , जो उनकी पहली यात्रा होगी , की प्रतीक्षा स्कूली बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। चैरिंग क्रास के पास 'रायल एम्पायर सोसाइटी' के भवन के कमरे उत्साह और उमंग के वातावरण से भरे हैं । दीवारों पर बर्फ की भूमि को पार करने वाले बच्चों के चित्र टंगे हैं। एक दीवार पर आइसलैंड का नक्शा टंगा हुआ है और उसी के पास उत्तरी नार्वे के एक भाग का बड़ा नक्शा जो अन्वेषण यात्रा के बाद बच्चों ने बनाया था। मेज़ पर साथ ले जाई जाने वाली खाने पीने की चीज़ों और अन्य वस्तुओं की एक सूची रखी हुई है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी अन्वेषण यात्राओं की तैयारी करना सरल काम नहीं है । 'समाज' के मन्त्री , कमान्डर एन०डी०जी० वेमाउथ के शब्दों में , 'आइसलैंड की यात्रा के लिए मैं पन्द्रह दिन पहले जाऊंगा और अपने साथ सारी सामग्रियां — कुलमिलाकर नौ टन — ले जाऊंगा । इसमें चार टन खाने पीने की चीज़ें होंगी। तब मैं एक मूल शिविर के लिए स्थान ढूंढकर वहां शिविर लगाऊंगा। बच्चों के आ जाने के बाद मैं वहां से किसी पास के स्थान में चला जाऊंगा और रेडियो के द्वारा मूल शिविर के साथ सम्पर्क बनाए रक्खूंगा। इसके बाद, उन्होंने कहा , लड़के तीन से लेकर पांच दिनों तक की यात्रा के लिए रवाना होंगे। रात को वे सोने का प्रबन्ध करेंगे और आवश्यक चीज़ें अपनी पीठों पर लिए रहेंगे । इसके बाद कुछ चुने हुए लड़के चौदह या पन्द्रह दिनों की लम्बी सफर करेंगे ।

अन्वेषण यात्रा समूह के सब सदस्य , जिनकी आयु साढ़े सोलह से उन्नीस वर्षों तक है , अमीरी और गरीबी का ध्यान रक्खे बिना चुने जाते हैं ।

N.E.H.44

"एशिया को आह्वान"

बी०बी० सी० का नया प्रोग्राम

१३ मई से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सुनने वालों के लिए "लन्दन कालिंग एशिया" नामक एक नया क्षेत्रीय प्रोग्राम बी०बी०सी० द्वारा अंग्रेज़ी में प्रारम्भ किया जाने वाला है जो प्रतिदिन सायंकाल पौने सात से साढ़े सात तक १६ और १९ मीटर बैन्डों की फ्रीक्वेंसियों पर प्रसारित होगा या ब्रिटिश फार ईस्टर्न ब्राडकास्टिंग सर्विस से १३, १६ और ४१ मीटर बैन्डों पर रिले किया जाएगा ।

"लन्दन कालिंग एशिया" के पहले ब्रिटिश फार ईस्टर्न ब्राडकास्टिंग सर्विस के अन्तर्गत एक समाचार बुलेटिन सुनाई जाएगी : यों इस प्रोग्राम के प्रथम पन्द्रह मिनटों में एशियाई मामलों पर ब्रिटिश समाचारपत्रों की सम्मतियां और वर्तमान घटनाओं के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण समझाने वाली टीकाटिप्पणी सुनाई जाएगी। इस प्रकार उन लोगों को, वर्तमान गतिविधियों में जिनकी विशेष रूचि है, ब्रिटिश फार ईस्टर्न ब्राडकास्टिंग सर्विस से आधे घन्टे के लिए समाचार और टीकाटिप्पणी सुनने का अवसर मिलेगा। कलाओं और विज्ञानों में रूचि रखने वाले "लन्दन कालिंग एशिया" प्रोग्राम के अंतिम आध घन्टे में अपनी रूचि की सामग्री पाएंगे ।

H/L.P.S.184

अधिक विस्तृत सुरक्षा प्रणाली की सम्भावना

आस्ट्रेलिया , न्यूज़ीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुए प्रशान्त समझौते पर मत प्रकट करते हुए 'डेली हेरल्ड' ने लिखा है : ऐसे समझौते पर हमारे हस्ताक्षर करने का कोई मतलब नहीं होगा । अटलांटिक सन्धि के अन्तर्गत हम अमेरिका के प्रति पहले ही से वचनबद्ध हैं । और आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के साथ हमारे सम्बन्धों के साधन अलिखित होने पर भी बहुत सन्निकट और किसी भी सन्धि की तुलना में अधिक बाध्य करने वाले हैं ।

यदि यह प्रशान्त में या उसके पास प्रदेश रखने वाले सब स्वतन्त्र देशों की एक अधिक विस्तृत प्रतिरक्षा व्यवस्था का प्रश्न होता तो दूसरी बात थी । हो सकता है कि ऐसी प्रतिरक्षा व्यवस्था आगे चलकर उत्पन्न हो , उसी प्रकार जैसे पश्चिमी संघ से उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन उत्पन्न हुआ था । किन्तु इस समय यह सम्भव नहीं है, ऐसे कई कारणों से जिनपर हमारा काबू नहीं है ।

N.E.H.45

'लोकतन्त्र' की लीला

रंगून से प्रकाशित 'न्यू टाइम्स आफ बर्मा' के जान हाकिंग नामक लन्दन स्थित सम्वाददाता ने निम्नलिखित कहानी, जो पत्र के दूसरे मार्च वाले अंक में प्रकाशित हुई थी, बताई है। कहते हैं कि एकबार कुछ चोरों ने प्राग के साम्यवादी केन्द्रीय कार्यालय में घुसकर कुछ बड़े काम के कागज़ात चुरा लिए थे। पता चला कि ये कागज़ात चेकोस्लोवाकिया में अगले वर्ष होने वाले निर्वाचनों के परिणाम थे।

N.E.H.46

सिंगापुर की सफलता

१९४९ में सिंगापुर की मृत्युरेट ब्रिटेन की मृत्युरेट से अधिक नहीं थी और बच्चों की मृत्युरेट घटकर प्रति एक हज़ार के पीछे ७३ हो गई थी, जबकि १९३९ में १३० थी। इतनी नीची संख्या कहीं स्वतन्त्र अयनवृत्तीय और अयनवृत्त की सीमा के पास स्थित देशों में जहां प्रति एक हज़ार के पीछे १०० काफी साधारण रेट है, नहीं देखी गई। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अयनवृत्तीय ब्रिटिश उपनिवेशों में सिंगापुर की शिशु मृत्युरेट सबसे नीची है : ज़ंज़ीबार में, उदाहरणार्थ, वह लगभग ५५ के है।
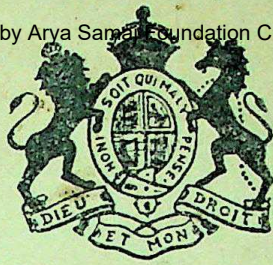
BRITISH INFORMATION SERVICES

FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

April 29 to May 12, 1951.

HINDI

F.H.215/

सोवियट रूस की नीति
और
पेरिस की बातचीत

डब्ल्यू०एन०ईवर,
'डेली हेरल्ड', लन्दन के राजनैतिक
सम्वाददाता

इस बात के लक्षण दीखते हैं कि पश्चिमी शक्तियों को ठीक अपनी इच्छा के सम्मेलन के लिए राज़ी करने में असफल होने के कारण सोवियट सरकार अब किसी प्रकार के सम्मेलन का न होना ही अच्छा समझती है। यही इन सारी बातों का परिणाम हो सकता है।

चार विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन को सम्भव बनाने के लिए तीनों पश्चिमी शक्तियों ने पेरिस में भरसक प्रयत्न किया। उनके प्रस्ताव थे : १. उनके नवीनतम विस्तृत सुझावों के आधार पर विचाराधीन विषयों की एक सहमति प्राप्त सूची, २. विचाराधीन विषयों की ऐसी सूची जो उन विषयों की भाषा और रूप, जिनपर सहमति नहीं प्राप्त की जा सकी, के निर्णय स्वयं विदेश मन्त्रियों पर छोड़ेगी और ३. विचाराधीन विषयों की ऐसी सूची जिनपर विदेश मन्त्रियों के वाद विवाद के पांच मुख्य विषय मात्र अंकित हों।

विचाराधीन विषयों की सूची विषयक सम्मेलन की समाप्ति में विलम्ब के कारण जनमत अधीर हो उठा है और यह स्वाभाविक ही है।

... जब पहले

जब पहले दिन तीनों पश्चिमी उप विदेश मन्त्रियों ने एक प्रकार का प्रारूप प्रस्तुत किया और श्री० ग्रामीको ने दूसरी तरह का तो यह एक दूसरे से अत्यधिक विपरीत दीखे थे। पर इन्हें देखने से पहला विचार यह उत्पन्न हुआ था कि इनमें समन्वय सम्भव होगा। आखिर उपविदेश मन्त्रिगण तत्व की बातों पर वाद विवाद नहीं कर रहे थे, वे तो अपने प्रधानों के वाद विवाद के लिए विषयों की सूची बना रहे थे।

किन्तु यह पहले ही सप्ताह में स्पष्ट हो गया था कि श्री० ग्रामीको (और इसलिये अनुमानत: सोवियट सरकार भी) किसी विषय की भाषा और शब्द और विचाराधीन विषयों की सूचियों में उसके स्थान को अत्यधिक महत्व देते थे। श्री० ग्रामीको ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि वह विषय पहले और पृथक रूप में लिया जाए जो उनके प्रारूप में यों प्रकट हुआ था : जर्मनी के सैन्य विघटन और उसके पुन:सैनिकीकरण को रोकने से सम्बन्धित पाट्सडम समझौते की पूर्ति।

पश्चिमी शक्तियों के उपविदेश मन्त्रियों को स्वाभाविकतया इस बात का स्मरण आया कि तभी जब मन्त्रियों के सम्मेलन में बातचीत हो रही थी सोवियट सरकार ने वाद विवाद को केवल इसी विषय तक सीमित रखने की इच्छा प्रकट की थी। तब बहुत धीरे धीरे, बड़ी अनिच्छा के साथ, विचाराधीन विषयों में अन्य बातों को लेने और सम्मेलन के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने के लिए सोवियट ने सहमति दी। ग्रामीको इस बात पर जितना ज़ोर दे रहे हैं उससे मालूम होता है कि सोवियट सरकार शायद यह समझती है कि "जर्मनी के पुन:सैनिकीकरण" को एजेन्डे में प्रथम और पृथक स्थान देने से इस पर वाद विवाद उसी समय हो सकेगा और यों मिल सकेगा अधिक आगे न बढ़ने का बहाना।

लम्बे तक वितर्क

प्रारम्भ से ही तीनों पश्चिमी शक्तियों की यह धारणा रही है कि जर्मनी के सैनिकीकरण का प्रश्न इस प्रकार पृथक नहीं किया जा सकता और उसपर गम्भीरता के साथ तथा उपयोगी ढंग से विचार विनिमय तभी सम्भव है जब वह योरोपीय अशांति के उन कारणों के साथ रक्खा जाए जर्मनी के सैनिकीकरण से सम्बन्धित झगड़ा जिनका एक परिणाम, एक लक्षणभर है। ग्रामीको के प्रस्ताव (बाहर से सीधासादा पर वास्तव में आज्ञासूचक) को स्वीकार कर इस विषय को पूरी प्राथमिकता देने से सम्मेलन का सारा रंग ढंग ही बदल जाएगा।

... इसलिये

इसलिये आवश्यक हुआ था वह लम्बा तर्क वितर्क जिसे बहुत से बाहरी लोगों ने अनावश्यक बारीकियों पर लम्बी चौड़ी बहस समझा होगा। तब कुछ सप्ताहों के बाद समझौते की एक सम्भावना दिखाई दी। श्री० ग्रामीको इस बात पर राज़ी हो गये कि पहले "अशान्ति के कारणों" पर एक आम बहस हो और इसके बाद मन्त्रिगण ख़ास ख़ास विषयों पर विचार करे। पर जब मन्त्रिगण ख़ास ख़ास विषयों पर विचार शुरू करे तो, ग्रामीको ने बड़ी गम्भीरता से कहा, "जर्मन पुनःसैनिकीकरण" को पहला स्थान दिया जाए।

इस बीच में एक दूसरा प्रश्न उपस्थित हो गया। रूस के पहले प्रारूप में इस आशय का प्रस्ताव रक्खा गया था कि मन्त्रिगण "चारों शक्तियों के सशस्त्र बलों में कमी की बात पर विचार करें।

ऐसे प्रस्तावों पर जिनके फलस्वरूप शस्त्रास्त्रों में सामान्य कमी होगी विचार विनिमय करने, उन्हें कार्यान्वित करने से भला किस को आपत्ति हो सकती है, पर स्पष्ट है कि ऐसा वाद विवाद तभी सच्चा और गम्भीर हो सकता है जब उसके अन्तर्गत शस्त्रास्त्रों के वर्तमान स्तर पर सबसे पहले विचार किया जाए। विचाराधीन विषयों की सूची में शस्त्रास्त्रों के वर्तमान स्तर की ओर किसी प्रकार का संकेत सम्मिलित करना बहुत समय तक ग्रामीको को पसन्द नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता कि यह बात पूर्णतया आश्चर्योत्पादक थी।, कारण, लेक सक्सेस में श्री० विशिंस्की ने कहा था कि सोवियट सरकार अपनी सशस्त्र सेना के बल के बारे में पूरी सूचना तभी देगी जब अन्य देश अपने शस्त्रास्त्रों में एक तिहाई की कमी करने का वचन दे दें।

इस प्रस्ताव को कोई नहीं स्वीकार कर सकता था। क्योंकि इसके फलस्वरूप रूस को अपनी सैनिक श्रेष्ठता को ठोस और स्थायी बनाने का अवसर मिलता, वही श्रेष्ठता जो रूस ने पश्चिमी शक्तियों की भांति अपने शस्त्रास्त्रों में कमी न करने से प्राप्त की थी।

ग्रामीको का लक्ष्य

इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता था कि ग्रामीको उसी लक्ष्य की ओर एक दूसरे मार्ग से बढ़ रहे थे। वे फिर पश्चिमी शक्तियों को मन्त्रि के सम्मेलन से पहले ही आंख मूंदकर अपने शस्त्रास्त्रों में कमी करने के लिए फुसला रहे थे।

... यह नहीं

यह नहीं कहा जा सकता कि अन्त में जाकर रूस पश्चिमी शक्तियों से ऐसे छिपे हुए किन्तु बिल्कुल निश्चित अग्रिम वचन पाने के प्रयत्न जारी रखेगा या छोड़ देगा। इस बात के लक्षण दीखते हैं कि पश्चिमी शक्तियों को ठीक अपनी इच्छा के सम्मेलन के लिए राज़ी करने में असफल होने के कारण सोवियट सरकार अब किसी प्रकार के सम्मेलन का न होना ही अच्छा समझती है। यही इन सारी बातों का परिणाम हो सकता है। यदि ऐसी ही बात है तो कई लोगों की इस धारणा की पुष्टि होगी कि प्रारम्भ से ही रूसी लोग न ऐसे सम्मेलन की इच्छा रखते थे और न उसके लिए तैयार थे जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अशांति के कारणों को हटाने का प्रयत्न करें। वे तो केवल प्रचार के नए अवसर ढूंढ रहे थे, इस अनौपचारिक युद्ध में नए आक्रामक कृत्यों के मौके मात्र।

H.S.15

समाचार संकलन

दक्षिण पूर्व एशिया को टेक्निकल सहायता

कोलम्बो योजना की टेक्निकल सहयोग परिषद को अन्तरिम प्रशासन ने बताया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को टेक्निकल सहायता देने की दिशा में काफी उन्नति देखी जा सकती है। टेक्निकल सहायता तीन रूपों में दी जा रही है : विशेषज्ञ और सलाहकार, समुद्रपारस्थ देशों में ट्रेनिंग और कुछ प्रकार की साधन सामग्रियां अबतक तीन देशों, लंका, भारत और पाकिस्तान से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं।

`इन्स आफ कोर्ट` का नवनिर्माण

इस आशय की घोषणा ने कि इनर टैम्पल और पुस्तकालय की आधारशिला अक्तूबर के महीने में सम्राट द्वारा रखी जायेगी लन्दन के ऐतिहासिक `इन्स आफ कोर्ट` (इंग्लैंड के वकीलों का संघ) के पुनर्निर्माण और मरम्मत के कार्य को और आगे बढ़ा दिया है। पाठकों को स्मरण होगा कि युद्धकाल में जर्मन बमवर्षा से इन्स आफ कोर्ट बुरी तरह नष्ट हो गये थे।

`स्काटिश सिलवर`

स्काटलैंड के राज्य मन्त्री हेक्टर मेकनील ने बताया है कि `स्काटिश सिल्वर` नामक एक विशिष्ट प्रकार की धातु ब्रिटेन में फिर से निकाली जाएगी।

...एडिनबरो के

एडिनबरो संगीत में भारतीयों का भाग

एडिनबरो के कास्मापालिटन क्लब द्वारा आयोजित एक संगीत समारोह में भारतीय विद्यार्थियों ने प्रमुख भाग लिया था । यह आयोजन विद्यार्थी दयादान सप्ताह के प्रसंग में किया गया था । कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक गीत और कई देशों के नृत्य सम्मिलित थे । कैनडा , स्याम , गोल्ड कोस्ट , मलाया और इस्रायल का प्रतिनिधित्व विद्यार्थियों ने किया था । अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता और पारस्परिक समझ , विशेषतया विद्यालयों में , बढ़ाना और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन कास्मापालिटन क्लब के उद्देश्य हैं ।

मलाया में मुद्रास्फीति रोकना

मुद्रास्फीति और जीवननिर्वाह खर्चों में वृद्धि के विरुद्ध मलाया संघ की सरकार जो योजना कार्यान्वित कर रही है उसके अन्तर्गत साठ नई सहकारिता के आधार पर संचालित दुकानें खोली जा चुकी हैं । आगे चलकर अन्य दुकानें खुलेंगी। प्रारंभिक खर्चों में हाथ बटाने के लिये सरकार की ओर से १ लाख ७५ हज़ार पौंड की अग्रिम पूंजी दी जाएगी ।

अणुशक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अणुशक्ति के लाभदायक प्रयोगों के विषय में सूचना के आदान प्रदान के लिये आक्सफर्ड में जो सम्मेलन जुलाई १६ से २१ तक चलने वाला है वह ब्रिटेन के लिये इस विषय से सम्बन्धित सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जा सकता है । आशा है कि लगभग बीस देश के प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित होंगे ।

शिशु पक्षाघात के लिए नया संगठन

ब्रिटेन में शिशु पक्षाघात में अनुसन्धान करने के लिये एक नया , महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किया जा रहा है । "ब्रिटिश इन्फेंटाइल पेरालिसिस फेलोशिप" के अध्यक्ष रेनेनसन काउशर के शब्दों में , " आज शायद अन्य कोई रोग इतनी चिन्ता नहीं उत्पन्न कर रहा है जितना कि शिशु पक्षाघात।" आगे चलकर उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के प्रमुख चिकित्सकों और औषधिशास्त्र विशेषज्ञों को इस संगठन में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

... इस ग्रीष्मकाल

भारतीय तेल कामकाजियों की ब्रिटेन यात्रा

इस ग्रीष्मकाल में भारत सहित ५८ देशों के १२०४ तेल कामकाजी ब्रिटिश शेल आयल कम्पनी के लन्दन स्थित प्रधान कार्यालय के अतिथि रूप में ब्रिटेन का समारोह देखने जायेंगे। ये सब इस कम्पनी के कर्मचारी हैं जो समूहों में ब्रिटेन की यात्रा करेंगे और प्रत्येक दल ब्रिटेन में लगभग एक महीना व्यतीत करेगा। पांच में का पहला समूह (जिसमें उनकी पत्नियां भी सम्मिलित होंगी) १७मई से ७ जून तक रहेगा।

ताज रत्नों की अदृश्य रक्षा

ब्रिटेन के विश्व विख्यात क्राउनस (ताज) रत्नों की रक्षा अब लोहे के भारी छड़ों से नहीं की जाती। आजकल उन्हें लन्दन टावर बुर्ज पर रखे कांच के एक ऐसे शो-केस (प्रदर्शन बक्स) में दिखाया जा रहा है जिसमें रक्षा का कोई दृश्य साधन नहीं है। प्रदर्शन के नये तरीके में उस दैदीप्यमान राजचिन्ह का प्रत्येक भाग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। रक्षा की यह नई और अदृश्य विधि (जिसे बिल्कुल गोपनीय रखा गया है) को उन छड़ों की जगह प्रयुक्त किया गया है जो पहले शो-केस के चारों ओर लगी रहती थीं।

ऐतिहासिक भवनों की रक्षा

ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। संसद में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मन्त्री श्री० ह्यू० गेटस्केल ने कहा था कि सुन्दरता, ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य महत्व की दृष्टि से ये राष्ट्र की सम्पत्ति है जिनके संरक्षण के लिये राष्ट्र को कुछ और उत्तरदायित्व लेना चाहिये।

ग्लासगो की निर्देशिका

स्काटलैंड के प्रमुख जहाजनिर्माण और औद्योगिक शहर ग्लासगो ने समुद्रपारस्थ देशों के व्यापारिक आगन्तुकों के लाभार्थ एक नई और विशेष प्रकार की निर्देशिका बनाई है। इसमें ग्लासगो के दस सबसे बड़े उद्योगों, उसके विदेशी व्यापार, उसके प्रसिद्ध बन्दरगाह इत्यादि के बारे में विस्तृत सूचना दी गई है।

H/L.P.S.217

ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति :

आई०सी०एफ०टी० यू० का
क्षेत्रीय सम्मेलन

कराची की बातचीत में पचास से
अधिक प्रतिनिधि

आशा की जाती है कि एशिया और सुदूरपूर्व के लगभग एक करोड़ संगठित कामकाजियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पचास से अधिक प्रतिनिधि स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ के प्रथम एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में, जो कराची में २८ से ३१ मई तक होगा, भाग लेंगे। स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ के सदस्य ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि भारत, लंका, पाकिस्तान, फारमोसा, हांगकांग, ईरान, जापान, कोरिया, मलाया और थाइलैंड से आएंगे।

सुदूरपूर्व और एशिया के लिये स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ के एक स्थायी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना सम्मेलन का तात्कालिक लक्ष्य है। आर्थिक विकास, ट्रेड यूनियनों के अधिकार, श्रम विधान और औद्योगिक सम्बन्ध जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा।

काश्मीर के लिए संयुक्त राष्ट्रीय मध्यस्थ

फ्रैंक ग्रैहम के चुनाव पर गार्जियन की सम्मति

'मध्यस्थ' शीर्षक से 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने दूसरी मई के अंक में लिखा है कि काश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ दव्ारा डाक्टर फ्रैंक ग्रैहम की नियुक्ति बहुत सन्तोषप्रद है। यदि कोई व्यक्ति इस गत्यवरोध को ठीक कर सकता है तो ऐसे ही व्यक्ति दव्ारा इस काम की सम्भावना है। डाक्टर ग्रैहम ने नार्थ केरोलीना के विश्व विधालय को, कई वर्षों तक जिसके वे अध्यक्ष थे, ज्ञान का एक महान केन्द्र बनाया था। कई लोक निकायों के अध्यक्ष रूप में इन्होंने अपने देशवासियों की अच्छी सेवा की थी।

सेनेट के सदस्य रूप में आप जातीय सहिष्णुता के ज़ोरदार समर्थक थे। इधर कुछ समय से आप श्रम विभाग में प्रतिरक्षा सम्बन्धी जनशक्ति मामलों के सलाहकार थे और इनकी उपस्थिति से ट्रेड यूनियनों और प्रशासन के मतभेदों के मिटने में सहायता की आशा की जाती थी।

'मैनचेस्टर गार्जियन' के मतानुसार ऐसे महत्वपूर्ण समय में डाक्टर ग्रैहम को भेजने की इच्छा दिखाकर राष्ट्रपति ट्रूमन ने प्रदर्शित किया है कि काश्मीर के मामले को वे कितना महत्व देते हैं।

F.H.219

पश्चिमी योरप में साम्यवाद का पतन

सदस्यसंख्याओं में कमी

एडवर्ड ऐशक्राफ्ट

संख्याएं सदैव सच्चे मार्गदर्शक का काम नहीं करतीं । इसलिए किसी राजनैतिक तर्क वितर्क को बल प्रदान करने के लिये संख्याओं के उपयोग को सन्देह की दृष्टि से देखना ही अच्छा है । कामिन्फार्म के "शान्ति" आन्दोलन का (१९४९-५०) संसार को, और विशेषतया लौह आवरण की जनता को, सोवियट "शान्ति" के समर्थकों की संख्या से अवाक् करना था ।

फिर भी संख्याओं पर कभी कभी दृष्टिपात करना अच्छा है । कुछ समय पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम योरप में साम्यवादियों की शक्ति से सम्बन्धित कुछ संख्याएं प्रकाशित की थीं। इनसे मालूम होता है कि १९४६ में पश्चिमी योरप में साम्यवादी दलों के अन्दर चालीस लाख सदस्य थे और आज इनकी संख्या २७ लाख है। यह अनुमान परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालने वाला है, क्योंकि, यद्यपि कुछ बातें जिनपर यह अनुमान आधारित है सन्देह से खाली नहीं कही जा सकती, पर संख्याएं मोटे तौर पर सही हैं। इन संख्याओं से वह मालूम होता है जो निष्पक्ष लोगों के लिए इधर कुछ समय से स्पष्ट रहा है : अर्थात् पश्चिमी योरप में साम्यवाद का पतन ।

यहांतक कि १९४६ में भी, जब साम्यवाद अपनी शक्ति के शिखर पर था और जब मिलेजुले शासन में फ्रांस के साम्यवादी दल को अपने छः विभागों का गर्व था, ऐसे देशों की संख्या जहां एक लाख से अधिक साम्यवादी थे केवल चार थी । ये देश थे फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी और आस्ट्रिया ।

... इस बात के

इस बात के कई प्रमाण हैं कि उन देशों में जहां साम्यवादी दलों की सदस्यसंख्या १६४६ में कम थी दल को बहुत हानियां उठानी पड़ी हैं। १६४६ में दल ने हालैंड में केवल ११.४ प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे और १६५० के प्रान्तीय निर्वाचनों में इस संख्या की आधी से कुछ ही अधिक। डेनमार्क में, जहां नगरपालिका निर्वाचन १६५० में हुए थे, साम्यवादी दल ने २६ स्थान खो दिये थे। और आस्ट्रिया के सोवियट क्षेत्र में साम्यवादियों ने केवल पांच प्रतिशत वोट प्राप्ट किये थे।

ब्रिटेन में, जहां १६५० के आमनिर्वाचनों में सौ साम्यवादी उम्मीदवार थे, इस दल को संसद में कोई स्थान नहीं मिल सका।

अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित संख्याएं बताती हैं कि बेल्जियम, नार्वे और डेनमार्क में दल की सदस्यसंख्या में ६० से लेकर ६५ प्रतिशत की कमी हुई है। नार्वे में, जहां १६४५ में साम्यवादी दल की लोकप्रियता इतनी अधिक थी, आज ३२ लाख की जनसंख्या में केवल १४ हज़ार साम्यवादी हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार स्वीडन में, जिसकी जनसंख्या नार्वे के लगभग दुगनी है, साम्यवादी दलकी सदस्य संख्या ३३ हज़ार हैं।

अन्य प्रमाण

योरप में साम्यवादी समाचारपत्रों की बिक्री सम्बन्धी संख्याएं विदेश विभाग की संख्याओं को बल प्रदान करती हैं। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि समस्त पश्चिमी योरप में ऐसे कई पत्र और पत्रिकाएं बिक्री में कमी के कारण बन्द हो चुके हैं। क्योंकि १६४७ - ५० पश्चिमी योरप के कामकाजियों के रहनसहन के स्तरों में वृद्धि के वर्ष थे इसलिये साम्यवादी समाचारपत्रों को न खरीदने का कारण उनकी बढ़ती हुई निर्धनता नहीं कहा जा सकता है।

फिर भी हम देखते हैं कि सारे योरप में क्षेत्रीय साम्यवादी समाचारपत्र गायब हो गये हैं और राष्ट्रीय समाचारपत्रों की बिक्री बहुत कम हो गई है। उदाहरणार्थ, १६४५ में ला ह्यूमेनाइट " की ५,३०,००० प्रतियां बिकती थीं पर आज केवल २,५०,००० । बेल्जियम में "ली ड्रापेयू राउज " की बिक्री पहले की पांचवी भाग मात्र रह गई है। हालैंड में १६४५ में साम्यवादी समाचारपत्र की चार लाख प्रतियां बिका करती थीं पर आज का अनुमान ८० हज़ार तक बैठता है। इटली में " यूनीता " की ५ लाख

... प्रतियां

प्रतियां दैनिक प्रकाशित होती हैं पर विश्वसनीय सूचनाओं के अनुसार १९४६ में इस पत्र के सच्चे खरीदारों की संख्या दो लाख थी और आज डेढ़ लाख रह गई है।

स्पेन को छोड़ते हुए पश्चिमी योरप की सम्पूर्ण जनसंख्या २२ करोड़ ७० लाख है। इसका अर्थ यह हुआ कि, इस क्षेत्र में २७ लाख साम्यवादियों का विदेश विभाग का अनुमान यदि सही है तो, दो प्रतिशत से कम साम्यवादी दलों के सदस्य हैं। पर वास्तव में २७ लाख की सम्पूर्ण संख्या में से आधी से अधिक इटालियन साम्यवादी दल (१६,००,०००) और फ्रेंच साम्यवादी दल (६ लाख) की बताई जाती हैं। कुछ लोगों के अनुसार इटालियन साम्यवादी दल की सदस्यसंख्या विदेश विभाग के अनुमान से अधिक है। पर यह बात तो पश्चिमी योरप के अधिकांश देशों में साम्यवादी दल की सदस्यसंख्या की तुलनात्मक कमी पर ज़ोर डालती है।

संख्याएं [illegible] अब तथ्य

यह तो हो गई संख्याओं की बात। अब कुछ तथ्य जो परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ, इटली को लीजिए : दल के सदस्यों की संख्या चाहे २० लाख हो या उससे अधिक (या उससे कम) यह सर्वविदित है कि पिछले दो वर्षों में उत्तरी इटली के निपुण और शिक्षित कामकाजियों का समर्थन इसे खोना पड़ा है। इसके बदले में उसने दक्षिण इटली में अपनी परिस्थिति सुधारी है। और भूमिहीन कामकाजियों की ओर से प्राप्त समर्थन पहले तो कम महत्वपूर्ण है और, दूसरे, डीगैस्पेरी शासन के भूमि वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वित होने से यह समर्थन समाप्त भी हो सकता है। उधर बेकारी में भी कमी हो रही है और इसका अर्थ यह है कि दल के सदस्यों की

... संख्या में

संख्या में और भी कमी होगी। पश्चिमी जर्मनी में, जहां विदेश विभाग ने साम्यवादी दल के सदस्यों की संख्या का अनुमान दो लाख लगाया है, हाल की घटनाओं से मालूम होता है कि एक स्तालिन विरोधी आन्दोलन बल पकड़ रहा है और साम्यवादी दल के सामने एक गम्भीर खतरे के रूप में खड़ा है।

साम्यवादी दल की शक्ति का यह संक्षिप्त अवलोकन ऐसे समय किया जा रहा है जब पश्चिमी योरप में साम्यवादी शक्ति पतन के कई चिन्ह प्रकट कर रही है। पर हमें भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो साम्यवादी शक्ति के पतन का परिचय देने वाली कुछ संख्याएं दी हैं। पर संख्याओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है यह बात कि पश्चिमी योरप के उन दो देशों में जहां साम्यवाद सबसे अधिक शक्तिशाली है, अर्थात् फ्रांस और इटली में, राष्ट्रीय साम्यवादी दलों ने अपनी अपनी श्रेणी के बाहर कामकाजियों की एक बड़ी शाखा को प्रभावित करने की शक्ति खो दी है।

फ्रांस और इटली में, जहां अमेरिकन शस्त्रास्त्रों से लदे हुए जहाज़ों से माल उतारने के विरूद्ध एक तगड़ा आन्दोलन १९४९ और १९५० में दोनों देशों के साम्यवादी दलों और कामिन्फार्म के पूरे बल और साधनों से किया गया था, सफलता पास न आ सकी। जनमत ने, जिसे साम्यवादी नेताओं ने 'जगाने' का प्रयत्न किया था, कोई अनुकूल जवाब नहीं दिया।

यह असफलता पश्चिमी योरप में साम्यवादी प्रभाव के पतन की एकमात्र परिचायक यद्यपि नहीं पर एक बड़ी अर्थपूर्ण बात अवश्य है।

N.E.H.47

सोवियट के उद्देश्यों में सन्देह

"साम्यवादियों ने रूस के मुस्लिम प्रतिनिधियों को मोतापर (विश्व इस्लामी कांग्रेस) में सम्मिलित न होने देकर हमारे भाइयों की स्वतन्त्रता पर प्रहार किया है। इस कृत्य ने मुस्लिमजगत को सोवियट उद्देश्यों के प्रति सन्देहग्रस्त बना दिया है और सोवियट यूनियन के मुस्लिम निवासियों के प्रति व्यवहार की ओर से चिंतित", ये शब्द "मुस्लिम भ्रातृत्व" के एक प्रमुख सदस्य, सय्यद मुहम्मद मुबारक, ने, जो सीरिया के जनकार्य मन्त्री हैं, हाल में कराची में हुए सम्मेलन के प्रति सोवियट रूख पर प्रकाश डालते हुए कहे थे।

H.S.15B

भारत के लिए पैडिल स्टीमर

ग्लैसगो की एक जहाज़ निर्माण फर्म अवध तिरहुत रेलवे की गंगा नदी पर यात्री और माल सर्विस के लिए तीन पैडिल स्टीमर बना रही है। इनमें से पहली, जिसका नाम "यमुना" है, बनकर तैयार हो गई है। यह लन्दन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के आदेश के अनुसार बनाई गई है।

H.S.16

युगान्डा में सूती टेक्सटाइल उद्योग

आर्थिक उन्नति के लिये ब्रिटेन की सहायता

(ट्रेवर ब्लोर)

उपनिवेशों की आर्थिक उन्नति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये ब्रिटिश अधिकारि[यों] और प्राइवेट व्यवसायियों के संयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण इस घोषणा से सामने आया कि युगान्डा में न्यांज़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी पंजीबद्ध की गई है। यह कम्पनी, जिसके लिये सरकार और जनता ने मिलकर पन्द्रह लाख पौंड (२ करोड़ रूपये) की रकम प्रारम्भिक पूंजी के रूप में प्रदान की है, युगान्डा प्रोटेक्ट्रेट को संसार का एक महत्वपूर्ण रूई उत्पादन केन्द्र बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

प्रोटेक्ट्रेट सरकार, जिसे यह योजना लोगों के लिये बहुत लाभदायक जंची, मिली-जु[ली] प्रारम्भिक पूंजी में की छः लाख पौंड (८० लाख रूपये) रकम प्रदान करने को राज़ी हो गई थी, जबकि ब्रिटेन स्थित कैलिको प्रिन्टर्स एसोसिएशन लि० नामक कम्पनी ने साढ़े सात लाख पौंड (एक करोड़ रूपये) दिये थे और मैनचेस्टर की ब्लीचर्स एसोसिएशन लि० नामक कम्पनी ने जिन्जा स्थित एक टेक्सटाइल मिल के लिये एक लाख पौंड (१३.१३ लाख रूपये) की आर्थिक सहायता प्रस्तुत की थी। जिन्जा स्थित मिल का काम अब चालू हो गया है।

जिन्जा स्थित मिल में उत्पादन दो वर्षों के बाद प्रारम्भ हो जायेगा और तीन साल बाद इसके पूरी तरह से जम जाने पर नब्बे लाख गज़ प्रतिवर्ष की दर से कपड़ा तैयार होने लगेगा। इसमें युगान्डा की रूई का सूत कातकर कपड़ा तैयार किया जायेगा।

...यह मिल

यह मिल यूगान्डा की आर्थिक अवस्था के लिये एक तगड़ी सहायता ही नहीं बल्कि २,७०,००,००० गज़ कपड़ा प्रति वर्ष की दर से उत्पादन करने पर पांच हज़ार से छ: हज़ार अफ्रीकियों तक को धन्धा भी प्रदान करेगी।

वार्षिक ख़र्च की व्यवस्था

यूगान्डा के रूई उत्पादन उद्योग, जिसपर प्रोटेक्ट्रेट के बहुत सारे निवासी आश्रित हैं, के लिये केवल हाल का यही ब्रिटिश अंशदान नहीं है बल्कि कम्पाला से सोलह मील परे नामलांग नामक स्थान में स्थापित नया अनुसन्धान केन्द्र एक दूसरा उदाहरण है। यह केन्द्र एम्पायर काटन ग्रोइंग कार्पोरेशन दव्ारा (ब्रिटिश अफ्रीका के एक उपयुक्त अयनवृत्तीय स्थान पर रूई-उगाने की समस्याओं को हल करने के लिये) पिछले नवम्बर मास में स्थापित किया गया था जिसमें अत्यन्त उपयुक्त बीजों और कृमिनाशक पदार्थों का विकास किया जा रहा है।

इस योजना की अनुमानित लागत का आधा भाग औपनिवेशिक विकास तथा कल्याण निधियों से प्रदान किया गया था, जबकि काटन इंडस्ट्री वार मेमोरियल के ट्रस्टियों ने कार्पोरेशन को इस कार्य में सहायता पहुंचाने के लिये पच्चीस हज़ार पौंड (३.३३ लाख रूपये) का एक अनुदान प्रस्तुत किया था और इसके बाद रा काटन कमीशन ने भी मंहगाई के कारण बढ़ी हुई क़ीमतों को पूरा करने के लिये पन्द्रह हज़ार पौंड (२ लाख रूपये) का एक अनुदान दिया था।

इस योजना पर पहले दस वर्षों में अनुमानतया औसतन चालीस हज़ार पौंड (५.३३ लाख रूपये) प्रति वर्ष ख़र्च हुआ करेंगे। यह रक़म कार्पोरेशन, और केन्या, यूगान्डा, टांगानाइका, न्यासालैंड, नाइजीरिया तथा सूडान की सरकारों के अतिरिक्त औपनिवेशिक विकास तथा कल्याण निधियों से प्राप्त हो रही है।

N.E.H.48

ब्रिटिश उपनिवेशों में उच्च शिक्षा की उन्नति

लेखक,
सर हैमिल्टन फाइफ

युद्ध के सबसे अधिक कठिन दिनों में, जब ब्रिटेन के राष्ट्रीय साधनों पर अत्यधिक भार था, ब्रिटेन के करदाताओं ने औपनिवेशिक विकास और कल्याण के लिये एक विशाल धनराशि को अपनी स्वीकृति दी थी। इस विशाल धनराशि का एक काफी बड़ा भाग उच्च शिक्षा पर खर्च किया गया था। उस समय जब धनराशि के खर्च के बारे में पहले पहल स्वीकृति दी गई थी, उपनिवेशों में चार पूरे विश्वविद्यालय थे : माल्टा, हांगकांग, लंका और यरूशलम। तब से लंका एक डोमीनियन बन गया है और यरूशलम विश्वविद्यालय एक विदेशी विश्वविद्यालय है। किन्तु इस सूची में मलाया का सिंगापुर स्थित विश्वविद्यालय और पांच विश्वविद्यालय कालेज : एक ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ और चार अफ्रीका में : जोड़े गए हैं। इनमें माल्टा के लोग, हांगकांग के चीनी, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़, सूडानी और पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीकी उपनिवेशों के सब लोग सम्मिलित हैं। किन्तु आप इन सब को मिलाकर इनके विषय में एक सामान्य परिभाषा नहीं दे सकते क्योंकि इनमें बहुत पृथकता है।

पश्चिमी अफ्रीका के विश्वविद्यालय कालेजों का मुझे कुछ व्यक्तिगत ज्ञान है। एक नाइजीरिया की राजधानी लैगोस से डेढ़ सौ मील अन्दर की ओर इबादान में है और दूसरा अशिमोता में, गोल्ड कोस्ट उपनिवेश की राजधानी, आकरा, से कुछ मील बाहर

यह पूछा जा सकता है कि इन पश्चिमी अफ्रीकियों के लिए उच्च शिक्षा क्यों

... आवश्यक है

आवश्यक है। 'क्या ये लोग उच्च-शिक्षा के बिना सुखी नहीं रह सकते?', शायद आप पूछें। इसका उत्तर यह है कि यदि आप इन्हें पृथक रख सकते तो शायद यह सम्भव होता। पर पृथक इन्हें आप कर सकते नहीं। मच्छड़ और विषैली मक्खियों से लोगों को किसी हद तक बचाया जा सकता है, पर विचारों, नए विचारों, के प्रवाह पर कौन प्रतिबन्ध लगा सकता है? और पश्चिमी अफ्रीकियों के हृदय में उच्च शिक्षा की अभिलाषा काफी समय से रही है।

ये लोग साहसी यात्री हैं: सब प्रकार की नई बातें जानने की इच्छा रखते हैं। जहाज़ों में ये जगत के कोने कोने घूम आए हैं, और वापस आएं हैं नए विचारों, और नए विचारों की अभिलाषाओं, से पूर्ण होकर। और अब ऐसे व्यक्तियों के लिए जो किसी समय मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले यातायात मात्र से परिचित थे वायुयान एक परिचित वस्तु हो गई है। उधर कानो के वायुयान अड्डे पर, जहां उत्तरी नाइजीरिया सहारा की तरफ बढ़ती है, हर तरह के वायुयान हर तरह के नए विचार लाते हैं और इनके परिणामस्वरूप पश्चिम अफ्रीकियों की एक बड़ी संख्या, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आतुर, ब्रिटेन और अमेरिका पहुंचती रहती है।

शिक्षित लोगों की आवश्यकता

उपनिवेश के साधारण दैनिक जीवन को देखने से ही शिक्षित अफ्रीकियों की आवश्यकता प्रकट हो जाती है। शिक्षित चिकित्सकों और वकीलों की संख्या काफी बड़ी है, किन्तु इस संख्या में वृद्धि, विशेषतया चिकित्सकों की, निस्सन्देह आवश्यक है। इसके अतिरिक्त असैनिक सेवाओं में शिक्षित अफ्रीकियों की बड़ी आवश्यकता है। सब प्रकार के इंजीनियर और अध्यापक भी आवश्यक हैं। सचमुच, अच्छी तरह प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता सबसे अधिक है क्योंकि भविष्य इन्हीं के भरोसे है।

सब ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए निश्चित लक्ष्य अन्त में जाकर ब्रिटिश राष्ट्रसमूह के अन्दर स्वशासन की प्राप्ति है। किन्तु जबतक इन सब पेशों के लिए सुशिक्षित अफ्रीकियों का अभाव है तबतक स्वशासन या तो देर में स्थापित होगा या वह उचित समय के पहले ही शीघ्रता से विकसित हो जाएगा। मुझे निश्चय है कि इस विषय में किसी को सन्देह नहीं है कि पश्चिमी अफ्रीका में उच्च शिक्षा की ज़रूरत है और इसकी कामना वहां के नर नारी हृदय से करते हैं।

... पश्चिम अफ्रीका

पश्चिमी अफ़्रीका के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण इन विश्वविद्यालय कालेजों का मूल उद्देश्य है, अर्थात् ऐसे लोगों का निर्माण जो एक स्थिर सभ्यता की सृष्टि में सहायक हो सकें। कारण, पश्चिमी अफ़्रीका के लोग अपनी प्राकृतिक संस्कृति का विकास करने लग गए हैं और ब्रिटेन उनकी सहायता के लिए प्रयत्नशील है। ब्रिटेन का कर्तव्य है अपनी ओर से उन्हें अपनी सर्वोत्तम देन देना ताकि वे इसे अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं और रूचि के अनुरूप अपना सकें। मेरे विचार से स्वशासन की ओर प्रगति, क्रमिक रूप से और निश्चितरूप से प्रगति, बहुत अंश तक इन्हीं विश्वविद्यालय कालेजों के प्रभाव के परिणामस्वरूप हो रही है।

विश्वविद्यालय के कर्तव्य

विश्वविद्यालय एक समुदाय है। और किसी भी विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थियों के आवास की सुविधाओं से युक्त होना उसकी सामान्य भावना के हित में है। पश्चिमी अफ़्रीका के लिए तो यह नितान्त आवश्यक है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के आवास की सुविधा से सम्पूर्णतया युक्त हो। अन्यथा वह एक सच्चे समुदाय के रूप में कदापि विकसित नहीं हो सकता। इसका कारण विद्यार्थी समूह की असाधारण पृथकता है।

विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या के लिए अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अन्य कोई आम भाषा नहीं है। उनकी सामाजिक परम्पराएं, उनके सामाजिक रीति रिवाज, और उनका खानपान तक एक दूसरे से बहुत पृथक हैं। और एक साथ रहकर ही ये बड़ी पृथकता, ये बड़े अन्तर, नई समझ और नई पारस्परिक भावनाओं में परिणत हो सकते हैं। जनजाति के लोगों से ये पश्चिम अफ़्रीकी बने और अब एक राष्ट्रीय पश्चिम अफ़्रीकी संस्कृति की सृष्टि कर रहे हैं।

और कालेज के योरोपीय सदस्यों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। अपने अफ़्रीकी साथियों और विद्यार्थियों के साथ समान स्तर पर रहकर वे एक शास्त्रीय समुदाय के सच्चे सदस्य बन सकते हैं।

मैं इससाभान्य शास्त्रीय जीवन के महत्व पर ज़ोर इसलिये दे रहा हूं क्योंकि यह भाषणों, कक्षा के अध्ययनों और प्रयोगशाला के अभ्यासों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उन स्नातकों के विकास और उन्नति में जो ब्रिटिश राष्ट्रसमूह के अन्दर स्वशासन की क्रमिक स्थापना में एक दायित्वपूर्ण भाग लेंगे। और यही विश्वविद्यालय कालेजों का मुख्य कर्तव्य होता है।

... विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय कालेज डिग्री नहीं प्रदान कर सकता । विश्वविद्यालय कालेज विश्वविद्यालय जीवन प्रदान करता है, और लन्दन विश्वविद्यालय डिग्रियों के लिए शिक्षाक्रम ।

पिछले समयों में कई अफ़्रीकियों ने अपनी बाहरी डिग्री लन्दन में ली थी और उनके पाठ्यक्रम बिल्कुल वैसे ही थे जैसेकि एक अंग्रेज़ी विद्यार्थी के होते हैं । अब लन्दन विश्वविद्यालय ने, जिसने इन कालेजों की स्थापना में सदैव एक सजीव और प्रमुख भाग लिया है, एक बहुत अच्छा नया प्रबन्ध किया है । अब वह एक औपनिवेशिक कालेज को "विशेष सम्बन्ध" में इस शर्त पर सम्मिलित कर सकता है कि कालेज पूर्णतया स्वायत्त है, अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है और वह अध्ययन की उचित अवस्था प्रदान करता है । ऐसी अवस्था में वह एक विश्वविद्यालय कालेज बन जाता है और औपनिवेशिक विकास तथा कल्याण निधि से पूंजीगत अनुदान का अधिकारी बन जाता है । चालू खर्च शुल्कों और स्थानीय सरकारों के अनुदानों से चलाए जाते हैं ।

इस विशेष प्रबन्ध का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि उपनिवेशों के प्रोफेसर ऐसे किसी विषय में जिसके लिये वे वांछनीय समझते हों एक विशेष पाठ्यक्रम का प्रस्ताव लन्दन विश्वविद्यालय के सामने उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर सकते हैं । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय कालेजों के अध्यापकों के साथ मिलकर लन्दन परीक्षापत्र बनाने और उन्हें जांचने के काम में भाग लेता है । यों अफ़्रीकियों को कला, विज्ञान और औषधिशास्त्र के विभागों में लन्दन विश्वविद्यालय की पहली डिग्री स्वयं अपने देश में प्राप्त करने का अवसर मिलता है । यों कालेज के अध्यापकगण और विद्यार्थी शनै शनै उस अत्यन्त उच्चस्तर के कार्य का अभ्यास प्राप्त कर लेते हैं जो विश्व ख्याति की डिग्री पाने के लिये आवश्यक होता है ।

समय के बीतने पर ये कालेज विश्वविद्यालय कालेजों से विश्वविद्यालयों में परिवर्तित हो जाएंगे, ये अपनी डिग्रियां स्वयं देंगे : लन्दन या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय जैसे स्तर की डिग्रियां । तबतक ये पूर्णतया अफ़्रीकी विश्वविद्यालय बन जाएंगे, ये स्वयं अपने डिग्री पाठ्यक्रमों का निर्माण करेंगे और इनके अध्यापक समूहों में सब या अधिकांश अफ़्रीकी होंगे । तब ये एक विश्वविद्यालय के सच्चे उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे : ज्ञान का संरक्षण, विस्तार और संचार, दायित्वपूर्ण सार्वजनिक आलोचना का कार्य, और विद्यार्थियों में ज्ञान पिपासा का विकास तथा बुद्धि, नैतिकता और चरित्र के ऊंचे स्तर की स्थापना ।

जनसंख्या में वृद्धि और भारत की खाद्य परिस्थिति

'टाइम्स' की सम्मति

'भारत की जनसंख्या' शीर्षक से लन्दन 'टाइम्स' ने भारत की नवीनतम जनगणना की कुछ संख्याओं को उद्धृत कर जनसंख्या में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस विशाल जनसंख्या के भरण पोषण से देश के साधनों पर इतना अधिक भार पड़ेगा कि जीवनयापन में सुधार के लिए साधनों की उपलब्धि कठिन हो जाएगी।

वर्तमान खाद्य संकट से पहले भारत की सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक चार वर्ष योजना कार्यान्वित की थी और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत नई स्कीमें चालू की थीं किन्तु सफलता में दुर्भाग्यों ने बाधाएं डाल दीं। वर्तमान संकट के कारण भारत सरकार को विवश होकर जिस किसी देश के पास खाद्य सामग्री देने का सामर्थ्य है उससे खरीदना पड़ा है।

कई देश भारत की सहायता के लिये जो कुछ भी सम्भव हो कर रहे हैं और भारत की संसद में इस देश के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है।

पत्र का ख्याल है कि चाहे वर्तमान संकट पार भी किया जा सके जनसंख्या की विशालता कोलम्बो योजना और राष्ट्रपति ट्रूमन के चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम की तात्कालिक आवश्यकता प्रकट करती है। यदि भारत सरकार की उन योजनाओं को जिन्हें वह प्रारम्भ करने वाली है और जिन्हें वर्तमान वैज्ञानिक आविष्कार का योग आवश्यक होगा सफल होना है तो सहायता नितान्त आवश्यक है। जनता की उत्पादन क्षमता में उन्नति इन योजनाओं का लक्ष्य है।

म हो त्स व का उ द् घा ट न

राष्ट्रव्यापी प्रयास

"भूत का अभिमान —— भविष्य में विश्वास"

तीसरी मई को ब्रिटिश महोत्सव का उद्घाटन हुआ , उद्घाटन हुआ प्रदर्शिनियों की एक श्रृंखला का , कला और संगीत समारोहों का और कई अर्थपूर्ण घटनाओं के क्रम का । पांच महीनों तक ब्रिटेन के लोग संसार के विभिन्न कोनों से आने वालों की आवभगत करेंगे ।

<u>ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति संकलन</u> :

लन्दन के "टाइम्स" ने लिखा है कि ब्रिटेन को इस समय परीक्षा में प्रवेश होने से चाहे जितनी भी घबराहट हो रही हो पर ब्रिटेन ने दर्शकों को यह दिखाने का निश्चय कर लिया है कि १९५१ में उसकी भावनाएं क्या हैं और भविष्य की ओर वह किन किन भावनाओं से देख रहा है । इस मामले में पहले के अनुभव हमारे पथप्रदर्शक नहीं बन सकते , क्योंकि पहले की विशाल प्रदर्शिनियां अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में हुई थीं ।

"मैनचेस्टर गार्जियन" के मत में एक विचार हमारे जीवनों में अधिकाधिक भाग ले रहा है और वह इस महोत्सव में व्यक्त है । विचार यह है कि कलाएं हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण अंग हैं और इनका रसास्वादन केवल इनेगिने वर्ग नहीं पर उन सबको कर सकना चाहिये जो करना चाहते हैं । यदि लन्दन की प्रदर्शिनी महोत्सव का हृदय है तो उसका शेष शरीर सारे देश में फैला हुआ है । और यह एक कोरी प्रदर्शिनी " भी

... नहीं है

नहीं है। यह उन चीज़ों का विशाल रूप है जो हमारे समाज के निरन्तर अंग बन गए हैं।

"डेली टेलीग्राफ" ने ब्रिटेन की वित्तीय और आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हाल के वर्षों में किसी अन्य स्वतन्त्र राष्ट्र को उतना चिंतित नहीं होना पड़ा जितना कि ब्रिटेन। और हम यह निश्चय के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने खेलों का सामना जितनी खुशी के साथ किया है उतना अन्य किसी ने नहीं। महोत्सव के ज़रिए हम एक दूसरे को इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि अभी भी हम अपने पैरों पर खड़े हैं, कि हमने कई सफलताएं प्राप्त की हैं और प्राप्त कर रहे हैं।

"डेली मेल" ने ब्रिटेन के गौरवमय अतीत का अभिमान के साथ उल्लेख करते हुए लिखा है कि कोरिया में चीनी प्रवाह को रोकने वाले ब्रिटिश सैनिकों की सफलता और उनकी वीरता उन सफलताओं का एक अंश है जिनका समारोह महोत्सव में किया जा रहा है।

परिवार के भविष्य का प्रश्न

'गृहस्थी' की समाप्ति —— साम्यवाद का प्रयोजन

फ्रैंसिस वाटसन

एकबार जब मैंने युद्ध के बाद इंग्लैंड में एक छोटे से परिवार की देखभाल का दायित्व सम्हालने की सोची थी तब मैं सहसा यह भी सोचने लगा कि इस परिवर्तनशील संसार में विवाह और परिवार के विषय में राजनैतिक पंडितों और समाजशास्त्रियों के विचार भला क्या होंगे। जब मेरा ध्यान साम्यवादी सिद्धान्तों की ओर गया तो इन शब्दों को पढ़कर मैं आश्चर्य में डूब गया :

> इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'मेरे माता पिता', 'मेरे बच्चे', इत्यादि शब्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और इनके स्थान में हम 'बूढ़े लोग', 'प्रौढ़', 'बच्चे', इत्यादि कहने लगेंगे।

साम्यवादी समाज सम्बन्धी ये विचार लगभग २० वर्ष पहले लुनाचारस्की नामक व्यक्ति ने, जो किसी समय सोवियट रूस में शिक्षा अधिकारी थे, व्यक्त किए थे। पर इनसे पश्चिमी जनतन्त्रों की प्रवृत्ति : शायद ब्रिटिश 'जनकल्याण राज्य' की विशेषतया : की ओर ध्यान जाता है। आज के ब्रिटेन में पारिवारिक जीवन में सरकार का जितना हाथ है उसे देखकर हमारे पूर्वज हैरान हो जाते। क्या राशन की व्यवस्था, क्या बीमा कार्ड, क्या यह और क्या वह। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि यह सब कहां जाकर समाप्त होगा। पर वास्तव में जनतन्त्रों का ढंग साम्यवाद के ढंग से भिन्न है, सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में।

...राज्य द्वारा

राज्य द्वारा संचालित सेवाएं (यद्यपि एक स्वतन्त्र समाज में इनके आलोचक होते हैं) परिवार को शिथिल करने या शक्तिहीन करने के उद्देश्य से नहीं पर बलशाली बनाने के उद्देश्य से प्रेरित दीखती हैं। कामकाजियों और स्कूली बच्चों के लिये संयुक्त भोजन का प्रबन्ध उस 'गृहस्थी की गुलामी' पर आक्रमण का केवल एक अंग है जिसकी कड़ी आलोचना लेनिन ने की थी , पर जिसे समझे वे नहीं थे । घर के कामकाज में परिश्रम को घटाने वाली युक्तियों की निरन्तर खोज और उनमें नूतन विकास द्वारा पूंजीवादी प्रयास इस आक्रमण का दूसरा अंग प्रस्तुत करता है। ऐसी युक्तियों के प्रसंग में हम ब्रिटेन के जन प्राधिकारियों द्वारा लोगों के निवासस्थान के प्रबन्ध का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते । पर जहां लुनाचारस्की ने परिवार के अन्त की आशा की थी वहां जनतन्त्रवादी समाज में जीवनयापन की समस्याओं को सुलझाने में सारा ज़ोर परिवार के अस्तित्व पर दिया जाता है। न ही इस बात के लक्षण हैं कि 'मेरे पिता और माता' और 'मेरे बच्चे' जैसे शब्दों को हटने का प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वयं रूसियों ने अनुभव से सीखा है कि 'भागो' कहने भर से ये शब्द नहीं भागते और मालूम ऐसा होता है कि मनुष्यमात्र की आन्तरिक भावनाओं का मुकाबला करने पर कई साम्यवादी 'सुधारों' को मार्ग बदलना या स्थगित होना पड़ा ।

विवाहित सम्बन्धों की कठिनाइयां

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि पश्चिम में विवाहित सम्बन्धों को कई कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं , और ये हमारे देश की जनतन्त्रवादी संस्थाओं की कठिनाइयों से विपरीत नहीं हैं। विवाह सम्बन्धों ने विवशता की अवस्था से अधिक ऐच्छिक सम्बन्ध बनने के मार्ग में उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना किया जो ऐसे परिवर्तन में निहित होती हैं। बात केवल यह नहीं है कि विवाहित सम्बन्धों के विच्छेद में पहले से अधिक सरलता के कारण कानूनी बन्धन कमज़ोर हुये और विवाहितों पर अधिक उत्तरदायित्व पड़ा पर आज सब प्रकार के पारिवारिक रिश्ते , रीति रिवाजों की रोक से अधिक मुक्त हैं — इनमें माता पिता के साथ सन्तान के सम्बन्ध भी सम्मिलित हैं। सबसे अधिक स्पष्ट कठिनाई आर्थिक कठिनाई हो सकती है पर वह एकमात्र कठिनाई नहीं है।

यद्यपि शारीरिक दृष्टि से प्राय: कम आयु में विवाह का [illegible] किया जाता है पर आर्थिक सूझ बूझ के कारण और बढ़ते हुए मूल्यों की बला से बचने के लिये बहुतेरे नवयुवक और नवयुवतियां विवाह में विलम्ब करती हैं। इसीलिए, अर्थात् परिवार की आय बढ़ाने

... के लिए

के लिए, वे दोनों रोज़ी खोजते हैं। इसी बात से विवाह असफल न होने चाहिए पर गृहस्थी के निर्माण और परिवार के पोषण के लिए आपत्तियां इससे अवश्य उत्पन्न होती हैं।

ऐसी चिन्ताएं जटिल समाजों की विशेषताएं हैं। सीधेसादे और प्रधानतया कृषिकर्म करने वाले समुदायों में पत्नी और बच्चे अनावश्यक होना तो दूर आर्थिक निधियां होते है; उत्पत्ति और आय में उन्नति के लिए सहायक। जहां परिवार के पालन पोषण का खर्च मिलीजुली आय से अधिक होता है वहां ऐसे आर्थिक रोग का आविर्भाव होता है जिसका उपचार करना आवश्यक हो जाता है। रहनसहन के स्तर में सुधार इस रोग का उपचार है : इसी उपचार को संसार के स्वतन्त्र राष्ट्र संयुक्तरूप में कर रहे हैं। हां, यदि इसी समय उन्हें आक्रमण से बचाव की तैयारियां भी न करनी पड़तीं तो उपचार के इस कार्य में वे अधिक उन्नति कर पाते।

अन्य बातें

अमेरिका में, जहां मनुष्य की मेहनत और सूझबूझ तथा अधिक विशाल प्राकृतिक सम्पत्ति की सहायता से, जीवनयापन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक उन्नत है, परिवार की समस्याएं आज आर्थिक दृष्टि से नहीं किन्तु अन्य दृष्टियों से देखी जाती हैं।

और साम्यवाद के आदर्शों की अवस्था क्या है, वही जिन्होंने किसी समय बड़े सुनहरे स्वप्न दिखाए थे? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं : १. साम्यवाद के मानवीय सिद्धान्त मनुष्य की स्वतन्त्रता के विरोधी आर्थिक सिद्धान्तों के कारण मिट गए। आर्थिक कार्यपटुता के नाम पर गृहस्थी को गायब होना है और सामूहिकवाद को लेना है उस परिवार का स्थान जिसने अपनी भूमि की सेवा की और शताब्दियों से जिसके मालिक बनने की कामना अपने मन में लिए हुए है। २. साम्यवाद ने एक ऐसा पुलिस राज्य स्थापित किया है, एक ऐसी तानाशाही, जो विश्व की सबसे अधिक विशाल, सबसे अधिक कठोरतया नियंत्रित, तानाशाही है।

इसका अर्थ यह है कि, हिटलरशाही जर्मनी की भांति, राजनैतिक राज्यभक्ति पारिवारिक बन्धनों से अधिक बड़ी मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि परिवार की चिन्ताओं में कमी के कारण उत्पन्न होने वाले अवकाश का उपयोग मस्तिष्क के मुक्त प्रयोग और रचनात्मक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। एक ऐसा केन्द्रीय राजनैतिक नियन्त्रण है इसका अर्थ जिसपर सुरक्षा का भूत इतना अधिक सवार है कि युद्धकाल में

... विदेशियों

विदेशियों (और वह भी साथी राष्ट्रों के लोगों) से विवाह करने वाली महिलाएं अपने पतियों के साथ रहने के लिए वापस नहीं जा सकतीं, कि पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी नेता, ओटो ग्राटवाल, अपने बच्चों की माता को छोड़कर सरकार द्वारा नियुक्त अपनी सेक्रेटरी से विवाह करने के लिये साम्यवादी दल द्वारा विवश किए जा सकते हैं, कि साम्यवादी न्याय किसी की आज्ञाकारिता निश्चित करने के लिए उसके परिवार को बन्धक की तौर पर प्रयुक्त करना बुरा नहीं समझता।

एक बात और। जनतन्त्रवादी देशों में लोकप्रिय भावनाओं का लिहाज़ करने वाले स्वतन्त्र समाचारपत्रादि परिवार के हितों और गृहस्थी की भावनाओं में गहरी अभिरुचि रखते हैं। किन्तु साम्यवाद के अन्तर्गत नौकरशाही पर ऐसा कोई नियन्त्रण असम्भव है। फिर भी, अपनी तरफ से लड़ने वाले के न होने पर भी, परिवार अपनी जीवित रहने की शक्ति सिद्ध कर सकता है —— जैसे पहले वैसे अब।

H/L.P.S.218

चीन के साथ ब्रिटेन का व्यापार

चीन के साथ ब्रिटेन के व्यापार के विषय में व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सर हार्टले शाक्रास, के वक्तव्य पर "टाइम्स" ने लिखा है : सर हार्टले शाक्रास के वक्तव्य से मालूम होता है कि संयुक्त राष्ट्रों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर चीन के साथ व्यापार विषयक सरकार की नीति उचित है और उसके विरुद्ध अमेरिका में कही गई कुछ बातें अनुचित ।

आगे चलकर पत्र ने लिखा है : यद्यपि पिछले वर्ष चीन के साथ ब्रिटेन का व्यापार बढ़ा था पर सरकार ने युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण सारी सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी है : और ऐसी अन्य चीज़ों पर भी जो चीन को कोरिया में सामरिक कार्रवाइयों में सहायक हो सकती हैं। केवल एकमात्र अपवाद : मलाया से रबड़ के निर्यात में बड़ी वृद्धि : अब रोक दिया गया है : यद्यपि चीन अपनी आवश्यकता की रबड़ अन्यत्र खरीद सकेगा।

हांगकांग के मामले को अधिक पेचीदा बताते हुए पत्र ने लिखा है : नियन्त्रण की बड़ी कठिनाइयों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष के प्रथम तीन मासों में हांगकांग द्वारा चीन को बिक्री मूल्य की दृष्टि से १९५० के प्रथम तीन महीनों की तुलना में आधे से भी कम थी और इसमें न पेट्रोलियम के पदार्थ थे, न वायुयान और युद्धसामग्रियां जैसी प्रत्यक्ष सामरिक महत्व की चीज़ें ।

यह कहने के बाद कि अमेरिका के बहु संख्यक लोगों के अनुसार चीन के साथ सब प्रकार का व्यापार अनैतिक है, पत्र ने बताया है कि इस विषय में दृष्टिकोणों के अन्तर से सुदूरपूर्व और चीन की सारी समस्या पर ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारों की विभिन्न नीतियां प्रकट होती हैं। ब्रिटिश सरकार चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दे

... चुकी है

चुकी है और उसे अभी भी आशा है कि कोरिया के युद्ध के बारे में वह चीन को बातचीत के ज़रिए समझौते पर राज़ी कर सकेगी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार चीन के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध : जहांतक सम्मान और सुरक्षा को हानि पहुंचाए बिना ऐसा सम्भव हो : जारी रखने की इच्छुक है । इसके विपरीत , अमेरिका की सरकार चीन के साम्यवादियों को अपना असाध्य विरोधी मानती है। इसलिये अमेरिका की सरकार का चीन के साथ व्यापार पर पूरी प्रतिबन्ध लगाना तर्कयुक्त है।

इसके बाद पत्र ने वाशिंगटन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करते हुये अमेरिका को आश्वासन दिया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र चीन पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय करते हैं या ब्रिटिश सरकार और जनता को निश्चय होता है कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई नीति सम्भव नहीं है तो यह देश नाकाबन्दी को यथासाध्य प्रभावदायक बनाने का प्रयत्न करेगा ।

H/L.P.S.220

ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति संकलन :

ईरानी तेल का प्रश्न

वैधानिक और व्यावहारिक पहलू

"डेली हेरल्ड" ने १० मई के अंक में लिखा है : उस पत्र में जो फारस की सरकार ने ब्रिटिश विदेश मन्त्री को दिया है, दो बातें उठाई गई हैं। एक कानूनी है और दूसरी व्यावहारिक। कानूनी अंग के बारे में फारस का कहना है कि राज्यक्षेत्र के अन्दर किसी भी उद्योग और किसी भी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण संसद के सर्वोच्च अधिकारों के अन्तर्गत है और संसद का यह अधिकार समझौतों इत्यादि से उत्पन्न होने वाले अधिकारों से ऊपर है।

इसके विपरीत, ऐंग्लो ईरानी कम्पनी कह सकती है कि १९३३ के समझौते में फारस की सरकार ने इस आशय का स्पष्ट वचन दिया था कि नई सुविधाओं की शर्तें किसी भावी संसद द्वारा भी रद नहीं की जा सकेंगी।

और समस्या के व्यावहारिक अंग क्या हैं ? १. क्या फारस की सरकार ऐसे किसी समझौते के लिए तैयार है जिससे तेल के उत्पादन और शोधन को कार्यकुशलता से करना जारी रखा जा सकता है। २. क्या वह यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि तेल अभी भी पुराने ग्राहकों के हाथों उचित शर्तों पर बेचा जाएगा। ३. क्या वह ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी को, उसकी महत्वपूर्ण सम्पत्ति के अपहरण के लिए, उचित

... क्षतिपूर्ति देने

क्षतिपूर्ति देने की इच्छा रखती है । पत्र के अनुसार इन प्रश्नों की दृष्टि से फारस सरकार का पत्र सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता । उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है।

"डेली टेलीग्राफ" : श्री० मारिसन के प्रति डाक्टर मुसद्दीक के सन्देश और फारस के विदेश मन्त्री की बातों से प्रकट होता है कि फारस की सरकार को अब जाकर मालूम हुआ है कि उस तेल उद्योग का , जिसका अपहरण उसने किया है , संचालन वह अकेले नहीं कर सकती। पर इन दोनों वक्तव्यों में से कोई यह नहीं दिखाता कि यह जानकारी फारस की सरकार को उसके अवैधानिक मार्ग से हटाने वाली है। और उसका मार्ग तो निस्सन्देह अवैधानिक है। प्रधान मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रत्येक वैधानिक अंग की दृष्टि से ऐंग्लो ईरानी कम्पनी की सुविधाएं "उचित" हो सकती हैं।

तब, पत्र पूछता है , उसके एकपक्षीय उल्लंघन का फारस को क्या अधिकार है?

N.E.H.49

'वी ट मि न्ह की वा णी'

'इन्डोचाइना में साम्यवादियों की वाणी', वीटमिन्ह रेडियो, से प्रसारित सामग्री का अधिकांश भाग मार्क्सवादी राजनैतिक विषयों से सम्बन्ध रखता है। पश्चिम सम्बन्धी समाचारों में केवल आर्थिक आपत्तियों और हड़तालों का हाल दिया जाता है। कुछ समय पहले वीटमिन्ह रेडियो ने बताया था कि साम्यवादी विश्व शांति आन्दोलन में वीटमिन्ह के लोग रुचि रखते हैं और उसका समर्थन करते हैं। इनकी दयालुता का दृष्टान्त देते हुए रेडियो वीटमिन्ह ने कहा था कि फ्रांस के बन्दी रेड क्रास को वापस कर दिये गये हैं। किन्तु यह बताते हुए कि वीटमिन्ह के कुछ सैनिकों ने देश वापस आने से इन्कार कर दिया है रेडियो अपनी परेशानी छिपा न सका। उसकी परेशानी उस समय भी प्रकट थी जब, आगे चलकर, एक ब्राडकास्ट में उसने वीटमिन्ह की सरकार द्वारा आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया था। नई राष्ट्रीय वीटनाम सेना के विकास ने रेडियो पर कई आक्षेपों को अवसर दिया है। साथ ही साथ इस आशय की घोषणा की गई थी कि होचिमिन्ह ने शस्त्रास्त्रों और युद्ध सामग्रियों के उपयोग में कम खर्च का आदेश दिया है। अन्त में, रेडियो वीटमिन्ह ने युवकों से अपील की कि वे 'टेनिस और फुटबाल जैसी बेकार चीज़ों में' न फसें।

H.S.17/51

लो अर सै क्सो नी के नि र्वा च न

लोअर सैक्सोनी के निर्वाचनों पर, जिसमें नए नाज़ी समाजवादी रीश दल को ग्यारह प्रतिशत वोट और लैन्टाग में सोलह स्थान मिले थे टाइम्स ने १० मई के अंक में लिखा है : जर्मनी में सदैव कई पक्के नाज़ी रहे हैं और घटनाओं ने इन सबको जनतन्त्रवादी नहीं बना डाला। युद्ध के बाद ये शान्त इसलिये थे क्योंकि तब शांत रहने में भी भलाई थी। अब वे बाहर आ रहे हैं, शायद जनतन्त्रवादी दलों की कमज़ोरियों और संसार की गतिविधि से प्रोत्साहित होकर।

... पत्र ने

पत्र ने आगे चलकर नए दल की प्राइवेट सेना पर प्रतिबन्ध लगाने की फेडरल सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है और कहा है कि अब फेडरल सरकार स्वयं इस दल को बन्द करने की बात गम्भीरतापूर्वक सोच रही है । "जनतन्त्र की रक्षा के ऐसे स्वस्थ संकल्प को निरूत्साहित न करना चाहिये ।" पत्र ने केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने और एक विश्वसनीय फेडरल पुलिस दल की रचना की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है । इससे भी अधिक आवश्यक, "टाइम्स" के अनुसार है जर्मनी के जनतन्त्रवादी दलों को पुष्ट करना और रिपब्लिक को इस नए नाज़ीवाद से बचाना ।

H.S.18/51

मद्रास में ब्रिटेन के नए उप हाई कमिश्नर

स्वर्गीय जे० डब्ल्यू० डी लाकर के स्थान में श्री० जार्ज एडमन्ड क्राम्बी, सी०एम० जी०, मद्रास में ब्रिटेन के नए उप हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं । श्री० क्राम्बी २३ जून को नई दिल्ली आने वाले हैं और उसके कुछ दिनों बाद मद्रास में अपना नया कार्यभार सम्हालेंगे ।

H.S.18B/51

ब्रिटिश महोत्सव का उद्घाटन

लन्दन में ब्रिटिश महोत्सव का मुख्य भाग, थेम्स नदी के दक्षिण तट की प्रदर्शिनी, का उद्घाटन शुक्रवार, मई चार को हुआ था । प्रात:काल प्रदर्शिनी के प्रथम दर्शकों में सम्राट और साम्राज्ञी थीं । इनके साथ राजपरिवार के अन्य सदस्य भी थे । इस विशेष प्रात:कालीन पूर्वदर्शन में ब्रिटिश सरकार और विरोधी पक्ष के सदस्य और कूटनीतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।
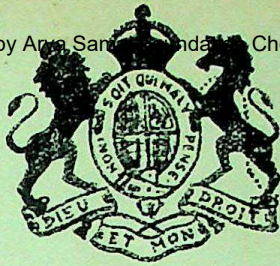
BRITISH INFORMATION SERVICES

FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

May 27 to June 9, 1951.

HINDI

ब्रिटिश महोत्सव में भारतीयों की अभिरुचि

लेखक,
जी० डानॉड टेलर

थेम्स नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित प्रदर्शिनी में, जो ब्रिटिश महोत्सव का मुख्य भाग है, प्रतिदिन हज़ारों आगन्तुक आया करते हैं।

अबतक विदेशी आगन्तुकों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान सबसे ऊपर है।

पाकिस्तान और लंका भी आगन्तुकों की संख्या की सूची में अच्छा स्थान रखते हैं। आगन्तुकों में से अधिकांश अपने अपने अवकाश के समयों को बिताने के लिये आये हुये वे लोग हैं जो महोत्सव के इस वर्ष में ब्रिटेन की महिमा देखना चाहते हैं। अन्य लोग सरकारी कामों पर आये हैं पर महोत्सव को देखने के लिये समय निकाल सके हैं। सबसे प्रारंभिक आगन्तुकों में भारत के शिक्षा मन्त्री, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, का नाम उल्लेखनीय है। क्योंकि उनके पास एक सम्पूर्ण कार्यक्रम में से अलग निकालने के लिये समय बहुत थोड़ा था इसलिये उन्होंने प्रदर्शिनी में आते ही यह निश्चय कर लिया था कि क्या क्या देखेंगे। आते ही मौलाना आज़ाद "नए स्कूल" नामक भाग में गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह केवल एक सुन्दर प्रदर्शिनी ही नहीं है पर एक बहुत शिक्षाप्रद स्थान भी। इस भाग में शिक्षा की उन साधन सामग्रियों का दिग्दर्शन कराया गया है जो बच्चों की शिक्षा से पूर्णतया लाभ उठाने में सहायता देने के लिये आजकल प्रयुक्त की जा रही है।

इसके बाद मौलाना आज़ाद ने पांच छोटी चित्रमय प्रदर्शिनियां देखीं, जिनमें से प्रत्येक में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के पृथक अंगों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया था।

> पिछले पांच वर्षों में ब्रिटेन ने इतनी अधिक उन्नति की है कि यदि आप युद्ध की हानियों को ढूंढने निकलें तो दूसरी बात है अन्यथा आप कही नहीं सकते कि युद्ध भी हुआ था। मौलाना आज़ाद

माध्यमिक

माध्यमिक शिक्षा की शाखा में चार छोटी छोटी प्रदर्शिनियों द्वारा माध्यमिक, व्याकरण और टक्निकल स्कूलों तथा ग्राम और नगर के आधुनिक माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषयों का सन्तुलन दिखाया गया है । इस शाखा का विस्तृत निरीक्षण करने के बाद मौलाना आज़ाद ने प्रदर्शिनी की अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा ।

H.S.25/51

लन्दन में
भारतीय स्वास्थ्य मंत्रिणी का स्वागत

कुछ समय पहले भारत की स्वास्थ्य मंत्रिणी, राजकुमारी अमृतकौर, का लन्दन में महिला परिषद (विमेन्स कौंसिल) द्वारा स्वागत किया गया था । स्वागत करने वाली महिलाओं में लेडी रजेर्टन और लेडी हार्टिंग (परिषद की उपाध्यक्षाएँ) थीं। लगभग २०० व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें भारत, पाकिस्तान, लंका और आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी थे ।

राजकुमारी अमृतकौर ने भारत के वर्तमान खाद्य संकट में "गहरी सहानुभूति" दिखाने के लिये ब्रिटिश महिलाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । उन्होंने कहा कि यद्यपि ब्रिटेन भारत को खाद्य सामग्री नहीं भेज सकता था पर उसने अन्य देशों से खाद्य भारत पहुंचाने के लिये जहाज़ के रूप में सहायता की ।

राजकुमारी अमृतकौर ने पांचवीं जून को रेडियो द्वारा प्रसारित एक भाषण में यह कहा कि राजनैतिक स्वातन्त्र्य प्राप्त करने के बाद से भारत ने जो अनेक आपत्तियां उठाई हैं उनमें ब्रिटेन ने गहरी सहानुभूति दिखाई है । इस प्रसंग में उन्होंने भारत की खाद्य समस्या के अत्यधिक गम्भीर हो जाने के समय से ब्रिटेन की सहानुभूति का विशेष उल्लेख किया ।

अन्त में स्वास्थ्य मंत्रिणी ने भारत के वर्तमान खाद्य अभाव पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कमी के कारणों का विवेचन किया ।

H.S.26

भारत का खाद्य संकट

ब्रिटिश पत्रों का मत

५ जून के अंक में 'टाइम्स' और 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर श्री० कृष्ण मेनन द्वारा चौथी जून को लन्दन के प्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन में बताई गई बातों का विशेषतया उल्लेख करते हुए भारत की खाद्य परिस्थिति पर सम्पादकीय लेख लिखे हैं :

'टाइम्स' : इस देश में जैसे ही यह मालूम हुआ कि इन गर्मियों में भारत को एक गम्भीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा, ब्रिटिश लोग सब सम्भव सहायता देने के लिए उत्सुक हो गए। सरकार ने आस्ट्रेलिया का गेहूं, जो भारत एक लम्बी अवधि के आधार पर लौटा सकता है, उपलब्ध कराया और जहाज़ी यातायात की सुविधा भी प्रदान की ताकि भारतीय खाद्य मन्त्रालय द्वारा विदेशों में खरीदे जाने वाले चालीस लाख टन खाद्यान्नों में से लगभग ६० प्रतिशत को ढोया जा सके। इसके बाद पत्र ने सहायता देने के लिये इच्छुक व्यक्तिगत नागरिकों को दिए गए अवसरों का उल्लेख किया और लिखा है : अपने मामलों को स्वयं सम्हाल सकने की योग्यता में भारतीय स्वाभाविकतया गर्व करते हैं। यद्यपि भारतीय प्रवक्ता कुछ क्षेत्रों, विशेषतया बिहार, की खाद्य अवस्था की गम्भीरता छिपाने के प्रयत्न नहीं करते पर वे बल देकर कहते हैं कि भारतीय सरकार संकटकाल का सामना सफलता और स्फूर्ति के साथ कर रही है।

चाहे अन्त में यह बात सत्य सिद्ध हो — जैसा कि भारतीय सरकार को भरोसा है — कि वास्तविक भुखमरी से मृत्यु की घटना कोई न हो या बहुत कम पर यातना निश्चय ही एक बड़े पैमाने पर होगी। इसलिये दवाइयों, टिनों में बन्द खाद्य सामग्रियों और अन्य छोटी मोटी चीज़ों की आवश्यकता उत्पन्न होगी। जो कुछ भी सहायता यह देश भेज सके उसका स्वागत किया जाएगा।

... मैनचेस्टर गार्जियन

"मैनचेस्टर गार्जियन" ने खाद्यान्नों के लिये समुद्री यातायात के लिये ब्रिटेन द्वारा दी गई सहायता और उस सहायता की ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर की प्रशंसा का उल्लेख करने के बाद लिखा है कि यद्यपि अनावश्यक चिन्ता न उत्पन्न करने की भारतीय सरकार की इच्छा समझी जा सकती है पर वास्तविक बातों की यथासम्भव सम्पूर्ण जानकारी बहुत महत्वपूर्ण बात है । वास्तविक बातें ही सहायता को प्रोत्साहन और प्रेरणा दे सकती हैं ।

H.S.27

ब्रिटिश कौंसिल की छात्रवृत्तियां

चार भारतीयों के अध्ययन की अवधि अधिक हुई

१९५० - ५१ के शैक्षणिक वर्ष के लिये ब्रिटिश कौंसिल की छात्रवृत्ति प्राप्त चार भारतीय अनुसन्धानकर्ताओं के अध्ययन की अवधि, उनके अबतक के अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य के कारण बढ़ा दी गई है। ये व्यक्ति हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डाक्टर आर.सी. मेहरोत्रा , "इंस्टिट्यूट आफ सायंस", पूना के डाक्टर सी.आर.कानेकर , मद्रास विश्वविद्यालय के डाक्टर ए.आई.नारायणस्वामी और प्रेज़िडेंसी कालेज , कलकत्ता के श्री० डी.के.सेन । डाक्टर मेहरोत्रा की छात्रवृत्ति एक वर्ष और शेष तीनों की छ: महीनों के लिये बढ़ाई गई हैं।

N.E.H.52

साम्यवादी पार्टी को सलाम

लन्दन "टाइम्स" के अनुसार हैक्ने कौंसिल के साम्यवादी सदस्य, श्री० सी.एच.डार्क,ने दल से इस्तीफा दे दिया है । आप पिछले १८ वर्षों से दल के सदस्य रहे हैं और संसदीय निर्वाचनों तथा कोरिया सम्बन्धी नीति से असहमत होने के कारण उससे अलग हो रहे हैं । आप कहते हैं , " कोरिया में ब्रिटिश जानें जा रही हैं और मैं ब्रिटिश लोगों को साम्यवाद से अधिक बड़ा समझता हूं ।"

F.H.245

चीन तिब्बत सम्बन्ध

नए समझौते पर 'मैनचेस्टर गार्जियन' का मत

चीन और तिब्बत के मध्य में कुछ समय पहले हुए समझौते पर टीका टिप्पणी करते हुए 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने ३० मई के अंक में कहा है कि तिब्बत में साम्यवादी चीनियों को जो कुछ वे पाना चाह सकते थे मिल गया। और कोरिया में उनकी हानि के बाद यह समझौता उन्हें अवश्य सन्तोष प्रदान करेगा। समझौता, पीकिंग रेडियो पर जिसकी घोषणा की गई थी, चीनियों को तिब्बत की प्रतिरक्षा और उसके वैदेशिक समबन्धों के क्षेत्र में नियन्त्रण प्रदान करता है। यद्यपि ल्हासा में एक 'राजनैतिक और सामरिक परिषद' में प्रधानतया तिब्बत के लोग होंगे पर मालूम होता है कि वहां चीनी सेनाएं तैनात की जाएंगी। इस प्रकार तिब्बत १९११ में मन्चु के पतन से पहले की अवस्था पर वापस हो सकता है। स्मरण रहे कि उस समय चीनी सेनाओं ने ज़ोरशोर से हस्तक्षेप किया था।

आन्तरिक मामलों के लिए वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था योंही रक्खी जाएगी। पर इसमें सन्देह नहीं है कि बहुत समय बीतने से पहले की तिब्बत की एक पीपुल्स पार्टी अधिकार पद पर आसीन हो जाएगी। नए समझौते की कुछ बातें ध्यान विशेषतया आकर्षित करती हैं। पंचन लामा का अधिकार और पद बनाए रखे जाएंगे। यदि पंचन लामा चीन के बल पर वापस आते हैं तो दलाई लामा को यह समझना चाहिये कि उसे अब जाना है। वर्तमान पंचन लामा एक बालक है जिसके चुनाव के लिए चीनियों ने दावपेच की थी। इसलिये कई तिब्बतियों ने पंचन लामा को अस्वीकार किया था। समझौते की एक बात यह है कि तिब्बत की भाषा का विकास 'स्थानीय आवश्यकताओं

... के अनुसार

के अनुसार ` किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है, पत्र पूछता है ? शायद यह तिब्बत की एक नई बोलचाल की भाषा लामाओं के अधिकार को शिथिल करने के साधनरूप में बनाने का प्रयत्न है। तिब्बत के महत्व के विषय में विपरीत धारणाएं हैं। कोई सचमुच यह नहीं जानता कि तिब्बत की प्राकृतिक सम्पत्तियां क्या हैं। सबसे अधिक मूल्यवान सम्पत्ति शायद उत्तर पश्चिम में है। भारतीय सरकार अपनी प्रतिरक्षा अवस्था पर पुनर्विचार करने में संलग्न है। नेपाल की घटनाओं की ओर अब अधिक ध्यान आकर्षित होगा।

F.H.246

ब्रिटेन के लिये कैनडा का अल्युमिनियम

ब्रिटिश सरकार और कैनडा की अल्युमिनियम कम्पनी के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन के लिए कैनडा के अल्युमिनियम की सप्लाई में अगले वर्ष तीस हज़ार मेट्रिक टनों की वृद्धि होगी।

ब्रिटिश स्कूलों से भारतीय प्रभावित

बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के मन्त्री श्री० एस.डी. पांडे ने, जो ब्रिटिश कौंसिल के प्रबन्ध के अन्तर्गत चार महीनों के लिये ब्रिटिश शिक्षा संस्थाओं का भ्रमण कर रहे हैं और उनकी कार्य पद्धति का अध्ययन, अबतक कई प्रकार के स्कूलों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों का भ्रमण किया है। श्री० पांडे जून के महीने में विश्वविद्यालयों का भ्रमण करने का विचार कर रहे हैं।

N.E.H.53

ब्रिटिश निर्वाचन विधान
में
सब जन एक समान

गाई एडेन
"डेली एक्सप्रेस, लन्दन, के राजनैतिक सम्वाददाता

ब्रिटेन के निर्वाचन विधान की उचित प्रशंसा में यही कहा जा सकता है कि उसे सब दल मुक्त रूप से मानते हैं ।

१९५० के पिछले सार्वजनिक निर्वाचनों में इंग्लैंड, वेल्स, स्काटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ६२५ चुनाव क्षेत्रों में बाटे गए थे और प्रत्येक क्षेत्र संसद में एक सदस्य भेजता था। १९४५ के निर्वाचनों में चुनावक्षेत्रों की संख्या ६४० थी पर १९५० के निर्वाचनों के पहले सीमाओं का निर्धारण फिर से हुआ था। इसके फलस्वरूप लन्दन शहर (सिटी आफ लन्दन) (बड़े लन्दन के बीच की वह ऐतिहासिक वर्ग मील) का पृथक अस्तित्व जाता रहा और वह सिटी आफ वेस्टमिन्सटर में मिला दिया गया । उसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संसद में सिटी आफ लन्दन के दो सदस्य हुआ करते थे । अब, सिटी आफ वेस्टमिन्सटर में मिलाए जाने के बाद, एक सदस्य । विश्वविद्यालय भी उन प्राचीन निर्वाचन क्षेत्रों में थे जो अब समाप्त कर दिये गये थे : यहां मतदाताओं (स्नातकों) के ये वोट उनके साधारण वोटों के अतिरिक्त थे । इस प्रकार वे दो बार वोट दे सकते थे।

विश्वविद्यालयों के पृथक प्रतिनिधित्व का हटाया जाना इस नियम का अपवाद था कि ऐसे परिवर्तन सब दलों की सहमति से होते हैं : कांज़र्वेटिव दल ने अधिकार पाने पर विश्वविद्यालय के १३ वोटों को पुनः चालू करने की इच्छा प्रकट की है।

मतदान क्रिया को पूर्णतया गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी से काम लिया जाता है।

... अभ्यर्थी लोग

अभ्यर्थी लोग निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च नहीं कर सकते । इस नियम का उद्देश्य निर्वाचन क्रिया को न्यायपूर्ण बनाना और देखना है कि संसद की सदस्यता कहीं धनी लोगों का अधिकारक्षेत्र न बन जाए। कानून के अनुसार निर्वाचन के लिये खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव के काम पर किए गए खर्च का पूरा हिसाब देना पड़ता है : चाहे धन वास्तव में उसने खर्च किया हो अथवा उसके एजेन्ट ने। निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने वाले सफल अभ्यर्थी अपनी सीट खो सकते हैं और ऐसे लोग कई वर्षों तक फिर चुनाव लड़ने के अयोग्य बनाए जा सकते हैं।

स्पष्ट है कि ये सारे प्रबन्ध चुनाव को यथासम्भव पक्षपातरहित बनाने और निर्धन से निर्धन व्यक्ति को धनी के समान अवसर देने के उद्देश्य से किए गए हैं।

निर्वाचन व्यवस्था का सम्पूर्ण संचालन राजनैतिक "तटस्थों" के हाथों होता है। केन्द्रीय सरकार निर्वाचन में कोई भाग नहीं लेती। निर्वाचन व्यवस्था के लिये स्थानीय अधिकारी उत्तरदायी होते हैं। इस मामले में केन्द्रीय सरकार का प्रवेश सफल अभ्यर्थी के संसद सदस्य घोषित किए जाने पर ही होता है।

कुछ अपवादों, जैसे इंग्लैंड और स्काटलैंड के चर्चों और रोमन कैथलिक चर्च के पादड़ियों और अमुक्त दिवालियों, के अतिरिक्त संसद की सदस्यता के लिये खड़े होने के मार्ग में नागरिकों की योग्यता पर केवल एक रोक लगाई जाती है : अर्थात् १५० पौंड जमा करने की आवश्यकता जो सारे वोटों के १/८ से भी कम पाने वालों को वापस नहीं मिलता। यह नियम निर्वाचन पद्धति को सस्ती बनने से रोकने और उसकी प्रतिष्ठा के बचाव के लिये बनाया गया था।

निर्वाचन की उत्तेजना में राजनीतिज्ञ एक दूसरे के विषय में चाहे जो कुछ भी कहें पर किसी से यह कभी नहीं सुना गया कि ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली पक्षपातरहित नहीं है। न ही किसी ने यह कहा है कि निर्वाचनों के बाद ऐसी संसद नहीं बनती जो मोटे तौर पर अधिकांश मतदाताओं के मत प्रकट करती हो। यह ऐसी बात है जिसका सबको गर्व है, चाहे उनके राजनैतिक दृष्टिकोण कुछ भी हों। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि न्यायालयों को निर्वाचन विधान सम्बन्धी किसी बात पर निर्णय देना पड़ा हो। इससे स्पष्ट है कि नियमों का पालन कितनी अच्छी तरह किया जाता है।

H/L.P.S.259

बर्मा के आगामी निर्वाचन

दलों की अवस्था का विवेचन

बर्मा के आगामी निर्वाचनों पर विचार प्रकट करते हुए 'टाइम्स' पत्र ने ६ जून के अंक में 'बर्मी लोगों की आत्मविश्वासपूर्ण भावना' का उल्लेख किया है।

पत्र ने कहा है कि सबसे शक्तिशाली दल 'ऐन्टी फाशिस्ट पीपुल्स लीग' है जिसने अपनी प्रतिष्ठा को सामाजिक और आर्थिक सुधारों द्वारा बढ़ा लिया है। इसके बाद पत्र ने इस दल की लोकप्रियता के कारणों का थोड़ा सा उल्लेख करने के बाद कहा है कि फिर भी उसे विरोधियों का सामना करना है। पत्र की दृष्टि में इस दल को जिस विरोधी का मुख्य भय है वह मार्क्सवादी सिद्धान्तों और युद्धप्रिय पश्चिमविरोधी नीति के आधार पर चलने वाली कामकाजियों और किसानों की नई पार्टी है।

बर्मा के विदेशी सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए 'टाइम्स' लिखता है : बर्मा के लोगों का विश्वास है कि दिल्ली का अनुसरण करने वालीउनकी सरकार की विदेश नीति से उन्हें साम्यवादी और असाम्यवादी समूहों के मध्य किसी संघर्ष में तटस्थता का आश्वासन मिलता है। बर्मा के कुछ विदेशी मित्र समझते हैं कि बर्मा की बचावहीन अवस्था और साम्यवादी चीन के साथ उसकी लम्बी और, कुछ अंश तक, अनिर्धारित सीमा वैसे ही हस्तक्षेप का मार्ग तैयार करती है जो कुछ समय पहले तिब्बत पर लादा गया था। पर बर्मा के लोग अपने विदेशी मित्रों के इस भय को गम्भीरता से नहीं लेते। प्रधान मन्त्री थाकिन नू, पीकिंग के इस मित्रतापूर्ण आश्वासन को मानते हैं कि बर्मा और चीन के बीच ऐसी कोई बात नहीं है जो शांतिपूर्वक न सुलझाई जा सके। आगे चलकर पत्र कहता

... है कि

है कि बर्मा की सीमा में घुस आने वाले चीनी राष्ट्रवादी सैनिकों को निकाल या नज़रबन्द कर थाकिन नू ने पीपुल्स रिपब्लिक के साथ अच्छे सम्बन्धों की इच्छा प्रकट की थी। थाकिन नू यह भी नहीं मानते कि बर्मा में साम्यवादी विद्रोहियों को चीन से किसी प्रकार की सहायता मिल रही है।

दक्षिण-पूर्व-एशिया में क्रान्ति सम्बन्धी साम्यवादी निर्देश की मुख्य बात यह है कि उसमें इस समय प्रत्येक देश में राजविद्रोही आन्दोलनों को अलग-अलग चलाने की बात कही गई है। 'फिर भी', 'टाइम्स' समझता है, 'स्पष्ट है कि जबतक बर्मा की सरकार को सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ता है तबतक पराजित नेता चीन में शरण पायेंगे और अपनी शक्ति को फिर से संगठित करेंगे। संघर्ष को फिर से प्रारम्भ करने के लिये काचिन लोगों की एक विद्रोही शाखा सीमा के बाहर फिर से संगठित हो रही है पर चीन के अधिकारी बर्मा के साथ अपनी मित्रता को इतनी दूर नहीं ले जाते कि इन लोगों को निकाल बाहर करें। यदि बर्मा को भविष्य की ओर आशा से देखना है तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता शांति और सुव्यवस्था है और उसके पश्चिमी मित्रों में यह आशा उत्पन्न होनी चाहिये कि अपने साम्यवादी पड़ोसियों में बर्मा का विश्वास गलत नहीं है।

H/L.P.S.255/

ब्रिटिश समाचारपत्र सम्मति संकलन

जापानी शांति सन्धि सम्बन्धी वार्ता

डलेस की लन्दन यात्रा

"मैनचेस्टर गार्जियन" ने चौथी जून के अंक में यह आशा प्रकट की है कि लन्दन में श्री० डलेस की बातचीत जापानी शांति सन्धि विषयक विचार विनिमयों की अन्तिम चरण सिद्ध होगी। जापानी शांति सन्धि के अमेरिकन और ब्रिटिश रूपों में कुछ अंश तक संयोग स्थापित किया जा चुका है। अब श्री० डलेस को यह कार्य पूरा करना है। अमेरिका की इच्छा थी कि सन्धि पर हस्ताक्षर करने वालों में च्यांग काई शेक भी हों और फारमोसा कुओमिंटांग को दे दिया जाता। पर ब्रिटेन ने कहा है कि चीन की ओर से हस्ताक्षर करने वाले का प्रश्न तथा फारमोसा का भाग्यनिर्णय बाद में किए जाएं। आगे चलकर पत्र ने जापान की विदेशी सम्पत्तियों और ऋणों तथा जापान द्वारा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने की चर्चा की है और कहा है कि इस विषय में कि जापान की आर्थिक उत्पत्ति में सीमाएं न लगाई जाएं अमेरिका के साथ ब्रिटेन सहमत हो चुका है।

शांति सन्धि के विषय में पत्र ने कहा है : यद्यपि सन्धि बहुत समय तक स्थगित रखी गई थी वह जापानियों को निराश नहीं करेगी। सत्य तो यह है कि लगभग सब जापानी उसे बहुत उदार मान रहे हैं। इतिहास में विजयी राष्ट्रों की उदारता के अधिक पूर्वदृष्टान्त नहीं हैं। जो दृष्टान्त हैं वे हमें इस प्रयास के प्रति आशावादी होने का प्रोत्साहन देते हैं।

जापान ने अपने हाल के अच्छे आचरण और अपनी आगामी कठिनाइयों के कारण उदार शांति सन्धि प्राप्त की। घोर कठिनाइयों के बाद भी स्थिरता का उदाहरण

... देकर

देकर जापान ने एशिया की नई राजनैतिक प्रणाली में शक्तिशाली भाग ले सकने की क्षमता दिखाई है। पर जापान के आगे नई आपत्तियां हैं : अत्यधिक जनसंख्या से उत्पन्न संकट और, यदि वह चीन से व्यापार नहीं करता तो, कच्ची सामग्रियां और बाजार पाने की कठिनाइयां। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये जापान को एक उदार सन्धि दी जानी चाहिये : कम से कम ब्रिटेन और अमेरिका का यही मत है।

N.E.H. 54/~~51~~

दाता और हरता की समता

नक्षत्रविद्या में नई सीख

अध्यापक : सूरज और सोवियट यूनियन में क्या समानता है?

विद्यार्थी : दोनों के 'सैटेलाइट' (उपग्रह : कठपुतली) होते हैं।

अध्यापक : और अन्तर भला क्या है, दोनों में?

विद्यार्थी : बहुत बड़ा अन्तर।

अध्यापक : क्या?

विद्यार्थी : सूरज अपने उपग्रहों को गर्मी और रोशनी देता है और सोवियट यूनियन अपने अनुचरों का तेल और कोयला हरता है।

H.S.28

गरम देशों के रोगों पर रोक

ट्रेवर ब्लोर

हाल की दो घटनाओं ने ब्रिटेन में हो रहे ऐसे कार्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, ऐसे मार्ग की ओर, जिसपर चलकर ब्रिटेन पीड़ित मनुष्यों का उद्धारक बन रहा है। एक घटना उपनिवेशों में अन्धेपन के निवारण के लिये "ब्रिटिश एम्पायर सोसाइटी फार दि ब्लाइंड" द्वारा दस लाख पौंडों की निधि सम्बन्धी आन्दोलन है और दूसरी घटना गरम देशों की बीमारियों के लिये लन्दन में एक नये अस्पताल का उद्घाटन है। इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि उपनिवेशों के लोगों के कल्याण में संलग्न ब्रिटिश औषधिशास्त्र और ब्रिटिश विज्ञान ने यों सारे संसार के स्वास्थ्य में एक महान अंशदान दिया है।

गरम देशों के रोगों में अनुसन्धान तथा उनकी चिकित्सा और इस विषय से सम्बन्धित शिक्षा का केन्द्र सबसे पहले "अयनवृत्तीय औषधिशास्त्र के पिता" सर पैट्रिक मैन्सन द्वारा उस समय के उपनिवेश मन्त्री जोज़ेफ चैम्बरलेन के समर्थन और "सीमेन्स हास्पिटल सोसाइटी" के अध्यक्ष की व्यावहारिक सहायता से १८९९ में स्थापित किया गया था।

आज ब्रिटेन, जिसने गरम देशों के रोगों से सम्बन्धित स्कूल और अस्पताल लन्दन, लिवरपूल और एडिनबरो में स्थापित किए हैं, उस क्षेत्र में जिसका किसी समय वह मार्गदर्शक था अकेले नहीं रहा। इस प्रकार के स्कूल और अस्पताल आज जर्मनी, हालैंड, फ्रांस, लेटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में एक संस्था ब्रिटिश स्कूल के नमूने पर बनाई गई है। पर सारे संसार के विद्यार्थी और नर्स (परिचारिका) "लन्दन स्कूल आफ हाईजीन ऐन्ड ट्रापिकल मेडिसन" में प्रवेश करते हैं। इसका कारण इस स्कूल की महान प्रतिष्ठा है जो सर पैट्रिक मैन्सन और सर रोनैल्ड रास के

... महत्वपूर्ण कार्यों

महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्भर है। इन्हीं दोनों ने यह प्रमाणित किया था कि मलेरिया का रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। इस प्रकार उन्होंने इस दिशा में किए जाने वाले सारे आगामी अनुसन्धानों का मार्ग तैयार किया था। आज ब्रिटेन के वैज्ञानिक संसार के विभिन्न भागों में मलेरिया के विरूद्ध सफल संघर्ष कर रहे हैं और व्यावहारिक प्रयोग भी ताकि इस तथा अन्य विनाशकारी बीमारियों से लड़ने की विधियां सुधारी जा सकें। दूसरी घटना, अर्थात् अन्धेपन के उन्मूलन के लिये एक निधि स्थापित करने की अपील, एक नया प्रयास है। 'ब्रिटिश एम्पायर सोसाइटी फार दि ब्लाइंड', जिसकी स्थापना १९५० में हुई थी, एक स्वतन्त्र निगम है : यह औपनिवेशिक सरकारों की सहायता के बल पर स्पष्ट रूप से सब उपनिवेशों की सेवा के लिये स्थापित पहला स्वैच्छिक संगठन था।

इस 'सोसाइटी' का अनुमान है कि सब ब्रिटिश उपनिवेशों में लगभग दस लाख लोग अन्धेपन तथा नेत्रों के अन्य रोगों से पीड़ित हैं। क्योंकि इनमें से अधिकांश के रोग रोके जा सकते हैं 'सोसाइटी' ने इस समस्या को विधिपूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। 'सोसाइटी' ने अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों, सरकारों, और सामाजिक कल्याण संगठनों इत्यादि से प्रत्येक उपनिवेश में सम्पर्क स्थापित किया है ताकि बिना किसी भेदभाव के सब अन्धों के कष्ट निवारण के प्रयत्न किये जायें।

पत्रकारिता में महिला

'कैन्ट ऐन्ड ससेक्स कोरियर' नामक पत्रिका की सम्पादिका श्रीमती फ्लारेंस क्लेमेटसन ने पत्रिकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि पत्रकारिता में उच्च पद और श्रेणी की प्राप्ति महिलाओं का काम नहीं है। 'लेकिन मैं तो समझती हूं कि स्त्रियों को पुरूषों के साथ किसी भी काम में प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिये। समान पद के लिये संघर्ष करने में वे अपने प्रभाव के सच्चे केन्द्र को छोड़ती जा रही है।'

F.H.257

ब्रिटेन और
विश्व तेल व्यापार

जान किंग्सले,
आर्थिक और वित्तीय टीकाकार

यद्यपि संसारका ध्यान ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित ईरानी सरकार के प्रस्तावों पर केन्द्रित है पर तेल के अन्तराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिटेन के भाग पर दृष्टिपात करना असंगत नहीं है। ब्रिटेन के तेल हित हैं क्या ? यद्यपि ये विश्वव्यापी हैं पर उनपर विचार करने के लिये हम उन्हें तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं: उत्पत्ति , शुद्धि और तेलवाही जहाज़ ।

ब्रिटेन में तेल लगभग पाया ही नहीं जाता और ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन लगभग पूर्णतया समुद्रपारस्थ देशों में होता है। यद्यपि ब्रिटिश स्वामित्वके अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण तेल कम्पनियों का संचालन हो रहा है पर दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कम्पनियां ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी तथा 'शैल ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग कम्पनी' हैं ।

ब्रिटेन में तेल लगभग पाया ही नहीं जाता और ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन लगभग पूर्णतया समुद्रपारस्थ देशों में होता है। दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कम्पनियां ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी तथा 'शैल ट्रान्सपोर्ट और ट्रेडिंग कम्पनी' है।

... ऐंग्लो ईरानी

ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी के उत्पादन क्षेत्र फारस तथा अन्य मध्यपूर्वीय प्रदेशों में केन्द्रित हैं। "शैल ट्रान्सपोर्ट ऐन्ड ट्रेडिंग कम्पनी" "रायल डच कम्पनी" (जिसपर नेदरलैंड का नियन्त्रण है) के साथ मिलकर कार्य करती है और इस प्रकार वेनेज्युला, अमेरिका और मिस्र में विभिन्न प्रकार के उद्यमों पर नियन्त्रण में उसका भी भाग है। ब्रिटिश स्वामित्व के अन्तर्गत काम करने वाली छोटी कम्पनियां मुख्यतया वेस्ट इंडीज में हैं।

ईरानी तेल का महत्व

यद्यपि उसके हित मध्यपूर्व के अन्य भागों में फैल गए हैं पर ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी के मुख्य उत्पादन क्षेत्र अभी भी ईरान में हैं। यहां उसने तेलकूपों, तेलशोधक कारखानों और अन्य यन्त्रादि में तीस करोड़ पौंडों से अधिक लगाया है। १९३८ से ईरानी तेल का उत्पादन तीन गुना बढ़ गया है : १९५० की संख्या लगभग ३ करोड़ बीस लाख टन थी, अर्थात् संसार की कच्चे तेल की उत्पत्ति के छ: प्रतिशत से कुछ अधिक और मध्यपूर्व के सम्पूर्ण उत्पादन की लगभग एक तिहाई।

द्वितीय महायुद्ध के समय से ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी के अन्य मध्यपूर्वीय हित अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। कुवाइत के तेल क्षेत्रों में ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी का हित आधा है : ये तेल क्षेत्र, जिन्होंने उत्पादन केवल १९४६ में प्रारम्भ किया था, आज दो करोड़ टन वार्षिक दे रहे हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र संसार का छठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया है।

ईराक में भी, जहां की "ईराक पेट्रोलियम कम्पनी" में "ऐंग्लो ईरानी तेल कम्पनी" का भाग लगभग एक चौथाई है, उत्पत्ति बढ़ रही है। जब नए तेल क्षेत्रों से उत्पादन होने लगेगा और भूमध्य सागर तक एक तीस इंच वाली पाइप लाइन पूरी हो जाएगी तब, आशा की जाती है, ईराक का वार्षिक उत्पादन दो करोड़ टनों से अधिक होगा।

किन्तु मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से उपभोक्ता क्षेत्रों के लिये ईरानी तेल सप्लाई के महत्व को घटाकर नहीं देखना चाहिये। ईरानी तेल का लगभग ९५वें प्रतिशत निर्यात किया जाता है और १९५० में इसका अर्थ यह था कि लगभग १४ प्रतिशत तेल का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से था। इसके अतिरिक्त अबादान स्थित ऐंग्लो ईरानी तेल शोधक कारखाना, जिसकी क्षमता दो करोड़ पचास लाख टन है, संसार का सबसे विशाल और आधुनिकतम है।

... हाल की

हाल की संख्याओं से मालूम होता है कि ब्रिटेन को लगभग २३ लाख टन या कच्चे तेल की समस्त प्राप्ति के एक चौथाई से अधिक , ईरान से मिलता है । पश्चिमी योरप के अन्य देशों को ईरान से उनकी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग १/५ भाग मिलता है ।

यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संसार के अन्य भागों में कच्चे तेल की बढ़ती हुई उत्पत्ति समय बीतने पर ईरान से कच्चे तेल की प्राप्ति में कमी को पूरी कर सकती है पर हमें अबादान स्थित तेल शोधक कारखाने की उत्पत्ति का ध्यान रखना भी आवश्यक है । यह साधन ब्रिटेन और पश्चिमी योरप के लिये अभी तक महत्वपूर्ण है और योरोपीय देशों में कारखानों की तेल शोधन क्षमता ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों अबादान का महत्व कम होता जाएगा । यह स्मरण रखना आवश्यक है कि अबादान की उत्पत्ति का एक बड़ा भाग भारत , पाकिस्तान , मिस्र , पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका , तथा आस्ट्रेलि की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी कर रहा है । यों ईरानी तेल के बन्द होने पर न केवल इन देशों को पर कुछ हद तक ब्रिटेन और पश्चिमी योरप को भी असुविधा होगी।

तेल शोधक कार्य

युद्ध के समय से तेल शोधक कारखानों का विकास युद्धपूर्व की भांति उत्पादन क्षेत्रों में नहीं किन्तु मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों में विकसित करने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति देखी जा रही है। और इस विकास में अन्य पश्चिमी देशों के साथ ब्रिटेन भी आगे रहा है।

१९३८ में ब्रिटेन की तेल आवश्यकताओं के एक करोड़ २५ लाख टनों में से २५ लाख टनों से कुछ कम का शोधनकार्य ब्रिटेन में हुआ था । किन्तु युद्ध की समाप्ति के समय से तेल शोधक यन्त्रों की क्षमता को १२ करोड़ ५० लाख पौंडों के खर्च पर १९५३ तक बढ़ाकर दो करोड़ टन तक पहुंचाने के लिये पांच बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन नए यन्त्रादि में से पहले यन्त्र ने उत्पादन कार्य १९४९ के अन्त तक प्रारम्भ किया था और १९५० में ब्रिटेन के तेल शोधक कारखानों की सम्पूर्ण उत्पत्ति लगभग ९० लाख टन थी। इस प्रकार दो करोड़ टनों के सम्पूर्ण खर्च को पूरा करने में यह प्रगति काफी सहायक हुई थी

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश तेल कम्पनियां दक्षिण पूर्व एशिया में तेल शोधन यन्त्रों की

... मरम्मत

मरम्मत और कैरीबियन प्रदेश में तेल शोधक यन्त्रों के क्षमता को बढ़ाने में सक्रिय रही हैं। स्पष्ट है कि इस नीति से, विशेषतया ब्रिटेन में तेल शोधन यन्त्रों के निर्माण से, कच्चे तेल की प्राप्ति के साधन बहुत विस्तृत हो जाएंगे।

तेल का वहन

तीसरी बात तेल वाहक जहाजों की तौल और क्षमता है। सौभाग्यवश युद्ध के बाद से तेलवाहक जहाजों की तौल में काफी बड़ी वृद्धि हुई है, पर अभी भी अवस्था यह है कि इनकी वाहन क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। तेलवाहक जहाजों की तौल में इस वृद्धि में ब्रिटेन ने काफी भाग लिया है, न केवल अपने तेलवाहक जहाजी बेड़े को बढ़ाकर पर शेष संसार के लिये भी इन साधनों का निर्माण कर।

१९३९ से ब्रिटेन के तेल वाहक जहाजी बेड़े में १/३ की वृद्धि हुई है और संख्या चालीस लाख टन तक पहुंच गई है। इस प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में अमेरिका के संरक्षित जहाजों को जोड़ते हुए सम्पूर्ण संसार के तेलवाहक जहाजों की तौल दो करोड़ ९० लाख निकलती थी। अर्थात् ब्रिटेन का भाग लगभग १४ प्रतिशत था। तेलवाहक जहाजों के निर्माण की दिशा में ब्रिटेन के अंशदान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च, १९५१ के अन्त तक, ब्रिटिश निर्माणशालाओं में ११ लाख ५० हजार टनों से अधिक वाले ९७ तेलवाहक जहाज बन रहे थे।

साम्यवादी न्यायालय —— राजनैतिक
साधन

वाल्टर कोलार्ज,
जिन्होंने सोवियट और पूर्व योरोपीय मामलों
का विशेष अध्ययन किया है।

लौह आवरण के पीछे प्रतिदिन कोई न कोई राजनैतिक मुकदमा चला करता है। प्रतिदिन लोगों को "विध्वंसक कार्वाइयों", "देश द्रोह" इत्यादि अपराधों के लिये अदालतों में उपस्थित होना पड़ता है। कुछ मुकदमें सार्वजनिक रूप से होते हैं, कुछ गोपनीय रक्खे जाते हैं, पर सब यह सिद्ध करते हैं कि कठपुतली देशों की परिस्थिति कठोर भले ही हो पर वह कानून की व्यवस्था पर आधारित दीखती है।

यह बात पूर्णतया औपचारिक अर्थ में कुछ अंश में ठीक है। यद्यपि सब साम्यवादी राज्यों के जीवन में यातना-शिविरों और गुप्त पुलिस का उल्लेखनीय भाग होता है पर कानून के शासन के बाहरी लक्षण भी मौजूद होते हैं। यहां हम न्यायालय, न्यायाधीश और जन अभियोक्ता सब पाते हैं।

कानून का यह भ्रम समस्त साम्यवादी राज्यों के संविधानों में सम्मिलित है। उदाहरणार्थ, सोवियट संविधान के १२२वें अनुच्छेद के अनुसार, न्यायाधीश स्वतन्त्र होते हैं और केवल कानून का पालन उनका कर्तव्य है। इस अनुच्छेद को सब कठपुतली देशों के संविधानों में स्थान दिया गया है।

बल्गेरिया के संविधान के ५६वें अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने निर्णय देने में स्वतन्त्र होते हैं। वे केवल कानून के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। अल्बेनिया के संविधान में तो यह बात और भी स्पष्ट कर दी गई है : उसमें कहा गया

... है कि

है कि न्यायालय प्रशासन के आदेशों के अन्तर्गत नहीं हैं । और अन्य कठपुतली देशों के संविधानों में भी न्यायालयों की स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐसी ही बातें पढ़ने को मिलती हैं।

भ्रामक आश्वासन

पर साम्यवादी व्यवहार से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये संविधानिक आश्वासन बिल्कुल भ्रामक हैं । इसलिये पोल्यांस्की जैसे प्रमुख सोवियट विधि विशेषज्ञ का 'न्यायाधीशों और न्यायालयों की स्वतन्त्रता' जैसे शब्दों से उत्पन्न हो सकने वाले भ्रामक विचारों को दूर करने का प्रयत्न निस्सन्देह एक सौभाग्य की बात है ।

पोल्यांस्की ने मास्को विश्वविद्यालय के पत्र में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उसने बताया था कि सोवियट न्यायालय 'साम्यवादी दल और सोवियट शासन की नीति का संचालक है।' यों साम्यवादी राज्य में अदालतों के असली कार्य पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और अनेक भ्रांतियां दूर हो सकती हैं ।

पोल्यांस्की के अनुसार न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता नामक संविधानिक सिद्धान्त इसबात का स्पष्ट उदाहरण है कि सोवियट और 'बुर्जुवा' विधानों में एक ही शब्द के दो अत्यन्त भिन्न अर्थ हो सकते हैं, कभी कभी तो इन शब्दों के व्यवहार से प्रकट होता है कि उनके अर्थ भिन्न ही नहीं किन्तु बिल्कुल विपरीत भी हैं ।

'बुर्जुवा' राज्यों में 'न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता' का अर्थ है राजनीति से न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता । इससे प्रकट होता है कि 'बुर्जुवा' राज्यों में न्यायाधीश न्याय की देवी के पक्षपातहीन अनुचर हैं । पोल्यांस्की ने इस विचार को अपने उपहास और व्यंग का विषय बनाया है और कहा है कि, जहांतक सोवियट रूस का सम्बन्ध है, (और यह बात कठपुतली देशों पर भी लागू है) न्यायालय राजनैतिक साधन होते हैं । विधि के प्रति अधीनता और साम्यवादी दल के प्रति एक ही बात है ।

पोल्यांस्की ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायाधीशों को निर्देश केवल कानून से ही न प्राप्त करना चाहिये पर न्याय मन्त्रालय से भी : न्याय मन्त्रालय समय समय पर न्यायालयों और न्यायाधीशों को इस आशय के नि आदेश दिया करता है कि किन किन प्रकार के अपराधों का कठोरता के साथ दमन किया जाना चाहिये । बार बार न्याय मन्त्रालय इन्हें बताया करता है कि उनके कर्तव्य साम्यवादी दल के और सोवियट राज्य के आधारभूत लक्ष्यों की पूर्ति तक सीमित नहीं है पर प्रत्येक अल्प अवधि के

... राजनैतिक और

राजनैतिक और आर्थिक आन्दोलन को समर्थन देना भी उनके कर्तव्यों में है । वास्तव में कई दृष्टियों से न्यायालयों और न्यायाधीशों के कार्य किसी अर्थ मन्त्रालय की स्थानीय शाखाओं के कर्तव्यों से मिलते जुलते है।

ये चौकीदार ।

उदाहरणार्थ, यह सब जानते हैं कि सोवियट यूनियन में लकड़ी का अभाव है और इससे सम्बन्धित उद्योग ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वे बार बार अपूर्ण रही हैं। इसलिये लकड़ी सम्बन्धी इस योजना की पूर्ति में सहायता देना न्यायालयों और न्यायाधीश का कर्तव्य हो जाता है । पोल्यांस्की द्वारा उद्घरित न्याय मन्त्रालय के एक पत्र में न्यायालयों को लकड़ी उद्योग के कर्मचारियों द्वारा काम की उपेक्षा के मामलों को प्राथमिकता देने का आदेश है । उसमें कहा गया है कि ऐसे मामले पर पांच दिनों के अन्दर विचार हो जाना चाहिये । पर यह सम्भव है कि सोवियट शासन में भी कोई न्यायालय या न्यायाधीश कुछ हद तक राजनैतिक स्वातन्त्र्य बनाए रखने के प्रयत्न करें । अतएव ऐसी अवस्था के लिये साम्यवादी राज्य ने बचाव की सारी आवश्यक व्यवस्था कर ली है ।

साम्यवादी राज्य न्यायालयों और न्यायाधीशों पर चौकीदारी करने के लिये 'प्राक्यूरेटरों' से काम लेता है । ये लोग जो एक शक्तिशाली 'प्राक्यूरेटर जनरल' के अन्तर्गत सारे देश में फैले हुए हैं 'अवैधानिक और पर्याप्त प्रमाणहीन' दंडादेशों का विरोध करने का अधिकार रखते हैं ।

संसार के अन्य किसी देश में 'अवैधानिक और पर्याप्त प्रमाणहीन' दंडादेश कानून का स्पष्टतया और प्रत्यक्षतया उल्लंघन करने वाले दंडादेश कहे जाएंगे। पर रूस में नहीं।

पोल्यांस्की ने बताया है कि दंडादेश उस समय भी अवैधानिक हो सकता है जब कोई न्यायालय किसी कानून का राजनैतिक महत्व समझने में असमर्थ हो या कोई न्यायाधी किसी के अपराध के राजनैतिक महत्व को ठीक से समझ न पाया हो । हां, राजनैतिक दृष्टि से न्यायालयों और न्यायाधीशों के कार्यों की जांच करना सोवियट के प्राक्यूरेटरों और जन अभियोक्ताओं के कर्तव्यों का एक अंगमात्र है। 'सोवियट यूनियन की न्याय पद्धति' नामक अपनी पुस्तक में श्री० विशिंस्की ने कहा है कि अभियोक्ता सोवियट शासन के हित में लड़ने और प्रचार करने वाला भी होता है । किन्तु यह परिभाषा तो स्वयं न्यायाधीशों पर भी लागू होती है । साम्यवादी राज्य में जन अभियोक्ता और न्यायाधी के मध्य में तत्व की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं होता। अन्तर होता है मात्रा मात्र का।

L.P.S.243

रूस के साथ चीन के सम्बन्ध

कोरिया के अभियान के विषय में 'आब्ज़र्वर' पत्र ने २७ मई के अंक में लिखा है : कोरिया में चीन के पाचवें और सबसे बड़े आक्रमण की शोचनीय पराजय से रूस के साथ उसके सम्बन्ध संकट में पड़ सकते हैं। सुदूरपूर्वीय मामलों के लिये श्री० ट्रूमन के उप राज्यमन्त्री, श्री० डीन रस्क ने, पीकिंग को 'एक औपनिवेशिक रूसी शासन कहा है', स्लाव जाति का मन्चूकुओ, एक बड़ी मात्रा पर।

यद्यपि बहुत लोग श्री० रस्क की इस परिभाषा से सहमत होंगे पर उनकी परिभाषा की पुष्टि के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। रूस की नीति, जैसाकि लेनिन और स्तालिन ने उसे निर्धारित किया था, निश्चय ही सदैव पश्चिम पर ऐशिया के ज़रिये आक्रमण करने के लिये चीनी साम्यवादियों के उपयोग की नीति रही है। पर वास्तव में रूस बहुत कम भौतिक सहायता दे सका। चीनी साम्यवादियों की सफलता पूर्णतया उनके अपने प्रयासों का परिणाम है। इस बात के प्रमाण हैं कि यद्यपि चीन के साम्यवादी निश्चय ही रूस के साथ शक्तिशाली सम्बन्ध चाहते हैं पर रूस की कठपुतली बनना उन्हें कभी भी पसन्द नहीं रहा। चीन की वर्तमान परिस्थिति में, जो उसने स्वयं अपने ऊपर लादी है, रूसी साथी पर चीन की ओर से सम्भवत: बड़ा बोझ लादा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति उनमें या तो पृथकता या मेल उत्पन्न कर सकती है। पर अन्तिम परिणाम के अनुमान का समय अभी नहीं।

N.E.H.55

<u>नवसेना का नया जेट वायुयान</u> : सी वेनम नामक सब ऋतुओं में काम आने वाला और रात्रि में भी उपयुक्त हो सकने वाला एक नया जेट उड़ाकू वायुयान जो वायुयान वाहक जहाज़ (ऐयर क्रैफ्ट कैरियर) पर आधारित है उड़ाया जा चुका है और अब परिमाण में तैयार किया जा रहा है। यह ऊंचे स्तर के कार्यों के लिये बनाया गयाहै।

* * * * *

N.E.H.56

<u>ब्रिटेन की वनभूमि</u> : ब्रिटेन की वास्तविक और सम्भावित वनभूमि का क्षेत्रफल ३४,४८,३६२ एकड़ है। ५ एकड़ों से कम वाले वनों का अनुमान १,८७,००० एकड़ लगाया गया और इस प्रकार सम्पूर्ण संख्या ३६,४०,००० एकड़ बैठती है, अर्थात् ब्रिटेन की भूमि सतह के ६.५ प्रतिशत के बराबर।

H.S.29

"सिविल डिफेन्स स्टाफ कालेज"

नागरिक सुरक्षा का घर

राय ब्रिउवर

बर्कशायर नामक रमणीक कांउटी के सनिंगडेल नामक स्थान में, जो लन्दन से पश्चिम की ओर थोड़ी दूर पर अवस्थित है, आप "सिविल डिफेन्स स्टाफ कालेज" को देख सकते हैं। यह नागरिक बचाव की विधियों और कलाओं में खोज तथा अध्ययन का ब्रिटिश केन्द्र है। कुछ समय पहले तक सारे संसार में यह अपने ढंग का एकमात्र स्थान था। पर अब हालैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे केन्द्र स्थापित कर लिये हैं। यह कालेज त्रिभुज की एक भुजा है : अन्य दो भुजाएं हैं कैम्बरले और ब्रेकनेल जो क्रम से सेना और वायुसेना के कर्मचारी वृन्दों के कालेज हैं।

"सिविल डिफेन्स स्टाफ कालेज" नवम्बर, १९४८ में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना का विचार दिवतीय महायुद्धकाल में उत्पन्न हुआ था। सरे की पास वाली काउंटी में स्टोक डेबेरनान नामक स्थान में नमूने के तौर पर एक कालेज स्थापित किया गया था। वहां युद्धकाल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सनिंगडेल की रूपरेखा विस्तार में तैयार की गई थी।

कालेज भवन में एक निजी सिनेमा है जहां शिक्षाप्रद चित्रपट दिखाये जाते हैं और सदस्यों दवारा रचित छोटे मोटे नाटक भी खेले जाते हैं। सनिंगडेल का मुख्य सम्बन्ध

... नागरिक बचाव

नागरिक बचाव की विस्तृत समस्याओं से है । टेक्निकल ज्ञान की बारीकियां अन्यत्र नागरिक बचाव स्कूलों में बताई जाती हैं । सब शिक्षाक्रमों में जिन समस्याओं पर ज़ोर दिया जाता है वे नागरिक बचाव और सशस्त्र बल , आग बुझाने की व्यवस्था और पुलिसदल तथा ऐच्छिक कल्याण संगठनों के पारस्परिक सम्पर्क इत्यादि हैं ।

छोटे शिक्षाक्रम, जो एक सप्ताह के होते हैं और जिनका सम्बन्ध समूचे योजनानिर्माण की मोटी मोटी बातों से होता है , स्थानीय और केन्द्रीय सरकारों के कार्यपालक प्रधानों, पुलिसदल तथा आग बुझाने की व्यवस्था और नागरिक बचाव के योजनानिर्माण से सन्निकटरूप में सम्बन्धित अन्य संगठनों के लिये सुरक्षित होते हैं । बड़े शिक्षाक्रम , जो पांच सप्ताह तक चलते हैं , और जिनके विषय योजनानिर्माण की बारीकियां होती हैं , मुख्यरूप से ऐसे नर नारियों के लिये होते हैं जो अपने अधिकारियों और संगठनों के लिये स्थानीय नागरिक सुरक्षा की योजना बनाने में पूरे समय के लिये नियुक्त होते हैं ।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये भी विशेष शिक्षाक्रमों की आयोजना की गई है । एक शिक्षाक्रम विदेशी आगन्तुकों के लिये आयोजित किया गया था और इसमें कई योरोपीय देशों तथा मिस्र , संयुक्तराज्य अमेरिका और राष्ट्रमंडल के लोग सम्मिलित हुये थे । पांच सप्ताहों के शिक्षाक्रम भाषण और प्रदर्शन , कागज़ी अभ्यास और वाद विवाद के सम्मिश्रण थे ।

अणुबम से बचाव , रसायनिक और वैज्ञानिक युद्ध की विधियां , आग बुझाने के नए नए तरीके , उद्योग में नागरिक बचाव की युक्तियां , बड़े नगरों में संगठन के सिद्धान्त , जनता का साहस बनाए रखने , आपत्तिकाल में उनके खाने पीने का प्रबन्ध और हताहतों की समस्या —— ये हैं अध्ययन के विविध विषयों में से कुछ । शिक्षाक्रमों की सूची में ३८ विभिन्न कक्षाएं सम्मिलित हैं । कालेज के कर्मचारियों द्वारा भाषण तो होते ही हैं , साथ ही साथ बाहरी विशेषज्ञ भी आया करते हैं । इसके अतिरिक्त , जटिल स्थानीय समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये घने क्षेत्रों की यात्रा भी की जाती है , जैसे लन्दन का आग बुझाने का केन्द्र और सेना का स्वास्थ्य स्कूल । साधारणतया भाषण ४० से लेकर ६० मिनटों तक के होते हैं । इनके बाद आधे घन्टे की बहस जो प्राय: मिलेजुले अनुसन्धान की कक्षा का रूप ले लेती है । सब नई बातों और उत्पन्न होने वाली सारी नई समस्याओं को लिखना और छांटना कालेज के कर्मचारियों का दायित्व होता है । तब वे इन्हें गृह विभाग को भेजते हैं । और गृह विभाग नागरिक बचाव के सब मामलों के लिये उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार का मन्त्रालय है ।

N.B.H. 57/51

१० मई के "सोवियट लिटरेरी गज़ेट" ने सोवियट यूनियन में विदूषकों के लिये एक "विदूषक विभाग" बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि सर्कस के विदूषकों को "राजनैतिक, सामाजिक तथा कलात्मक अनुशासन" में शिक्षा दी जा सके।

व ह वि ल क्ष ण वि दू ष क

छोड़ पुराने रीति रिवाज,
नए नए हम नियम बनाएं।
शुद्धि करें अपने सर्कस की,
गम्भीरता का पुट लगाएं।।

नई नीतियों के उपासक,
अन्य सब के मार्गदर्शक।
शिष्ठ और अनुशासित बनें तब,
रूस के अद्भुत विदूषक।।
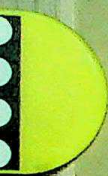
BRITISH INFORMATION SERVICES

FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

June 10 to June 23, 1951.

HINDI

BRITISH INFORMATION SERVICES

FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

June 10 to June 23, 1951.

HINDI

The contents of this Review may be used in any form

कोरिया में एक वर्ष

आक्रमण के विरूद्ध स्वतन्त्र राष्ट्र एकता में बद्ध

वाल्टर टैपलिन,
"स्पेक्टेटर", लन्दन, के सहायक
सम्पादक

एक सिद्धान्त के समर्थन में संकोचहीन संसारव्यापी सहयोग का सुन्दर उदाहरण : इसी रूप में जून २५, १९५० का स्मरण किया जायेगा। केवल कुछ घन्टों पहले ३८वें अक्षांश के उस पार उत्तरी कोरिया की सेनाओं द्वारा आक्रमण हुआ था : इस आक्रमण की निन्दा करने में संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद ने जो शीघ्रता दिखाई, और जानबूझ कर किए गए इस आक्रमण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्रों के सब सदस्यों से की गई अपील के जो प्रभावदायक परिणाम उत्पन्न हुए उनकी तुलना पहले के इतिहास से नहीं की जा सकती। वास्तव में ये दोनों घटनाएँ भविष्य के लिये बहुत प्रेरणात्मक थीं।

इस प्रेरणात्मक उदाहरण का महत्व अच्छी तरह समझने के लिये पहले और बाद की राजनैतिक घटनाओं को स्मरण रखना चाहिये। कारण, इन्हीं घटनाओं ने उस कार्य के औचित्य और यथार्थवादिता को बल प्रदान किया था जो, मूल रूप से, एक आदर्शवादी कार्य था।

कोरिया का प्रश्न जून २५, १९५० को केवल भविष्य की ओर संकेत नहीं कर रहा था परन्तु भूत की पूर्वपीठिका भी लिये हुये था। वास्तव में, जहांतक इन घटनाओं से सम्बन्धित एक दल (अर्थात् सोवियट यूनियन) का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता था कि परिस्थिति पर स्पष्ट प्रकाश डालने वाली बातें वे घटनाएं थीं जो इस मूल आक्रमण

... से पहले

से पहले प्रकट हुई थीं । देखिए : यद्यपि रूसियों ने अगस्त, १९४५ में पाट्सडम में काहिरा के इस आशय के समझौते का समर्थन किया था कि कुछ समय में कोरिया को मुक्त और स्वतन्त्र हो जाना चाहिये पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के आयोग की स्थापना का निरन्तर विरोध किया । (यह आयोग कोरिया को एक बनाने और रूसी तथा अमेरिकन सेनाओं को, जिनका क्रम से ३८वें अक्षांश के उत्तर तथा दक्षिण में अधिकार था, वहां से हटाने के काम में सहायता देने के लिये नियुक्त किया जाने वाला था ।)कोरिया में स्वतन्त्र जनतन्त्र की स्थापना में बाधाएं डालने का दोष संयुक्त राष्ट्रीय आयोग दव्ारा रूसियों पर ही डाला गया था । रूसियों ने ही उत्तरी कोरिया में आयोग के प्रेक्षकों को प्रवेश देने से इन्कार किया था ।

अन्त में, जून २५,१९५० को, ऐसे प्रदेश से जिसपर सामरिक अधिकार केवल रूसियों के पास था, आक्रमण किया गया । इस बात से कि पिछले वर्ष रूसियों ने सामरिक दृष्टि से अपने को स्पष्ट बाहर नहीं प्रकट किया था, परिस्थिति पर पर्दा न पड़ने देना चाहिये । कुछ महीनों तक युद्ध में संयुक्त राष्ट्रों का भाग प्रधानतया राजनैतिक महत्व का ही था । अमेरिकन सलाहकारों का समूह (जुलाई १९४९ के बाद कोरिया में केवल यही एक बल बच रहा था) साम्यवादी प्रवाह को रोकने के लिये कुछ भी नहीं कर सकता था ।

संयुक्त राष्ट्रीय बलों की प्रारम्भिक कार्रवाई एक राजनैतिक प्रदर्शन के रूप में थी : आक्रमण के प्रति विरोध और अन्त में उसे रोकने का संकल्प । इसके विपरीत साम्यवादियों का प्रयत्न युद्ध की कलाओं पर केन्द्रित दीखता था : शान्ति की विधियों पर बिल्कुल नहीं : पहले पहल ३८वें अक्षांश के उस पार उत्तरी कोरिया दव्ारा सुनिश्चित समय पर और सावधानी से तैयार योजना के अनुसार आक्रमण, तब अक्तूबर नवम्बर में चीन की ओर से बड़ा हस्तक्षेप और उसके बाद अप्रैल तथा मई, १९५१ के पूरी मात्रा पर किए गए आक्रमण । साम्यवादियों की ओर से शांति के कोई प्रस्ताव रक्खे ही नहीं गये । साम्यवादियों दव्ारा समय समय पर प्रकाशित (प्रचार की भाषा में ढके हुए और असंभव शर्तों से घिरे हुये) लक्ष्यों के विवरण तो केवल एक राजनैतिक युद्ध के साधन हैं ।

१७ राष्ट्रों के सैन्यदलों से युक्त संयुक्त राष्ट्रों दव्ारा एकता का ऐसा प्रदर्शन करने के बाद भी साम्यवादियों की ओर से शान्ति की सच्ची राजनैतिक या कूटनीतिक विधि का आश्रय लेने का उदाहरण नहीं मिला । युद्ध के प्रत्येक चरण में अधिकांश संयुक्त राष्ट्रों ने शांति स्थापना का प्रयत्न किया है ।

... सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषद के जून २५ वाले मूल प्रस्ताव में युद्ध विराम की बात उठाई गई थी। और जनरल एसेम्बली के छः अक्तूबर वाले वक्तव्य में कोरिया में पुनः शान्तिपूर्ण शासन के स्थापनार्थ आवश्यक कार्यवाहियां प्रकट की गई थीं । १३ जनवरी १९५१ को जनरल एसेम्बली की राजनैतिक समिति ने युद्ध विराम, कोरिया से विदेशी सेनाओं के हटाये जाने, सारे देश में जनतन्त्रवादी निर्वाचन और सुदूरपूर्व की समस्याओं का सामान्यरूप में समाधान इत्यादि से सम्बन्धित एक कार्यक्रम बनाया था । पहली फरवरी को जनरल एसेम्बली ने औपचारिक रूप से यह स्वीकार करते हुये कि चीनी साम्यवादियों ने हस्तक्षेप किया था और इस हस्तक्षेप को रोकने की अपील करने पर भी बड़े हठ से अभी भी युद्ध को रोकने की बात दोहराई थी ।

और इस सारे प्रकरण में रूस का अंशदान क्या था ?

१. कोरिया की सामरिक सहायता की अपील करने वाले २७ जून के प्रस्ताव को इस कारण अवैध ठहराना क्योंकि रूस उपस्थित नहीं था और चीन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी सरकार ने किया था ।

२. पहली अगस्त को सुरक्षा परिषद में अपनी सीट पर फिर बैठकर कोरिया के आक्रमण के विरूद्ध सुरक्षा परिषद को कोई भी प्रभावदायक निर्णय न लेने देना ।

३. इसके बाद शांतिपूर्ण समझौते के लिये एसेम्बली के सब प्रयत्नों को विरोध का शिकार बनाना ।

पर शांतिपूर्ण समझौता प्राप्त करने के प्रयत्न रूके नहीं । और इस सीधेसादे मामले के तथ्य ढके नहीं; चाहे लड़ाई में कैसे भी उतार चढ़ाव क्यों न रहे हों, चाहे सच्ची बातों को टालने के लिये साम्यवादियों ने सभी कोशिशें क्यों न की हों और चाहे सुदूरपूर्व की सारी परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो । कोरिया के युद्ध की बातों पर पक्षपातरहित दृष्टिपात केवल उसकी वास्तविकता प्रकट करता है। स्वतन्त्र राष्ट्रों द्वारा आक्रमण के अन्त का प्रयत्न और झगड़े को शांतिमय विधियों से सुलझाने की उनकी इच्छा: यही है सत्य, यही वास्तविकता ।

चलता फिरता अस्पताल

भारत को उपहार

एक चलता फिरता अस्पताल, जिसका उपहार देना अधिकांशतया लेडी माउंटबैटन के एक हज़ार पौंड के अंशदान के कारण सम्भव हो सका था, लन्दन में चौदहवीं जून को भारत की स्वास्थ्य मंत्रिणी राजकुमारी अमृतकौर को भेंट किया गया था। लेडी माउंटबैटन ने कहा कि उपहार देते हुए उन्हें अत्यधिक हर्ष हो रहा है। राजकुमारी अमृतकौर ने लेडी माउंटबैटन को धन्यवाद देते हुए भारतीय ग्रामों में ऐसे अस्पताल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस भ्रमणशील अस्पताल के नाम ('एडवीना माउंटबैटन वैन') को उन्होंने अत्यधिक उपयुक्त बताया और कहा कि यह चिकित्सालय भारत और ब्रिटेन की गहरी मित्रता का चिन्ह है। राजकुमारी अमृतकौर ने भारत के प्रति सद्भावना के कई कृत्यों (विशेषतया खाद्य संकट में) के लिए ब्रिटेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आपने ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं के नमूने पर करना होगा।

> 'भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं के नमूने पर करना होगा'
>
> रा० अमृतकौर

ब्रिटिश उपनिवेशों में उच्च शिक्षा

आजकल उपनिवेशों के दो विश्वविद्यालयों और पांच कालेजों में ३८८ पूर्णकालीन प्रोफेसर और अध्यापक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनमें ६६ लघुकालीन विशेषज्ञ प्रोफेसर तथा अध्यापक भी पढ़ाते हैं। इन विश्वविद्यालयों और कालेजों में ३,०५६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि विद्यार्थियों की संख्या पहलेसेबहुत बढ़ गई है इसलिये विश्वविद्यालय और कालेज भवनों का अधिकाधिक विस्तार किया जा रहा है। औपनिवेशिक विश्वविद्यालय और अनुदान मंत्रणा समिति ने पिछले वर्ष औपनिवेशिक विकास तथा कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों में से १७,५०,००० पौंड के बटवारे की सिफारिश की थी।

F.H.264

भारत के संविधान में परिवर्तन

ब्रिटिश सूचनापत्र का मत

— ग्लैसगो हैरल्ड

भारतीय संविधान के परिवर्तनों पर 'ग्लैसगो हेरल्ड' ने एक सम्पादकीय में लिखा है : इन सब मामलों में संविधान में कुछ संशोधन के लिये औचित्य अवश्य है। जहांतक भारतीय सरकार उन साधारण रक्षाकवचों का संविधान में फिर से प्रवेश कर रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में थे वहां तक उस पर अनुभव से सीखने के सिवा और कोई दोष शायद ही लगाया जा सकता है। इसके विपरीत सरकार के आलोचकों का कहना है कि उसे ऐसे मूल महत्व के विधान को हाथों में लेने से पूर्व आगामी आम निर्वाचनों की प्रतीक्षा करनी चाहिये थी।

आगे चलकर पत्र ने कहा है : ऐसा मालूम होता है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये उन खतरों की गम्भीरता जो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति पर रोक लगाने वाले खंड में निहित है वर्तमान शासन द्वारा उसके उपयोग पर उतनी निर्भर नहीं जितनी कि भावी भारतीय सरकारों द्वारा उसके सम्भावित निर्वचन पर।

अन्त में पत्र ने कहा है कि संविधान में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। कारण, संविधान राष्ट्रवाद की विजय के प्रारंभिक उत्साहकाल में बनाया गया था और वह व्यावहारिकता के लिये अनुकूल समय नहीं था। ऐसे संशोधक विधानों को उतावली से नहीं करना चाहिये। उन्हें स्वतन्त्रता पर रोक लगाए बिना स्वतन्त्रता के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध तक सीमित रहना चाहिये।

F.H.273

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत
ट्रेनिंग पाने वाले
ब्रिटेन में

भारत से चार और लंका से तीन लोग, जो कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग पाएंगे, ब्रिटेन आए हैं। ये कोलम्बो योजना की टेक्निकल सहयोग स्कीम के अन्तर्गत ब्रिटेन आए हुए पहले व्यक्ति हैं। चारों भारतीय —— एच०एस० रंगनाथ राव, भास्कर राव, यू०एस० भटनागर और वाई०ए० हेगडे —— भारतीय डाक तार विभाग के हैं और ब्रिटेन में छः महीने बिता कर टेलिप्रिन्टर मशीन की देखभाल सम्बन्धी ट्रेनिंग पाएंगे।

ट्रेनिंग की यह सुविधा कोलम्बो योजना में ब्रिटेन के अंशदानों में एक है : ब्रिटेन टेक्निकल सहयोग स्कीम में २८ लाख पौंडों के अपने अंशदान में से ट्रेनिंग पाने वालों के यात्रा और ट्रेनिंग के खर्च उठाएगा और उन्हें ब्रिटेन में उनके खर्च के लिये भत्ता भी देगा।

F.H.270

"मुहं में राम राम बगल में छूरी"

स्ता लि न के सा म्रा ज्य वा दी स्व प्न

—— डब्लू०एन०ईवर

दस वर्ष पूर्व (जून २२, १९४१ को) हिटलर की सेनाओं ने नई सीमा लांघ कर अपने साथी सोवियट पर धावा बोल दिया था। अगले दिन मालोटाव ने जर्मन राजदूत से कहा था कि हमें यह किस खता की सज़ा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त केवल एक सप्ताह पूर्व उसने एक सरकारी विज्ञप्ति में यह घोषणा की थी कि सोवियट सरकार ने सोवियट जर्मन अयुद्ध करार की शर्तों को पूरा किया और करना चाहता है।

रूसियों ने कठोरता से और न्याय के साथ शिकायत की कि उनके जर्मन साथियों ने एक मूल प्रतिज्ञाभंग की कार्रवाई की थी। हिटलर ने एक धक्के से स्तालिन की विदेशी नीति के सम्पूर्ण आधार को चकनाचूर कर दिया था। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक अत्यन्त स्मरणीय किस्सा खत्म हो गया था। इसके प्रारंभ ने अगस्त १९३९ में संसार को चौंका दिया था और यह निस्सन्देह दिव्तीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ का एक संकेत था।

कम्यूनिस्ट स्तालिन ने एकाएक नाज़ी हिटलर के साथ मित्रता की एक सन्धि कर ली थी। इस बात ने संसार को इसलिये चकित किया क्योंकि अधिकांश लोग सोवियट संघ की सोवियट नीति के निजी चित्र में विश्वास करते थे। उन्होंने सोवियट संघ को शांति तथा लोकतन्त्र के चैम्पियन अथवा समर्थक और फाशिस्टवाद के एक क्रूर दुश्मन के रूप में पाया था। तब, एकाएक फाशिस्ट और कम्यूनिस्ट ने हाथ मिला लिये और एक अनन्त मित्रता के लिये वचन दिये थे। जैसाकि हुआ, मित्रता ने दो वर्षों से कम समय तक कायम रहना था।

... फिर भी

फिर भी संसार को चकित नहीं होना चाहिये था । उसे सोवियट प्रतिज्ञाओं के बाहरी रूप को नहीं देखना चाहिये था । वास्तव में स्तालिन नाज़ियों के साथ एक सौदे की इस बात के लिये छ: वर्षों से योजना बना रहा था । फाशिस्टवाद के विरोध और आक्रमण तथा साम्राज्यवाद के विरोध की प्रतिज्ञायें एक कोरा दिखावा थीं । स्तालिन ने स्वयं एकबार अपने असली इरादों का संकेत भी दिया था । इससे पूर्व १९३३ और १९३४ में स्तालिन ने शर्तें तय करने का प्रयत्न भी किया था । उसने कम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस में यहां तक कह दिया था कि फाशिस्टवाद विचारणीय विषय नहीं है। जनवरी १९३५ में मालोटाव ने घोषणा की थी कि हम तो जर्मनी के साथ केवल अच्छे सम्बन्ध जारी रखना चाहते हैं ।

गुप्त सन्धि

लेकिन यदि फाशिस्टवाद विचारणीय विषय नहीं था तो सोवियट नीति का असली ध्येय क्या था? एकबार फिर स्तालिन ने असावधानी से सच्ची बात प्रकट कर दी थी। उसने कहा था कि सोवियट संघ की विदेश नीति केवल सोवियट संघ के हितों की ओर निर्देशित की जाती है।

वे हित क्या थे ? उन दिनों में भी स्तालिन के असली इरादे क्या थे? वे १९३९ के नाज़ी - सोवियट अयुद्ध करार से सम्बन्धित गुप्त मसविदे और नाज़ी तथा सोवियट सरकार के बीच अगली बातचीतों में स्पष्टतया प्रकट हो गये थे । अयुद्ध करार अपने साथ वाली एक गुप्त सन्धि का एकमात्र बढ़िया लिफाफा था । और वह गुप्त सन्धि जिसके मूल कागज़ात आजकल हमारे पास हैं (जो जर्मन परराष्ट्र कार्यालय के ग्रंथरक्षा गृह में हाथ लगे थे), वस्तुत: सारे पूर्वी योरप को नाज़ी जर्मनी और सोवियट संघ के बीच बांटने की एक सन्धि थी । यह सोवियट नीति को एक साम्राज्यवादी , आक्रामक और विस्तारवादी के रूप में प्रकट करती है, यह स्तालिन के इस प्रयोजन को भी प्रकट करती है कि यथासम्भव पूर्वी योरप को प्रत्यक्ष सोवियट शासन अथवा कठपुतली देशों के अन्तर्गत कर लेना चाहिये । यह उस कार्रवाई की योजना थी जो उसने उस समय से की है। बाद की बातचीतों से, यद्यपि वे हिटलर के विश्वासघात के कारण बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हुईं , सोवियट संघ के और भी इरादों का पता चला था । १९४० की शरद ऋतु में बर्लिन की बातचीत के समय सोवियट सरकार ने अपने साथियों से केवल यही नहीं चाहा था कि वे दर्दानियालमें नौसेना सम्बन्धी और सैनिक अड्डों की स्थापना के लिये राज़ी हो जाएं ...

हो जाएं बल्कि यह भी घोषणा की थी कि वह फारस की खाड़ी के आम निर्देशन की भी अभिलाषाएं रखता था ।

इसके अतिरिक्त १९४५ में स्तालिन ने जापान के साथ युद्ध में शामिल होने के लिये एक यह शर्त पेश की थी कि युद्ध समाप्त होने पर सोवियट संघ को वे सारे प्रदेशीय लाभ और सारी आर्थिक सुविधाएं वापस मिल जानी चाहियें जो ज़ार ने उन्नीसवीं शताब्दि के अन्त में चीन से बलपूर्वक हथिया ली थीं।

साम्राज्यवादी विस्तार

सोवियट संघ संसार को यह जता रहा है कि वह शान्तिपूर्ण , अनाक्रामक और अपने सभी पड़ोसियों का एक मित्र है। किन्तु इस दिखावे की आड़ में वह साम्राज्यवादी विस्तार की एक नीति का अनुसरण कर रहा है। उसने फिनलैंड से लेकर रूमानिया तक के अपने सभी पड़ोसियों के प्रदेशों को संयुक्त कर लिया है , उसने , यद्यपि असफलता से , टर्की के सामने भी प्रदेशीय मांगें रखी थीं , और फारस को अपनी तरफ तोड़ने का भी प्रयत्न किया था , जापानी साम्राज्य को छोड़कर केवल वही एक ऐसा देश है जिसने चीनी गणराज्य की स्थापना के बाद चीनी राज्य-क्षेत्र को अपने में संयुक्त करने की श्रेष्ठता प्राप्त की है, उसने अतिक्रमण किया है अथवा अपनी लम्बी सरहद के इर्द - गिर्द वाले प्रत्येक पड़ोसी राष्ट्र के राज्य-क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया है ।

नाज़ी-सोवियट गठबन्धन , जिसका दस वर्ष पूर्व एक ऐसा आकस्मिक अन्त हुआ, सारे साम्राज्यवाद का विरोधी होने का दवा करने वाली एक साम्राज्यवादी शक्ति के इस लम्बे इतिहास की एक सच्ची घटना थी। सोवियट सरकार ज़ारशाही सरकार की उत्तराधिकारी है जो ऐसी स्थिर नीति का अनुसरण कर रही है जिसे उसके पूर्वजों ने पीटर महान के ज़माने से अपनाया था । ध्यान रखने की बात यह है कि आजकल , दस वर्ष पहले की तरह , सोवियट संघ अपनी असल नीति को छुपाने और अपने असली इरादों के बारे में संसार को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा है। एक बार फिर , जैसा कि तब , यह शान्ति के चैम्पियन , सभी छोटे राष्ट्रों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के समर्थक और सारे साम्राज्यवाद के दुश्मन तथा विरोधी का ढोंग रच रहा है ।

सोवियट संघ के शासकों के दिमाग़ में सोवियट संघ के हितों का बस यही मतलब है कि उनका राज्य और उनका नियन्त्रण अधिकाधिक क्षेत्र पर स्थापित हो जाना चाहिये, चाहे जीत कर हो या वशीभूत करके ।

H.S.32

विश्व युवा शिविर

भारतीय भाग लेंगे

विश्व युवा सभा (वर्ल्ड एसेम्बली आफ यूथ : डब्ल्यू० ए० वाई०) द्वारा आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय युवा शिविर में जिसका प्रबन्ध सात से लेकर २१ जुलाई तक के लिये चिगवेल (एसेक्स) में किया गया है तीस देशों के लगभग एक हजार तरुण भाग लेंगे । इन देशों में भारत भी है ।

डब्ल्यू०ए०वाई० की स्थापना दो वर्ष पूर्व तरुणों के मध्य मित्रता बढाने में सहायता के उद्देश्य से की गई थी। डब्ल्यू०ए०वाई के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय समितियां करती हैं । यद्यपि भारत , पाकिस्तान और लंका में ऐसी राष्ट्रीय समितियां नहीं बनी हैं पर इन तीनों देशों ने डब्ल्यू०ए०वाई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में रुचि दिखाई है । आशा है कि इस वर्ष के शिविर में भारत का प्रतिनिधित्व रहेगा । दो सप्ताहों की अवधि में अनौपचारिक वाद विवाद , नृत्य और खेलकूद के अतिरिक्त नागरिकता , संगीत और सामाजिक व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता पर भाषणादि होंगे ।

H.S.33/~~51~~

अनुसन्धान में नफील्ड निधि के अनुदान

छठी वार्षिक रिपोर्ट

फेलोशिप और छात्रवृत्तियों के अपने कार्यक्रम के अतिरिक्त नफील्ड निधि ने पिछले मार्च ३१को समाप्त हुए वर्ष में राष्ट्रमंडलीय देशों की अनुसन्धान स्कीमों की सहायतार्थ अनुदान दिये थे। इन अनुदानोंमें से एक:१,५०० पौं० (२०,०००रु)का:विशेष साधी: सामग्रियां प्राप्त करने के लिये वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कालेज को दिया गया था। इन नए अनुदानों की विस्तृत सूचना नफील्ड निधि की छठी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। इस निधि की स्थापना लार्ड नफील्ड ने १९४३ में १ करोड़ पौंड के उपहार से की था। पिछली रिपोर्ट के समय से भारत , पाकिस्तान और लंका ने नफील्ड फाउंडेशन से यात्रा सम्बंधी फेलोशिप (जो आस्ट्रेलिया , कैनडा , न्यूज़ीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका को उपलब्ध फेलोशिप जैसी हैं) प्राप्त की थीं । भारत को ब्रिटेन में अध्ययन के लिये प्रति वर्ष पांच फैलोशिप मिलती हैं (दो औषधिशास्त्र , एक इंजीनियरिंग , एक प्राकृतिक विज्ञान और एक समाजशास्त्रों में), पाकिस्तान के लिये तीन और लंका के लिए एक ।

H.S.34.

विद्यार्थी स्तम्भ

महोत्सव की प्रदर्शिनी में
भारतीय विद्यार्थी

जी०वी०टी० चर्च

थेम्स नदी के दक्षिणी किनारे की प्रदर्शिनी में, जो ब्रिटिश महोत्सव का केन्द्रीय भाग है, अधिकांश दिन, और विशेषतया सप्ताह के अन्त में, भारतीय विद्यार्थियों का अच्छा प्रतिनिधित्व पाया जाता है। कुछ दिन पहले मैं प्रदर्शिनी की सैर करने गया था। यहां पर मैंने १५ विद्यार्थी देखे : जिनमें से चार भारतीय थे। शेष आस्ट्रेलिया, माल्टा, बारबेडास, संयुक्तराज्य अमेरिका, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली के थे। बम्बई से आए जी०एन० पटेल तथा श्री० कन्हारे अपनी पत्नियों के साथ थे। श्री० पटेल लिन्कन्स इन में कानून के विद्यार्थी हैं और अर्थशास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं। उनकी पत्नी के अध्ययन का विषय समाजशास्त्र है। श्री० कन्हारे ने कुछ समय पहले शिल्पकला में अपनी अन्तिम परीक्षा पास की है और आजकल लन्दन में नगर निर्माण योजना के एक अध्ययन क्रम में जुटे हुये हैं। उनकी पत्नी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं।

श्री० कन्हारे ने प्रदर्शिनी में अपनी गहरी रुचि का उल्लेख करते हुये मुझे बताया कि यह रुचि एक उत्साही दर्शक की ही नहीं किन्तु, एक बड़ी मात्रा में, एक पेशेवर शिल्पकार की रुचि भी थी। श्री० पटेल ने कहा कि 'डोम आफ डिस्कवरी' (खोज और आविष्कार संग्रहालय) का चक्कर लगाने में ही एक पूरा दिन अच्छी तरह

... व्यतीत किया

व्यतीत किया जा सकता है। और हम लोगों ने उस दिन का अधिकांश भाग " डोम आफ डिस्कवरी " में ही बिताया। यहां अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज में ब्रिटिश प्रयत्नों का प्रभावदायक परिचय मिलता है। इससे पहले विद्यार्थियों ने कुछ समय प्रदर्शिनी की उस शाखा में बिताया था जहां विदेशी आगन्तुकों को ब्रिटिश राष्ट्र के चरित्र और परम्परा से कुछ परिचय दिया जाता है। चारों भारतीय विद्यार्थी उन छोटे छोटे मंचो से विशेषतया प्रभावित हुये थे जिनमें से प्रत्येक शेक्सपियर के किसी नाटक से कोई दृश्य दिखा रहा था। थेम्स नदी के दक्षिणी तट की प्रदर्शिनी के वे भाग जिनका विद्यार्थियों ने भ्रमण किया था स्वास्थ्य, नए स्कूलों इत्यादि से सम्बन्धित थे। उस दिन का भ्रमण समाप्त होने पर भी प्रदर्शिनी में देखने योग्य सारी वस्तुएं समाप्त नहीं हो पाई थीं।

श्री० पटेल ने प्रदर्शिनी के अपने पहले भ्रमण से उत्पन्न विचारों का उल्लेख करते हुये उसके शैक्षणिक महत्त्व पर ज़ोर दिया। श्री० कन्हारे ने कहा कि यह प्रदर्शिनी और उसके द्वारा चित्रित कहानी गौरव और गर्व की वस्तुएं हैं। दक्षिणी तट की प्रदर्शिनी के हाल में आए एक नए भारतीय आगन्तुक श्री० आर० जे० शाह हैं। आप अहमदाबाद से आये हैं और लिन्कन्स इन में कानून का अध्ययन कर रहे हैं।

H.S.35/51

पू र्व प श्चि म मै त्री प रि ष द

लन्दन में पूर्व पश्चिम मित्रता परिषद की हाल में हुई वार्षिक सभा के अवसर पर उपस्थित कई विदेशी विद्यार्थियों में भारत और पाकिस्तान के लोग भी थे। एक भारतीय विद्यार्थी तो सभा के व्याख्यानदाताओं में था। यह परिषद एक ऐच्छिक संगठन है जिसका कार्य ब्रिटेन आने पर विदेशी विद्यार्थियों का स्वागत, ब्रिटिश लोगों से इनका परिचय कराने के लिये सभा सम्मेलनों की आयोजना और ब्रिटिश परिवारों में परिवार के सदस्य रूप में इनके स्वागत की तैयारी करना है। परिषद की रिपोर्ट में, जिसमें इस समय ब्रिटेन स्थित औपनिवेशिक तथा पूर्व देशीय विद्यार्थियों की संख्याएं हैं, भारतीय विद्यार्थियों की संख्या २,७०० (पिछले वर्ष से ५०० अधिक), पाकिस्तान ७०० और लंका ५०० बताई गई हैं। इनमें वे विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हैं जिन्होंने अपने आगमन की सूचना किसी केन्द्रीय अधिकारी को न दी हो।

पूर्वदेशीय अध्ययनों में डिग्री

लन्दन में १६ जून को 'स्कूल आफ ओरियन्टल ऐन्ड आफ्रिकन स्टीज़' के वार्षिक दीक्षांत समारोह पर भारत, पाकिस्तान और लंका के कई विद्यार्थियों ने डिग्रियां प्राप्त कीं। आसाम के दो भारतीय विद्यार्थी : पी०के० चौधरी और अमला दत्त : ने इतिहास में विशेष योग्यता के साथ बी०ए० की डिग्री पाई और हैदराबाद (दक्षिण) के ख्वाजा मोइनुद्दीन जमील ने फारसी भाषा में एम०ए० की डिग्री ग्रहण की।

मद्रास उपकुलपति को उपाधि मिली

मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, सर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, को ग्लैसगो विश्वविद्यालय की ५००वीं वर्षगांठ के समारोहों के अवसर पर डाक्टर आफ ला की उपाधि दी गई। तीन दिनों के समारोह में, जो २१ जून को समाप्त हुये थे, कई विश्वविद्यालयों की ओर से सम्मान पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिनमें बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, लखनऊ और अन्नमलाई विश्वविद्यालय भी थे।

जेट वायुयान में छोटी दिशा दर्शक घड़ी

ब्रिटिश वायु सेना और नौसेना के नवीनतम जेट लड़ाकू वायुयानों में तीन औंसों के वज़न की एक अत्यधिक छोटी दिशा दर्शक घड़ी लगाई जा रही है। कहते हैं कि यह घड़ी, जो बड़ी (आकर्षण शक्ति युक्त घड़ियों) के नियम के अनुसार चलती है, वायुयान के उल्टे उड़ने पर भी अपना काम ठीक ठीक करेगी।

H.S.37

पेरिस वार्ता की असफलता

उप विदेश मन्त्रियों की पेरिस बातचीत के अन्तिम चरणों पर विचार प्रकट करते हुये "मैनचेस्टर गार्जियन" ने २२ जून के अंक में लिखा है कि यद्यपि विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के लिये विषय निर्वाचन का प्रयत्न छोड़ दिया जायेगा पर शायद कूटनीतिक मार्गों से कुछ बातचीत जारी रहे। पत्रों के और आदान प्रदान से कोई विशेष लाभ होता नहीं दीखता। यदि रूसी सचमुच सम्मेलन चाहते होते तो वे आसानी से उन तीन एजेन्डों में किसी एक को चुन सकते थे जो उनके सामने रखे गये थे। अटलांटिक सन्धि को सम्मिलित कराने की उनकी ज़िद सम्मेलन की आयोजना करने की असफलता के लिये पश्चिम को पूर्णतया दोषी ठहराने की चाल मालूम पड़ती है।

"टाइम्स" ने २२ जून के अंक में लिखा है : यह सभा सिर्फ चालबाज़ी का क्षेत्र रह गई जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक प्रचारात्मक लाभ उठाना है। कल की घोषणा के अनुसार पश्चिमी शक्तियां इस चाल से अब अलग रहेंगी। पश्चिम की ओर से सम्मेलन का प्रस्ताव अभी तक वैसा ही है और सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अब यही है कि एक सच्चे सम्मेलन का आधार (यदि आधार कहीं है भी तो) ढूंढा जाए ताकि ऐसा सम्मेलन सम्भव हो जो स्थानीय समझौते प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर चलें, बहस में बाज़ी मारने तक सीमित न रहे। ऐसा आधार ढूंढने के लिये यदि आवश्यक हो तो अन्य विधियां अपनाई जाएं और प्रयत्न कुछ समय के बाद किया जाए, अभी नहीं।

मोटर सुधार

ब्रिटिश मोटर इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन (ब्रिटिश मोटर उद्योग अनुसन्धान संस्था) एक लाख पौंड (१३.१३ लाख रुपये) से लेकर डेढ़ लाख पौंड (२० लाख रुपये) लागत तक की प्रयोगशालाएं बनाने वाली है जिनमें ब्रिटिश मोटरों को सुधारने के लिये अधिक वैज्ञानिक विकास कार्य किया जायेगा।

F.H.263

नए समझौते का प्रभाव ... ...

तिब्बत पर चीन का तगड़ा दबाव

डा० पर्सीवल स्पियर
आप सेल्विन कालेज, कैम्ब्रिज, के
फेलो हैं और किसी समय दिल्ली के
सैंट स्टीवेन्स कालेज में इतिहास के
प्रोफेसर थे

पीकिंग की यह घोषणा कि चीन और तिब्बत के बीच २३ मई को एक समझौता हुआ था सावधानी के साथ सोचविचार आवश्यक बनाती है। निस्सन्देह, बल के खुले प्रयोग द्वारा सम्पादित समझौते की अपेक्षा प्रतिबन्धों के बिना प्राप्त समझौता अधिक अच्छा है। पर क्या इस बात के प्रमाण हैं कि यह एक स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पादित समझौता था? तिब्बत का वर्तमान शासन निस्सन्देह तिब्बती जनता की इच्छाओं का सूचक है और प्रस्तुत समझौते में इस बात का कुछ लिहाज़ रक्खा गया है। पर क्या तिब्बत की **स्वायत्तता** का अस्तित्व अभी भी है? क्या इसकी स्वायत्तता का अस्तित्व भविष्य में भी बना रहेगा?

चीन ने तिब्बत पर तीन शताब्दियों से प्रभुत्व का दावा किया है। और सामान्यतया प्रभुत्व के इस दावे के साथ साथ तिब्बत की आन्तरिक स्वायत्तता की व्यावहारिक मान्यता भी थी। साधारण तौर पर चीन के प्रभुत्व का प्रश्न ब्रिटेन के लिये सन्देह का विषय नहीं रहा : उदाहरणार्थ चीन, तिब्बत और ब्रिटेन के बीच का

... १९१४ वाला

१९१४ वाला असफल समझौता जो इस विषय पर असफल नहीं हुआ था किन्तु सीमा निर्धारण के सवाल पर। इसके विपरीत, ब्रिटेन ने आन्तरिक स्वायत्तता के तिब्बती दावे को सदैव स्वीकार किया है और भारत में अपने उत्तरदायित्व के काल में इस दावे के समर्थन के प्रयत्न भी।

समझौते की शर्तें

नए समझौते में दलाई लामा का पद और उसकी सरकार का अधिकार स्वीकार किया गया है, धार्मिक स्वतन्त्रता को बनाए रखने और लामा मन्दिरों को संरक्षण देने की बात कही गई है। इसके विपरीत, साम्यवादियों के समर्थक, साम्यवादियों द्वारा नामजद, पंचन लामा को वापस लौटने और उत्तरी तिब्बत में फिर से जमने की अनुमति दी गई है।

इस प्रकार दलाई लामा पर तिब्बत के अन्दर से ही राजनैतिक दबाव डालने का रास्ता निकाल लिया गया है। सचमुच यह एक ऐसी साम्यवादी विधि है जिसका उपयोग हाल के वर्षों में पूर्वी योरप में इतनी सफलता के साथ किया जा चुका है। पहले एक जनतन्त्रवादी शासन के साथ साम्यवादी सहयोग की बात, तब मार्क्सवादी तानाशाही को स्थापित करने वाली 'शान्तिपूर्ण' क्रान्ति की चाल। यदि इस प्रसंग में आप 'जनतन्त्रवादी' की जगह 'आध्यात्मिक' शब्द रख दें तो यह समता स्पष्ट हो जायेगी।

पर सारी बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। समझौते की अन्य बातों से चीन के रुख पर अच्छी रोशनी पड़ती है। तिब्बत की सेना चीन की सेना में मिला दी जायेगी और तिब्बत की सरकार उस सेना के प्रवेश में सहायता करेगी। दूसरे शब्दों में, तिब्बत में चीन की एक अधिकार सेना होगी, और, समझौते की पूर्ति निश्चित करने के लिये, एक 'सैनिक मुख्य केन्द्र और राजनैतिक तथा सैनिक परिषद'।

लोगों द्वारा 'मांगे गये' सुधार कार्यान्वित किए जाएंगे। इसका अर्थ तो स्पष्ट है: अर्थात् यह कि पीकिंग की सरकार तिब्बतियों पर पीकिंग की इच्छानुसार सुधार मांगने के मामले में भरोसा नहीं करती। क्या क्या मांगा जाए यह भी सिखाया जायेगा, फूट फैलाने का कार्य चीनी 'कमिसारों' द्वारा किया जायेगा। विरोधियों को डराया जायेगा और, यदि आवश्यकता हुई तो, चीनी साम्यवादी शस्त्रास्त्रों से विरोध का दमन करने के लिये काम लिया जायेगा। चीन की घटनाओं से स्पष्ट

... है कि

है कि चीनी साम्यवाद लाल वेशभूषा में कनफूशियनवाद नहीं किन्तु स्तालिनवादी साम्यवाद है। ऐसी चतुराई से पीकिंग जिन "सुधारों" को कार्यान्वित कर सकता है वे केवल साम्यवादी होंगे। यदि इन चीजों की लोगों में स्वाभाविक इच्छा होती तो चतुरता की क्या आवश्यकता होती, शारीरिक बल की क्या ज़रूरत ? इस बात की पुष्टि तिब्बत और चीन के शासनों पर दृष्टि डालने से ही हो सकती है।

"... बदले या कुचले"

तिब्बत के समाज का सारा ढांचा धार्मिक है। दलाई लामा अपने आध्यात्मिक अधिकारों के बल पर, बुद्ध के एक रूप के अवतार की तौर पर, शासन करता है। लोगों पर न केवल शासन की लम्बी अवधि पर मठों और मन्दिरों का ज़ोर और प्रभाव है।

पर पीकिंग में तो एक ऐसा युद्धप्रिय साम्यवादी शासन है जो स्पष्टतया भौतिकवादी है, धर्म का विरोधी। कनफूशियन मंदिरों की उपेक्षा की जाती है। और कोरिया में चीनी कार्रवाई से स्पष्ट है कि वे अपने सिद्धान्त को बलपूर्वक चीन के बाहर ले जाने के लिये तैयार हैं।

साम्यवाद मुख्यतया आक्रमणात्मक है। पृथक प्रकार के शासन के साथ उसकी नहीं पट सकती, न पूर्व में, न पश्चिम में। उन्हें यह या तो बदले या कुचले। इसमें सन्देह नहीं कि तिब्बत पर चीन का दबाव, जो समझौते से स्पष्ट है, समय के साथ साथ और भी तगड़ा होता जाएगा।

F.H.278

कच्ची सामग्रियों की न्यूनता पूरक व्यवस्था

ब्रिटेन के नये मन्त्रालय का कामकाज

जान किंग्सले

आजकल ब्रिटिश संसद सामग्रियों के एक नये मन्त्रालय (जिसके प्रथम मन्त्री श्री० रिचर्ड स्टोक होंगे) की स्थापना से सम्बन्धित एक विधेयक पर विचार-विमर्श कर रही है ताकि कच्ची सामग्रियों की न्यूनता को दूर करने वाली कार्रवाइयां कार्यान्वित की जा सकें ।

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि संसार कच्ची सामग्रियों के एक संकट की ओर चला जा रहा था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन उद्योग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों के उत्पादन की तुलना में बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। वैसे कच्ची सामग्रियों की समस्या ने कोरिया में साम्यवादी आक्रमण के बाद प्रतिरक्षा कार्यक्रम के कारण उग्र रूप धारण किया था , किन्तु इससे पहले भी कई मुख्य सामग्रियों के ज्ञात विश्व संचय तेज़ी से कम होते जा रहे थे । ऐसा जचा था कि गन्धक , सीसा और जस्ता दस या बीस वर्षों और ज्ञात तांबा साधन लगभग चालीस वर्षों में समाप्त हो जायेंगे ।

बहुत सी धातुओं का प्रयोग बीसवीं शताब्दि में विचित्र ढंग से बढ़ गया था। १९५० में विश्व ने १९०० से बारह गुना निकेल प्रयुक्त किया था । हाल में सामग्रियों की खपत उनके उत्पादन की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। योरप सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र आर्थिक आयोग की १९५० वाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व का औद्योगिक उत्पादन १९५० में तेरह प्रतिशत बढ़ा जबकि कच्ची सामग्रियों के उत्पादन में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई थी। चूंकि ब्रिटेन अधिकतर आयात की जाने वाली कच्ची सामग्रियों पर निर्भर करता है इसलिये उसको समस्या का समाधान करने के लिये सरकार के एक विभाग की विशेष आवश्यकता है।

... जबकि विश्व

जबकि विश्व मांग के दबाव से कच्ची सामग्रियों का उत्पादन अधिकाधिक बढ़ना चाहिये किन्तु इस वृद्धि को शीघ्र प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि खान-खोदाई नवीन साधनों की लम्बी खोज, नये विद्युत केन्द्रों और शायद नये रेलमार्गों या सड़कों तथा निवासस्थानों के निर्माण पर निर्भर हो सकती है। जूट और ऊन जैसी कृषि सामग्रियों का विस्तार भी एक धीमा ढंग है जिसे रूई के समान हर वर्ष बदला नहीं जा सकता। इसलिये नये सामग्री मन्त्रालय को (पुन:शस्त्रीकरण कार्यक्रम की तत्काल अवधि के बाद) बहुत समय तक एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा।

मन्त्रालय का कार्य

नये मन्त्री को सामग्रियों की पर्याप्त सप्लाइयों की व्यवस्था तथा जहां उपयुक्त हो दुर्लभ सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ाने की कार्रवाई करनी है और यह भी देखना है कि वे किफायतशारी से इस्तेमाल की जाती हैं, फेंकी हुई सामग्रियों को नष्ट होने से बचाया जाता है तथा एवजी चीज़ों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक ये कार्रवाइयां व्यापार मंडल और सप्लाई मन्त्रालय द्वारा की गई हैं। नये सामग्री मन्त्रालय की स्थापना के फलस्वरूप व्यापार मंडल और सप्लाई मन्त्रालय की सामग्री शाखाओं को एक संगठन में संयुक्त कर दिया जायेगा। नया मन्त्रालय अधिकतर वही कार्य करेगा जो पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। उदाहरणार्थ, इस बात को निश्चित करने की कार्रवाई करेगा कि दुर्लभ सामग्रियों का सर्वश्रेष्ट प्रयोग किया जाता है। सप्लाई मन्त्रालय ने बहुत सी कम आवश्यक चीज़ों के उत्पादन के लिये जस्ता, पीतल और निकेल के प्रयोग पर पाबन्दी लगा दी है, और व्यापार मंडल गन्धक के बटवारे का जिम्मेदार रहा है।

इस्पात को कड़ा करने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली टंग्स्टेन नामक धातु की मौजूदा कमी के कारण उद्योग से टंग्स्टेन को अन्य कतरनों से पृथक रखने के लिये कहा जा रहा है। सप्लाई मन्त्रालय (जिसपर लोहा तथा इस्पात की जिम्मेदारी बाकी रहेगी) लोहा तथा इस्पात के संग्रह की वृद्धि करने के एक अन्दोलन को भी आगे बढ़ा रहा है ताकि जर्मनी से कतरन की बहुत तेज़ी से घटी हुई सप्लाइयों की कमी को पूरा किया जा सके। सल्फ्यूरिक ऐसिड की कमी के कारण वस्तुनिर्माताओं को प्रयुक्त ऐसिड फेंकने के बारे में दो बार सोचना पड़ता है। एवजी चीज़ों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे ऐन्हिडराइट नामक पदार्थ से (जिसकी ब्रिटेन में कमी नहीं है) सल्फ्यूरिक

... ऐसिड की

ऐसिड की तैयारी। स्वदेशी कच्ची धातुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस्पात उद्योग को आशा है कि वह १५,००,००० टन अतिरिक्त ब्रिटिश कच्चा लोहा प्रयुक्त करके कतरन और विदेशी कच्ची धातुओं की थोड़ी-बहुत कमी पूरा कर लेगा।

कोयला विकास कार्यक्रम

कोयला ब्रिटेन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वदेशी कच्ची सामग्री है और खानों के आधुनीकरण और नई खानों की खोदाई के लिये एक विस्तृत विकास कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है। किन्तु सामग्री मन्त्रालय इसकी सीधी ज़िम्मेदारी नहीं रखेगा क्योंकि राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग ईंधन तथा शक्ति मन्त्रालय की देखरेख के अन्तर्गत है। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विदेशी राज्य-क्षेत्रों से आने वाली कच्ची सामग्रियों की सप्लाइयों के विकास की ओर भी औपनिवेशिक कार्यालय द्वारा बहुत ध्यान दिया जा रहा है।

यद्यपि ब्रिटिश सामग्री मन्त्रालय कच्ची सामग्रियों की सप्लाइयों की सारी ज़िम्मेदारी नहीं सम्हालेगा किन्तु यह वर्तमान महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सरकार के बहुत से विभागों की नीतियों को एकीकृत करने का केन्द्र बहुत अच्छी तरह बन जायेगा।

N.E.H.58

साम्यवादी प्रेम की परिभाषा :

'गम्भीर, बौद्धिक, क्रान्तिकारी'

ला ल प्रे मि यों की
ब लि हा री

'सिलोन डेली न्यूज़' में 'थिसैयान' नाम से लिखने वाले व्यक्ति ने किसी चीनी व्यक्ति के (हांगकांग के किसी पत्र में प्रकाशित) पत्र का संकेत करते हुए लिखा है : साम्यवादी प्रेम में स्त्री और पुरुष के मध्य कोई स्वार्थी सम्बन्ध न होने के कारण प्रेम अपने उच्च से उच्च रूप को प्राप्त हो पाता है। ...यह प्रेम गम्भीर, बौद्धिक और निश्चित रूप से क्रान्तिकारी होता है।'

'थिसैयान' का कहना है : ज़रा सोचिए। यदि कोई कम्यूनिस्ट कन्या आपको बाग में सैर के लिये बुलाती है तो डरने की ज़रूरत नहीं। शायद वह अर्थशास्त्र के किसी गम्भीर विषय पर वाद विवाद करना चाहती है। इसके बाद 'थिसैयान' ने अपने चीनी मित्र के उपर्युक्त पत्र के शब्द उद्धृत किए हैं : चांदनी रातों में पेड़ों के नीचे स्कूली लड़कों और लड़कियों के समूह गम्भीर विषयों पर बहस करते पाए जाते हैं। आप लड़कों और लड़कियों को कानाफूसी करने के लिये अलग जाते नहीं पाएंगे। यदि शत्रु के एजेंट हमें प्रेम के मामलों में फसाने का प्रयत्न करते हैं तो वे मुंह की खाते हैं।'

आगे चलकर 'थिसैयान' लिखता है : लाल देशवासी प्रेम का मज़ा नहीं ले रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय अवस्था है। पर कोई कर क्या सकता है? साम्यवादियों ने चांद की रोशनी खोदी। जैसाकि हंगेरी के एक कवि ने लिखा था, साम्यवादी प्रेमी और प्रेमिका जब चांद की ओर देखते हैं तो वे केवल यही सोचते होंगे : 'चांद कितना सौभाग्यशाली है कि वह स्तालिन पर प्रकाश डालने का सुअवसर पाता है।'

F.H.275

केन्द्रीय अफ्रीकी संघ की ओर

संवैधानिक सुधार की सिफारिशें

केनेथ ब्रैडले

उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया, न्यासालैंड और ब्रिटेन के उच्च अधिकारियों ने पारस्परिक विचार विनिमय के फलस्वरूप एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। इन अधिकारियों की एक सभा दक्षिणी रोडेशिया के प्रधान मन्त्री, सर गाडफ्रे हगिन्स, के प्रस्ताव पर आयोजित की गई थी : पक्षपातरहित अध्ययन कर चारों सरकारों के सामने उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया तथा न्यासालैंड के मध्य अधिक सन्निकट राजनैतिक मैल स्थापित करने के विषय में सलाह देने के लिये। प्रतिवेदन ने कहा है कि कुछ विषयों के मामले में इन्हें 'ब्रिटिश केन्द्रीय अफ्रीका' का नाम देकर एक संघ के रूप में बनाना चाहिये। प्रतिवेदन ने संघ की आवश्यकता को तात्कालिक बताया है।

यद्यपि यह साहसी और दूरगामी प्रस्ताव प्रतिवेदन को अत्यन्त महत्व की सामग्री बनाता है पर इस बात को न भूलना चाहिये कि यह अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी सरकारों के सामने सिफारिशों तक ही सीमित है। यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रतिवेदन के फलस्वरूप जो कुछ निर्णय लिये जायेंगे वे तीनों केन्द्रीय अफ्रीकी सरकारों, ब्रिटिश सरकार और, अन्त में, संसद द्वारा। ये निर्णय तीनों प्रदेशों की जनता के साथ सम्पूर्ण विचार विनिमय के बाद और उत्तरी रोडेशिया तथा न्यासालैंड के अफ्रीकियों के अभिप्रायों का ध्यान रखते हुये ही लिये जायेंगे।

इस अन्तिम बात पर इसलिये ज़ोर दिया गया है क्योंकि, १९३८ से, ये लोग एक अधिक घनिष्ठ संघ का विरोध कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार, नैतिक दृष्टि से ... तथा पहले

तथा पहले की सन्धियों और वचनों के कारण, उनके हितों की रक्षा करने और उनकी इच्छाओं का पूरा ध्यान रखने के लिये बद्ध है।

प्रतिवेदन की सिफारिशें

प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि तीनों प्रदेशों के मध्य में अधिक सन्निकट मेल की आवश्यकता सच्ची और तात्कालिक है। उनकी अर्थ व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरिकाएं हैं। अफ्रीका के बचाव के लिये ये, स्पष्टतया, एक इकाई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अफ्रीका में अन्तर्जातीय सहयोग और उदारता के आदर्शों के आधार पर एक शक्तिशाली राजनैतिक अस्तित्व बनाने की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों से अधिकाधिक स्पष्ट हो रही है।

केन्द्रीय अफ्रीका के भावी विकास के लिये इन बातों की आवश्यकता को पूर्णतया समझते हुये उच्च अधिकारियों की इस सभा ने तब तीनों देशों की देशीय नीतियों का विश्लेषण किया और अधिक सन्निकट मेल स्थापित करने के लिये ऐसा ढंग निकालने का प्रयत्न जिससे उपर्युक्त आवश्यक अस्तित्व प्राप्त हो सके, वह शक्तिशाली बन सके, अफ्रीकियों का भविष्य सुरक्षित हो सके और यह सब उन्हें मान्य हो सके।

विश्लेषण से मालूम होता है कि इन तीनों देशों में देशीय नीति के अन्तिम लक्ष्य एक से हैं : अफ्रीकियों द्वारा योरोपीय लोगों के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में पूर्ण साझेदारी। प्रतिवेदन से यह भी मालूम होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुओं के स्वास्थ्य और वनसम्पत्ति के विकास जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं में (जैसाकि ये विषय अफ्रीकियों को प्रभावित करते हैं) कोई अन्तर नहीं है : शायद केवल यह कि इन पर दक्षिणी रोडेशिया ने अधिक धन खर्च किया है।

नीति के विषय में अन्तर तो अवश्य हैं और ये विशेषतया राजनैतिक विकास के रास्ते में पाए जाते हैं। संरक्षक सरकारों का विश्वास है कि अफ्रीकियों की राजनैतिक शिक्षा का एक आवश्यक अंग इस समय केन्द्रीय शासन तथा स्वयं उनके शीघ्रता से विकसित हो रहे स्थानीय सरकार के संगठनों में भाग लेने का अवसर है। इसके विपरीत दक्षिणी रोडेशिया का विश्वास है कि इस समय मुख्य ज़ोर आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी प्रगति पर डालना चाहिये। इस अन्तर का परिणाम उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया के विकास की अवस्थाओं में देखा जा सकता है। यद्यपि प्रतिवेदन ने ऐसे अन्तरों को उनके वास्तविक महत्व से वंचित नहीं किया है पर वह इन्हें विधि और समय का

... अन्तर समझता

अन्तर समझता है, सिद्धान्त का नहीं। प्रतिवेदन में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि संघ से ये अन्तर और कम हो जायेंगे और संघ योरोपियों के साथ अफ्रीकियों द्वारा सम्पूर्ण राजनैतिक साझेदारी पाने के अवसरों को बढ़ायेगा, कम नहीं करेगा।

संघ की रूपरेखा

इन सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुये अधिकारियों की इस सभा ने बड़े परिश्रम और बड़ी निपुणता से संघीय संविधान का ऐसा स्वरूप सामने रक्खा है जो एक तरफ दक्षिणी रोडेशिया के आत्मशासन के पद और, दूसरी तरफ, दोनों संरक्षक प्रदेशों में देशीय अधिकारों और नीतियों को बनाये रखने में सहायक होगा। इसमें प्रस्तावित संघ कठोर नहीं है। उसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश संविधान का अपना वर्तमान रूप बनाए रखेगा और संघीय सरकार को केवल कुछ विशिष्ठ विषयों का नियन्त्रण और संगठन सौंपेगा : जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के विषय, सम्वाद परिवहन, प्रतिरक्षा, चुंगी, योरोपीय शिक्षा, दीर्घ और मध्यकालीन अनुसन्धान इत्यादि। शेष सब विषय (अर्थात् अफ्रीकियों को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने वाले विषय) प्रादेशिक आधार पर और बिल्कुल आज जैसे रूप में संचालित होंगे।

संघीय सरकार में एक महाराज्यपाल और ३५ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका होगी। व्यवस्थापिका में १७ सदस्य दक्षिणी रोडेशिया, ११ उत्तरी रोडेशिया और ७ न्यासालैंड के होंगे जिनमें से प्रत्येक प्रदेश से अफ्रीकी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य होंगे। (और इनमें से प्रत्येक संरक्षक प्रदेश से दो अफ्रीकी होंगे)। संघीय मंत्रिमंडल साधारण ढंग का होगा जिसमें अफ्रीकी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के मध्य से एक व्यक्ति महाराज्यपाल द्वारा सेक्रेटरी आफ स्टेट की स्वीकृति के बाद अफ्रीकी हितों के मन्त्री के रूप में नियुक्त किया जायेगा। यह मन्त्री अफ्रीकी विषयों की एक मंडली का अध्यक्ष होगा। और इस मंडली में प्रादेशिक सरकारों के देशीय मामलों के लिये तीन मन्त्री होंगे : प्रत्येक व्यवस्थापिका से एक निर्वाचित अथवा गैर सरकारी सदस्य और प्रत्येक प्रदेश से एक अफ्रीकी।

अफ्रीकी हितों के मन्त्री का कर्तव्य संघीय विधान और नीति में अफ्रीकी हितों का ध्यान रखना होगा। अफ्रीकी विषयों की मंडली ऐसे सब विधान पर, उनके प्रकाशन के पूर्व, सोचविचार करेगी और उनके विषय में अपनी सम्मति संघीय सरकार के सामने रखेगी। यदि मंडली के अनुसार कोई विधेयक अफ्रीकियों के लिये हानिप्रद है तो इसका कार्य ... यह नहीं

यह नहीं कि विधेयक रुक जायेगा । सरकार उस विधेयक को लेकर फिर भी आगे बढ़ सकती है और व्यवस्थापिका उसे अपनी स्वीकृति दे सकती है। पर महाराज्यपाल को ऐसे मामले सेक्रेटरी आफ स्टेट के सामने रखना होगा। इस प्रकार बचाव के साधनों का प्रबन्ध कर प्रतिवेदन ने संरक्षक प्रदेशों में वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने का सुझाव दिया है और यह भी कहा है कि सब प्रादेशिक मामलों में संरक्षक प्रदेशों की सरकारें और उनकी नीतियां इस समय की भांति औपनिवेशिक विभाग के प्रति प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी हों ।

प्रतिवेदन में अन्य कई प्रस्ताव पाए जाते हैं जिनका कार्यान्वित किया जाना या न किया जाना बहुत अंश तक राजनैतिक सुझावों और तीनों प्रदेशों में इनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है ।

युवकों द्वारा संसार का सत्कार

थेम्स नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित ब्रिटिश महोत्सव के भाग में [illegible] युवकों और युवतियों की शाखा है जहां ये लोग संसार का आतिथ्य सत्कार करते हैं। इनके पास एक छोटी नाट्यशाला है जहां विभिन्न प्रकार के नाटक खेले जाते हैं। ऊपर की मंजिल में बाहरी खेल तमाशों का प्रबन्ध है । इसका सूचना कक्ष अच्छी पाठ्य सामग्री से सज्जित है ।

बड़े लोग , खबरदार

कोरम्स फील्ड नामक बच्चों के खेलने के मैदान में जो पश्चिम केन्द्रीय [illegible] में कोई व्यस्क व्यक्ति अकेले नहीं जा पाता । ६ एकड़ की यह भूमि , जिसका संचालन समझ और कल्पना का सूचक है , और जो कई प्रकार की साधन सामग्रियों तथा सुन्दर उद्यानों से युक्त है , केवल बच्चों के लिये है। इस भूमि को १६२६ में एक प्रसिद्ध समाचारपत्र स्वामी और लन्दन काउन्टी कौंसिल ने बच्चों की भलाई के लिये बिकने से रोक लिया था। यहां बच्चों के समूह विभिन्न प्रकार की कलाओं और आमोद प्रमोदों में तल्लीन पाए जाते हैं ।

F.H.265,

भारत का अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

ग्रामीण विकास में ब्रिटिश फर्म की सहायता

ब्रश - ऐबो कम्पनी समूह के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री० ए०पी० गुड ने (जो हाल में भारत की विस्तृत यात्रा करके गये थे) लन्दन के एक प्रेस सम्मेलन में यह बताया था कि आजकल उनकी कम्पनी पंजाब , बिहार और उत्तर प्रदेश में ट्यूब वेल्स (नल कूप) लगाने के अपने पहले ठेके को पूरा करने में लगी हुई है। श्री० गुड ने मुख्यतया यह पता करने को, कि उनकी कम्पनी समूह भारतीय कृषि तथा उद्योग के विकास में कैसे अत्यधिक सहायता पहुंचा सकता है , और प्रमुख अधिकारियों से सम्बद्ध समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये यह यात्रा की थी। श्री० गुड ने भारत में रहते हुए प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू, राजकुमारी अमृतकौर (स्वास्थ्य मन्त्री) और श्री० के०एम० मुन्शी (खाद्य मन्त्री) से बातचीत की थी।

उन्होंने यह बताया था कि जब कच्ची सामग्रियों की अत्यधिक कमी हो तो कच्ची सामग्रियां उस दिशा की ओर भेजी जानी चाहिये जहां वे अधिक समय तक काम दे सकें — जैसे भारत के किसान को वे साधन दिये जाने चाहिये जिनकी उसे आवश्यकता है। इस बात का प्रमाण कि ट्यूब वेल्स से क्या किया जा सकता है और क्या किया जा चुका है कैलिफोर्निया (अमेरिका) में देखा जा सकता है जहां की रेगिस्तानी ज़मीन को फल तथा सब्ज़ी उपजाने वाले एक उपजाऊ क्षेत्र में बदल दिया गया था । ट्यूब वेल्स लगाने से पहले यह ज़मीन बिल्कुल बंजर थी।

कम्पनी के एक हज़ार ट्यूब वेल्स के वर्तमान ठेके पर प्रकाश डालते हुए श्री० गुड ने बताया था कि मैं अब तक की जांच-पड़ताल से सन्तुष्ट हूं कि गंगा घाटी चालीस लाख

... पौंड की

पौंड की लागत पर एक लाख ट्यूब वेल्स को संभाल लेगी। यह सारी लागत गेहूं की वर्तमान कीमत को देखते हुए डेढ़ वर्ष से कम समय में लौटा दी जायेगी। इस रकम में ट्यूब वेल्स, पम्पिंग साधन और बिजली उत्पादन यन्त्र जैसी सब चीज़ें सम्मिलित हैं। आशा है कि इतनी रकम की सहायता आर्थिक सहयोग प्रशासन (ई०सी०ए०) अथवा विश्व बैंक से मिल जायेगी। लेकिन धन के अतिरिक्त यह भी देखना है कि कच्ची सामग्रियां और जनशक्ति अनावश्यक चीज़ों के लिये नहीं खपनी चाहिये।

सिंचाई और बिजली

यह कम्पनी समूह खेत सिंचाई के लिये ब्रिटेन से यथासम्भव छोटे इंजनों का निर्यात कर रहा था और किर्लोस्कर नामक भारतीय कम्पनी को खेत सिंचाई पम्पों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता भी पहुंचा रहा है। श्री० गुड ने श्री० मुंशी से यह भी वायदा किया था कि पहले ठेके के अलावा और भी १२,५०० इंजन भेजे जायेंगे। उनका ख्याल है कि जब तक औसत भारतीय गांव में जीवन स्तर ऊंचा नहीं किया जाता तबतक गांव से अधिक बुद्धिमान लोग शहरों की ओर जाते ही रहेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि शहरों में नियोजन पर अधिक बोझ पड़ने लगेगा और देहातों में दिमागों का स्तर नीचा ही रहेगा। संसार को कायम रखने के लिये देहातों और खेतों में बढ़िया से बढ़िया दिमाग पहुंचने चाहिये।

आगे चलकर श्री० गुड ने बताया कि गांव में बिजली पैदा करने पर बहुत लाभ पहुंच सकता है। कुओं, पम्पों और पिसाई मशीनों के संचालन के लिये शक्ति पैदा होनी चाहिये। यह काम निजी लागत से किया जा रहा है। हमने दिल्ली के निकट एक गांव चुना है। यदि यह विद्युतकरण योजना सफल रहती है तो कम्पनी समूह भारत में अपने स्टैन्डर्ड बिजली उत्पादन यन्त्र (जिसमें के दस हज़ार यन्त्र यह पहले ही बना चुका है) बनाने, लोगों को प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिये तैयार है। औसतन पांच हज़ार जनसंख्या वाले गांव के विद्युतकरण पर लगभग १२,५०० पौंड की लागत बैठेगी। इसमें शक्ति और बिजली दोनों सम्मिलित हैं —— किन्तु अधिकतर शक्ति।

यह बात निम्नलिखित संख्याओं से पता चल सकती है कि इस कम्पनी ने भारत में जीवन स्तर को सुधारने के आन्दोलन में कितना अंशदान दिया है :

... खेती के

१. खेती के छोटे डीसेल इंजनों का निर्यात : १६४६ में ८,००,००० पौंड मूल्य के (ब्रिटेन के कुल निर्यात के चालीस प्रतिशत के बराबर) , १६५० में १५,००,००० पौंड मूल्य के (ब्रिटेन के कुल निर्यात के ६५ प्रतिशत के बराबर) और १६५१ में १६५० जितने भारत के लिये भेजे जा चुके हैं ।

२. उद्योग और शक्ति उत्पादन के लिये बड़े डीसेल इंजनों का निर्यात : १६४६ में २,००,००० पौंड मूल्य के (ब्रिटेन के कुल निर्यात के २२ प्रतिशत के बराबर) और १६५० में ५,००,००० पौंड मूल्य के (ब्रिटेन के कुल निर्यात के आधे के बराबर) भारत के लिये भेजे जा चुके हैं ।

बच्चों का सेवा कार्य

लीड्स में बच्चों का एक समूह है जो अपने को "दि सिक्रेट फाइव" कहता है। इस समूह में १३ वर्ष के लड़के और लड़कियां हैं जो अपनी छुट्टी का समय पड़ोसियों , विशेषतया बड़े बूढ़ों के लिये छोटे मोटे कार्य करने में बिताते हैं ।

युवकों को शारीरिक शिक्षा

ब्रिटेन की बीस काउन्टियों के ४८ लड़के और लड़कियां ऐसी शारीरिक शिक्षा ले रहे हैं जो , उनके शिक्षकों के अनुसार , इस दिशा में ब्रिटेन का गौरव बढ़ाएगी। इस शिक्षाक्रम की आयोजना लन्दन के एक समाचारपत्र ने की है। इसपर व्यय भी वही कर रहा है। युवकों का यह शिक्षा केन्द्र लिलेशाल हाल , श्रापशायर में है । केन्द्र के पास ४३ कमरों का एक घर है और ६० एकड़ की भूमि ।

H.S.38

सन्धि बचाव की युक्तियों से परिपूर्ण
रहे किन्तु हो उदार : जापान के
विषय में अमेरिकन ब्रिटिश नीति का सार ... ...

जा पा न के सा थ
सन्धि की रफ़्तार

गाई विन्ट
सुपरिचित टीकाकार

कुछ समय पहले लन्दन में अमेरिकन राजनीतिज्ञ, श्री० जान फास्टर डलेस, और ब्रिटिश विदेश मन्त्री, श्री० मारिसन, दोनों सरकारों के मध्य में जापान के साथ शांति सन्धि विषयक मतभेद पर विचार कर रहे थे और उनकी बातचीत अब पूर्ण समझौते के रूप में समाप्त हो गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सन्धि के पक्की होने में अब बहुत समय न लगेगा : विशेषतया इसलिये क्योंकि सन्निकटरूप से सम्बन्धित अन्य सरकारें प्रगति के विषय में सूचित कर दी गई हैं और विश्व की घटनाओं पर ब्रिटेन की नीति से राष्ट्रमंडलीय सरकारों को अवगत रखने की व्यवस्था सारे समय पूरे ज़ोर से काम करती रही थी।

सोवियट सरकार ने इस अवसर को सन्धि को असफल बनाने या कम से कम उसमें विलम्ब डालने के एक और प्रयत्न के रूप में प्रयुक्त किया। उसने ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारों को एक बहुत लम्बा और बड़ी चतुराई से लिखा गया पत्र भेजा जिससे यह मालूम होता था कि, रूसी सरकार के मत में, यह सन्धि उन सब शक्तियों के एक सम्मेलन के सामने उपस्थित की जाए जिन्होंने जापान से लड़ाई की थी।

...यदि यह

रूसी प्रस्ताव

यदि यह प्रस्ताव वास्तव में उतना सीधा सादा होता जितना वह बाहर देखने में था तो पश्चिमी शक्तियां उसे बहुत उचित मानती । उनकी यह सदैव इच्छा रही है कि शान्ति सन्धि की रचना के कार्य में वे सब देश भाग लें जिन्होंने जापान से लड़ाई की थी। पर रूसी चाल का सार यह था कि, यद्यपि सन्धि की पुष्टि आम सम्मेलन द्वारा हो, पर उसका प्रारूप तैयार करना बड़े राष्ट्रों के हाथों में, उनकी विदेश मन्त्री परिषद में। विदेश मन्त्री परिषद के नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी अप्रिय निर्णय को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। यदि जापान की शांति सन्धि परिषद के सामने प्रस्तुत की जाती तो रूसी उसे निस्सन्देह अपने निषेधाधिकार का निशाना बनाते और सन्धि से सम्बन्धित निर्णय न जाने कब तक के लिये स्थगित हो जाते।

रूसी पत्र में ब्रिटेन और अमेरिका के जापान विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध कई शिकायतें भी की गई थीं। इस पत्र के अनुसार जापान का पुन:शस्त्रीकरण पाट्सडम घोषणा का उल्लंघन है और इस प्रकार अवैधानिक। पर अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून में यह सामानतया स्वीकार कर लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्रों का घोषणा पत्र अन्य सब समझौतों और रूढ़ियों से ऊपर है। और घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि आपत्तिकाल में अपने बचाव का अधिकार सब राष्ट्रों को है। कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र स्थायी और सम्पूर्ण रूप से शस्त्रास्त्रहीन नहीं रक्खा जा सकता।

इसी तरह की वैधानिक त्रुटियां रूस के पत्र में थीं। पर यद्यपि इस पत्र के तर्क वितर्कों का खंडन करना कठिन नहीं है किन्तु जापानी पुन:शस्त्रीकरण की आलोचना करने के कारण यह रूसी पत्र उन लोगों को पसन्द आयेगा जो जापानी आक्रमण के भुक्तभोगी हैं। ऐसी सन्धि जिसके आवरण में जापान की युद्धप्रियता फिर से जाग सकती है स्वाभाविकतया गहरी चिन्ता उत्पन्न करती है। लोग व्याकुल होकर पूछते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के लक्ष्य आखिर क्या हैं।

इसका उत्तर सीधा सादा नहीं है। उत्तर का एक भाग यह है कि जापान आज वही देश नहीं है जो वह दस वर्ष पहले था। यद्यपि उसके सुधार और उसमें नये जीवन के संचार सम्बन्धी जनरल मेकार्थर और उनके कर्मचारियों के कुछ विचार अतिरंजित हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हुये हैं और इनके

... कारण

कारण इस समय जापान के नागरिक और शांतिप्रिय तत्व ऊपर उठ गये हैं । इन तत्वों को अपनी श्रेष्ठता स्थायी बनाने का अवसर मिला है । इसके अतिरिक्त, जापान पर अधिकार के आरम्भ से ही यह मान लिया गया था कि अधिकार अस्थायी होगा। अधिकार का लक्ष्य था अपना शासन अपने आप करने वाले और शांतिप्रिय जापान का जन्म ।

इसलिये ब्रिटेन और अमेरिका का कहना है कि क्योंकि जापान को अन्त में जाकर सम्पूर्ण प्रभुता देनी होगी और क्योंकि उसका युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है इसलिये जापान को तुरत एक अत्यन्त उदार शान्ति सन्धि देना बुद्धिमत्ता का कार्य होगा । यह तो निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि प्रयोग सफल होगा या असफल । पश्चिमी देश जानते हैं कि जापान सम्बन्धी उनके प्रयोग खतरों से भरे हैं । जापानी समाज में सामरिकवाद और ऊटपटांगवाद का बिल्कुल अन्त होने में कई वर्ष लगेंगे । इसलिये जापान के सामरिकवाद की पुन:स्थापना से बचाव का प्रबन्ध न करना अमेरिका और ब्रिटेन के लिये भारी भूल होगी। सत्य तो यह है कि वे बचाव के सम्पूर्ण साधनों से युक्त एक उदार सन्धि सम्भव समझते हैं। वे जापान पर आर्थिक विधियों से नियन्त्रण जारी रखेंगे । जापान की आर्थिक अवस्था ऐसी है कि वह अपनी युद्ध मशीन का पुनर्निर्माण आयातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर रखने से ही कर सकता है । यदि उसकी आयात की संख्याएं इतनी अधिक बढ़ी कि सन्देह उत्पन्न होने लग जाए तो पश्चिमी शक्तियां आर्थिक प्रतिबन्धों के ज़रिये पुन:शस्त्रीकरण को तुरत रोक सकती हैं ।

H.S.39

हंगेरी का 'शुद्धि' संस्कार

मन्त्रियों पर वार

'हंगेरी में शुद्धि' शीर्षक देकर 'टाइम्स' ने १३ जून के अंक में लिखा है कि हंगेरी की राजनीति उसी मार्ग पर चल रही है जो रूस की साम्राज्यवादी पद्धति में 'पीपुल्स डिमाक्रेसियों' के लिये निर्धारित किया गया है। स्वयं नियुक्त साम्यवादी नेतृत्व के अन्तर्गत विभिन्न दलों का मेलजोल सबसे पहले चरण में साम्यवादी दल की प्रत्यक्ष तानाशाही के रूप में परिवर्तित होता है। यही बात हंगेरी में १६४८ में हुई थी : जब साम्यवादी और सोशल डिमाक्रेटिक दल हंगेरी के कामकाजियों के दल में मिल गये थे। दूसरा अध्याय, जिसका आरम्भ बाहरी घटनाओं के कारण तीव्र हो गया है, तथाकथित मास्को वाले साम्यवादियों द्वारा एकाधिकार ग्रहण करने के रूप में प्रकट होता है। इसके बाद पत्र ने उन तीन मन्त्रियों के नाम बताये हैं जो आजकल हंगेरी में हो रही 'शुद्धि' के शिकार हुये हैं। इन लोगों ने हंगेरी के विरोध आन्दोलन का संगठन किया था और, लाल सेना के प्रवेश पर, उन्होंने एक अस्थायी सरकार स्थापित की थी। मास्को वाले साम्यवादियों में से इस 'शुद्धि' के लिये कोई नहीं चुना गया।

H.S.40/51

ग्लैसगो विश्वविद्यालय के ५०० वर्ष

डाक्टर की उपाधियां : उत्सवों का उत्कर्ष

'टाइम्स' ने २१ जून के अंक में ग्लैसगो विश्वविद्यालय की स्थापना की ५००वीं वर्ष गांठ से सम्बन्धित उत्सवों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा है कि कई प्रमुख व्यक्तियों, जिनमें ब्रिटिश प्रधान मन्त्री, श्री० एटली भी थे, को डाक्टर की उपाधि देने की घटना ने उत्सवों को उनके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। आगे चलकर पत्र ने कहा है कि ग्लैगो की प्रसिद्धि शायद १८वीं शताब्दि के दूसरे भाग में अपनी चरम सीमा पर थी क्योंकि उस समय उसके साथ राजनैतिक अर्थशास्त्र के संस्थापक जार्ज एडम स्मिथ, ब्रिटेन में आधुनिक शरीर रचना शास्त्र के पिता, विलियम हंटर, और वाष्प गति के नये युग के सूत्रधार, जेम्स वाट, के नाम सम्बन्धित थे। ग्लैसगो विश्वविद्यालय बढ़ते बढ़ते सात हजार दो सौ विद्यार्थियों, जिनमें से १,४०० स्त्रियां हैं, का अध्ययन स्थान हो गया है।
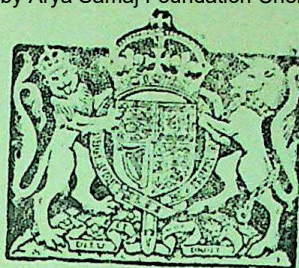
FORTNIGHTLY REVIEW OF NEWS AND EVENTS

HINDI

September 2 to September 15, 1951.

ISSUED BY THE
BRITISH INFORMATION SERVICES
EASTERN HOUSE, MANSINGH ROAD, NEW DELHI.

शान्ति सन्धि और
जा पा न के न ए दि न

****

वाल्टर टैपलिन

जापानी शांति सन्धि जापान और शेष संसार के साथ शांतिप्रिय तथा स्थिर सम्बन्धों की स्थापना की दिशा में एक निश्चित प्रयास है , एक पक्का योगदान । यह है शांति सन्धि से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो सम्भवत: भुलाई जा सकती है। मैंने ऊपर इसे एक 'निश्चित' योगदान कहा है और आगे बढ़ने से पूर्व फिर कहना चाहता हूं कि इस शब्द पर विशेष बल दिया जाना चाहिये ।

जैसाकि आप जानते हैं , रूसी प्रतिनिधियों की विरोधी प्रवृत्तियों के कारण सैन फ्रैंसिस्को सम्मेलन का बहुत समय सन्धि के बचाव में बीत गया और यों इस बात पर, कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नए समय का समारम्भ होता है, आवरण सा पड़ गया । केवल यही नहीं : बचाव का यह कार्य इतना प्रमुख प्रतीत हुआ कि सन्धि की रचना और तत्सम्बन्धी विचार विमर्श के विराट कार्य और उसपर व्यतीत समय को कोरी उतावली कहा जाने लगा।

पिछले ग्यारह महीनों के उन घोर प्रयत्नों से , जिनके फलस्वरूप सन्धि का अंतिम प्रारूप सामने आ सका , निस्सन्देह यह प्रकट होता था कि उसके विधेयक — अमेरिका और ब्रिटेन — इसे एक तात्कालिक महत्व का कार्य मानते हैं। यहां यह कहना असंगत न होगा कि शीघ्रता के साथ इस कार्य को सम्पादित करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को तनिक भी सन्देह नहीं था। वह श्री० डलेस द्वारा सन्धि की प्रारूप रचना का बड़ा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही जापान के साथ सन्धि करने की आवश्यकता प्रकट कर रही थी ।

... इसका कारण

इसका कारण स्पष्ट है। जापान के साथ औपचारिक युद्ध अवस्था का अन्त बहुत पहले हो जाना चाहिये था। जापान पर अधिकार का उद्देश्य —— युद्धजनित दुष्परिणामों के दिनों में देश की दशा सम्हालना —— पूरा हो चुका था। अब जापानी जनता और उनकी सरकार को अपनी शांतिप्रियता और जनतन्त्र में आस्था की यथार्थता प्रमाणित करने के अवसर देने चाहिए। उन्हें उसी अवस्था में रक्खे रहने से कोई लाभ नहीं था।

विश्व व्यापार में प्रवेश

सन्धि को स्वीकृति देनेवाली जापानी सरकार जापान की राजनीति के उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है जो नए प्रकार की आक्रमणप्रियता, नए सामरिकवाद, पर रोक लगने से हर प्रकार लाभान्वित होंगे। कुशासन के उन दिनों की, जब सेना के प्रधान राजनैतिक नेताओं की उपेक्षा कर सम्राट तक पहुंच पाते थे, पुनरावृत्ति रोकने से ही जापानी नीति का शांतिपूर्ण परिपालन और सच्चे शासन के रूप में उसका जीवन सम्भव है।

एक ओर प्रतिरक्षा के प्रभावदायक प्रबन्ध की मांग पूरी की गई है और उधर, जापान तथा अमेरिका के मध्य पृथक व्यवस्था के द्वारा, (जिसके अनुसार जापान में अमेरिकन सेना रक्खी जा सकती है) इस प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध को सीमा के अन्दर रक्खा गया है। इस अधिक दूरस्थ सम्भावना का ध्यान रखते हुये कि प्रशान्त सागर के अन्य देश जापानी सशस्त्र बलों की ओर से भयभीत हो सकते हैं अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के मध्य पृथक प्रतिरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं। यों आप देखते हैं कि जापान के लिए शांति का मार्ग भी खोल दिया गया है और उस मार्ग से च्युत होने में निहित खतरों का भी आगामी अनेकों वर्षों तक के लिए ख्याल रक्खा गया है।

जापान चाहे तो नूतन औद्योगिक विकास का अध्याय आरम्भ कर सकता है : वह चाहे तो बड़ी मात्रा पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश कर सकता है। इस दिशा के द्वार भी उसके लिये खोल दिये गये हैं। जापान के यन्त्रविदों द्वारा युद्धविनष्ट देशों की सहायता का उपबन्ध सम्भवत: जापानियों को व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करने में उतनी ही सहायता पहुंचाएगा जितना कि तात्कालिक लाभ देगा वह उसके पहले के शत्रुओं को। मनुष्य के अधिकारों और उसकी सुखसमृद्धि सम्बन्धी

... उन नियमों

उन नियमों का, जो संयुक्त राष्ट्रीय सदस्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, उल्लंघन किए बिना जापान के उत्पादक और निर्यातक मुक्त रूप से अपने मन के मार्ग पर चल सकते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यथाशीघ्र एक स्वीकार्य सन्धि की रचना के लिए इस दिशा में कुछ खतरों की सम्भावना के लिये तैयार रहना आवश्यक हुआ है। और ब्रिटिश सरकार को तो जापान की ओर से गहरी प्रतियोगिता — विशेषतया टेक्सटाइल और जहाज़निर्माण के क्षेत्रों में — की सम्भावना का सामना करने के लिये तैयार रहना है। यह कहना निरर्थक होगा कि उस युद्धपूर्व स्थिति के पुनरागमन की सम्भावनाएं समाप्त कर दी गई हैं जब असन्तोषप्रद श्रम स्थितियों के कारण सस्ते जापानी निर्यात प्राय: सम्भव हुआ करते थे। पर ब्रिटिश सरकार ने केवल यह औपचारिक शर्त अवश्य रखी है कि जापान के व्यापार और उसके व्यापारिक आचरण को देखे-समझे बिना उसके साथ विशेष सुविधायुक्त व्यवहार नहीं किया जाएगा।

निरापद नहीं

जहांतक शेष बातों का सम्बन्ध है, वास्तविकता को मान्यता देने से मुख नहीं मोड़ा गया : जापान के लिए स्वस्थ वैदेशिक व्यापार अत्यन्त आवश्यक है और संसार — विशेषतया एशिया — को वैसी तैयार वस्तुएं शीघ्र चाहिए जो जापान दे सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग जितने खुले रखे जा सकें उतना ही अच्छा है।

स्पष्ट है कि जापानी सन्धि को यथाशीघ्र सम्पादित करने की दिशा में अपना भाग लेकर ब्रिटिश सरकार ने सम्भवत: एक आपत्तियुक्त कार्य किया है। पर ऐसे खतरों से भयभीत होने से उन्नति हो ही नहीं सकती। जापानियों को विश्व घटनाओं में एक निश्चित भाग लेने की स्वतन्त्रता लौटाने में विलम्ब से अधिक गम्भीर संकट सामने आ सकते थे।

इसी बात ने सन्धि की त्रुटियों को अप्रधान महत्त्व की बात बना दी : मेरा तात्पर्य हस्ताक्षर के लिये चीनी सरकार को न बुला सकने, फ्रिस्को सम्मेलन में भारत के भाग न लेने और रूसी विरोध के होते हुए भी सन्धि के कार्य को पूरा करने से है। ये सारी बातें निस्सन्देह शोचनीय हैं।

... पर जापान

पर जापान के प्रति सच्ची सद्भावना और उसे संसार में उपयोगी भाग का नया अवसर प्रदान करने की इच्छा से प्रेरित किसी भी देश की सरकार सन्धि में आगे चलकर सम्मिलित हो सकती है या (ऐसी ही शर्तों पर) उसके साथ द्विपक्षीय समझौता कर सकती है। जापानी शांति सन्धि के अभाव आसानी से दूर किए जा सकते हैं। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक , अपने वर्तमान रूप में , यह सन्धि प्रशान्त क्षेत्र तथा अन्यत्र की शान्ति , स्थिरता और अभिवृद्धि में एक निश्चित योग दे सकती है ।

इन्हीं तीनों — शान्ति , स्थिरता और अभिवृद्धि — के लिए ब्रिटिश सरकार जापान के विषय में आपत्तियों की सम्भावना के लिये तैयार हैं ।

फ्रिस्को सम्मेलन की नई युक्ति

ब्रिटिश पत्रों की सम्मति

"सन्डे टाइम्स" ने सितम्बर ९ के अंक में कहा है कि जापान के साथ शांति करने की नई युक्ति बड़ी निर्विघ्नतासेपूरी की जा सकी। १९वीं शताब्दि की विधि पेरिस में १९१९ में असफल सिद्ध हुई । पर उसके बाद उसका स्थान लेने के लिये कोई सन्तोषप्रद युक्ति न मिली । जापानी शांति सन्धि के विषय में, प्रयुक्त की गई युक्ति की मुख्य बात केन्द्रीय निर्देशन है — शायद एक व्यक्ति का : जैसेकि इस मामले में श्री० डलेस द्वारा । पर परिणाम पर प्रभाव डालने वाली चीज़ निर्देशन है ; आज्ञा और आदेश नहीं ।

"डेली एक्सप्रेस" ने ११ सितम्बर के अंक में कहा है कि जापान के साथ शांति सन्धि कर अमेरिका ने केवल साम्यवादियों पर एक प्रबल विजय नहीं प्राप्त की पर ऐसी शांति की आशा को वह समीप लाया है जो स्थायी बन सकती है ।

"मैनचेस्टर गार्जियन" के मत में श्री० ग्रामीको की असफलता वर्तमान रूस विरोधी संगठन का बल दिखाती है । मास्को को एकमात्र सन्तोष सम्मेलन से भारत की अनुपस्थिति में प्राप्त हो सकता है । पर ऐसा रूसी कूटनीति के कारण नहीं हुआ ।

H.S.67

नदी तथा नहर यातायात
का अध्ययन

भारतीय विशेषज्ञों की ब्रिटेन यात्रा

ब्रिटेन में २१ सितम्बर को छः दूर पूर्वीय देशों (भारत, पाकिस्तान, बर्मा, हिन्देशिया, थाइलैंड तथा वियट नाम) से आये बारह आन्तरिक जल यातायात विशेषज्ञों के एक दल में भारत का शिष्टमंडल सबसे बड़ा है। यह यात्रा उस भ्रमण का भाग है जो योरप तथा उत्तरी अमेरिका के लिये संयुक्त राष्ट्रों की ओर से आयोजित किया गया है।

अपनी तरह की इस सर्वप्रथम यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि नदी तथा नहर यातायात के शिल्पकला विवरण सम्बन्धी (टेक्नोलोजिकल) प्रगतियों का अध्ययन किया जाए। इसका आयोजन एशिया तथा दूरपूर्व के लिये टैक्निकल सहायता प्रशासन तथा आर्थिक आयोग ने मिलकर किया है।

भारतीय शिष्टमंडल में के० बाथा, पी० बसु, ए० चौधरी, एम०एल० सूद और जे०एम० स्वीट आदि सज्जन सम्मिलित हैं। आगन्तुक दल सरकारी पदाधिकारियों शिल्पकलाविदों, यातायात प्रबन्धकों तथा इंजन निर्माताओं से भेंट तथा बातचीत करेगा और ब्रिटेन की अत्यन्त महत्वपूर्ण जलमार्ग व्यवस्थाओं को देखने जायेगा।

इस दल में सम्मिलित सदस्यों के देश अपने उन छोटे जल यातायात साधनों की चीजें लाने लेजाने की क्षमता को बढ़ाने की समस्या हल करना चाहते हैं जिनसे इन देशों में आजकल काम लिया जा रहा है। इस भ्रमण के पश्चात् विशेषज्ञ सार्वजनिक प्रयोगों के लिये एक स्कीम तैयार करेंगे। वे मौजूदा आन्तरिक यातायात समस्याओं का अध्ययन भी करेंगे।

यह दल पहली अक्तूबर को अमेरिका के लिये रवाना होगा।

सिं गा पु र का स म्मा न

नया पद प्रदान

पूर्व के एक अत्यधिक स्वस्थ तथा अत्यन्त सफल बन्दरगाह , सिंगापुर, को २२ सितम्बर के दिन एक बड़े नगर का दर्जा तथा महत्व प्रदान किया गया था । मलाया को मुख्य भूमि से जोहोर के तंग जलडमरूमध्यों द्वारा पृथक किया गया और संसार के एक मुख्य समुद्र मार्ग का प्रहरी यह द्वीप अपने आकार के अनुपात में कहीं अधिक सामरिक , व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

एक सौ बत्तीस वर्ष पूर्व , जनवरी १८१६ में , जब इस बस्ती के संस्थापक थामस स्टैमफर्ड रैफिल्स ने जोहोर के सुल्तान से २८ मील लम्बे दलदल से भरे हुए द्वीप का एक भाग व्यापारिक केन्द्र की स्थापना के लिये पट्टे पर लिया तो इसकी कुल जनसंख्या १३० मलायी और ३० चीनी लोगों की थी। आज यह सब जातियों के लगभग दस लाख आदमियों का घर है। जनसंख्या जैसी वृद्धि व्यापार, सम्पन्नता और सामाजिक प्रगति में भी हुई है । सिंगापुर का निर्माण व्यापार के आधार पर किया गया है। हर रोज़ रबड़ और टिन संसार के सभी भागों की ओर जाने के लिये इस प्रायद्वीप में आते हैं। जावा, सुमात्रा , हिन्द-चीन , बर्मा और स्याम आदि सभी देश अपने माल का कोटा (निर्धारित अंश) सप्लाई करते हैं जिससे सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया का एक व्यापारिक केन्द्र बन गया है ।

संस्थापक का स्वप्न यह था कि सिंगापुर अपनी व्यापारिक सफलता के अलावा पूर्व की शान्ति का पहरा देने वाला एक गढ़ और एक विद्या केन्द्र बन जाए किन्तु ऐसी बात बहुत वर्षों के पश्चात् प्रारम्भ की जा सकी थी। इस द्वीप ने द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने से कुछ समय पूर्व तक एक गढ़ का रूप धारण नहीं किया था, और यह तबतक भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था जब जापानियों ने इसे पराजित किया। यद्यपि १८२३ में रैफिल्स ने लिखा था : "शिक्षा की गति व्यापार के अनुसार होनी चाहिये ताकि इसके लाभ निश्चित और इसकी बुराइयां दूर की जा सकें।" उच्च शिक्षा के लिये यहां का सर्वप्रथम कालेज, रैफिल्स कालेज , कई वर्षों के बाद खोला गया था। हाल के वर्षों में सिंगापुर को वैसा बनाने की योजना ने जैसाकि इसके संस्थापक ने कहा था एक नई प्रेरणा प्राप्त की है। १९१९ में रैफिल्स कालेज को औषधिशास्त्र के किंग एडवर्ड सप्तम कालेज से संयुक्त कर दिया गया ताकि दक्षिण-पूर्व एशिया के एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में मलाया विश्वविद्यालय स्थापित हो सके।

N.E.H.73

ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली -- १

दलों दव्ारा नीति का स्पष्टीकरण

गाई एडेन
राजनैतिक सम्वाददाता, " डेली एक्सप्रेस ", लन्दन

> दलों और निर्वाचनों की वर्तमान ब्रिटिश प्रणाली, जिसका शताब्दियों से क्रमिक विकास होता आया है, देश को जगत के सबसे सच्चे जनतन्त्र का स्वरूप प्रदान करती है।

ब्रिटेन के समस्त राजनैतिक दलों के सामान्य सदस्य नीति के स्पष्टीकरण (और इस प्रकार देश के शासन) में भाग ले सकते हैं। जहाँतक नीति के निर्माण के लिये प्रत्येक दल की लम्बी चौड़ी कार्रवाई का प्रश्न है, इसका उद्देश्य तो दल के प्रचार के लिए जनता की स्वीकृति प्राप्त करना होता है।

यह व्यावहारिक दृष्टि से ठीक भी है। कारण, किसी दल को साथियों और समर्थकों को प्राप्त करने में सफलता उस समय तक नहीं मिल सकती जबतक उसकी नीति सदस्यों को आकर्षित करने के योग्य न हो। प्रत्येक दल के कुछ विश्वासी और पक्के समर्थक होते हैं जो उसके लिये मत देते और उसकी नीति का समर्थन करते हैं। पर संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिये प्रत्येक दल को "अस्थिर मत" अच्छे

... अनुपात में

अनुपात में आकर्षित करना पड़ता है। "अस्थिर मत" का अर्थ उन निर्वाचकों से है जो किसी दल के साथ औपचारिक सदस्यों के रूप में सम्बन्धित नहीं हैं और उसी दल को अपना वोट देंगे जिसकी नीति उन्हें पसन्द है। इस दृष्टि से अधिकांश निर्वाचक "अस्थिर मत" की श्रेणी में आते हैं। जहांतक वास्तविक "सदस्यों का सम्बन्ध है श्रम दल शायद ब्रिटेन का सबसे अधिक शक्तिशाली दल है। ट्रेड यूनियनों, सहकारिता आन्दोलन और अन्य संगठनों से उसका सुदृढ़ सम्बन्ध इसका कारण है। पर अन्य दलों दल (कांज़रवेटिव और लिबरल) के पास भी स्थायी सदस्यता काफी होती है। हां, शायद कम सुसंगठित।

जनमत का निर्माण, नीति का स्पष्टीकरण और निर्वाचकों में अपनी सर्वश्रेष्ठता का विश्वास उत्पन्न करना —— ये सब दल कैसे करते हैं? आजकल नीति की अधिकांश बातें सामान्य आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों से उत्पन्न होती हैं। इसलिये इनमें उपयोगिता और लाभ का गुण होता है —— केवल सैद्धान्तिक और आदर्शवादी गुणों के विपरीत। एक उदाहरण लीजिए। विश्व की वर्तमान कठिन परिस्थिति देखते हुये मुख्य दलों में मोटे तौर पर पुन:शस्त्रीकरण के विषय में कोई मतभेद नहीं हैं। हां, यदि संसार की हालत अधिक अच्छी हो तो बात दूसरी हो सकती है। तब शायद एक दल अधिक शस्त्रों का पक्ष लेगा और दूसरा इस नीति का घोर विरोध करेगा। तब यह होगा कि अधिक शस्त्रों के पक्ष में बोलने वाला दल सार्वजनिक सभाओं का आयोजन कर अधिक शस्त्रों की आवश्यकता पर प्रकाश और बल डालेगा। सभा में सम्मिलित व्यक्तियों में इस नीति की प्रतिक्रिया ध्यान से देखी जायेगी। सम्भव है कि जनता की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप किसी नीति के उस रूप में जो उसके प्रथम प्रकाशन के समय था संशोधन किया जाएगा। सम्भव है कि यह नीति जनता की प्रतिक्रिया के कारण कम दूरगामी बनाई जाए, अथवा अधिक दृढ़। इस प्रकार नीति पर मतदान का प्रश्न प्रकट होने से पूर्व ही निर्वाचकों का प्रभाव अपने को प्रकट करता है।

इसलिये प्रारंभिक चरणों में नीतियों की रचना की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है और सार्वजनिक सभाओं तथा समाचारपत्रों इत्यादि के द्वारा उन्हें निर्वाचकों के सामने रखने में सावधानी से काम लिया जाता है। इस चरण में किसी दल के उन विश्वासी और स्थिर समर्थकों का महत्व प्रकट होता है जिनका मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूं। नई नीति पहले उनके सम्मुख रखी जाती है और तब अन्यत्र प्रसारित

... होती है

दल के सम्मेलनों में सामान्यतया दलों के विभिन्न क्षेत्रों (नगरों , ग्रामों या बड़े क्षेत्रों) के उत्साही सदस्य होते हैं जो सम्मेलनों में प्रतिनिधियों के रूप में भेजे जाते हैं। सम्मेलन या तो वार्षिक होते हैं या देश के राजनैतिक जीवन की कुछ नई घटनाओं पर सोचविचार के लिये बुलाए जाते हैं। सम्मेलनों में प्राय: दलों के नेता बोलते हैं। वे प्रस्तुत नीति का समर्थन करते और आपत्तियों तथा आलोचनाओं को ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार सामान्य लोगों को नीति की रचना और उसके स्पष्टीकरण में भाग मिलता है।

प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत होने पर नीति दल के केन्द्रीय कार्यालय में जाती और प्रचार का विषय बन जाती है। इसके कई रूप हो सकते हैं : नई नीति को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझने के कारण उसे रेडियो द्वारा प्रसारित करना आवश्यक समझा जा सकता है। राजनैतिक दलों के प्रसारण के लिये "ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" निश्चित समय अलग रखता है। दलों के मध्य समझौते से यह समय उनमें बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त दल के केन्द्रीय कार्यालय को नई नीति के विषय में प्रचार सामग्री प्रकाशित करने का आदेश मिलता है। इनमें यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि नई नीति सारे देश और जनता के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी। राजनैतिक प्रचार की शाखा हाल के कुछ वर्षों से अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है और प्रत्येक दल की निधि के बड़े अंश का व्यय इस प्रकार किया जाताहै। राजनैतिक प्रचार यहसामग्री प्राय: निर्वाचक की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और प्रत्येक दल के केन्द्रीय कार्यालयों के अधिकारियों का कर्तव्य होता है इस प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और दल के नेताओं को उसके विषय में सूचित करना ।

प्राय: यह देखा जाता है कि देश के एक भाग को मान्य नीति दूसरे को अमान्य होती है। तब उसे यथासम्भव सबके लिए लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नीति की सामान्य स्वीकृति की बात के समुचित रूप से स्पष्ट हो जाने पर प्रचार का अधिक तीव्र किया जाता है।और सभाएं बुलाई जाती हैं। और पाठ्य सामग्री प्रकाशित की जाती है। उसी समय जब किसी नीति का समर्थन करने वाला दल उसके पक्ष में सारे तर्क उपस्थित करता है , दूसरा दल , जो इस नीति का विरोधी है , निर्वाचकों में उसकी हानियों की बात जमाने के प्रयत्न करता है। और यों जनता को दलों की विभिन्न नीतियों के पक्ष और विपक्ष में सारी धारणाएं सुनने का सम्पूर्ण अवसर मिलता है ।

जनता को विभिन्न नीतियां अच्छी तरह समझाने में राजनैतिक एजैंट महत्वपूर्ण भाग लेता है।

H.S.68

संसार में संकट के सम्भावित स्थान

"संकट स्थल" शीर्षक से "आब्ज़र्वर" पत्र ने सितम्बर 8 के अंक में लिखा है : कई लोग युद्ध की आशंका को रूस और उधर अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तियों के मध्य मुठभेड़ के रूप में देखते हैं। वे अमेरिका की नीति के प्रति आशंका और क्रोध-उत्पादक हो जाने के भय से देखते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका न केवल एक विराट शस्त्रीकरण कार्य में संलग्न है पर रूस के बाहर के देशों को आयुध भी प्रदान कर रहा है। अमेरिका न केवल संसार में सर्वत्र वायु के अड्डे स्थापित कर रहा है, वह जर्मनी तथा जापान के शस्त्रीकरण पर भी कृतसंकल्प है। इसके अतिरिक्त, इस विचारधारा के व्यक्तियों का कहना है, अमेरिका च्यांगकाई शेक की सहायता कर रहा है। तब क्या, ये व्यक्ति पूछते हैं, यह आशंका नहीं की जा सकती कि रूस अपने विरोधियों की शक्ति को यों बढ़ते देखकर और उसके अधिक बढ़ने के भय से, युद्ध की अग्नि में कहीं उतर न आए।

पत्र लिखता है : यह आशंका निश्चय ही रही है और अभीतक दूर नहीं हुई है। यह खतरा पश्चिमी शक्तियों के उस निर्णय का साथी है, उस निर्णय का अनिवार्य अंग है, जिसका उद्देश्य शान्ति की सुरक्षा के लिए सबल बनना है। पर हमारे सामने के तात्कालिक प्रमाण आश्वासन देने वाले हैं। युद्ध को रोकने के लिये युद्ध रूस द्वारा प्रारम्भ किये जाने के लक्षण नहीं दीखते।

"आब्ज़र्वर" के अनुसार यह आपत्ति आगामी वर्ष भी रहेगी, पर सब प्रकार के तर्कयुक्त अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह नियमितरूप से कम होती जाएगी। वह समय दूर नहीं है जब क्रेमलिन के लिए पश्चिम के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्य करना आत्महत्या को आमंत्रित करना होगा। युद्ध के इस विशिष्ट भय के पीछे हट जाने की बात हम सच समझते हैं। हां, सामान्यरूप से शायद वह अभी पूर्णतया समझी नहीं जाती।

...आब्ज़र्वर" का

'आब्ज़र्वर' का विचार है कि विश्वयुद्ध की सम्भावना सोवियट यूनियन की ओर से किसी प्रत्यक्ष आक्रमण में नहीं किन्तु ऐसी छोटी छोटी घटनाओं में है जो रूसी साम्राज्य के भयंकर विस्तार का सन्देह उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसी ही स्थिति कोरियाई संघर्ष से उत्पन्न हो सकती थी। न ही इस प्रकार के भय का अन्त हो गया है।

पर संकट की सम्भावना की दृष्टि से संसार में कुछ अन्य स्थान भी हैं : फ़ारस, काश्मीर, मध्यपूर्व। पत्र कहता है कि अमेरिकन नीति के विषय में चिन्ता के कारण हमें उपर्युक्त स्थानों के सम्बन्ध में ब्रिटेन के गम्भीर उत्तरदायित्व की ओर उदासीन नहीं होना चाहिये। कोरिया के अतिरिक्त, ये स्थान आज संसार के उन स्थानों में हैं संकट की सम्भावना जिनके समीप है।

भारत में शिशु पक्षाघात संस्था

शिशु पक्षाघात की चिकित्सा में मार्गदर्शिका, श्रीमती फातिमा इस्माइल, आजकल ब्रिटेन में हैं और शिशु पक्षाघात संस्था का व्यक्तिगत परिचय प्राप्त कर रही हैं। आपको आशा है कि बम्बई वापस आने के बाद वे वहां इस संस्था की पहली समुद्रपारीय शाखा खोल सकेंगी। शिशु पक्षाघात संस्था में लगभग नौ हज़ार सदस्य हैं और समस्त ब्रिटेन में चालीस शाखाएं। इसका जन्म १३ वर्ष पूर्व शिशु पक्षाघात पीड़ितों को पूर्ववत जीवन प्रदान करने की समस्या के सम्बन्ध में हुआ था।

तेल शुद्धि कार्यक्रम की विशालता

फाउले, साउथैम्पटन, में १४ सितम्बर को योरप का सर्वाधिक विशाल तेल शोधक कारखाना खोला गया। इसपर चार करोड़ पौंडों के व्यय का अनुमान लगाया है और इसकी गणना संसार के सबसे बड़े शोधक कारखानों में होगी। अलग अलग अंगों की दृष्टि से फाउले ब्रिटेन के तेल शोधक कार्यक्रम का सबसे बड़ा अंग है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य दो हैं : प्रथम, बढ़ती हुई मांग की पूर्ति और दूसरा शोधित तेल के आयातों में कमी।

F.H.388

राष्ट्रमंडलीय व्यापार का सतत विस्तार

तीन वर्षों में निर्यातों का दुगना परिमाण

जान किंग्सले,
आर्थिक और वित्तीय मामलों के
सुप्रसिद्ध टीकाकार

विश्व मामलों में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य का पता इस बात से चलता है कि आजकल इधर से उधर होने वाले व्यापार के लगभग १/३ भाग का श्रेय इसे प्राप्त है। ब्रिटिश व्यापार मंडल पत्रिका में प्रकाशित संख्याएं प्रकट करती हैं कि १९५० के आयातों का मूल्य ६,६४,६०,००,००० पौंड और निर्यातों तथा पुनर्निर्यातों का मूल्य ६,३५,८०,००,००० पौंड बैठा था।

पहले के वर्षों से तुलना करने पर पता चलता है (विश्व मूल्यों में परिवर्तनों के लिये छूट रखने के बाद भी) कि द्वितीय युद्ध के बाद विश्व व्यापार खुलने-चलने पर इसके व्यापार का विस्तार सन्तोषप्रद रहा है। उदाहरणार्थ, १९५० के कुल निर्यातों का मूल्य १९४७ के ३,२९,००,००,००० पौंड की संख्या से लगभग दुगने के बराबर था जबकि १९४८ के निर्यातों की रकम ४,३६,२०,००,००० पौंड और १९४९ के निर्यातों की रकम ४,७७,५०,००,००० पौंड थी। इसके विपरीत आयातों का मूल्य तीन वर्षों में ५० प्रतिशत बढ़ा अर्थात् १९४७ के ४,२९,५०,००,००० पौंड से १९४८ में ५,०५,६०,००,००० पौंड, १९४९ में ५,६२,४०,००,००० पौंड और १९५० में ६,६४,६०,००,००० पौंड तक पहुंचा था।

... इसमें कोई

इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९५० की अधिकतर वृद्धि कोरिया युद्ध के बाद मूल्यों की तीव्र वृद्धि की देन थी। फिर भी इससे यह बात नहीं छुपनी चाहिये कि कुछ सदस्यों ने पिछले वर्ष अपने निर्यातों के परिमाण को बढ़ाने की व्यवस्था की थी। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन के निर्यातों का परिमाण १९४९ की तुलना में लगभग १६ प्रतिशत बढ़ा और भारत ने इसी अवधि में अपने निर्यातों के परिमाण को दस प्रतिशत अधिक किया था। मलाया ने बहुत ही उल्लेखनीय वृद्धि की थी जहां रबड़ निर्यातों के परिमाण में २३ प्रतिशत की वृद्धि और साथ में १७५ प्रतिशत के एक औसत मूल्य सुधार से कुल निर्यातों के मूल्य में १३६ प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी।

उल्लिखित चीज़ों के व्यापार के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल बिल्कुल नये सोने का भी एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। दक्षिण अफ्रीका संघ और कैनडा इस मूल्यवान निर्यात व्यापार के लिये सबसे बड़ा अंशदान देने वाले हैं।

आर्थिक विकास

राष्ट्रमंडलीय व्यापार का एक बहुत भाग सदैव ही "परिवार" के अन्दर किया गया है। ब्रिटेन जो सबसे बड़ा खरीदार और विक्रेता है, अपने आयातों का २/५ से अधिक अंश साथी सदस्यों से प्राप्त करता और उन्हें अपने निर्यातों का लगभग आधा अंश भेजता है। इसमें का बहुत सारा व्यापार एक दूसरे का पूरक होता है। ब्रिटेन अपने आयातों का औसतन ४/५ अंश बाकी के राष्ट्रमंडल से मंगाता है जिसमें खाद्यान्न, ऊन, रूई, रबड़, खाने योग्य तेल और ऐसी अन्य कच्ची सामग्रियां सम्मिलित हैं जिनकी उसे अपने लोगों को खिलाने या अपने विशाल उद्योगों को चलाने के लिये आवश्यकता होती है। इसके बदले उसके निर्यातों का लगभग ६० प्रतिशत भाग साथी सदस्यों को जाता है जिसमें प्लान्ट, मशीनरी, कृषि साधन, वाहन, जहाज़, टेक्सटाइल और अन्य तैयार चीज़ें सम्मिलित हैं।

इस परस्पर व्यापार की उपयोगिता उन प्रयत्नों से निश्चित हो जाती है जो ब्रिटेन सारे राष्ट्रमंडल के नवीन उद्योगों के विकास में सहायता के लिये कर रहा है। वह केवल प्लान्ट, मशीनरी और अन्य आवश्यक साधनों को बड़े परिमाणों में निर्यात नहीं बल्कि टेक्निकल सहायता और वित्त की सप्लाई में सहयोग भी प्रदान कर रहा है। "परिवार" के अन्य सदस्यों के साथ वह पिछड़े हुये क्षेत्रों के जीवनस्तरों

... के सुधार

के सुधार की स्कीमों में भी सहयोग दे रहा है। इनमें की सबसे बड़ी स्कीम दक्षिण तथा दक्षिण - पूर्व एशिया के छ:-वर्ष विकास से सम्बन्धित कोलम्बो योजना है। अन्य स्कीमों में औपनिवेशिक राज्यक्षेत्रों के विभिन्न विकास सम्मिलित हैं —— औपनिवेशिक विकास अधिनियमों के अन्तर्गत पहले ही स्वीकृत स्कीमों पर लगभग २२,७०,००,००० पौंड की लागत बैठेगी।

राष्ट्रमंडल संसार के अन्य देशों के (जिनमें अमेरिका उल्लेखनीय है) व्यापार में भी एक बड़ा स्थान रखता है। पिछले वर्ष अमेरिका के आयातों का लगभग चालीस प्रतिशत भाग राष्ट्रमंडल दवारा सप्लाई किया गया था जिसके एक बड़े भाग में कागज़ सम्बन्धी वृक्ष का गुद्दा , रबड़ , ऊन , टिन और कोका आदि चीज़ें सम्मिलित थीं। इसके विपरीत , उसके निर्यातों का तीस प्रतिशत से अधिक अंश राष्ट्रमंडल को गया था । अमेरिकी व्यापार का एक बड़ा भाग कैनडा दवारा किया जाता है।

पश्चिम योरप के वे देश भी जो योरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन में शामिल हैं , राष्ट्रमंडल से आये भारी आयातों पर निर्भर रहे हैं , जिसने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के १९५० के कुल आयातों का लगभग १/५ भाग प्रदान किया था। निर्यातों का लगभग १/६ भाग राष्ट्रमंडल को गया था। इस वर्ष की प्रारम्भिक अवधि में इस व्यापार का मूल्य और भी बढ़ गया था।

इस प्रकार राष्ट्रमंडल विश्व व्यापार में बहुत सक्रिय है और आगे चलकर और भी प्रगति होने की सम्भावना दिखाई देती है।

ब्रिटेन — अमेरिका के सहयोग की शक्ति

स्वतन्त्रता की सारभूत बातों पर सहमति

राबर्ट वेटमैन, लन्दन
"न्यूज़ क्रानिकल" के प्रधान "वाशिंगटन स्थित सम्वाददाता

यदि इस निश्चयहीन संसार में कोई बात पक्की है तो वह यह कि ब्रिटेन और अमेरिका को पारस्परिक सहयोग करना है और यह भी कि वे ऐसा करेंगे — न केवल आज किन्तु भविष्य में भी : अर्थात् उस भविष्य तक जिसका अनुमान लगाने की आशा कोई कर सकता है ।

यह एक ऐसा सत्य है जिसे वर्तमान घटनाओं की सूचनाएं पृष्ठभूमि में डाल देती हैं । बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के मध्य में निरन्तर मतभेद होते रहते हैं और समय समय पर झगड़े भी । अमेरिका की सीनेट का कोई सदस्य किसी विषय पर ब्रिटिश नीति की आलोचना करता है तो उधर अमेरिका का विचार और उसका आचरण किसी ब्रिटिश संसदीय सदस्य की आलोचना का विषय बन जाता है। इस वाद विवाद में अटलांटिक के दोनों ओर के समाचारपत्र सम्मिलित हो जाते हैं और कुछ ऐसे परिचित तथा सब लोगों द्वारा प्रयुक्त किये जा सकने वाले तर्क वितर्कों से काम लिया जाता है जो शेष संसार को प्राय: यह दिखाते हैं कि ये दोनों राष्ट्र पारस्परिक मतभेदों के पाश में बन्धे हुये हैं।

पर वह व्यक्ति जो अपनी दृष्टि शीर्षकों तक सीमित नहीं रखता सरलता से इस बात का स्मरण कर सकता है कि यह अवस्था बहुत समय से चली आ रही है

... और इसने

और इसने किसी संकट का आभास मिलते ही शीघ्र आपस में मिलकर सुदृढ़ता के साथ कार्य करने की इनकी क्षमता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाला है। एक बात और : जैसाकि आप जानते हैं अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रति जितनी स्पष्टवादिता — कभी तो अशिष्टता तक — प्रदर्शित करते हैं वह उसी सहकारिता, उसी साझेदारी, के बस की बात है जो अत्यधिक बलशाली हो।

वास्तव में अमेरिका और ब्रिटेन की सहकारिता अत्यधिक शक्ति सम्पन्न है : इसे २०वीं शताब्दि की सर्वाधिक शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी कहना अत्युक्ति शायद न होगा। इस सहयोग की शक्ति का स्रोत न अमेरिकावासियों को त्रुटिहीन और सर्वथा सराहनीय समझने की ब्रिटिश प्रवृत्ति है और न ब्रिटिशवासियों को इस दृष्टि से देखने की अमेरिका की आदत। न ही इसका कारण वाशिंगटन में ब्रिटेन की समर्थक अथवा लन्दन में अमेरिका की समर्थक सरकारों का होना है।

पारस्परिक समझ

यह अटलांटिक के दोनों और स्पष्टतया समझी जाने वाली इस बात पर आधारित है कि ऐसी किन्हीं परिस्थितियों और परीक्षाओं में जिनकी कल्पना की जा सकती है, किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अवस्था में, इन दो राष्ट्रों के आधारभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा समान या सदृश नीतियों के पालन से ही हो सकती है।

'उस वातावरण की स्थापना करना और जीवित रखना जिसमें स्वतन्त्रता के विषय में अमेरिका का महान अभ्यास जीवित रह और फलफूल सके', यही, जैसाकि अमेरिका के परराष्ट्र मन्त्री, श्री० डीन ऐचिसन, ने कहा था, प्रजातंत्र के आदिकाल से अमेरिकन नीति का लक्ष्य और उसकी दिशा रही है। इस धारणा की एक सजीव तुलना कई वर्षों से ब्रिटेन के विभिन्न परराष्ट्र मन्त्रियों द्वारा भाषणों में व्यक्त विचारों से की जा सकती है। श्री० ऐचिसन के कथन में इन विचारों का एक सजीव सादृश्य है।

' ब्रिटेन भी ऐसे ही वातावरण में जीवित रह और अभिवृद्धि कर सकता है। वे स्वतन्त्रताएं जिनका सुख आज संसार का एक बड़ा भाग उठा रहा है शताब्दियों से ब्रिटेन में कई कष्टों और बलिदानों के साथ रची गई थीं।

... जब अमेरिका

जब अमेरिका और ब्रिटेन के लोग स्वतन्त्रता के विषय में कहते हैं तो उनका अर्थ महत्वपूर्ण राजनैतिक स्वतन्त्रताओं —— भाषण, समाचारपत्र, उपासना और सभा सम्मेलन —— तक सीमित न रहकर आर्थिक स्वतन्त्रताओं को भी —— जिन्हें प्रेज़िडेंट रूज़वेल्ट ने "अभाव से मुक्ति" का संक्षिप्त नाम दिया था —— सम्मिलित करता है।

अपनी भूमि के स्वामी होने और (बिना अपने साथियों या राज्य के हस्तक्षेप के) उसका उपयोग कर सकने, अपने गृह पर अधिकार करने और अपने तथा अपनी सन्तान के लिये निर्विघ्न जीवकोपार्जन करने के मनुष्यमात्र के अधिकार —— वास्तव में वह आर्थिक स्वतन्त्रता जिससे मनुष्य अपना कारबार या अपनी वृत्ति स्वयं चुनकर उसमें सफल हो सकता है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सकता है और किसी राज्य अथवा किसी सरकार के दास बनने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता —— ये ही ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों की मूल आवश्यकताएं हैं।

वे न केवल एक भाषा बोलते हैं पर एक परिवार के हैं। चाहे कुछ गौण विषयों पर उनके विचार विपरीत हों पर स्वतन्त्रता की सारभूत बातों के विषय में उनमें गहरी सहमति है। कारण, उनके विचार केवल सामान्य विश्वासों पर ही नहीं पर सामान्य अन्तःप्रेरणाओं पर आधारित हैं।

एक उदाहरण

इतिहास के पृष्ठ पलटने से यह प्रकट हो जायेगा कि उस समय से जब डेढ़ सौ वर्षों से अधिक पूर्व अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवासियों ने अपने को एक पृथक राष्ट्र का रूप दिया था अमेरिका और ब्रिटेन के मतभेद अभीष्ट परिणाम के विषय में लगभग कभी नहीं थे और लगभग सदैव सम्बन्ध रखते थे उनके मतभेद ऐसे परिणाम की प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि के विषय में जो दोनों को पसन्द था।

यही बात अमेरिका और ब्रिटेन के आज के मतभेदों के विषय कही जा सकती है। उदाहरण के लिये हम यों तो किसी बात को ले सकते हैं पर चीन विषयक नीति का प्रश्न शायद सबसे अधिक स्पष्ट उदाहरण होगा। साम्यवादी रूस चीन को अपना अनुचर राज्य बनाने में कभी भी सफल न होगा, चीन के अपरिवर्तनीय हित कभी न कभी ऐसी चीनी साम्यवादी सरकार का अस्तित्व असम्भव बना देंगे जो रूस की अनुगामिनी होगी, इसलिये उस द्वार को जिसमें अन्त में जाकर चीन

... स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता और आशा की पुन:प्राप्ति के लिये प्रवेश करेगा खुला रखने में ही बुद्धिमत्ता है : यह है ब्रिटेन का विश्वास ।

पर अमेरिका का विश्वास है कि यह परिणाम इतना अनिश्चित है, इतनी दूर, कि वह नीति का आधार नहीं बनाया जा सकता । अतएव एशिया की अधिक तात्कालिक आपत्तियों को देखते हुये एक पृथक मार्ग पर चलना आवश्यक है ।

किन्तु इस बात पर कि किस प्रकार का चीन और कैसा एशिया संसार की शांति और सम्पन्नता में सर्वाधिक योग दे सकता है अमेरिका और ब्रिटेन के दृष्टिकोण एकसे हैं । यह कार्य वही चीन और वही एशिया करेगा जिनमें जनता की सत्ता सम्मान पायेंगी और उसके अधिकारों को आदर की दृष्टि से देखा जायेगा, जिनमें श्रेष्ठतर अवसर और उच्चतर जीवनस्तर की जनता की नई अभिलाषा प्रोत्साहन प्राप्त करेगी और जिनमें पश्चिम की सहायता ऐसी शर्तों पर प्राप्त होगी जिनके विषय में किसी को लज्जित न होना पड़ेगा।

अभीष्ठ वातावरण

इसीसे सहायता मिलेगी उस वातावरण की रचना में जिसकी ब्रिटेन और अमेरिका समानरूप से कामना करते हैं : वह वातावरण जिसमें स्वतन्त्रता, राजनैतिक और आर्थिक उन्नति के तत्वों, अमेरिका और ब्रिटेन के सफल जीवन की अवस्था, इन सबका अस्तित्व और इनकी प्रगति सम्भव होगी।

यह कोई संयोग की बात नहीं है कि इस शताब्दि के दो महायुद्धों में अमेरिका के लोगों ने अटलांटिक पार कर उन शक्तियों के विरूद्ध संघर्ष किया जिनके कारण अमेरिका के हित — जो ब्रिटेन के हितों के सदृश पाये गये थे — आपत्तिग्रस्त थे । यह कोई राजनैतिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संयोग नहीं है कि आज अमेरिका और ब्रिटेन अन्य अटलांटिक राष्ट्रों के साथ मिलकर ऐसी शक्तियों से अपनी प्रतिरक्षा के लिये संलग्न हैं जो स्वतन्त्रता के वातावरण का विनाश कर सकती है ।

युद्ध, अशांति और स्वतन्त्रता का अपहरण, चाहे वे संसार में कहीं भी हों, ब्रिटेन और अमेरिका की प्रिय निधियों के अपहरण के कारण हो सकते हैं। शांति, स्थिरता और स्वतन्त्रता पर आचरण से उनको सब प्रकार के लाभ हो सकते हैं । ये

... लाभ इतने

लाभ इतने अधिक हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान इतना पूर्ण है कि आज ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे पुन:शस्त्रीकरण का व्यय सहन कर रहे हैं और बलिदानों का बोझ उठा रहे हैं जो उनकी अभीष्ठ स्वतन्त्रता और शांति की एकमात्र आशा प्रदान कर रहा है : ऐसा न होता तो उन्होंने बहुत पहले ही इस पुन:शस्त्रीकरण का परित्याग कर दिया होता ।

यद्यपि ये एक दूसरे के आयुधों की श्रेष्ठता के विषय में वाद विवाद करते हैं और एक दूसरे की योजना को अपनी आलोचना का विषय बनाते हैं पर उनका दृढ विश्वास और उनकी अन्त:प्रेरणा उन्हें बताती है कि उचित मार्ग वही है जिसपर आज वे दोनों चल रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वे इस यात्रा को सम्पूर्ण करने की पूरी आशा भी रखते हैं, उसी प्रकार जैसेकि हाल में उन्होंने अन्य यात्राएँ साथ साथ समाप्त की थीं।

H.S.69

तिब्बत पर चीन का नियन्त्रण

अधिकार का जाल फैल रहा है

"तिब्बत चीन के नियन्त्रण में" शीर्षक से "टाइम्स" पत्र ने ५ सितम्बर के अंक में कहा है कि तिब्बत की घटनाओं का काफी स्पष्ट चित्र खींचना अब सम्भव है। मई मास में दलाई लामा के प्रतिनिधियों ने पीकिंग में ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अनुसार स्वशासन के तिब्बती अधिकार के बदले में तिब्बत की प्रतिरक्षा व्यवस्था और उसके वैदेशिक सम्बन्धों के प्रश्न पर चीन द्वारा नियन्त्रण का अधिकार मान लिया गया था। घर वापस आने पर तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस आशय की शिकायत की थी कि उनके सामने हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प रक्खा ही नहीं गया था। तिब्बती प्रतिनिधियों के बाद शीघ्र ही दो चीनी मिशन आए।

एक मिशन ने, जो चैंग चिंगवू की देखरेख में आया था, पूर्वी तथा मध्य तिब्बत पर अधिकार जमाना, पुराने अधिकारियों को पदच्युत करना और विश्वसनीय व्यक्तियों को उनके स्थानों में टिकाना प्रारम्भ कर दिया है। दूसरा मिशन जिसके प्रमुख चैंग कुओहुआ हैं, एक नई "तिब्बती जनसेना" में चीनी साम्यवाद में पूर्णतया प्रशिक्षित तिब्बती सैनिकों को सम्मिलित करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है।

आगे चलकर "टाइम्स" कहता है: यह स्पष्ट है कि चीनी तिब्बत में डेरा डालने के लिये आये हैं। उन्होंने बेकार पड़ी भूमि से मार्ग बनाना प्रारम्भ कर दिया है। वे महत्त्वपूर्ण नगरों में छोटे छोटे दुर्गरक्षक दल नियुक्त कर रहे हैं। वे चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, यन्त्रविद्याशास्त्रियों को भेज रहे हैं। पूर्वी और मध्य तिब्बत में, जहां दलाई लामा का अधिकार अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहा है, चीनियों ने वर्तमान प्रशासन प्रणाली को ग्रहण कर ही सन्तोष कर लिया। पश्चिमी तिब्बत में उन्होंने अभी ही से बड़े बड़े परिवर्तन कर दिये हैं।

... आगे चलकर

भारत को ख़तरा

आगे चलकर पत्र ने कहा है कि यदि चीन अपने अधिकारों का आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करता तो तिब्बतियों से , जो बड़े बड़े सामन्तशाही नवाबों और मठों की स्वार्थपरता से ऊब गए हैं , उसे काफी समर्थन मिल सकता है । तरूण दलाई लामा विज्ञान और अपने देश की प्रगति में रूचि रखते हैं और यदि उन्हें सचमुच अवसर दिया गया उस अधिकार के उपयोग का जिसका सम्मान करने का वचन चीन दे चुका है तो वे चीन के लिए एक उपयोगी साथी सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि चीन ने उनकी उपेक्षा का प्रयत्न किया तो उसे अधिकाधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा । अन्त में पत्र लिखता है : भारत की सरकार निस्सन्देह तिब्बत की घटनाओं को ध्यानपूर्वक देख रही है । यदि यह अफवाह सच निकली कि तिब्बत में रूसी वैज्ञानिक और यन्त्रविद्याशास्त्री चीनियों की देखरेख में सक्रिय हैं तो भारतीय सरकार इस बात का सम्भवत: शीघ्र अनुभव करेगी कि उसके दव्वार के प्रति इस साम्यवादी प्रगति की तुलना में काश्मीर में `पश्चिमी साम्राज्यवाद` का भय एक दूरस्थ ख़तरा है ।

`का मे ट` की बड़ी
स फ ल ता

भारत और पाकिस्तान के प्रति `ब्रिटिश ओवरसीज़ ऐअरवेज़ कार्पोरेशन` के `कामेट` नामक जेट वायुयान की उड़ान को उसके प्रधान चालक , कैप्टन ए०एम० मैजेन्दी , ने एक `महान सफलता` कहा है । `कामेट` वायुयान अपनी उड़ानों के बाद सितम्बर ५ को ब्रिटेन वापस आया था ।

ब्रिटेन आने पर कैप्टन मैजेन्दी ने भारत और पाकिस्तान में प्रदर्शित स्वागत और इन दोनों देशों में `कामेट` के प्रति उपस्थित उत्साह के प्रति हार्दिक सन्तोष प्रकट किया । उन्होंने कहा कि प्राप्त सुविधाएं आशा से अधिक थीं । कैप्टन मैजेन्दी ने कलकत्ता में डमडम वायुयान के नए `रनवे` (वह भूमि जिसपर वायुयान उतरता और जिसपर थोड़ी दूर दौड़कर ऊपर उठता है) के विकास की प्रशंसा की और कहा कि यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि यह कार्य यथासम्भवशीघ्र समाप्त कर दिया जाएगा

H.S.70

रा ष्ट्र मं ड ली य वि श्व वि द्या ल यों में आदान - प्रदान

भारतीयों को अध्ययन अनुदान

राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालयों की विनिमय योजना के प्रथम दो वर्षों में राष्ट्रमंडल के ५४ विश्वविद्यालयों ने अध्यापकों को भेजकर या बुलाकर भाग लिया था। यह बात इस वर्ष ३१ मार्च को समाप्त हुए दो वर्षों के प्रतिवेदन से, जो हाल में राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालय विनिमय की समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रकट होती है।

जैसाकि समिति के अध्यक्ष, सर हैक्टर हेदरिंग्टन, (ग्लैगो विश्वविद्यालय के उपकुलपति और प्रधान) ने प्रतिवेदन के प्राक्कथन में कहा है, "यह राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षणिक आदान प्रदान के सफल प्रयास का उदाहरण है।"

यह योजना १९४८ की राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालय कांग्रेस से थोड़े ही समय पूर्व हुई विश्वविद्यालयों के प्रधानों की सभा द्वारा बनाई गई थी। स्वयं कांग्रेस ने इसे स्वीकृति दी थी, और ब्रिटिश कौंसिल ने लिया था भार उन साधनों को जुटाने का जिनकी सहायता से इसे एक पर्याप्तरूप से बड़ी मात्रा पर वास्तविकता में परिणत करना सम्भव हो सके। राष्ट्रमंडल में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के आवागमन को प्रोत्साहन प्रदान करने के उन कई प्रस्तावों में एक थी यह योजना जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति दी।

सर हैक्टर ने इस स्कीम के विषय में ये शब्द भी लिखे हैं: अबतक सारा अभीष्ठ नहीं प्राप्त हो सका। अबतक मुख्य आवागमन ब्रिटेन और समुद्रपारीण देशों के मध्य होता रहा है, पर स्वयं समुद्रपारीण देशों के मध्य पर्याप्त मात्रा में नहीं। ज्यों साधन विकसित होंगे यह भी सम्भव होगा और वर्तमान आदान प्रदान का विस्तार भी।

... इस विवरण

इस विवरण से सम्बन्धित दो वर्षों में १०२ अध्यापकों और विद्यार्थियों ने इस स्कीम में भाग लिया था । ये तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं । पहली श्रेणी में अध्ययन के लिये अवकाश पाने वाले ऐसे अध्यापक थे जिन्हें यात्रा के लिए अनुदान दिये गये थे और जो कम से कम छः महीनों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों में रहे । इस श्रेणी में पांच भारतीय थे और ये पांचों ब्रिटेन गये थे ।

इनके नाम हैं : प्रयाग विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यापक , श्री० ओ०पी० भटनागर , जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन सम्बन्धी अनुसन्धान के कार्य को पूरा करने गये थे । लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापक , डाक्टर जी०एस० वर्मा , लन्दन के इम्पीरियल कालेज में पौधों की चिकित्सा और उनके रोगों के निदान का अध्ययन करने गये थे । दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायनशास्त्र अध्यापक , डाक्टर आर०पी०मित्रा , भी इम्पीरियल कालेज गये थे : रसायनशास्त्र में उच्च अनुसन्धान के लिए । आगरा के एक कालेज के प्रधान , डाक्टर आर० के० सिंह ने लन्दन और लेस्टर में शिक्षा सम्बन्धी विधियों और प्रशासन का अध्ययन किया । बंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्था से डाक्टर एस०के०के० जटकर ने ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालयों का भ्रमण कर भौतिकी रसायनशास्त्र का अध्ययन किया था ।

समुद्रपारीण विश्वविद्यालयों के अन्य अध्यापक भी , जो इस श्रेणी में हैं , ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में आए : कैनडा से चार , आस्ट्रेलिया १३ , न्यूज़ीलैंड ६ और दक्षिण अफ्रीका १२ ब्रिटेन के दो अध्यापक दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों और दो कैनडा के विश्वविद्यालयों में गए थे ।

दूसरी श्रेणी में सम्मिलित किए गए व्यक्ति निमन्त्रण देने वाले विश्वविद्यालयों के आवेदनपत्रों के आधार पर थे , पहली श्रेणी के व्यक्तियों की भांति नहीं जिनके मामलों में आवेदनपत्र आगन्तुकों की ओर से थे ।

तीसरी श्रेणी के अनुदान पोस्ट ग्रेजुएट अनुसन्धानकर्ताओं , जिनमें अनुसन्धान की डिग्री के लिए काम करने वाले विश्वविद्यालय अध्यापक भी थे, को दिये गये थे । इस श्रेणी में दो वर्षों की इस अवधि में ४१ व्यक्तियों ने पंचाट (एवार्ड) पाए जिनमें से तीन भारतीय ब्रिटेन गए थे । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री० बी० भट्टाचार्य भौतिकशास्त्र के अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज गए थे , मैसूर के

...श्री० एम०

श्री०एम० शेषाद्रि लन्दन में पुरातत्व विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और सागर के श्री० डी०एस० श्रीवास्तव बेल्फास्ट के क्वीन विश्वविद्यालय में पशुविज्ञान का अध्ययन पा रहे हैं ।

१९४९ ५० में, जो इस स्कीम के कार्यरूप का पहला वर्ष था, अध्यापकों और ग्रेजुएटों द्वारा की गई यात्राओं के लिए ब्रिटिश कौंसिल ने ५००० पौंडों की राशि दी थी। आगामी वर्ष यह राशि बढ़ाकर ७००० पौंड कर दी गई । मांग के इतनी अधिक होने के कारण १९५१ - ५२ के लिए ९००० पौंड अलग रख दिये गये हैं ।

प्रतिवेदन के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस स्कीम के सम्पूर्ण संचालन में विलम्ब सम्भव हैं । आशा की जाती है कि कुछ समय बीतने पर राष्ट्रमंडलीय सरकारों के लिये इस स्कीम में समानान्तर अंशदान देना सम्भव होगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अबतक जिन व्यक्तियों को पंचाट दिये गये हैं उनमें भारत के दो और लंका के एक प्रोफेसर हैं । ये सब ब्रिटेन गए हैं।

कच्ची सामग्री विषयक वार्ता

कच्ची सामग्रियों की उपलब्धि और उनके उत्पादन से सम्बन्धित एक सभा, जिसमें राष्ट्रमंडलीय मन्त्रीगण भाग लेंगे, लन्दन में २४ सितम्बर को प्रारम्भ होगी और शायद लगभग एक सप्ताह तक चलेगी। इससे पहले भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के मध्य सरकारी स्तर पर विचार विमर्श होगा ।

F.H.413

रूसी ग्राम पर दृष्टिपात

*****

वाल्टर कोलार्ज

सोवियट सरकार ने व्यक्तिगत भूस्वामियों के वर्ग का अन्त कर दिया है और रूसी कृषकों को धनी (कुलाक), मध्यमवर्गीय (सेरेद्याक) और निर्धन (बेद्न्याक) में बाटने की प्रथा भी बन्द हो गई है। पर इसको अर्थ यह नहीं कि ग्रामों में देखी जाने वाली पहले की असमानता का स्थान अब समानता की किसी नई प्रणाली ने ले लिया है। सचमुच ग्रामों में विशेष सुविधाओं से सम्पन्न, विशेष अधिकारों से युक्त, एक नए वर्ग की स्थापना हुई है। इसके विषय में हाल में सोवियट यूनियन से आनेवाले शरणार्थियों ने विस्तार में बताया है।

ये शरणार्थी सोवियट यूनियन के लगभग सब भागों से आए हैं — स्मालैंस्क और उत्तरी काकेशस, खारकाव और साइबेरिया के टाम्स्क नामक प्रान्त जैसे दूर दूर बसे क्षेत्रों से। यद्यपि इन लोगों ने अपने अनुभव अलग अलग बताए पर उनके कथनों में इतनी सहमति है कि उनसे हम नए सोवियट ग्रामों की दशा का ऐसा दृश्य खींच सकते हैं जो पर्याप्तरूप से ठीक हो।

'कोल्खोज' (सामूहिक खेतों) के सच्चे स्वामी हैं मशीन ट्रैक्टर स्टेशन: इस तथ्य की पुष्टि करते हैं शरणार्थियों के कथन।

'कहीं अच्छा होता यदि मशीन ट्रैक्टर स्टेशन (एम०टी०एस०) को जोतने, बोने और काटने के लिये इतने पैसे देने के स्थान में हम कृषि सम्बन्धी यन्त्रादि स्वयं खरीद सकते', 'यही बात अधिकांश किसान कहते हैं और सोचते हैं। इस बात से किसानों में बहुत असन्तोष है कि एम० टी०एस० के इन बहुसंख्यक कामकाजियों — जिनमें सबसे ऊपर टेक्निकल निर्देशक और राजनैतिक उपनिर्देशक होते हैं — की देखभाल का व्यय उनसे लिया जाता है।

...अपनी आय

अपनी आय और रहनसहन की दशा के कारण एम०टी०एस० के कर्मचारी ग्रामों के नए अधिकारसम्पन्न समुदाय के आधार बने हुए हैं। उदाहरणार्थ, चकालव प्रान्त के एक शरणार्थी के अनुसार उसके ग्राम में घरों में बिजली का सुख केवल कुछ उच्च एम०टी०एस० अधिकारियों और 'कोल्खोज़' के प्रधान अधिकारी को मिलता है। साधारण कृषकों को साधारण, पुराने ढंग के, दीपक ही दिए जाते हैं। उसी ग्राम में 'कोल्खोज़' के अधिकारी के अतिरिक्त अन्य सब किसानों के पास एक कमरे वाले घर है। और एम०टी०एस० कर्मचारियों के पास ? प्रत्येक परिवार को चार कमरों वाले घर प्राप्त है।

किसानों का रोना

जीवन निर्वाह के उच्च ढंग को देखकर एम०टी०एस० कामकाजियों से जलन करना ठीक न होगा। वे प्रत्येक अर्थ में प्रसन्न नहीं हैं। 'असन्तोषजनक' कार्य के लिए उन्हें नौकरी से अलग करने का असीमित अधिकार मिला हुआ है एम०टी०एस० के निर्देशकों को।

टेक्निकल दृष्टि से एम०टी०एस० का मूल्य क्या है ? इस विषय में पृथक पृथक विचार प्रकट किये गये हैं। पश्चिमी साइबेरिया के चेल्याबिंस्क नामक प्रान्त के एक निवासी ने, जो कृषिसम्बन्धी विषयों से भलीभांति परिचित है, बताया कि अप्रैल या मई मास में 'कोल्खोज़' को प्राप्त होने वाले ट्रैक्टरों में से साधारणतया आधे से अधिक देखभाल की त्रुटियों और कल पुर्जों की कमियों के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। इस बात से कि सोवियट के सबसे बड़े ट्रैक्टर संयंत्रों में से एक चेल्याबिंस्क में स्थित है प्रस्तुत कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय बन जाता है। फलत: इस आशय की अफवाहों से आश्चर्य नहीं उत्पन्न होना चाहिये कि प्रचार के लिए नए नए सोवियट ट्रैक्टर तो चीन और अन्य देश भेजे गए और सोवियट किसानों को पुराने और टूटे ट्रैक्टरों से काम चलाना पड़ा।

यद्यपि रूस के अन्य भागों — विशेषतया उत्तरी काकेशस क्षेत्र, कज़ाकस्तान और क्राइमिया — से रूसियों द्वारा लाई सूचना के अनुसार मशीन ट्रैक्टर स्टेशन काफी अच्छी हालत में हैं पर उन स्थानों में भी जहां मशीन ट्रैक्टर स्टेशन सन्तोषप्रद कार्य कर रहा है उसके द्वारा सामूहिक खेतों की आय के इतने बड़े अनुपात का हड़प करना किसानों का रोना है।

ग्रामों का

ग्रामों का यह नया सुविधासम्पन्न वर्ग एम०टी०एस० के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसमें सामूहिक खेतों का अधिकारी समूह भी सम्मिलित है। अपने अवकाश का समय मास्को प्रान्त के किसी सामूहिक खेत पर व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति ने, जो पहले सोवियट सेना में था, 'कोल्खोज़' के प्रशासकवर्ग की रुचिप्रद रूपरेखा दी है। उच्च श्रेणी में 'प्रधानाधिकारी और प्रबन्धक, एक कृषि सम्बन्धी अधिकारी, हिसाब किताब रखनेवाला एक व्यक्ति, उसके दो सहायक, दुग्धशाला का प्रबन्धक, पशुचिकित्सक, मुनीम, भंडारी, छः प्रधान कर्मचारी, एक ग्राम पुस्तकाध्यक्ष और ग्राम क्लब का एक प्रबन्धक होते हैं।

हां, 'कोल्खोज़' के प्रधानाधिकारी और अन्य अधिकारियों को साथी किसानों के विरुद्ध सरकार का पक्ष लेने वाले समझना ठीक नहीं है। कई शरणार्थियों के कथनों से प्रकट होता है कि सामूहिक खेतों के कई प्रधानों को किसानों की हित रक्षा के 'अपराध' में हानि उठानी पड़ी। खारकाव प्रान्त के एक सामूहिक कृषक के अनुसार उसके 'कोल्खोज़' के मुखिया को राज्य के लिये असाधारणतया अधिक अनाज का संग्रह न करने पर दस वर्षों के कारावास का दंडादेश मिला था।

किसानों के स्थान में विशेषज्ञ रखना

कई सामूहिक कृषक 'कोल्खोज' के प्रधानाधिकारी पद के लिये ऐसे अभ्यर्थियों को अविश्वास से देखते हैं जो साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं। चेल्याबिंस्क प्रान्त के शरणार्थियों के अनुसार, वहां के कृषकों ने अपने 'कोल्खोज़' के प्रधान के पद पर अदलीय व्यक्तियों को आसीन कराने के लिए एक आन्दोलन चला रक्खा है। स्वयं इन व्यक्तियों ने १९४७ में निर्वाचन सम्बन्धी एक ऐसी सभा में भाग लिया था जिसमें साम्यवादी ज़िला समिति का अभ्यर्थी असफल रहा था। हां, वह बेचारा निर्वाचित व्यक्ति कुछ महीनों के बाद धन अपहरण के अपराध में पकड़ लिया गया।

क्यूबान क्षेत्र के एक किसान ने बताया था कि १९४६ की भुखमरी के भयंकर दिनों में 'कोल्खोज़' प्रधानाधिकारियों को सामूहिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। तब 'कोल्खोज़' के प्रधानों ने अधिकारियों से इस आशय की अनुमति मांगी थी कि ग्राम में संकटकालीन संग्रह के रूप में एकत्रित अनाज क्षुधापीड़ितों तक पहुंचाया जाए। जब अनुमति की अप्राप्ति से उत्पन्न आवेश में आकर कुछ ने आज्ञा

... की अवहेलना

की अवहेलना कर संचित अनाज जनता में बाटना प्रारम्भ किया तो गुप्त पुलिस ने इस दृश्य में प्रवेश किया और 'कोल्खोज़ों' की व्यवस्था को 'पुनर्संगठन' का रूप दे दिया।

'कोल्खोज़ों' के मुखिया लोगों से सम्बन्धित ये घटनाएं तत्सम्बन्धी सोवियट नीति के कुछ परिवर्तनों पर अच्छा प्रकाश डालती है। मेरा तात्पर्य पृथक पृथक 'कोल्खोज़ों' को आपस में मिलाने और कृषिशास्त्र विशेषज्ञों को उनके प्रधानाधिकारी बनाने की उस नीति से है जो १६५० की ग्रीष्मऋतु से चली आ रही है। स्पष्टत: सरकार किसानों के मध्य से चुने गए व्यक्तियों की अपेक्षा इन विशेषज्ञों को साम्यवादी दल और राज्य के लिए अधिक विश्वसनीय समझती है।

'कोल्खोज़' की व्यवस्था में किसानों के स्थान में विशेषज्ञों को लगाने की यह क्रिया एक बड़ी मात्रा पर की जा चुकी है। यों हम देखते हैं कि 'कोल्खोज़' की व्यवस्था का कार्य किसानों के हाथों से उसी प्रकार हटा लिया गया है जैसे बीस से अधिक वर्ष पहले उद्योगशालाओं की व्यवस्था में साधारण कामकाजियों का भाग समाप्त कर दिया गया था।

उपभोक्ता खर्च की एक ब्रिटिश जांच से पता चलता है कि कई आय समूहों में पुरूष अपने बालोंके सौन्दर्य के लिये स्त्रियों की तुलना में अधिक ख़र्च करते हैं।

का न्ति की की म त

ब्रिटेन में बालों के सौन्दर्य तथा कान्तिवर्धक चीज़ों के लिये १२,००,००,००० पौंड वार्षिक ख़र्च किये जाते हैं और इस रकम का लगभग तीन चौथाई भाग महिलाओं के लिये ख़र्च होता है। ये सारी बातें सूचना सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यालय के सामाजिक जांच विभाग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दी गई हैं। यह जांच उपभोक्ता खर्च सम्बन्धी उस सीरीज़ का एक भाग है जो केन्द्रीय गणना कार्यालय के निवेदन पर तैयार की गई है और इसमें सोलह तथा अधिक की आयुवाले उन २,९१६ व्यक्तियों का एक मामूली नमूना प्रस्तुत किया गया है जिनसे १९४९ के नम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में ब्रिटेन के ११६ क्षेत्रों में पूछताछ की गई थी।

सम्पूर्ण ख़र्च की रकम में से ८,००,००,००० पौंड कान्तिवर्धक तथा श्रृंगार पदार्थों और ४,००,००,००० पौंड बालों की कटाई आदि पर व्यय किये गये थे। इन तीनों चीज़ों पर प्रतिव्यक्ति के ख़र्च की मासिक औसत ३ शि० पौने ग्यारह पे० थी। स्त्रियों ने कान्तिवर्धक चीज़ों पर ५ शि० ढाई पे० मासिक औसत से ख़र्च किया था (इसमें १७ प्रतिशत दांत मंजन तथा लेस पर ख़र्च होता है) इस मद में के अधिक ख़र्च करने वाले १६ से १९ वर्ष तक के तरूण और पांच पौंड से अधिक की साप्ताहिक आय वाली स्त्रिएं हैं। एक विस्तृत जांच पड़ताल से पता चलता है कि कान्तिवर्धक चीज़ों पर तरूण ८ शि० मासिक , बीसवें वर्ष तक की स्त्रिएं लगभग ७ शि० ६ पे० , ३० - ४९ वर्षीय समूह वाले ६ शि० १ पे० और साठ वर्ष की आयु के बाद वाले केवल १ शि० ६ पे० ख़र्च करते हैं। इस रकम में से ११ प्रतिशत भाग चेहरा क्रीम में चला जाता है और हरेक स्त्री साढ़े छ: पे० मासिक व्यय करती है। पाउडर पर साढ़े पांच पे० और ओठों की लाली पर ५ पे० का मासिक ख़र्च बैठता है। बाल काटने तथा श्रृंगार करने वाले नाई की दूकान पर स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जाते हैं। थोड़ी आय वालों में पुरूष अपने बालों की काटछांट आदि पर स्त्रियों की तुलना में अधिक ख़र्च करते हैं किन्तु अधिक आमदनी वाले समूहों में इससे उल्टा होता है।

F.H.426

दायित्वपूर्ण पदों के लिये कामकाजियों का प्रशिक्षण

ग्रीष्मकालीन स्कूलों की उपयोगी सहायता

हरबर्ट ट्रेसी,
ब्रिटिश टी०यू०सी० के सदस्य

ब्रिटेन में ट्रेड यूनियनवादियों के ग्रीष्मकालीन स्कूलों ने अब एक स्थापित संस्था का रूप धारण कर लिया है। इनमें के बहुत से स्कूल विभिन्न शिक्षात्मक निकायों की देखरेख में हर वर्ष चलाये जाते हैं। ऐसे निकायों में ब्रिटिश ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का शिक्षा विभाग, कामकाजियों की शिक्षात्मक संस्था, श्रम कालेजों की राष्ट्रीय परिषद, श्रम दल, सहकारी संघ का शिक्षात्मक विभाग —— और हाल में, ब्रिटेन के राष्ट्रीयकृत उद्योगों के शासी मंडल सम्मिलित हैं।

उदाहरणार्थ, आजकल चार सौ तथा पांच सौ के बीच खान-कामकाजी उस ग्रीष्मकालीन स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीय कोयला मंडल ने ब्रिटेन के एक सबसे पुराने विश्वविद्यालय कालेज में आयोजित किया है। मैगडेलेन कालेज, आक्सफर्ड में अवस्थित इस स्कूल ने कोयला उद्योग की सभी शाखाओं के पुरूषों तथा स्त्रियों के अलावा कोयलाखानों के पचास से अधिक प्रमुख कामकाजियों को एक जगह एकत्रित कर दिया है।

इस स्कूल में जाने वाले युवक खनिकों को आक्सफर्ड का कालेज जीवन ज़रा कड़ा मालूम दे रहा है। किन्तु वे कालेज के आंगन में राष्ट्रीयकृत उद्योगों के प्रमुख कामकाजियों तथा अपने शिक्षकों और ग्रीष्मकालीन स्कूल की कार्य अवधियों के विशेष वक्ताओं के साथ मिलजुल कर बहुत लाभ उठा रहे हैं।

... खानकामकाजियों

खान कामकाजियों के ग्रीष्मकालीन स्कूल में (जो अब अपने तीसरे वर्ष में है) मुख्यतया उद्योग के उच्च पदों से लिये गये विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, किन्तु इनमें खानों के बाहरी तथा अन्दरूनी कार्यों से लिये जाने वाले कामकाजी भी सम्मिलित होते हैं। स्कूल में वे लोग दर्जन भर विषयों के अध्ययनार्थ अपने को तीस या चालीस समूहों में बांट लेते हैं। वे आम और विशेष प्रकार के भाषण भी सुनते हैं। इस वर्ष ऐसा ही कार्यक्रम अपनाया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

आवश्यक लक्ष्य

इसी तरह के ग्रीष्मकालीन स्कूल आजकल ब्रिटिश एलेक्ट्रिसिटी आथारिटी की देखरेख में चल रहे हैं। इनका शिक्षाक्रम भी लगभग उसी तरह का होता है। विद्यार्थियों की रूचि प्रशासन तथा प्रबन्ध की समस्याओं के अतिरिक्त इसके वितरण तथा व्यावसायिक अभ्यास की समस्याओं पर भी केन्द्रित होती है।

खानखोदाई उद्योग और विद्युत सप्लाई उद्योग दोनों के ही ग्रीष्मकालीन स्कूलों का आवश्यक लक्ष्य यह है कि उद्योग के कामकाजियों को दायित्व तथा सेवा के पदों का अधिकाधिक प्रशिक्षण दिया जाए। खान-खोदाई उद्योग के तरूण खान कामकाजियों तथा वयस्कों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विनियम कोई १९४५ में ईंधन तथा शक्ति मन्त्री द्वारा तैयार किये गये थे, और तब से अब तक लागू हैं।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण की स्कीम तरूणों के एक प्राथमिक शिक्षाक्रम के साथ प्रारम्भ होती है, और इसके साथ आवासयुक्त प्रशिक्षण कार्यालय तथा केन्द्र भी सम्बन्धित हैं जिनकी देखरेख ऐसे प्रशिक्षण पदाधिकारी करते हैं जो अपने इस निगरानी कार्य को हाथ में लेने से पहले विशेष शिक्षाक्रमों में शामिल हो चुके हों।

स्कीम का एक पृथक भाग प्रतिभाशाली लड़कों के प्रशिक्षण के लिये प्रगति की अच्छी आशाएं प्रस्तुत करता है। उनके लिये टेक्निकल प्रशिक्षण का एक विस्तृत रूप प्रदान किया जाता है जिसमें मशीनी इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग तथा खान की जांच-पड़ताल और सम्बन्धित शिक्षा सम्मिलित होती हैं। इसी स्रोत से उद्योग के भावी प्रमुख कामकाजी, कोयलाखान टेक्निशियन, जांचक और उप-प्रबन्धक प्राप्त होंगे। उद्योग के उच्च टेक्निकल योग्यताप्राप्त लोगों के लिये शिक्षा का एक तीसरा क्रम भी जारी है जिसके द्वारा वे प्रबन्ध सम्बन्धी पदों की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।

... भविष्य में

भविष्य में ऐसे कोयलाखान प्रबन्धकों की संख्या काफी रहेगी जो उद्योग में इस शिक्षात्मक पद्धति के ज़रिये तरक्की करेंगे।

विश्वविद्यालय शिक्षाक्रम

ये औद्योगिक शिक्षात्मक स्कीमें शिक्षा प्राप्ति के उस आम कार्यक्रम से बिल्कुल मेल खाती हैं जो टी०यू०सी० जनरल कौंसिल की शिक्षा समितियों के निर्देश में बहुत विस्तृत रूप से विकास कर रही हैं। यह निकाय केवल स्वयं ग्रीष्मकालीन स्कूल, सप्ताहांत स्कूल, दैनिक स्कूल तथा ऐसी शिक्षा कक्षाएं (जिनमें विशेष रुचि के बहुत से विषय सम्मिलित होते हैं) ही प्रदान नहीं करती बल्कि कामकाजियों के स्थापित शिक्षात्मक संगठनों, आन्दोलन के निजी रस्किन कालेज और अनेकों टेक्निकल कालेजों तथा कुछ विश्वविद्यालयों से भी सम्बन्ध रखती हैं।

ग्लैसगो विश्वविद्यालय, नाटिंघम विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, साउथैम्पटन विश्वविद्यालय कालेज और ट्रेड यूनियन अध्ययन के विशेष शिक्षाक्रमों के लिये लन्दन स्कूल आफ इकानमिक्स आदि से प्रबन्ध किये गये हैं। इन अभिप्रायों के लिये नेशनल टेक्निकल कालेजों से सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, टी०यू०सी० जनरल कौंसिल ने हाल में अपने ही सदस्यों को चमड़ा उद्योग के एक राष्ट्रीय कालेज की शासी निकाय में काम करने के लिये नियुक्त किया था और इस प्रकार के सम्बन्ध दूसरे उद्योगों में जारी अन्य टेक्निकल कालेजों के साथ पहले से ही मौजूद हैं।

यह बात टी०यू०सी० की शिक्षात्मक नीति के बिल्कुल अनुरूप है कि इसकी जनरल कौंसिल की उत्पादन समिति टेक्निकल कालेजों में शिक्षा के क्रमों, कारखानों के अध्ययन और औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ाने में सक्रिय रही है। यह विकास जो एक बड़े आम कामकाजी संघ (नेशनल यूनियन आफ जनरल ऐन्ड म्यूनिसिपल वर्कर्स) के उपक्रमण की देन है आजकल ब्रिटेन के आठ केन्द्रों में इन विषयों के ऐसे शिक्षाक्रमों के रूप में स्थान पा चुका है जो लगभग एक महीने तक चलते हैं। अन्य संघों को अपने निजी उद्योगों के ऐसे ही शिक्षाक्रम जारी करने के लिये सक्रियरूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

F.H.407

ब्रिटिश ट्रेड यूनियन आन्दोलन
का अध्ययन सम्पूर्ण

भारतीय पदाधिकारियों की स्वदेश वापसी

चार भारतीय और दो पाकिस्तानी ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों के एक दल ने हाल ही में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन संगठन का एक चार-मास अध्ययन पूरा किया है। दल के सदस्यों ने लगभग दो सप्ताहों के बाद स्वदेश लौटना है।

भारत के चार ट्रेड यूनियनवालों के नाम ये हैं : सुमन्त देसाई तथा कालीपादा मुकर्जी (भारत की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) और पी०डब्ल्यू०खांडेकर तथा हित नरायन सिंह (हिन्द मज़दूर सभा)। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व अखिल पाकिस्तान श्रमिक महासंघ के ए०कासिम और एम०सुलेमान ने किया है।

दल के अध्ययन की व्यवस्था ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से की गई थी जिसने ब्रिटेन में उनके आतिथ्यकर्ता का भार सम्हाला और ब्रिटिश कौंसिल ने यात्रा खर्च के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

लन्दन में ११ सितम्बर को हुए एक प्रेस सम्मेलन में आगन्तुक ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने उन सभी बातों के सम्बन्ध में पूरे उत्साह के साथ अपने विचार प्रकट किये जो उन्होंने देखी थीं, और यह कहा था कि ब्रिटेन के ट्रेड यूनियन संगठन की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें अपने अपने देशों के सामान्य संगठनों के लिये अच्छी तरह से अपनाया जा सकता है।

इन पदाधिकारियों ने ब्रिटेन में रहते हुये श्रम मन्त्रालय का कई बार दौरा किया जहां उन्होंने औद्योगिक सम्बन्ध, संयुक्त परामर्शदायक व्यवस्था, युवक नियोजन सर्विस और परीक्षात्मक नियोजन तथा शारीरिक अयोग्यता रखने वाले

... लोगों के

लोगों के पुनर्वास जैसे विषयों पर बातचीत की थी। वे लन्दन काउन्टी कौंसिल के प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय मध्यस्थ - निर्णय न्यायाधिकरण तथा औद्योगिक कचहरी की यात्रा कर चुके हैं और टी०यू०सी० के एक प्रशिक्षण शिक्षाक्रम, आक्सफर्ड स्थित टी०यू०सी० के समर स्कूल, वेल्स स्थित वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन समर स्कूल और ब्लैकपूल में हाल की ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी उपस्थित हुए हैं।

बड़ा अनुभव

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से श्री० कालीपादा मुकर्जी ने इस यात्रा के आयोजन के लिये ब्रिटिश टी०यू०सी० और ब्रिटिश कौंसिल के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि उनको ब्रिटेन के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के संगठन की कई बातों को देखने से एक बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है। वे केवल ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों से ही नहीं बल्कि साधारण सदस्यों से भी मिले और खनिकों से मिलने के लिये खानों तक गये थे। उन्हें हर जगह सहानुभूति और सहयोग प्राप्त हुआ और उनके मतानुसार प्राप्त किए गये अनुभव भारत के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि श्री० सुलेमान ने कहा कि वह ब्रिटेन के असैनिक कर्मचारियों के कार्य तथा उत्तरदायित्व से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी प्रकट किया कि वह शारीरिक अयोग्यता वाले लोगों के प्रशिक्षण और नियोजन की बहुत सी बातें सीख कर जा रहे हैं। पुनर्वास सम्बन्धी वह कार्य जो उन्होंने देखा था ऐसे लोगों को नवजीवन का अवसर प्रदान करता है।

N.E.H.74

पूर्वी जर्मन पुलिस का सैनिक प्रशिक्षण

रूसी नियन्त्रण और निरीक्षण

पूर्वी जर्मनी की समानान्तर सेना सम्बन्धी उन बातों से, जो जर्मनी स्थित ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से १० सितम्बर को प्रकाशन के लिए प्राप्त हुई है, प्रकट होता है कि "बेरेत्शाफेन" (भूसेना) को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है — आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित आरक्षक बलों के कर्तव्य मात्र नहीं सिखाए जा रहे हैं। समुद्र और वायुबल ("समुद्र पुलिस" और "वायु पुलिस") अभी तक विकास के प्रारंभिक चरणों में है।

"बेरेत्शाफेन" की वर्तमान शक्ति लगभग ५४,००० है। यद्यपि इस प्रकार संख्या की दृष्टि से नवम्बर की तुलना में केवल तीन हजार की वृद्धि प्रकट होती है पर, ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष उन्होंने कार्यकुशलता में बड़ी वृद्धि की होगी। हां, भारी आयुधों, भारी शस्त्रास्त्रों में पर्याप्त प्रशिक्षण और सप्लाई यूनिटों के अभाव के कारण उनकी उपयोगिता सीमित है।

प्रत्येक "बेरेत्शाफ" (यूनिट) में ३७१ अधिकारी और "नान कमिशंड अफसर" तथा १,४३२ अन्य श्रेणी वाले हैं। कुछ यूनिट पूर्णतया शक्ति सम्पन्न नहीं है। अधिकारियों और "नान कमिशंड अफसरों" की संख्या से मालूम होता है कि वर्तमान यूनिट ऐसे हैं जिनका विस्तार शीघ्रता से किया जा सकता है।

१९४९ के आदिम रूप की तुलना में "बेरेत्शाफेन" के ढांचे और उसके प्रशिक्षण में पूर्ण पुनर्संगठन हुआ है। १९४९ में उसका सम्पूर्ण बल १०,००० था, प्रत्येक यूनिट की संख्या २५० थी और प्रशिक्षण के अन्तर्गत पैदल सेना की आधारभूत शिक्षा तथा पुलिस के कर्तव्यों का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण थे। तब पुलिस टेक्निकल प्रशिक्षण शीघ्र सम्पूर्णतया सामरिक बन गया।

आज प्रत्येक "बेरेत्शाफ" शस्त्रास्त्रों से सज्जित सोवियट रेजिमेंट के आधार पर संगठित है: इसमें एक भारी शस्त्रास्त्रों और तीन पैदल सेना के लड़ाकू यूनिट

... तथा सहायक

तथा सहायक तत्व होते हैं। प्रत्येक यूनिट के कमान स्तर पर एक उच्च रूसी अधिकारी और तीन रूसी सहायक होते हैं। प्रशिक्षण सम्भवत: पूर्णतया सोवियट युद्धविद्या और सोवियट साधन सामग्रियों के संचालन तक सीमित है। डेढ़ सौ ऐसे उच्च अधिकारी, जिन्हें हाल में सोवियट यूनियन में एक वर्ष तक काम सिखाया गया था, प्रशिक्षण कार्य में मुख्य भाग ले रहे हैं।

"बेरेत्शाफेन" के पास छोटे अस्त्र और बड़ी तोपें (रूसी तथा जर्मन) अच्छी संख्या में हैं। इसके अतिरिक्त जर्मन और रूसी भारी शस्त्रास्त्रों तथा कुछ टैंकों और शस्त्रास्त्रों से सज्जित गाड़ियों की प्राप्ति भी प्रशिक्षण कार्य के लिए हुई है।

"बेरेत्शाफेन" का केन्द्रीय कार्यालय, जो अधिकारी रूप से "प्रधान प्रशिक्षण प्रशासन" कहलाता है और आन्तरिक व्यवस्था मन्त्रालय में मिला हुआ है, पिछले साल सोवियट सैनिक केन्द्रीय कार्यालय के आधार पर पुनर्संगठित किया गया था।

सबसे ऊपर एक इन्सपेक्टर जनरल है। उसके अन्तर्गत एक निरीक्षण विभाग है। तब राजनैतिक सिद्धान्तों की शिक्षादीक्षा, कर्मचारीवृन्द, सप्लाई और स्टाफ के विभागों का नम्बर आता है। स्टाफ सम्बन्धी मुख्य विभाग के नीचे एक ओर कार्य संचालन विभाग है और दूसरी ओर सैनिक कार्यालय का उपप्रधान तथा सामान्य प्रशासन का प्रधान (परिवहन और वित्त जैसी शाखाओं के लिए) है।

FORTNIGHTLY REVIEW
OF
NEWS AND EVENTS

HINDI

December 9 to December 22, 1951.

ISSUED BY THE
BRITISH INFORMATION SERVICES
EASTERN HOUSE, MANSINGH ROAD, NEW DELHI

इस वर्ष भारत ने ब्रिटेन से १६५० की तुलना में आवश्यक सामान की उपलब्ध सप्लाइयों का अधिक बढ़ा हुआ अंश प्राप्त किया । यों इस विषय में वह अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से आगे था । अबतक की उपलब्ध संख्याओं के आधार पर परिणाम निकालते हुए जान किंग्सले यह बताते हैं कि ब्रिटेन अपने प्रतिरक्षा वायदों और कच्ची सामग्रियों की कमी के बावजूद भी भारतीय आर्थिक स्थिति के विकास के लिये आवश्यक सामान की सप्लाई जारी रख रहा है ।

अन्त में लेखक यह लिखता है कि ब्रिटेन के लिये अत्यावश्यक सामग्रियों के निर्यात के ज़रिये भारत ज़रूरी सामान का अधिक बढ़ा अंश कैसे निश्चित कर सकता है ।

****

ब्रिटेन से भारत के लिये पूंजीगत सामान की सप्लाई जारी

****

जान किंग्सले

भारत को ब्रिटेन में बनी इस्पात की तैयार चीज़ों और कुछ अन्य आवश्यक सामान की प्राप्ति इस वर्ष के पहले अनुमान से काफी अधिक होगी। उसे १६५० की तुलना में उपलब्ध सप्लाइयों का एक बढ़ा हुआ अंश प्राप्त होगा। इस प्रकार, इस अर्थ में, उसकी स्थिति अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से अधिक अच्छी होगी। यद्यपि ... १६५१ के भारत

के भारत-ब्रिटिश व्यापार के अन्तिम आंकड़े अभी तक तैयार नहीं पर इन महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में निश्चित होने के लिये काफ़ी बातें मालूम हैं ।

ब्रिटिश पूंजीगत तथा ऐसे ही सामान की निर्यात स्थिति का पूर्वानुमान १९५१ के प्रारम्भ में अच्छा नहीं था । कच्ची सामग्रियों की कमियों , पुनःशस्त्रीकरण की मांगों और डालर निर्यातों को क़ायम रखने की आवश्यकता जैसी सभी बातों ने कुछ दिशाओं में भारी कटौतियों का संकेत किया था । उस समय यही वायदा किया जा सकता था कि कटौतियां यथासम्भव कम होंगी और भारत की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखा जायेगा ।

तैयार इस्पात सामान

इस्पात और तांबे का तैयार चीज़ों (जैसे नलियां) ने अत्यन्त गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया था । अनिच्छा से यह निर्णय करना पड़ा कि राष्ट्रमंडलीय देशों के लिये लोहा तथा इस्पात को चीज़ों के सम्पूर्ण निर्यातों को , वज़न की दृष्टि से , कमकर १९५० के ६५ प्रतिशत तक लाया जाए , किन्तु भारत के लिये की गई कमी इस लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंची । इस वर्ष के प्रथमार्द्ध की संख्याओं से पता चलता है कि वज़न की दृष्टि से भारत वास्तव में पिछले वर्ष के ८५ प्रतिशत और कुछ अधिक के बराबर प्राप्त कर सकेगा । देखिए : पहले छः मासों में निर्यात लगभग १७,५०० टन रहा होता पर पहले छः महीनों में वह वस्तुतः २३,०८३ टन था ।

उन चीज़ों के निर्यातों में जो " कापर सेमिज़ " कही जाती हैं और भी अधिक कमी होनी थी : और अधिकांश राष्ट्रमंडलीय देशों को पूर्ण कटौती सहनी पड़ी है। फिर भी भारत की प्राप्ति की रेट १९५० की तुलना में अधिक है । उसकी स्थिति अल्यूमिनियम और अल्यूमिनियम सामान के सम्बन्ध में भी अच्छी रही है — पहले नौ महीनों के निर्यात १९५० की इसी अवधि की तुलना में २५ प्रतिशत अधिक थे।

ब्रिटिश उत्पादन और निर्यातों पर प्रभाव डालने वाली सभी परिस्थितियों से मशीनरी की डिलिवरियों में कुछ कमी अनिवार्य थी । वज़न की दृष्टि से १९५१ के प्रथम नौ महीनों में भारत के प्रति निर्यात ७८,२३५ टन था — अर्थात् १६,००० टन कम । इस कमी का २/५ भाग टेक्सटाइल मशीनरी में हुआ था । इसका कारण यह है कि भारत का निजी उद्योग ब्रिटिश निर्माताओं के सहयोग से विकास कर रहा है ।

... वे वृद्धियां

वे वृद्धियां बहुत महत्वपूर्ण रहीं जो कोलम्बो योजना के सफल सम्पादन के लिये अत्यधिक आवश्यक कुछ मशीनरी और सामान में हुई थीं । उदाहरणार्थ खोदने तथा दबाने वाले साधनों , नलों (पम्पों) और इंटर्नल कम्बशन इंजनों (जैसे मोटर इंजन) के निर्यात १९५० के स्तरों से ऊंचे चलते रहे हैं। इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में निर्यात किये गये कृषि ट्रैक्टरों की संख्या दुगने से अधिक थी — ३७२५ ।

पारस्परिक सहायता आवश्यक

मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो १९५१ का सम्पूर्ण व्यापार १९५० की संख्याओं से काफ़ी अधिक रहेगा । भारत के लिये पहले नौ महीनों में ब्रिटिश निर्यातों की रकम पिछले वर्ष की इसी अवधि के ६,६०,००,००० पौंड और सम्पूर्ण १९५० के ६,७०,००,००० पौंड की तुलना में ८,५०,००,००० पौंड थी । ब्रिटिश आयातों की लागत की वृद्धि इससे बहुत ज़्यादा थी , १९५१ के पहले नौ महीनों की रक़म (पिछले वर्ष की इसी अवधि के ६,८५,००,००० पौंड और सम्पूर्ण १९५० के ९,८५,००,००० पौंड की तुलना में) ११,२५,००,००० पौंड थी ।

यद्यपि अधिकांश मौद्रिक (मानेटरी) विस्तार का कारण मूल्यों में वृद्धि है पर ब्रिटिश निर्यातों की तुलना में भारतीय निर्यातों की वृद्धि अधिक ऊंची रही है। उदाहरणार्थ , ब्रिटेन द्वारा १९५० के प्रथम नौ महीनों में आयात किये गये ६,६५,००,००० वर्ग गज़ जूट टुकड़ा माल की क़ीमत ३२,३५,००० पौंड थी किन्तु इस वर्ष की इसी अवधि में आयात किये गये १६,२०,००,००० वर्ग गज़ माल का मूल्य १,४१,७९,००० पौंड था । इसी तरह से १,३३,७६,००० पौंड का १५,०५२ टन खाल-चमड़ा ख़रीदा गया जबकि १९५० में १२,२९५ टन के लिये ७५,२४,००० पौंड दिये गये थे । चाय की संख्याएं यों थी कि १९५० के १४,००,००,००० पौंड (वज़न) के लिये १,९६,३३,००० पौंड मूल्य की तुलना में १७,८०,००,००० पौंड (वज़न)के लिये २,८२,०६,००० पौंड दिये गये थे ।

इसके विपरीत , भारत ने इस वर्ष के प्रथम नौ महीनों में १२,६२,००० पौंड मूल्य की १,६७,३७० बाइसिकिलें और २०,८६,००० पौंड मूल्य की ७७२६ मोटरकारें आयात की थीं, जबकि १९५० में २,७५,००० पौंड मूल्य की ४४,२२८ बाइसिकिलें और १६,४७,००० पौंड मूल्य की ६३५८ मोटर कारें ।

... ब्रिटेन भारत

ब्रिटेन भारत से मैंगनीज़ , काइस्नाइट एक खनिज सम्मिश्रण और खालें आदि शीघ्र ही अधिकाधिक परिमाण में प्राप्त करना चाहता है। किन्तु भारत को अपनी निजी आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ सामग्रियों के निर्यातों में कमी करनी या उनपर पाबन्दी लगानी पड़ी है। इससे प्रकट होता है कि भारत ब्रिटेन से बहुत भिन्न स्थिति नहीं रखता और यह बात भी सामने आ जाती है कि उपलब्ध सप्लाइयों का बटवारा अत्यधिक समुचित रूप से होना चाहिए ।

यह बात भारत के बस में है कि वह ब्रिटेन की उस योग्यता को बढ़ाये जो उसके लिये आवश्यक सामान अधिक परिमाण में सप्लाई कर सके । ब्रिटिश इस्पात उत्पत्ति अन्य बातों के साथ साथ मैंगनीज़ पर निर्भर करती है और भारत से अधिक बढ़े हुए निर्यात बहुत ज्यादा सहायक रहेंगे । तांबे की कमी इस तरह पूरी हो सकती है कि पुरानी सामग्रियों के स्थान में नई चीज़ों का आर्डर देते समय पुरानी सामग्री ब्रिटेन भेज दी जाए । आर्डरों की उपयुक्त योजना के फलस्वरूप बढ़ी हुई पारस्परिक सहायता उत्पन्न होगी जिससे भारत की चालू होने वाली कई बहु अभिप्राय पूंजीगत स्कीमों के लिये आवश्यक सामान ब्रिटेन से समय पर आने लगेगा ।

N.E.H. 94/51

साइबेरिया का 'सुख' : यू०एस०ए की 'यातना'

'अमेरिका में सब लोग दुखी , बेकार और भूखे हैं', साम्यवादी दल के प्रचारक ने एक राजनैतिक सभा में कहा । 'सोवियट यूनियन में सब लोग सुखी हैं, सब के पास काम है और भरपेट खाने को है । पर हमारे बीच अभी भी कुछ अशिष्ठ युद्धलिप्सु और साम्राज्यवादी गुप्तचर हैं । इन सब को साइबेरिया भेज देना चाहिये ।'

इसके उत्तर में श्रोताओं में से एक व्यक्ति उठा और बोला : कामरेड , मैं आपके प्रत्येक शब्द में विश्वास करता हूं । पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। युद्धलिप्सु और साम्राज्यवादी गुप्तचरों को दंड देने के लिये दुखी अमेरिका क्यों न भेजा जाए , उन्हें सुखी सोवियट यूनियन में ही क्यों रक्खा जाए ?'

मलाया के लिए छः सूत्री योजना

लिटिलटन की घोषणा

मलाया में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्य सम्बन्धी ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव, आलिवर लिटिलटन, की घोषणा पर विचार प्रकट करते हुए 'टाइम्स' ने लिखा है : मलाया संघ के अधिकारियों द्वारा आतंकवादियों का दमन न कर सकना यहां और मलाया में इतनी काफी चिन्ता उत्पन्न कर रहा है कि आवश्यक कार्य के विषय में साधारण बातों की घोषणा कर औपनिवेशिक सचिव ने समझ का परिचय दिया है।

उनकी घोषणा, स्वाभाविकतया, उन प्रस्तावों तक सीमित थी जो वे मन्त्रिमंडल के सम्मुख रक्खेंगे। पर उनके द्वारा बताई गई बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वे नीति और प्रशासन की उन कई त्रुटियों पर ध्यान केन्द्रित कर सके हैं जिनके कारण बहुत हानि हुई है। औपनिवेशिक सचिव ने यह आश्वासन दिया कि ब्रिटेन अपने मिशन के सम्पूर्ण होने तक और स्वशासन के मार्ग पर भागिता सम्भव होने तक मलाया नहीं छोड़ेगा। साम्यवादी आक्रमण और आतंक राजनैतिक और संवैधानिक प्रगति के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं और सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि सैनिक तथा असैनिक, सब बलों का निर्देश शत्रु के विरुद्ध अविभक्त रूप से किया जाए।

पत्र ने उस छः सूत्री योजना का विवरण देने के बाद औपनिवेशिक सचिव ने जिसकी घोषणा की है इस बात पर बल दिया है कि एक चीनीगृह रक्षकदल होना चाहिए। औपनिवेशिक सचिव का यह सुझाव उस नीति के निश्चित विसर्जन का परिचायक है फेडरेल सरकार जिसका अनुसरण कर रही है। इससे आतंकवाद के अन्तत: पराजय में काफी योग मिल सकता है। केवल चीनी लोग ही यह निश्चित कर सकते हैं कि ऐसा आन्दोलन, जो प्रेरणा और सदस्यता की दृष्टि से प्रधानतया चीनी है, उस समुदाय से पृथक कर दिया जाए जिसके (इच्छापूर्वक अथवा अन्यथा) समर्थन पर वह जीवित रहने के लिये आश्रित है। औपनिवेशिक सचिव ने लगभग उन सब बातों को समझ लिया है जो मलाया के वर्तमान शासन के आलोचक पिछले कुछ समय से कह रहे हैं। अब आवश्यकता है उनके द्वारा निर्धारित मार्ग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना समय खोए प्रबल कार्य करने की।

चीन और पश्चिमी शक्तियां

पारस्परिक समझ की स्थापना में भारत का भाग

चीन के साथ भारत के सम्बन्धों के विषय में 'टाइम्स' पत्र ने लिखा है : भारत में राजनीति का ज्ञान और उसमें रुचि रखने वाले अनेक व्यक्ति श्री० नेहरू की इस धारणा से सहमत हैं कि चीनी जन सरकार , चाहे वह साम्यवादी रंग में डूबी हो , चीन की एकमात्र प्रामाणिक सरकार है , कि उसे अधिकांश चीनी जनता का समर्थन प्राप्त है और वह चीनियों द्वारा निर्मित की गई है , सोवियट रूस द्वारा लादी गई प्रणाली नहीं है ।

श्री० नेहरू की विचारधारा इस बात से भी प्रभावित है कि चीन और भारत पड़ौसी हैं और , यदि उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं रहते तो , अपने महत्वपूर्ण हितों के विषय में भारत सरकार को कठिनाई उठानी पड़ सकती है । हां , यह कहना कि श्री० नेहरू की विचारधारा <u>केवल</u> इन्हीं बातों से प्रभावित है उनके प्रति अन्याय करना होगा ।

आगे चलकर पत्र लिखता है : पंडित नेहरू का विश्वास है कि न केवल सुदूरपूर्व में एक स्थायी समझौते के लिये पर दक्षिण पूर्व एशिया की जनता की शांतिमय प्रगति के लिये भी चीन तथा पश्चिमी जगत के मध्य पारस्परिक समझ आवश्यक है। श्री० नेहरू को सचमुच यह आशा है कि चीन और पश्चिमी जगत के मध्य की गलतफैमियों को दूर करने में भारत सहायक हो सकता है ।

भारत का सम्बन्ध पूर्व और पश्चिम दोनों से है। भारत एक बड़ी एशियाई शक्ति है , उधर वह राष्ट्रमंडल तथा पश्चिमी जगत से सांस्कृतिक , राजनैतिक तथा आर्थिक सूत्रों से सम्बद्ध है। इस बात का पता लगाने का अवसर कि चीन के अन्दर

... क्या हो

क्या हो रहा है अन्य किसी राष्ट्रमंडलीय देश की अपेक्षा भारत को आज अधिक प्राप्त है । इस बात के लक्षण दीखते हैं कि भारत की मित्रता को चीन महत्वपूर्ण समझता है। कुछ पश्चिमी देशों में, पारस्परिक समझ उत्पन्न करने के श्री० नेहरू के प्रयत्नों की कड़ी आलोचना की गई है। अमेरिका में चीन के प्रति गहरा क्रोध है। वह चीन को एक स्पष्ट अभ्याक्रामक समझता है , कोरिया में जिसके हस्तक्षेप के कारण संयुक्त राष्ट्रों को बहुत नुक्सान उठाना पड़ रहा है। वह चीन को एक ऐसा साम्यवादी कठपुतली देश समझता है जिसने , अमेरिका और चीन के लोगों की मित्रता के पुराने सम्बन्धों की उपेक्षा कर , अपने को क्रेमलिन के मनोरथों की पूर्ति का साधन बनने दिया है। ब्रिटेन में भी अनिवार्यत: असन्तोष और सन्देह की ऐसी ही भावनाएं हैं। कोरिया में ब्रिटिश सैनिक चीन के विरूद्ध लड़ रहे हैं। वहां अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियां पास पास चल रही हैं। पंडित नेहरू को यह आशा है कि चीन और पश्चिमी शक्तियों के मध्य ऐसी पारस्परिक समझ उत्पन्न हो सकती है जिससे सुदूरपूर्व की शांति एक दृढ आधार पर खड़ी की जा सकती है । श्री० नेहरू की इस आशा से सहानुभूति न दिखाना कठिन है। पर , कोरिया में जबतक सचमुच युद्ध रोकने का प्रबन्ध नहीं होता तबतक इस आशा का पूरी होना सम्भव नहीं दीखता ।

टेलिविज़न में ब्रिटेन का भाग

'टेलिविज़न के लिये ब्रिटिश अंशदान' उस सभा का विषय है जो लन्दन में विद्युत सम्बन्धी इंजीनियरों की संस्था द्वारा अगले वर्ष २८ अप्रैल से ३ मई तक आयोजित की जाएगी । आशा की जाती है कि उसमें विदेशी आगन्तुक सम्मिलित होंगे जो संस्था द्वारा आयोजित इस विषय की सर्वप्रथम सभा है। बहुत से टेक्निकल निबन्ध पहले ही स्वीकार किये जा चुके हैं , और यह सम्भावना है कि उन विषयों की कुल संख्या जिनपर विचार विनिमय किया जायेगा साठ और अस्सी के मध्य रहेगी ।

निबंधि निर्वाचनों का विषय
और ... ...

जर्मन साम्यवादियों का चक्कर
*****
डब्ल्यू०एन०ईवर

पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी नेता गम्भीर चक्कर में पड़े हैं । सारे जर्मनी में स्वतन्त्र निर्वाचनों के पश्चिम के प्रस्ताव को ठुकराना पर राष्ट्रीय एकता की पुनर्स्थापना के एकमात्र सच्चे समर्थक बने रहना , यह कैसे सम्भव है, वे सोच रहे हैं ।

जर्मनी के दोनों भागों में राजनैतिक स्थिति की संयुक्त राष्ट्रीय प्रेक्षकों दव्ारा प्रारम्भिक जांच के विचार को अस्वीकार करने के लिये इन्होंने, कुछ संकोच के बाद, कुछ प्रतिनिधि पेरिस भेजे थे । इन प्रतिनिधियों की प्रवृत्ति से उनकी परेशानी के प्रमाण प्रकट होते थे ।

यह कहना आसान है कि ऐसी जांच जर्मन राष्ट्रवाद का अपमान है । पर, जहां एक तरफ पूर्वी बर्लिन के साम्यवादी मेयर , एबर्ट , ने कहा था कि जर्मन जनता की इच्छा जानने के लिये ऐसी कोई जांच आवश्यक नहीं है , वहां उनके साथी डाक्टर बोल्ज़ चार शक्तियों के नियन्त्रण के नीचे जर्मन जांच के लिये तैयार थे । (डाक्टर बोल्ज़ नैशनल डिमाक्रेटिक पार्टी में हैं : इसमें अधिकांशतया कल के नात्सी हैं जो रूसी कृपा के पात्र हैं) ।

यद्यपि यह स्वीकार्य लगता है पर पिछली घटनाओं से तो ऐसा जचता है कि इनका वास्तविक अर्थ यह है कि पूर्वी क्षेत्र में " जांच " रूसी देखरेख में पूर्वी जर्मनी की सरकार दव्ारा की जाए ।

... डाक्टर बोल्ज़

डाक्टर बोल्ज ने वह बात भी दोहराई थी जो पहले ग्राटवाल के मुख से सुनी गई थी : अर्थात् यह कि वीमर रिपब्लिक की निर्वाचन प्रणाली पूर्वी क्षेत्र में पुन: स्थापित कर दी जाए। सुनने में यह भी ठीक लगता है। पर, जैसाकि डा० एडेन्योर ने कुछ समय पहले कहा था, नात्सी शासन में यही निर्वाचन कानून प्रचलित था और इससे तो स्वतन्त्र और न्यायोचित निर्वाचन का आश्वासन नहीं मिल सकता।

ध्यान हटाने की बातें

जहांतक शेष का सम्बन्ध है, यह प्रतिनिधिमंडल प्रमुखरूप से बान की सरकार और पश्चिमी शक्तियों पर निन्दा की बौछार में संलग्न था। ध्यान हटाने की युक्तियां उसने प्रयुक्त कीं : निर्वाचन के पहले शान्ति सन्धि और हटने की मांग की। पश्चिम में पुन:शस्त्रीकरण (पूर्व में कदापि नहीं) के विचार का परित्याग चाहा।

इनकी दिव्विधा सचमुच बहुत गम्भीर होगी। वे अपने को उस अपील के आधार से वंचित होते देख रहे हैं जिससे उन्होंने बड़े बड़े परिणामों की आशा की थी। वे घृणित एडेन्योर की एकता के लिये ऐसे मार्गों पर और ऐसी क्रियाशैली के अनुसार आग्रह करते देख रहे हैं जिसे अधिकांश जर्मन पसन्द करते हैं। इनमें इसे स्वीकार करने का साहस नहीं।

पर स्पष्टरूप में वे इसका विरोध नहीं कर सकते। वे केवल मार्ग टटोल सकते हैं, केवल बातें टाल सकते हैं और बड़ी चिन्ता के साथ यह सोच सकते हैं कि उनके रूसी सर्वेसर्वा आखिर क्या करना चाहते हैं। कारण, इनके मस्तिष्कों में यह भय सदैव उपस्थित होगा कि यदि स्तालिन को अपने हित में ऐसा करना आवश्यक लगा तो, वे (स्तालिन) इनका बलिदान सहर्ष कर सकते हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन साम्यवादी नेताओं और दलों के साथ जो असफल होते हैं अथवा एक भार बन जाते हैं स्तालिन कैसा व्यवहार करते हैं।

पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी नेताओं और रूसियों को किसी समय आशा थी कि चतुर चालबाज़ी से ऐसी विधि से और ऐसी शर्तों पर जर्मन एकता की स्थापना हो सकेगी जो, तत्क्षण अथवा कुछ समय के पश्चात्, एक ऐसी साम्यवादी चाल सम्भव बनाएगी जिससे सारा देश साम्यवादी शासन में आ जाएगा और सोवियत

... साम्राज्य

साम्राज्य राइन नदी के तट तक फैल जाएगा। आवश्यक संशोधनों और परिवर्तनों के बाद पोलिश और चेक कृत्यों की पुनरावृत्ति जर्मनी में की जा सकती है।

एडेन्योर की शर्तें

पर यह आशा दुराशा बन गई। ये युक्तियाँ अनिश्चित काल तक दोहराई नहीं जा सकतीं। पश्चिम जर्मन सरकार और जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस जाल में उनके फँसने की तनिक भी आशा नहीं की जा सकती।

परिणामत:, वर्तमान परिस्थिति यों प्रकट की जा सकती है : जर्मनी को एकता चाहिए पर इसके लिये पश्चिम स्वतन्त्रता का बलिदान नहीं करेगा। यह है स्पष्ट अर्थ डाक्टर एडेन्योर की उन १४ शर्तों का जिसे, अल्प साम्यवादी दल को छोड़ते हुए, समस्त संसद का समर्थन प्राप्त है।

शर्तें बिल्कुल न्यायोचित हैं। उनका अर्थ यह है कि, स्वतन्त्र सर्व-जर्मन निर्वाचन करने से पूर्व, पूर्व और पश्चिम, दोनों में उन सारी आधारभूत राजनैतिक स्वतन्त्रताओं का पुन: संचार होना चाहिए जिनसे सचमुच स्वतन्त्र निर्वाचन सम्भव होते हैं। इन शर्तों से पूर्व में जो व्याकुलता उत्पन्न हुई है उसे देखकर हँसी आती है।

सबसे पहले डा० एडेन्योर के प्रस्ताव अमेरिकन साम्राज्यवाद की चाल कहे गए थे और निन्दा के पात्र बने थे। पर इससे काम न चला : तब ग्राटवाल ने सोचा कि शायद इनके विषय में विचार विनिमय किया जा सकता है, शायद इनमें से कुछ को स्वीकार करना सम्भव हो सकता है। अब डा० बोल्ज़ कहते हैं कि उनमें से अधिकांश अस्वीकार्य हैं। पर वास्तविक वाद विवाद टाला जा रहा है, यह बताना कि कौन अस्वीकार्य हैं और कौन नहीं, छिपाया जा रहा है। विषय बहुत कठिन है, इससे बड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है।

वास्तविक तथ्य

स्पष्ट बात यह है। साम्यवादी नेतागण भलीभाँति जानते हैं कि यदि पूर्वी क्षेत्र में सचमुच राजनैतिक स्वतन्त्रताओं की पुन:स्थापना हुई और सचमुच स्वतन्त्र निर्वाचन हुए तो उन्हें अपने पदों से वंचित होना पड़ेगा और उनके दल को बिल्कुल शक्तिहीन बनना पड़ेगा। जो कुछ समर्थन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने प्रति पैदा

... किया है

किया है वह समाप्त हो जाएगा । किसी सर्व जर्मन निर्वाचन में साम्यवादियों और उनके साथियों द्वारा बहुमत की प्राप्ति की सम्भावना इतनी कोरी कल्पना है कि आशावादी से आशावादी , कट्टर से कट्टर , मार्क्सवादी का उसमें विश्वास करना कठिन है । जर्मन एकता का वह विचार जो इन लोगों को तीन या चार वर्ष पूर्व आकर्षित किया करता था आज उन्हें दुखित कर रहा है। वे ऐसी घटना को रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके राजनैतिक जीवन की इतिश्री हो जाएगी और मास्को में उनकी बेइज्जती हो जाएगी।

पर एक क्षण के लिए भी इस बात को स्वीकार करने का उनमें साहस नहीं । अभी भी वे बाहर ऐसी बात की इच्छा प्रकट करते हैं , मन में जिससे सचमुच डरते हैं। अब उनके सामने यही रास्ता दीखता है कि विलम्ब के बहाने ढूंढे , तर्कयुक्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण खोजें और एक सीधीसादी बात को अस्पष्ट बनाने की युक्तियां ढूंढे । इसलिये वे सर्वत्र अपने मार्ग टटोल रहे हैं , एक दूसरे की बात को काट रहे हैं और दुखभरे चित्त से यह सोच रहे हैं कि शायद स्वयं उन्हीं के क्षेत्र के लोग उनकी वास्तविकता अब समझने लग गए हैं ।

ग्राटवाल के प्रस्तावों की असत्यता

`डेली टेलीग्राफ` ने १८ दिसम्बर के अंक में लिखा है : इस बात की सम्भावनाएं बहुत नहीं हैं कि संयुक्त राष्ट्रों के `नैतिक प्रभाव` के कारण पूर्वी जर्मन सरकार और उसके रूसी स्वामी निरीक्षकों का प्रवेश स्वीकार करेंगे ।

पर , पत्र का विचार है, पिछले कुछ महीनों ने ग्राटवाल के प्रस्तावों की असत्यता इतनी स्पष्टतया सामने रखी है कि वे विवश होकर कुछ संकेत देंगे ।

मध्यपूर्वीय राज्यों की अनुचित नीति

मिश्र की स्थिति के विषय में 'सन्डे क्रानिकल' ने १६ दिसम्बर के अंक में इस बात पर शोक प्रकट करते हुये कि फारूक की सरकार ने नागरिकों को शस्त्रयुक्त होने की अनुमति दी है आशा प्रकट की है कि यह स्थिति अनियन्त्रित सीमा तक फैलने नहीं दी जाएगी। पत्र के अनुसार मध्यपूर्व की राजनीति उचित मार्ग पर नहीं चल रही। मिश्र के नेताओं को मालूम है कि निर्धनताग्रस्त और अत्यधिक जनसंख्या का उनका देश 'ब्रिटिश लोगों से पिन्ड छुड़ाकर' कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। उन्हें यह भी मालूम है कि स्वेज़ नहर की प्रतिरक्षा के लिए संयुक्त सेना का पश्चिम का प्रस्ताव उसी प्रकार उनके राष्ट्रीय अभिमान को आघात नहीं पहुंचाता जिस प्रकार कि ईस्ट ऐंग्लिया में अमेरिकन वायुयानों की उपस्थिति हमारे राष्ट्रीय अभिमान को आघात नहीं पहुंचाती और हमारे प्रभुता को शिथिल नहीं करती। पर, जैसे कि फारस में वैसे ही मिश्र में, सत्य का गला दबाया जा रहा है। और यह है शोचनीय उदाहरण उस स्थिति का जो जनसाधारण को वास्तविक बातों की जानकारी से वंचित करने पर उत्पन्न होती है।

आकर्षक, बनने की रीति

४० से लेकर ६५ वर्षों तक की आयु की लन्दन की महिलाएं आजकल एक ३६ भाषणों के शिक्षाक्रम में भाग ले रही हैं। इस प्रकार वे इन भाषणों की सहायता से आकर्षक बनने का रहस्य सीख रही हैं। प्रत्येक भाषण के लिये प्रत्येक महिला को दो पें० : १ आना ६ पाई : देना पड़ता है। वे आकर्षक बनने से सम्बन्धित कई बातें, जिनमें केश प्रसाधन भी है, सीखती हैं। आचरण की कला पर विशेष बल दिया जाता है। इस शिक्षाक्रम का संचालन लन्दन कांउटी कौंसिल की वाटर्लू विमेन्स इन्स्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। यह तथा अन्य शिक्षाक्रम लन्दन कांउटी कौंसिल की सायंकालिक कक्षाओं के साधारण अंग हैं।

संसार में सूचनापत्रों का उपभोग

हररोज़ सूचनापत्र की कोई २२,४०,००,००० प्रतियां, १८,२०,००,००० रेडियो सेट और १,५०,००,००० टेलीविज़न सेट संसार के लोगों को खबरें तथा सूचना लाकर देते हैं, जबकि एक लाख से अधिक सिनेमागृह उनको मनोरंजन प्रदान करते हैं।

फिर भी ये सुविधाएं महाद्वीपों या राष्ट्रों द्वारा असमता से प्राप्त की जाती हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका विश्व के अखबारी कागज़ का ६७ प्रतिशत अंश खपाता है जबकि भारत, जो अमेरिका से दुगनी से भी अधिक जनसंख्या रखता है, एक प्रतिशत से कम का उपभोग करता है। यह असमान वितरण 'विश्व सम्वाद-परिवहन' से सम्बन्धित उस पुनरीक्षित प्रतिवेदन की एक मुख्य बात है जो हाल में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रतिवेदन ने बहुत सी उल्लेखनीय बातों पर प्रकाश डाला है। उदाहरणार्थ, इससे पता चलता है कि योरोपीय लोग विश्व के दैनिक सूचनापत्रों का ५३ प्रतिशत और उत्तर अमेरिका वाले २५ प्रतिशत अंश खरीदते हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के लोग मिलकर केवल १५ प्रतिशत अंश खरीदते हैं। सूचनापत्रों का सबसे अधिक उपभोग ब्रिटिश लोग करते हैं जिनमें प्रति हज़ार ५६६ प्रतियों का सर्क्युलेशन होता है।

सोवियट रूस में, जहां की जनसंख्या १६,३०,००,००० है, ७७०० दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकलते हैं जिनका संयुक्त सर्क्युलेशन ३,३५,००,००० है। अखबारी कागज़ की कमी को दूर करने की दृष्टि से, भारत कच्ची सामग्री के रूप में बांस का रेशा प्रयुक्त कर रहा है जबकि चीन चावल का कागज़ इस्तेमाल करता है। उत्तरी अमेरिका में विश्व के रेडियो सेटों का ५३ प्रतिशत और योरप में ३५ प्रतिशत अंश मौजूद हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका मिलकर केवल ११ प्रतिशत रखते हैं। टेलीविज़न १७ देशों में संचालित या विकसित किया जा रहा है किन्तु अब तक प्रोग्राम नियमितरूप से केवल चार देशों —— ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियट संघ और फ्रांस —— में प्रसारित किये जाते हैं। नाटकीय फिल्मों के सबसे बड़े निर्माता क्रमानुसार अमेरिका, भारत, जापान और इटली हैं। इज़रायल के लोग अत्यधिक सिनेमा देखने जाते हैं। प्रतिवेदन की ये बातें पिछले तीन वर्षों (१९४८-४९-५०) के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उ द् दे श्य और उ पा य

ब्रिटिश लोगों का विश्वास है कि उन्हें मलाया में एक उद्देश्य पूरा करना है । इस उद्देश्य का परित्याग वे तबतक नहीं करेंगे जबतक उन्हें यह निश्चय न हो जाए कि आतंकवाद का सम्पूर्ण अन्त हो गया है और सब समुदायों की भावी सहकारिता सच्चे और स्थिर स्वशासन की ओर बढ़ेगी । इस सहकारिता का मार्ग निस्सन्देह लम्बा होगा , शायद बहुत लम्बा । ... पर हम उसकी रक्षा करेंगे । ... ... हम तबतक नहीं हटेंगे जबतक हमारे लक्ष्य : जो सब प्रजातियों के लिए एकसे हैं : पूरे नहीं हो जाते । मेरा यह भी विश्वास है कि , स्वशासन प्राप्त हो जाने पर भी , ब्रिटेन के लिए मलाया में एक स्थान रहेगा , ब्रिटेन को मलाया में एक भाग लेना है। अन्य प्रजातियों के अपने सब साथी नागरिकों के साथ ब्रिटेन के सबलोग यह जान लें कि मलाया में उनके सामने एक भविष्य है : पहले तो समस्त समुदायों के मध्य सहकारिता उत्पन्न करने में और उसके बाद उस संयुक्त , स्वशासित मलाया में जिसका आविर्भाव होगा ।

आलिवर लिटिलटन,
औपनिवेशिक सचिव
११ दिसम्बर

** ** **

मैं आपके (डाक्टर एडेन्यौर के) इस विचार से सहमत हूं कि हमारा मिलन यौरप की एकता और विश्व शांति को बलशाली बनाने के हमारे सामान्य कार्य में बहुत उपयोगी रहा है ।

विन्सटन चर्चिल,
प्रधान मन्त्री
१० दिसम्बर

...तीन पश्चिमी

तीन (पश्चिमी) शक्तियों के हम लोग समझते हैं कि सोवियट (निशस्त्रीकरण) प्रस्तावों का परिणाम अणु आयुधों को रीतिबद्ध शस्त्रास्त्रों से पृथक करना होगा : चाहे ये प्रस्ताव कुछ भी कहें। इनका इस प्रकार पृथक किया जाना हमें अस्वीकार्य है। हमारे विचार से सोवियट की स्थिति यह है : पश्चिमी शक्तियां अपने प्रमुख्य आयुध का परित्याग कर दें ताकि अभ्याक्रमण के उन साधनों पर सोवियट यूनियन का अनियंत्रित अधिकार हो जाए जिनके उपयोग को निरूत्साहित करने में वह आयुध आजकल काम आ रहा है। जबतक सोवियट यूनियन साथ साथ (अन्तर्राष्ट्रीय देखरेख में) उन आयुधों और सेनाओं में कमी नहीं करता जो, हमारे विचार से, विश्व शांति को आपत्तिग्रस्त कर रही हैं, तबतक उस आयुध का परित्याग हम नहीं करेंगे जो शान्ति बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण हैं।

जे० सेल्विन लायड,
वैदेशिक विषयों के राज्य मन्त्री,
११ दिसम्बर

** ** **

वर्तमान अशांति को कम करना राजनय का प्रथम प्रयोजन है। इस अभीष्ठ की प्राप्ति के लिए हमें उस रीति को पलटना है जो आजकल इतनी प्रचलित है और जिसकी सहायता से राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग अपने अपने विचारों के पक्ष में यथाशक्ति चिल्लाने के लिये किया जाता है।

ऐन्टनी ईडेन,
विदेश मन्त्री
१० दिसम्बर

राष्ट्रमंडल संसदीय सभा

कोलम्बो में राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन की जनरल कौंसिल की एक सभा जनवरी में होगी जिसके लिये ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल में लार्ड लेवेलिन तथा विलियम ग्लेनविल हाल (संसद सदस्य) और सर हावर्ड डी एग्वाइल (कौंसिल के सचिव) सम्मिलित रहेंगे । ४७ सदस्यों वाली राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन की सभी मुख्य शाखाओं का ८ जनवरी को प्रारम्भ होने वाली सभा में प्रतिनिधित्व किया जायेगा। वे लोग १९५० ५१ के वर्ष में एसोसिएशन की कार्यवाइयों से सम्बन्धित रिपोर्ट और अगले राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन , जो शायद १९५२ के दिवतीय अर्द्ध भाग में होगा , के प्रबन्धों के विषय में विचार विनिमय करेंगे ।

** ** **

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिव्दलीय एकता

नई ब्रिटिश संसद के प्रथम अधिवेशन की समाप्ति के विषय में 'आबज़र्वर' पत्र ने १२ दिसम्बर के अंक में इस बात से सन्तोष प्रकट किया है कि दलीय राजनीति का तापमान जो दो वर्ष पहले इतना बढ़ाचढ़ा था अब गिरकर साधारण स्तर पर आ गया है । पत्र लिखता है : नई संसद के प्रथम मास ने दलों के मध्य एक बड़े क्षेत्र पर एकता स्थापित की है । वैदेशिक विषयों और प्रतिरक्षा सम्बन्धी वाद विवादों से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्पूर्ण दिव्दलीय एकता प्रकट हुई है ।

... ब्रिटेन ने

विदेशों को ब्रिटेन ने सहायता पहुंचाई

ब्रिटेन ने विदेशों और अन्तर्राष्ट्री एजेंसियों को दिव्तीय युद्ध के अन्त से लेकर जून १९५१ तक उपहारों और ऋण के रूप में १,२८,५०,००,००० पौंड प्रदान किये थे। यह बात ब्रिटेन के वित्त मन्त्री के एक वक्तव्य में प्रकट की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियों को दिये गये उपहारों में वे नियमित सहायता या चन्दे सम्मिलित नहीं हैं जो संयुक्त राष्ट्रों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को दिये जाते हैं।

** ** **

ब्रिटेन में पूर्वदेशों की पढ़ाई

पूर्वदेशीय और अफ्रीकी अध्ययनों के लन्दन स्कूल में अन्य विदेशी छात्रों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या अधिक है। यह बात स्कूल की हाल में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट हुई है। इससे पता चलता है कि १९५० ५१ वाले वर्ष के दौरान में स्कूल के १८९ विदेशी विद्यार्थियों में से ७९ राष्ट्रमंडल से आये जिनमें ३२ भारतीय छात्र सम्मिलित थे। इनमें से बहुत से छात्र भारतीय उप महादव्ीप और लंका की प्राचीन तथा आधुनिक भाषाओं और संस्कृति से सम्बन्धित कार्य में लगे हुए थे। इस स्कूल के वित्तीय सहायकों में भारत, पाकिस्तान और लंका की सरकारें भी सम्मिलित हैं। इसके शासी निकाय में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर श्री० वी० के० कृष्णा मेनन दव्ारा किया जाता है।

सूडान की कपास स्कीम से लाभ

प्रत्येक कृषक-भाटकी को आठ हजार रूपयों से अधिक

जान हिस्लाप,
'सूडान स्टार' के युद्धकालिक सम्पादक

भारत को सूडान की कपास के निर्यात से सम्बन्धित एक प्रबन्ध को पक्का करने के लिये सूडान से एक व्यापार मिशन शीघ्र नई दिल्ली आने वाला है। इस मिशन के प्रधान हैं आर्थर गैतस्केल, 'जज़ीरा बोर्ड' के साधारण प्रबन्धक। यह बोर्ड 'जज़ीरा कपास स्कीम' के तीन भागियों में से एक है।

'जज़ीरा कपास स्कीम' ने, जो संसार के अत्यधिक सफल वैज्ञानिक और सामाजिक प्रयोगों में से एक है, आंग्ल-मिश्री सूडान को नई सम्पत्ति प्रदान की है, हज़ारों कृषक-भाटकीयों (काश्तकारों) और उनके सम्बन्धियों का जीवनस्तर ऊपर उठाया है तथा मिश्र के इस दक्षिणी पड़ोसी के लिये १९५१ को उच्च सम्पन्नता का साल बनाया है।

'जज़ीरा', अथवा द्विीप, उसत्रिभुजाकार प्रदेश का नाम है जिसकी बाह्य रेखा लगभग समतल है और जो वाइट तथा बूलू नील नदियों (जिनका संगम राजधानी, खरतूम, के ठीक दक्षिण में है) के मध्य में अवस्थित है। इस सिक्त भूमि के दस लाख एकड़ों पर उच्च श्रेणी के कपास और अनाज का उत्पादन

... लाभों के

लाभों के विभाजन के आधार पर होता है । इस स्कीम में तीन भागी हैं : कृषक-भाटकी, जो कपास उगाते और चुनते हैं, सूडान की सरकार, जिसने भूमि दी और महान सेनार बांध तथा सिंचाई स्कीम की मुख्य नहरों का निर्माण किया और अभी भी उनकी देखभाल करती है, और ' जज़ीरा बोर्ड ', जिसके निरीक्षक कृषिकर्म का पर्यवेक्षण करते हैं, तथा कपास बटोरते, ओटते और उसकी हाट-व्यवस्था करते हैं ।

भूमि अधिकार प्रणाली की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, यद्यपि सरकार आदिम रूप से भूमि को उसके स्वामियों से पट्टे पर लेती है, पर भूमि के स्वामियों के आत्मधृत अधिकार (फ्री होल्ड राइट्स) बने हुये हैं और ये, जबतक भूमि को इतने छोटे भागों में नहीं बांटते कि स्कीम के अन्तर्गत उनका प्रशासन असम्भव हो जाए, तबतक अपनी इच्छानुसार भूमि का हस्तान्तरण कर सकते हैं ।

भूमि प्राप्त करने के बाद कृषक-भाटकीयों को उसपर कृषिकर्म ' जज़ीरा ' अनुसन्धान प्रक्षेत्र दव्ारा रचित युक्तियों के अनुसार तथा बोर्ड के सम्पदाप्रबन्धकों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत करना पड़ता है । सस्य आवर्तन (क्राप रोटेशन : फसलों की हेरफेर) प्रणाली स्कीम के समारम्भ से उपलब्ध अनुभव पर आश्रित है । यहां बारी बारी से तीन फसलें उगाई जाती हैं : कपास, ' डूरा ' (अनाज) और ' ल्यूबिया ' (चारा) । ' डूरा ', जो सूडानियों का प्रमुख आहार है, और ल्यूबिया पर कृषक-भाटकी का अधिकार होता है । इन्हें वह प्रयुक्त करता अथवा, जैसा वह ठीक समझे, बेचता है । पर कपास उसे बोर्ड को देनी होती है : ओटने तथा हाट व्यवस्था के लिए ।

कपास की बिक्री से वार्षिक लाभ एक संयुक्त कपास लेखे में समाकलित (क्रेडिटेड) किए जाते हैं और ओटने, बोरियों, गांठों, यातायात, बीमा, भाड़े और हाट व्यवस्था के व्यय विकलित (डेबिटेड) किए जाते हैं । शेष विभाजित किया जाता है : सरकार और कृषक-भाटकीयों को ४० प्रतिशत (प्रत्येक को चालीस) और बोर्ड को २० प्रतिशत ।

सेनार बांध

जल की सप्लाई स्कीम के संचालन की एक बड़ी कठिनाई है । कृषिकर्म के क्षेत्र की, जो व्हाइट और ब्लू नील नदियों के मध्य की त्रिभुजाकार भूमि में

... अवस्थित है

अवस्थित है, सिंचाई नदी से होती है और जलाशय में संग्रह से पानी का नियमित प्रवाह रक्खा जाता है। इस जलाशय की रचना ब्लू नील नदी पर सेनार बांध के बनाने से हुई है। नील नदी के प्रवाह और उसके जल के उपयोग पर १९२९ के एक समझौते का नियन्त्रण है। इस समझौते के अनुसार बाढ़ की अवधि, मध्यजुलाई से दिसम्बर, में सूडान बिना किसी रोकटोक के ले सकता है पर अन्य समयों में केवल दो प्रतिशत।

सेनार बांध 'जजीरा' सिंचाई स्कीम का प्रधान इंजीनियरिंग अंग है। इसकी रचना एक करोड़ तीस लाख पौंडों के उस ऋण की सहायता से हुई थी जो प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इसकी लम्बाई ३ हज़ार मीटर है और इसमें जल प्रवाह नियन्त्रण के लिये ८० जलमार्ग हैं। नहर प्रणाली के अन्तर्गत ३३० किलोमीटरों की प्रमुख और अप्रमुख नहरें हैं तथा ६४३ किलोमीटरों की प्रमुख और ३,२२६ किलोमीटरों की अप्रमुख विभाजिकाएं (डिस्ट्रीब्यूट्रीज़)। इस जलाशय की अधिकतम संग्रह-क्षमता ७८ करोड़ दस लाख घन मीटर है।

स्कीम का समारम्भ

इस स्कीम का समारम्भ एक छोटे प्रयोगात्मक प्रयास के रूप में १९०४ में हुआ था और पहले पहल उसकी वित्तीय व्यवस्था 'सूडान एक्सपेरिमेन्टल प्लान्टेशन्स सिन्डीकेट' द्वारा की गई थी। इसे पूंजी की प्राप्ति लन्दन से हुई थी। इसके बाद कसाला काटन कम्पनी ने, जिसने सूडान में अन्यत्र कार्य प्रारम्भ किया था, अपना वह उद्यम (गाश एन्टरप्राइज़) सरकार को दे दिया और उपर्युक्त सिन्डीकेट में सम्मिलित हो गई।

इस स्कीम के अन्तर्गत कपास उगाने के अधिकार पहले पहल ऐसे स्थानीय लोगों को दिये गये थे जो भूमि पर पहले कृषिकर्म कर चुकने के प्रमाण दे सकते थे। २५ वर्षों तक यह स्कीम न्यूनाधिक सफलता के साथ संचालित होती रही।

१९५० में सरकार ने स्कीम का राष्ट्रीयकरण किया। (अपने इस उद्देश्य की पूर्व सूचना वह पांच वर्ष हुए दे चुकी थी)। उसने दोनों कम्पनियों की ठोस सम्पत्तियां खरीद लीं। तब ये कम्पनियां अपनी इच्छा से बन्द हो गई और उन्होंने अपने हिस्सेदारों को संचयों से तथा पिछले वर्ष की फसल के लाभ से पैसा दिया। कम्पनियों का स्थान एक 'जन उपयोगिता बोर्ड' ने ले लिया। यह बोर्ड अपने आन्तरिक

... कार्यों में

कार्यों में सरकार की ओर से स्वतन्त्र है। इसका प्रबन्ध श्री० आर्थर गेतस्केल करते हैं। इससे पहले वे 'सूडान प्लान्टेशन सिन्डीकेट' का प्रबन्ध करते थे। कम्पनियों द्वारा प्रारंभित लाभ-विभाजन जारी रखा गया : पर एक अन्तर के साथ। बोर्ड के २० प्रतिशत का उपयोग उसे फिर संचयों में रखने के लिये, मशीनरी की देखभाल तथा कृषक-भाटकीयों की सुख सुविधा के लिये किया गया।

विश्व पुन:शस्त्रीकरण, सामग्री संग्रह और सफल फसल के कारण राष्ट्रीकरण के प्रथम वर्ष के परिणामस्वरूप रिकार्ड लाभ प्रकट हुआ। इसमें २४,७८७ कृषक-भाटकीयों ने एक करोड़ ६० लाख पौंडों, अथवा २१.३३ करोड़ रूपयों,का लाभ पाया, अर्थात् प्रत्येक को ६५० पौंड,अथवा ८,६०० रूपये। इसकी तुलना में १९३९ में ३० पौंडों अथवा ४०० रूपयों का लाभ हुआ था।

कृषक-भाटकी अपने भाग अपने गृहों और गृहों की सामग्रियों को सुधारने, अधिक पौष्टिक आहार खाने, अपनी स्त्रियों को आभूषणादि देने और, सामान्यतया, स्वयं अपने लिये और अपने सम्बन्धियों लिये अधिक अच्छे जीवन का सुख उठाने में प्रयुक्त कर रहे हैं। सरकार अपना भाग एक पंच वर्ष विकास योजना के लिये लगा रही है। कहना आवश्यक है कि इस योजना के लिये उसने साधारण वार्षिक व्यय के अतिरिक्त २४ करोड़ पौंड, अथवा ३२ करोड़ रूपये, अलग रखे हैं। इसका व्यय नई सड़कों, अधिक अच्छे टेलिफोन संचार, विद्यालयों और अस्पतालों तथा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान पर होगा। कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान के अन्तर्गत पशु के रोगों के निवारण और कपास के अतिरिक्त अन्य फसलों के अन्वेषण आते हैं। वर्षा के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के यन्त्रीकरण पर बहुत धन लगाया जा रहा है और,कैनडा के विशेषज्ञों की देखरेख,में सूडानियों को कृषिकर्म सम्बन्धी यन्त्रों के संचालन सिखाने पर भी।

बोर्ड के लाभ का एक बड़ा भाग कृषि अनुसन्धान और कृषक भाटकीयों की शिक्षा, उन्हें सामुदायिक उत्तरदायित्व सिखाने, बढ़इयों और कारीगरों के प्रशिक्षण, एक समाचारपत्र के संचालन और स्कीम में अभिमान तथा उसकी सफलता में दायित्व के ज्ञान पर लगाया जा रहा है।

भारत में तेल शोधन उद्योग का विकास

'इकानमिस्ट' का मत

लन्दन के 'इकानमिस्ट' नामक पत्र ने भारत के तेल शोधन उद्योग के विकास के सम्बन्ध में अपने अंक में लिखा है :

ऐसा दिखाई देता है कि उस शोधकशाला के बाद जिसका बम्बई के निकट ट्राम्बे नामक स्थान पर निर्माण करने के लिये न्यूयार्क की स्टैन्डर्ड वैकम आयल कम्पनी ने अनुमति प्राप्त कर ली है भारत में और भी शोधकशालाएं खुलेंगी । भारत सरकार, जिसने स्टैन्डर्ड वैकम शोधकशाला के लिये इस सप्ताह अपनी अनुमति दी, एक दूसरी शोधकशाला (जो सम्भवतया बम्बई में ही खुलेगी) के लिये बर्मा-शैल से भी बातचीत कर ली है। इसके अतिरिक्त कल्टेक्स नामक कम्पनी मद्रास में एक तीसरी शोधकशाला के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अपने प्रतिनिधि भेज रही है।भारत सरकार ने इन कम्पनियों से भारतमें शोधन कार्य पर विचार करने के लिये पहले-पहल १९४८ में कहा था । इस वर्ष बढ़ती हुई आन्तरिक मांग और अबादान (जिसपर भारत अपने लगभग तीन चौथाई तेल पदार्थ आयातों के लिये निर्भर था) की हानि के कारण शीघ्र ही एक दूसरा निमन्त्रण भेजना पड़ा ।

आगे चलकर पत्र लिखता है कि भारत सरकार कम्पनियों को राष्ट्रीयता की सम्भावित क्षतियों से वित्तीय सुरक्षा का विश्वास दिलाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। स्टैन्डर्ड-वैकम कम्पनी ने अपनी शोधकशाला के राष्ट्रीयकरण न होने की २५ वर्ष की गारंटी लेली है और यदि आगे चलकर राष्ट्रीयकरण का निर्णय हो तो पर्याप्त मुआवज़े का आश्वासन प्राप्त कर लिया है। कच्चा तेल शुल्क दिये बिना आयात किया जायेगा और शोधकशाला की तैयारी के लिये यन्त्र-साधन भी घटे हुए शुल्क पर मंगाये जा सकेंगे। कम्पनी अपने नफों को अमेरिका भेजने के लिये पर्याप्त विदेशी विनिमय प्राप्त करेगी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शोधकशाला के पदार्थों को उन मूल्यों से (जो आयात किये गये तेल पदार्थों के लिये प्राप्त किये जाते हैं) कम पर बेचने के लिये कोई मांग नहीं की जायेगी । नई शोधकशालाएं और दिग्बोई स्थित वह छोटी शोधकशाला भी जो आसाम के तेल क्षेत्रों की उत्पत्ति का शोधन करती है लगभग उस सारी मांग को पूरी कर सकेंगी जिसका बढ़ना निश्चय है ।

'नए इतिहास' का रूप

साशलिस्ट यूनिटी कम्यूनिस्ट पार्टी पूर्वी जर्मनी की ने मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तों के आधार पर इतिहास की एक नई पाठ्य पुस्तक का आदेश दिया है। पश्चिमी जर्मनी की प्रेस एजेन्सी के अनुसार, विचार यह है कि नई पुस्तक 'योग्यताप्राप्त लेखकों' द्वारा सामूहिक रूप से रची जाए और १९५३ तक छपकर तैयार हो जाए। यह पुस्तक 'साम्राज्यवादी मार्ग के घातक गुणों' का जर्मन इतिहास के उदाहरणों से निदर्शन करेगी। यह पुस्तक सोवियट यूनियन के साथ शान्तिमय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालेगी और सोवियट कामकाजी वर्ग का प्रमुख भाग प्रकट करेगी। यह पुस्तक 'इतिहास' के विषय में 'पहले की' 'अवैज्ञानिक विचारधाराओं' का विरोध करेगी।

लिबिया में ब्रिटिश दूत

सर एलेक कर्कब्राइड, जो आजकल जार्डन में मन्त्री नियुक्त हैं, लिबिया में ब्रिटेन के पहले दूत बनाए गए हैं।

यह निर्णय साइरेनाइका के अमीर के संवैधानिक राजतंत्र के अन्तर्गत लिबिया के एक स्वतन्त्र प्रभुतासम्पन्न राज्य के रूप में आविर्भाव की ओर अन्य चरण का चिन्ह है।

ना वं ग न में न व जी व न

****

हैरल्ड हचिन्सन

कुछ सप्ताह पूर्व कई सौ जहाज़ीघाट श्रमिक , जो आमतौर पर ब्रिटेन के प्रबलतम तथा अत्यन्त स्वतन्त्र लोग समझे जाते हैं , स्वेच्छिकरूप से आक्सफर्ड विश्व विद्यालय के एक ऐतिहासिक कालेज में भाषण सुनने के लिये कुछ दिन व्यतीत करने गये थे । इससे उस परिवर्तन का पता चलता है जो पिछले दस वर्षों में न केवल आक्सफर्ड के दृष्टिकोण किन्तु जहाज़ीघाट (नावंगन) की रूपरेखा में हुआ है ।

आजकल ब्रिटेन के ८३ बन्दरगाहों पर ८०,००० जहाज़ीघाट श्रमिक काम करते हैं और वे देश की एक सबसे बड़ी श्रम समस्या हो सकते हैं और कई बार रहे भी हैं । युद्ध से पहले का तुलना में उत्पादन ५० प्रतिशत और निर्यात ७५ प्रतिशत अधिक हैं ।

ब्रिटेन के रहन सहन में युद्ध के बाद होने वाले सभी परिवर्तनों में जहाज़ीघाट श्रमिकों से सम्बन्धित परिवर्तन सम्पूर्ण रहा है। इन लोगों से समय समय पर काम लिया जाता था अर्थात् वे अनियमित कामकाजी थे । वे अत्यधिक स्वतन्त्र विचारों के व्यक्ति थे । उनकी यह आदत एक परम्परा बन गई । लगभग ये सभी कामकाजी जहाज़ीघाट श्रमिकों के बेटे पोते हैं और इस स्वतन्त्र दृष्टिकोण और विचार के परिणामों का भय उनके सामने नहीं था । वे आपस में बहुत मिलजुल कर रहते और किसी भी झगड़े में पूर्णतया संगठित हो जाते थे । किसी भी घाट श्रमिक ने कभी भी हड़ताल का कारण नहीं पूछा , बस वह तो उसमें शामिल हो जाता था ।

१९४० में ब्रिटेन ने , जहाज़ीघाट में अनियमित श्रम का अन्त करने की दृष्टि से, प्रत्येक घाट श्रमिक का नाम दर्ज कर लिया था , और १९४१ में ऐसा उपबन्ध किया गया कि यदि घाट श्रमिक प्रात: और दोपहर की हाजरी के समय काम पर मौजूद रहे तो, चाहे काम हो या न हो, उसे 'हाज़री मज़दूरी' और एक गारंटी की हुई न्यूनतम मज़दूरी दी जाये । यह बात घाट श्रमिकों को एक अनुशासित , नियमित तथा कार्यकुशलता बढ़ाने वाले परिवर्तनों के प्रेमी श्रमिकवर्ग के रूप में परिवर्तित करने के

... प्रयास की

प्रयास की प्रथम चरण थी । परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से , डाक लेबर बोर्ड (जहाज़ीघाट श्रमिक मंडल) , जो सभी जहाज़ीघाट कामकाजियों का अन्तिम नियोजक है , जहाज़ीघाट के कार्य और सामाजिक जीवन को परिवर्तित कर रही है । जलपानगृह, स्नानागार , बचाव करने वाले वस्त्र , खेल-कूद क्लब आदि चीज़े प्रदान की जा रही हैं । मुख्य जहाज़ीघाटों के २८ बन्दरगाह चिकित्सा केन्द्रों ने १९५० में अस्वस्थता के दो लाख मामलों की चिकित्सा की जिससे कार्य-घन्टों की बहुत भारी बचत हुई थी।

यद्यपि १४०० व्यक्तिगत नियोजक अभी हैं पर डाक लेबर बोर्ड , जो कामकाजियों और नियोजकों का समानरूप से प्रतिनिधित्व करता है , सम्पूर्ण श्रम स्कीम और हरेक की ओर से सारा कल्याण कार्य संचालित करता है । प्रत्येक नियोजक बोर्ड द्वारा नियन्त्रित संगठन से उतने कामकाजी लेकर नियुक्त कर लेता है जितने की उसको दिन या सप्ताह के लिये आवश्यकता होती है और इसके बदले में कुल मज़दूरी का कुछ प्रतिशत भाग बोर्ड को देता है । बोर्ड इसी रकम में से 'हाज़री मज़दूरी' तथा उन लोगों को उस दिन जिस दिन उन्हें कोई काम-धन्धा न मिले गारंटी किया हुआ न्यूनतम वेतन देता और नई कल्याण सेवाओं का खर्च निकालता है ।

वह जहाज़ीघाट श्रमिक जो युद्ध से पहले अपनी मर्ज़ी से काम करता था आज संयुक्त संगठन के लिये आश्चर्यजनक तत्परता और रूचि दिखाने लगा है। क्योंकि उनके लिये प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण , सन्ध्याकालिक तथा सप्ताहांत वाले शिक्षाक्रम , सामाजिक क्लब , ग्रीष्मकालिक नाव दौड़ें , मुक्काबाज़ी प्रतियोगिताएं तथा गेंद खेल और बूढ़े जहाज़ीघाट श्रमिकों तथा बच्चों के लिये विशेष सैर-तफरी की व्यवस्था जैसी सभी बातें उन कल्याण सेवाओं में सम्मिलित हैं जो अबतक संगठित की जा चुकी हैं ।

कुछ ही वर्षों में जहाज़ीघाट श्रमिकों के जीवन का सम्पूर्ण नमूना बदल दिया गया है । उत्तरदायित्वविहीन और सामाजिक सोपान के सबसे नीचे अंग पर अवस्थित व्यक्तियों से इन्होंने इस सोपान के उच्चतम भाग पर उड़ान कर ली है । देश के लिये यह बात आर्थिक और सामाजिक लाभ के रूप में प्रकट हुई है ।

शारीरिक निर्योग्यता के शिकार

उपयोगी उपहार

बर्मिंघम की एक फ़र्म ने दुर्घटना अस्पताल के सहयोग से एक बैसाखी (शारीरिक अयोग्यताग्रस्त लोगों के सहारे की लकड़ी) बनाई है। यह बैसाखी अल्मोनियम की है। यह त्रुटिहीन बैसाखी कही गई है। यह बहुत सुरक्षित और हल्की है। इसमें आराम प्रदान करने की एक युक्ति भी लगी है।

मारिसक आस्टिन का संविलयन

मोटर उद्योग की अत्यन्त बड़ी व्यापारिक संस्थाओं : नफील्ड संगठन और आस्टिन मोटर कम्पनी : के संविलयन को ब्रिटिश उद्योग के इतिहास की सबसे बड़ी घटना कहा गया है। ब्रिटेन के मोटरकार उत्पादन का आधा इन दोनों फर्मों द्वारा मिलकर होता है। आजकल प्रत्येक की वार्षिक उत्पत्ति १५,००० एकक (यूनिट) है। इन दोनों में मिलकर ४२,००० कामकाजी है और इनके पास साढ़े छः करोड़ पौंडों से अधिक की सम्पत्ति है। इस संविलयन की घोषणा के पीछे ब्रिटिश उद्योग की सफलता की दो बहुत बड़ी गाथाएं हैं।

सबसे ऊंचा भवन

'मास्को का सबसे ऊंचा भवन कौन है?', एक सोवियट नागरिक ने अपने मित्र से पूछा।

'लेनिन विश्वविद्यालय', उसने कहा।

'नहीं, नहीं, पहला बोला। 'सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है, यहां से साइबेरिया दिखाई देता है।'

नाइजीरिया में उन्नति का निदर्शन

राजनैतिक और संवैधानिक गति-वर्द्धन

ट्रेवर ब्लोर
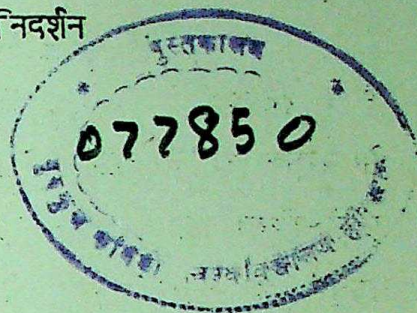
राष्ट्रमंडल के अन्दर स्वशासन : इस लक्ष्य के प्रति औपनिवेशिक प्रदेशों की प्रगति में आर्थिक और संवैधानिक उन्नति को साथ साथ पग बढ़ाना चाहिए। इस सिद्धान्त के निदर्शन के लिए नाइजीरिया से प्राप्त नई नई रिपोर्टों पर निगाह डालिए । पश्चिम अफ्रीकी प्रदेशों में इस सबसे बड़े प्रदेश ने पिछले चार वर्षों में राजनैतिक प्रगति का आकर्षक परिचय दिया है। उधर , आर्थिक उन्नति ने राजनैतिक उन्नति का अच्छा साथ दिया है। आर्थिक उन्नति का नवीनतम उल्लेख नाइजीरिया की १९५० की रिपोर्ट में हुआ है । इसका प्रकाशन अभी भी लन्दन से हुआ है ।

नए संविधान के अन्तर्गत एसेम्बली के तीनों क्षेत्रीय सदनों के सदस्यों का निर्वाचन प्रधान निर्वाचकगणों (एलेक्टोरल कालेज) से होगा । क्षेत्रीय सदन अपने सदस्यों के मध्य में से 'सेन्ट्रल हाउस आफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' (केन्द्रीय प्रतिनिधि सदन) के सदस्य चुनेंगे । नए संविधान के तीन प्राथमिक उद्देश्य ये हैं । समूचे नाइजीरिया की एकता को बनाए रखते और उसे अधिक बलशालिनी बनाते हुए तीनों प्रदेशों — उत्तर , पश्चिम , पूर्व — को अधिक उत्तरदायित्व सम्पन्न करना , २. प्रदेशों और केन्द्रों में , मताधिकार के विस्तार के आधार पर , नई , अधिक प्रतिनिधित्वकारिणी, अधिक विस्तृत अधिकारयुक्त विधायिकाओं की स्थापना , ३. नाइजीरिया के मंत्रियों को अपने कार्यों के संचालनार्थ कुछ दायित्व देना । अब नाइजीरिया के लोग न केवल, हाल के वर्षों की भाँति , विधि (कानून) की रचना में भाग ले सकेंगे पर , एक केन्द्रीय मन्त्रि परिषद और प्रादेशिक कार्यपालिका परिषदों के द्वारा , सरकारी नीति के रूप को निर्धारित करना और उसका कार्यान्वित होना सुनिश्चित करने में भी । आशा है कि नया प्रतिनिधि सदन मार्च १९५२ के नए बजट अधिवेशन से पूर्व एकत्रित होगा ।

... आर्थिक और

विविध प्रगति

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी नाइजीरिया ने बड़ी प्रगति प्रकट की है। १९५० में नाइजीरिया का बाह्य दृश्य व्यापार बढ़कर १४ करोड़ ७० लाख पौंडों से अधिक की रिकार्ड संख्या तक पहुंच गया था और इस प्रकार उसने एक अच्छा सन्तुलन प्रकट किया था। कोको, मूंगफली, गिरी और गरी का तेल उसकी मुख्य निर्यात वस्तुएं हैं। पर कपास और रबड़ के निर्यातों में भी हम अच्छी वृद्धि देखते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, युद्धोत्तरकाल के वर्षों में नाइजीरिया के निर्यातों के लिए प्रदत्त ऊंचे मूल्यों और उनकी बड़ी मांगों ने विपणि व्यवस्था मंडलों (मार्केटिंग बोर्ड) और प्रादेशिक उत्पादन विकास मंडलों को, जो उपनिवेश की अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाएं हैं, बहुत बलशाली बनाया है। उत्पादकों को मूल्यों में भावी गिरावट के समय सहायता देने और अनुसन्धान कार्य के लिये अथवा फसल उत्पादन क्षेत्रों के लाभार्थ बड़ी धनराशि देने के लिये मार्केटिंग बोर्ड प्रबल संचय निर्मित कर सके हैं। एक उदाहरण लीजिए : कोको मार्केटिंग बोर्ड ने इबादान विश्वविद्यालय में कृषि विभाग को १९५० में दस लाख पौंडों का धर्मस्व दिया था और पश्चिम के कोको उत्पादक क्षेत्रों को सड़क सुधार के लिये पांच लाख पौंडों का अंशदान मिला था।

आर्थिक उन्नति का एक अन्य परिचय सहकारिता आन्दोलन की गति के असाधारण वर्द्धन में मिलता है। आज नाइजीरिया में एक हज़ार एक सौ सहकारिता समितियां हैं। इनकी सम्पूर्ण सदस्य संख्या ७० हज़ार से भी अधिक है। इनकी चालू पूंजी लगभग पांच लाख पौंड हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी नाइजीरिया ने उल्लेखनीय उन्नति का परिचय दिया है। "नाइजीरिया में शिक्षाकार्य शीघ्रता से बढ़ रहा है", रिपोर्ट ने लिखा है।